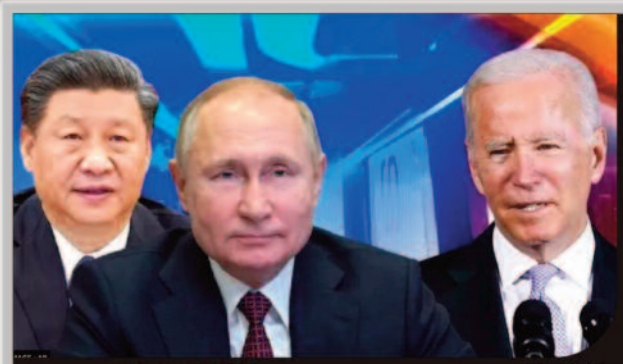

क्या 'विश्व व्यवस्था' बदलनी शुरू हो गयी है?

वैश्विक आर्थिक युद्ध के परिणाम क्या होंगे?

यूक्रेन में जीत के करीब पुतिन की सेना, यूक्रेन के साथ ही हारेगा अमेरिका-नाटो?

मूल्य 30/-

अप्रैल, 2022

डायलॉग इंडिया

परिवर्तन की चाह.. संवाद की राह

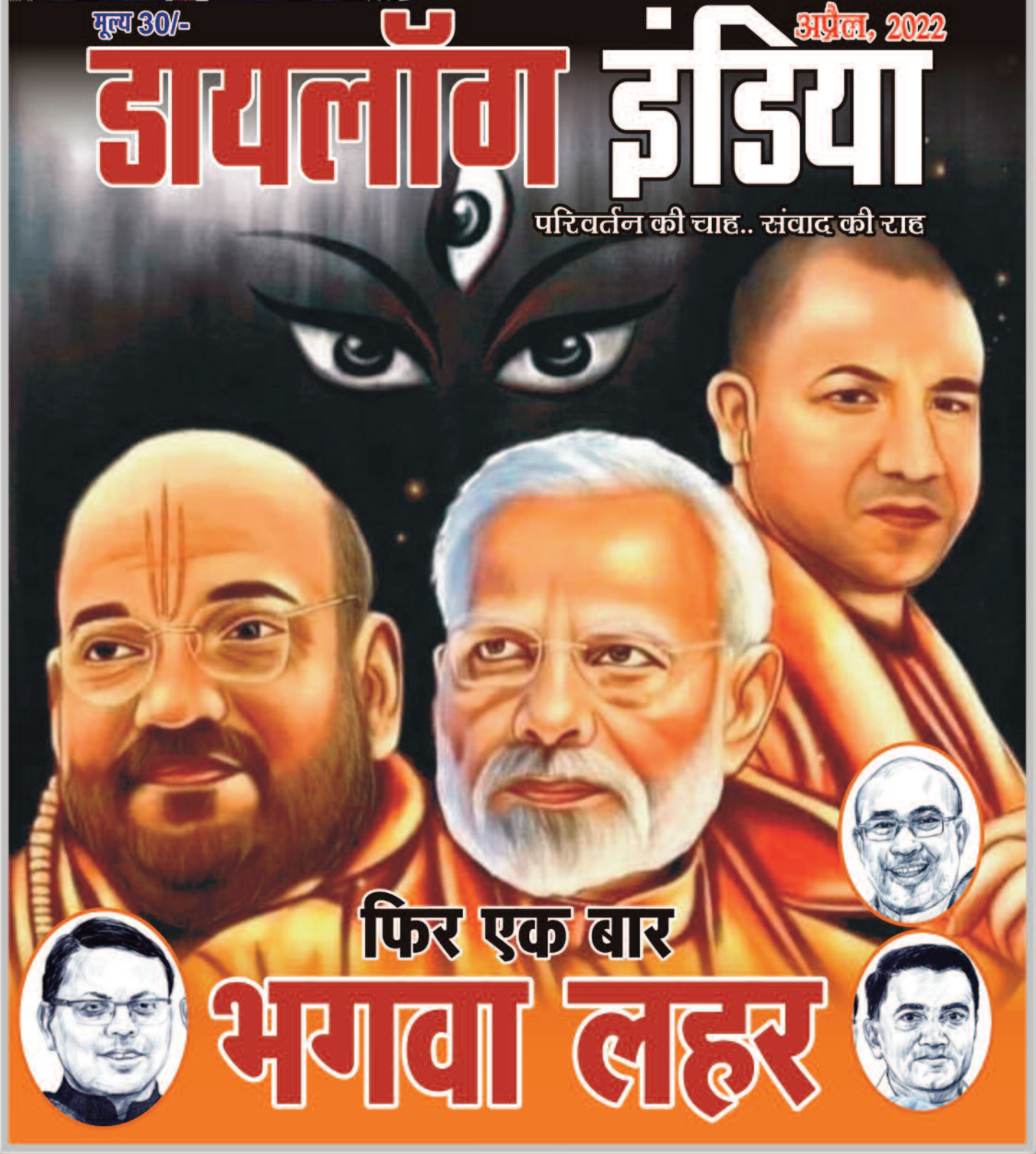

फिर एक बार भगवा लहर

भूगोल
(हिंदी माध्यम)
Career Plus Online
ONLINE - OFFLINE
For
WEEKEND COURSES
IAS/PCS By S.M.Zaki Ahmad
From 26th Feb. onwords
TIMING 2-6 p.m
(Classes Every Friday & Saturday)
Registered within 7day and Avail 50% discount
Call @ 9310151465, 9891086435,9811069629

समाज शास्त्र
(हिंदी माध्यम)
Career Plus Online
ONLINE - OFFLINE
For
WEEKEND COURSES
IAS/PCS By S.Kumar Sir
From 26th Feb. onwords
TIMING 10-2 p.m
(Classes Every Saturday & Sunday)
Registered within 7day and Avail 50% discount
Call @ 9310151465, 9891086435,9811069629

इतिहास
(हिंदी माध्यम)
Career Plus Online
visit us CAREER PLUS online.com
ONLINE - OFFLINE
For
WEEKEND COURSES
IAS/PCS By करुणेश चौधरी सर
From 26th Feb. onwords
TIMING 2 - 6 p.m
(Classes Every Friday & Saturday)
Registered within 7day and Avail 50% discount
Call @ 9310151465, 9891086435,9811069629

लोक प्रशासन
(हिंदी माध्यम)
Career Plus Online
ONLINE - OFFLINE
For
WEEKEND COURSES
IAS/PCS By HARUN SIR
From 26th Feb. onwords
TIMING 2 - 6 p.m
(Classes Every Friday & Saturday)
Registered within 7day and Avail 50% discount

राजनीति विज्ञान
(हिंदी माध्यम)
Career Plus Online
ONLINE - OFFLINE
For
WEEKEND COURSES
IAS/PCS By SUDHIR SIR
From 26th Feb. onwords
TIMING 10-2 p.m
(Classes Every Friday & Saturday)
Registered within 7day and Avail 50% discount

विषय सूची

डायलॉग इंडिया
परिवर्तन की वाह संवाद की राह

अप्रैल, 2022

बिना युद्ध विराम और शांति के कैसे होगी स्वास्थ्य सुरक्षा?

जा सकती है इमरान खान की सरकार, पर हौसले बुलंद हैं

क्या 'विश्व व्यवस्था' बदलनी शुरू हो गयी है?

यूक्रेन में जीत के करीब पुतिन की सेना, यूक्रेन के साथ ही हारेगा अमेरिका-नाटो?

कश्मीर से केरल सर से लेकर पैर तक एक समान चुनौती

हिजाब पर फैसले में बाबा साहेब की राय कितनी अहम

फिर एक बार भगवा लहर

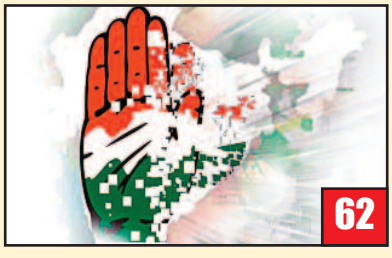

सशक्त लोकतंत्र के लिये सशक्त विपक्ष जरूरी

फसल की बर्बादी ने बढ़ाई खाने की थाली की कीमत

हमारे बारे में

डायलॉग इंडिया
परिवर्तन की राह संवाद की राह

वर्ष- 13 **अंक- 8**

संपादक
अनुज कुमार अग्रवाल

प्रबंध संपादक
डॉ. सारिका अग्रवाल

विशिष्ट संपादक
अमित त्यागी

विशेष संवाददाता
शरीफ भारती, आदित्य गोयल,
डॉ. यशवंत चौधरी, डॉ. अर्चना पाटिल

उप संपादक
नेहा जैन

मुख्य प्रबंधक (डिजिटल मीडिया)
सम्यक अग्रवाल

मुख्य प्रबंधक (विज्ञापन, वितरण एवं प्रसार)
विजय कुमार

जन सम्पर्क अधिकारी
पंकज कुशवाहा

ब्यूरोचीफ
उत्तर प्रदेश - एस.पी. सिंह
मध्य प्रदेश - संजीव चोकोटिया
राजस्थान - रामस्वरूप रावतसरे
बिहार - नंद शर्मा
महाराष्ट्र - तेजेन्द्र सिंह
दिल्ली - जितेन्द्र तिवारी
गौतमबुद्ध नगर - मनीष गुप्ता
गाजियाबाद - घनश्याम शर्मा

डिजाइन एवं ग्राफिक्स
विकास, मनीष, दीपक, रजत

मुख्य कार्यालय : 301/ए, 37-38-39
अंसल बिल्डिंग, कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स
मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन : 011-27652829, 08860787583
फैक्स : 011-27654588
ई-मेल : dialogueindia@yahoo.in
dialogueindia.in@gmail.com
ई-पत्रिका : www.dialogueindia.in

स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक अनुज कुमार अग्रवाल द्वारा स्टेलेंट प्रिंट एन पैक, ए-1, डीएसआईडीसी कॉम्पलैक्स, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली से मुद्रित एवं 301, 37-38-39, अंसल बिल्डिंग, कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 से प्रकाशित

© सर्वाधिकार सुरक्षित

अप्रैल, 2022 माह के लिए प्रकाशित

- डायलॉग इंडिया में प्रकाशित सभी लेख एवं सामग्री लेखकों के स्वयं के हैं, इससे प्रकाशक व सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।
- किसी भी विवाद की स्थिति में हमारा न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

समांतर व नई विश्व व्यवस्था के संघर्ष

जो बाइडेन के अनुसार पुतिन 'युद्ध अपराधी' व 'कसाई' हैं। सच में ऐसा ही है। पुतिन अत्यंत ही क्रूरता से अमेरिका के वर्चस्व की हत्या कर रहे हैं। यूक्रेन पर गिरती हर मिसाइल अमेरिक, नाटो, यूरोपियन यूनियन व जी-7 देशों के घमंड को तोड़ती जा रही है। नाटो देशों के हर नए प्रतिबंधों की घोषणा रूस की युद्ध आक्रामकता को और बढ़ा देती है। रूस यूक्रेन के शहर दर शहर सैन्य ठिकानों को नष्ट करता जा रहा है और उसका वि-सैन्यकरण कर रहा है तो उधर नाटो देशों से हथियारों की नई खेप पहुंच जाती है और फिर दूसरे चरण में रूस यूक्रेन के शहरों को तबाह कर देता है। यूक्रेन के वि-सैन्यकरण व उसको नाजीवाद से मुक्त करने के इस तथाकथित अभियान में यूक्रेन की एक चौथाई जनता विस्थापित हो गयी है इसके बाद भी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलांसकी अमेरिका व नाटो देशों की कठपुतली बन विनाश व तबाही के इस खेल को समाप्त करने को इच्छुक नहीं दिखते, ऐसे में अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद होना तय है। नाटो व अमेरिका के प्रोपेगेंडा के ने भ्रम का बाजार खड़ा कर दिया है और रुस व पुतिन को दैत्य बना दिया है, तरह तरह के हथियारों व युद्धों की आशंकाओं से समाचार चैनल भरे पड़े हैं, यद्यपि सच्चाई यह है कि रूस ने इस युद्ध में अपने हथियारों व सैन्य क्षमता का मात्र दस प्रतिशत ही उपयोग किया है, इसके साथ ही मानवीय क्षति भी बहुत कम हुई हैं और तब भी अधिकांश यूक्रेन उसके कब्जे में आ चुका है और कोई बड़ा युद्ध अभी नहीं होने जा रहा और परमाणु युद्ध तो बिल्कुल भी नहीं। ब्रुसेल्स में इकट्ठे हुए नाटो देश व पोलैंड गए बाईडेन बयानबाजी से ज्यादा कुछ भी न कर सके और उनकी सीमाए दुनिया को समझ आ गयीं। अमेरिका प्रोपेगेंडा के जवाब में रूस ने भी 'परमाणु हमले' के विकल्प को खुले रखने की बात बार बार कहकर यूरोप-अमेरिका सहित पूरी दुनिया को हिला दिया है और पुतिन की इन धमकियों से यूरोपीय देशों की जनता बेहद डर भी गयी है। युद्ध के व्यापारी अमेरिका की इन बयानबाजियों से बांछें खिली हुई हैं और वह 'डर' के इस बाजार को भुनाकर निरंतर मोटा मुनाफा कमा रहा है किंतु पूरी दुनिया हथियारों की होड़, सप्लाई चेन टूटने के कारण बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भूख व भय के बीच जी रही है।रुस देर सबेर यूक्रेन में अपनी कठपुतली सरकार बैठा ही देगा यह सब जानते हैं किंतु अमेरिका इस खेल को लंबा खींचना चाहता है ताकि ज्यादा लाभ कमा सके। साथ ही वह दुनिया के पुलिसमैन बने रहने व रुस को थकाने की अंतिम कोशिश कर रहा है। यधपि बाजी उसके हाथ से निकलती जा रही है। ऐसे में यूक्रेन पर रूस के कब्जे के बाद भी इस क्षेत्र में संघर्ष व तनाव कम नहीं होने जा रहा और रूस के और आक्रमणकारी होने की संभावनाएं प्रबल हो गयी हैं। । अब रुस भी दीर्घकालिक नीति पर काम कर रहा है। इसीलिए तुर्की की मध्यस्थता में वह यूक्रेन से वार्ता कर रहा है।

इस युद्ध का दूसरा व सबसे महत्वपूर्ण पहलू दुनिया के 'एक बाजार' व 'ग्लोबल विलेज' हो जाने के अमेरिका के दावे का छिन्न-भिन्न होना। जिस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां नाटो देशों के इशारों पर रूस से काम समेटने लगीं व अमेरिका ने रूस के विदेशी मुद्रा भंडार को जब्त कर लिया उससे स्पष्ट हो गया कि 'ग्लोबल इकॉनमी' का जैसी कोई अवधारणा नहीं है और इसका एक ही अर्थ है वो है अमेरिका व नाटो द्वारा नियंत्रित विश्व

अर्थव्यवस्था। अमेरिका व नाटो देश दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुए ब्रेटनवुड समझौते व 'डालर के वर्चस्व' के 'माइंडसेट' से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और दुनिया के देशों को अपनी कठपुतली ही समझ रहे हैं। इराक़ युद्ध, जैस्मिन क्रांति,अफगानिस्तान से वापसी और अब रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच जिस प्रकार अमेरिका ने इन देशों की अपने यहां रखे सिक्योरिटी फंड को जब्त किया उससे अमेरिका की साख घटी है और डालर को अंतरराष्ट्रीय लेनदेन की मुद्रा बनाए रखने के निर्णय पर दुनिया के देश मंथन करने लगे हैं। उनको लग रहा है कि उनका अमेरिका में जमा किया गया डालर या अपने पास रखा विदेशी मुद्रा भंडार कहीं मिट्टी न बन जाए। इसी कारण रूस ने यूरोप के देशों से गैस व तेल की आपूर्ति रूबल में ही करने की शर्त रख दी है। यूरोपीय देश भले ही रूबल में भुगतान से इंकार कर रहे हों किंतु गैस की आपूर्ति के लिए रूस पर उनकी निर्भरता उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। रुस भारत सहित अन्य देशों को उनकी ही मुद्रा में व सस्ते दाम पर तेल गैस व अन्य वस्तुएं देने का प्रस्ताव दे भी चुका है। चीन युआन को डॉलर के स्थान पर खड़ा करने के लिए पर्दे के पीछे सक्रिय है। चीन के विदेश मंत्री की दक्षिण एशिया की यात्रा के यही संदर्भ भी हैं और इसलिए वह यूएन में रूस के साथ खड़ा है। चीन अब भारत के साथ अपने संबंध ठीक करने का इच्छुक है और पाकिस्तान में भारत के अनुकूल हो रहे सत्ता परिवर्तन भी बता रहे हैं कि चीन अपना व पाक का भारत के साथ सीमा तनाव खत्म करने की पहल कर रहा है ताकि दक्षिण एशिया में अमेरिकी हस्तक्षेप की संभावना समाप्त हो सके। अमेरिका के उतावलेपन से यूरोप के युद्ध का मैदान बन जाने से चीन और एशिया के अधिकांश देश खुश हैं। वे इसे अगले कुछ वर्षों में यूरोप व अमेरिका के पराभव व 'एशिया की सदीं' के रूप में देख रहे हैं। रुस भी भारत को अपने पाले में लेने की हरसंभव कोशिश में है तो अमेरिकन उप राष्ट्रीय सलाहकार की भारत यात्रा व टू प्लस टू वार्ता की पहल भारत पर डोरे डालने की बड़ी कसरत है। इस बीच चीन 'शंघाई सहयोग संगठन' व 'ब्रिक्स' को बड़ी भूमिका में लाने के लिए सक्रिय हो गया है ताकि वह अमेरिका की जगह ले सके तो जवाब में अमेरिका 'क्वाड' को मजबूत बनाने के लिए लगा है ताकि एशिया उसकी पकड़ से न निकल सके। इधर अमेरिकी गुट के देश भी भारत में निवेश के नए नए समझौते कर भारत को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और रूस-चीन के बीच छिड़ गए इस 'मुद्रा युद्ध' या 'शीत युद्ध' नित नए आयाम ले रहा है। दोनो ही पक्ष दुनिया के राष्ट्रों को अपने अपने पक्ष में करने के लिए हर संभव उपाय कर रहे हैं। एक प्रकार से भारत के लिए यह एक अच्छी स्थिति है। कोरोना महामारी के रूप में 'जैविक युद्ध' दुनिया के सामने आ ही चुका है, अब इसके नए आयाम लेने की संभावना है। साइबर वार, आर्थिक व राजनयिक प्रतिबंध, आर्थिक सहायता, अनुदान, निवेश, सस्ता माल देना, धमकी, हत्या, गृहयुद्ध, तख्तापलट आदि सैकड़ों उपाय अब बड़े पैमाने पर अपनाए जा रहे है व अपनाए जाएंगे जिससे दुनिया में अनिश्चितता व संघर्ष बढ़ना तय है। निश्चित ही यह दशक दुनिया पर भारी पड़ रहा है और आगे भी पड़ेगा। तरह तरह के संघर्ष और गुटबाजी सामने आएंगे। डॉलर-पाउंड-यूरो की दुनिया बिखरने से बचाने के लिए नाटो देश किसी भी हद तक जा सकते हैं। आईएमएफ, विश्व बैंक और डब्ल्यूटीओ पर कब्जे या उसका स्वरूप बदलने की चीन-रूस की कोशिशें तीव्र होती जाएंगी अन्यथा वे इनके समानांतर नए संगठन भी खड़े कर सकते हैं। चीन, रूस व भारत के साथ ही जर्मनी,फ्रांस तुर्की आदि यूरोपीय देशों को अगर साथ जोड़ पाता है तो कई यूरोपीय व अरब देश भी साथ आ सकते हैं क्योंकि कोई भी यूरोपीय देश यूरोप को युद्ध का मैदान नहीं बने रहना चाहेगा। किंतु अमेरिका वर्चस्व के सिकुड़ने की हर कड़ी दुनिया के देशों को बड़े झटके देकर जाएगी। वह दुनिया में कई युद्ध क्षेत्र खोल सभी देशों को उलझाने की कोशिश करेगा। रूस व चीन के गुट से जुड़े हुए देश इसीलिए आक्रामक हो चले हैं। फिलहाल तो लग रहा है कि दुनिया दो आर्थिक समूहों या गुटों में बंटने जा रही है और चीन व रूस इस खेल को डॉलर बनाम युआन-रूबल बनाना चाहते हैं तो भारत व अन्य विकासशील देश अपनी अपनी मुद्राओं में लेनदेन या डिजिटल करेंसी के उपयोग पर जोर दे रहे हैं। भारत के लिए यह बहुत ही उलझा हुआ व संवेदनशील मसला है। प्रधानमंत्री मोदी का क़द हाल के विधानसभा चुनावों के बाद देश और विदेश सब जगह बढ़ा है और वे इन समस्या व संघर्ष को समाप्त करने में प्रमुख भूमिका निभा सकते है किंतु वैश्विक अर्थव्यवस्था का स्वरूप बहुत वृहद व देशों में परस्पर निर्भरता बहुत अधिक है, ऐसे में किसी एक गुट के साथ खड़ा होना किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल होगा। फिलहाल गुटनिरपेक्षता भी कोई विकल्प बनकर नहीं उभर पा रही है। जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक प्रयोग से अपेक्षाओं से अधिक तीव्र हो रहे 'जलवायु परिवर्तन' के दुष्प्रभाव भी इस लड़ाई को और घातक व विकट बना रहे हैं। इससे फसल चक्र बिगड़ रहा है और दुनिया खाद्य संकट के मुहाने पर खड़ी है। ऐसे समय जब पूरी दुनिया को एकजुट होकर अस्तित्व संकट की इस चुनौती का मिलकर सामना करना चाहिए था, बड़े राष्ट्र वर्चस्व व संसाधनों के संघर्ष व हथियारों की होड़ में लगे हुए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि समांतर व नई विश्व व्यवस्था के वर्तमान संघर्ष के बीच मानवता व प्रकृति दोनों ही अपने अस्तित्व के अंतिम मोड़ पर खड़े दिख रहे हैं।

अनुज अग्रवाल
संपादक

बिना युद्ध विराम और शांति के कैसे होगी स्वास्थ्य सुरक्षा ?

● बॉबी रमाकांत - सीएनएस

वैश्विक स्तर पर कोविड महामारी की जन स्वास्थ्य आपदा चल रही है, पर जब अस्पताल पर बमबारी हो रही हो तो ऐसे में स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करना कितना बेमायने है। यदि स्वास्थ्य सुरक्षा प्राथमिकता है तो यूक्रेन और रूस के मध्य तुरंत युद्ध विराम हो और शांति क़ायम हो। संवाद से समस्याओं का हल निकले क्योंकि युद्ध से समस्याएं सुलझती नहीं बल्कि और जटिल हो जाती हैं।

हालत इतने ख़राब हैं कि बच्चों के अस्पताल भी सुरक्षित न रहें। ऐम्ब्युलन्स हो या क्लिनिक, अस्पताल हो या स्वास्थ्यकर्मी या जख्मी लोग या अन्य रोगी, सब पर बमबारी हो गयी। इन स्वास्थ्यकर्मी या जख्मी लोगों या रोगियों पर हमला करने से क्या रूस और यूक्रेन की समस्या हल हो जाएगी? स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्वस्त करने से न सिर्फ वर्तमान बल्कि भविष्य भी अंधकारमय हो रहा है। इसीलिए पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने यह स्पष्ट कहा था कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर हमला करना 'वार क्राइम' (युद्ध अपराध) है, यानि कि युद्ध के दौरान एक संगीन अपराध है।

इसीलिए 2016 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव संख्या 2286 को पारित किया कि स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य से सम्बंधित आवागमन/ यातायात, स्वास्थ्यकर्मी आदि पर किसी भी युद्ध या लड़ाई के दौरान हमला करना अपराध है और निंदनीय है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन जो संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेन्सी है, के महानिदेशक डॉ टेडरोस अधनोम धेबरेसस ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब तक 18 ऐसे हमलों की खबरों को सत्यापित किया है जो यूक्रेन और रूस के मध्य चल रहे युद्ध के कारण हुए। यह हमले अस्पताल एवं अन्य स्वास्थ्य सेवा केंद्रों पर हुए, ऐम्ब्युलन्स पर हुए, और स्वास्थ्यकर्मी पर हुए। अब तक इनमें 10 लोग मृत हो चुके हैं और कम से कम 16 घायल हैं। इन हमलों के कारण पूरे समुदाय को स्वास्थ्य सेवा से वंचित होना पड़ता है। अब तक यूक्रेन से 20 लाख से अधिक लोग पलायन कर चुके हैं जिसके कारण, पड़ोसी देशों में विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन लोगों को स्वास्थ्य सेवा देने में सहयोग कर रहा है। इन पलायन किए हुए लोगों में अधिकांश बच्चे और महिलाएं हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के निदेशक डॉ माइकल राइयन ने कहा कि यूक्रेन और रूस युद्ध में, युद्ध की 'फ्रंटलाइन' से 10 क़िमी के भीतर अब तक 1000 से अधिक अस्पताल, क्लिनिक और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े अन्य केंद्र प्रभावित हुए हैं।

कुछ ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं जिनको अधिकारियों ने अब संचालित करना छोड़ दिया है क्योंकि इनको युद्ध के बीच संचालित रखना सम्भव ही नहीं है। कुछ ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां अस्पताल के समान और यंत्र आदि और स्वास्थ्यकर्मी को वहां से हटा के कहीं और पुनर्स्थापित किया जा रहा है जो इस स्थिति में सरल नहीं है।

यूक्रेन में विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य-सम्बन्धी राहत सामग्री तो भेज रहा है पर अस्पताल और स्वास्थ्य व्यवस्था को संचालित रखने के लिए सिर्फ राहत सामग्री नहीं चाहिए। स्वास्थ्य सम्बन्धी राहत सामग्री के साथ-साथ स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए सुरक्षित माहौल चाहिए, बिजली चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए, आदि। सुरक्षित आवागमन के लिए यातायात सेवा चाहिए जिससे स्वास्थ्यकर्मी और रोगी या जख्मी लोग बिना विलम्ब स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंच सकें।

यूक्रेन में ऑक्सिजन की कमी

पिछले महीने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अलार्म जारी किया था कि यूक्रेन में ऑक्सिजन की कमी हो रही है। यह ऑक्सिजन की कमी कोरोना वाइरस के कारण नहीं है बल्कि रूसी हमले के कारण हुई है। यह ऑक्सिजन की कमी पूरी तरह से टाली जा सकती थी यदि शांति रहती और युद्ध के बजाय संवाद से रूस और यूक्रेन ने अपने मसले सुलझाए होते। सीएनएस (सिटिजन न्यूज सर्विस) की संस्थापिका शोभा शुक्ला ने कहा कि एक ओर सरकारें कहती हैं जन स्वास्थ्य आपदा है और सतत विकास लक्ष्य

पूरे करने हैं और दूसरी ओर ऐसी स्थिति पैदा कर रही हैं कि लोग गम्भीर ख़तरा उठाने के लिए मजबूर हैं, प्राणघातक स्थिति में घिर रहे हैं। ऐसे में क्या युक्रेन-रूस हमले से जान बचा के भागते लोगों से, कोरोना वाइरस से बचाव की बात करना कितना बेमायने है आप स्वयं निर्णय लें। शांति नहीं रहेगी तो न स्वास्थ्य सुरक्षा रहेगी न सतत विकास। बल्कि युद्ध के कारण समुदाय एक लम्बे अरसे तक पीड़ा झेलता है क्योंकि जो भी विकास युद्ध के पूर्व हुआ होता है वह पलट जाता है या ध्वस्त हो चुका होता है।

2016 में रेड क्रॉस के तत्कालीन अध्यक्ष पीटर माउरर ने कहा था कि तब से 3 साल पहले तक 11 देशों में स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर 2400 हमले हो चुके थे। सरहद बगैर डॉक्टर (डॉक्टर विधाउट बॉर्डर) की तत्कालीन अध्यक्ष जोआन लियु ने कहा था कि 2016 में सीरिया में 10 दिन के भीतर 300 से ऊपर हवाई हमले हुए थे। उनके अनुसार, अफगानिस्तान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, सीरिया, यूक्रेन और येमन में स्वास्थ्य व्यवस्था पर बमबारी करना, उनको लूट लेना, या जला के राख कर देना, स्वास्थ्यकर्मी और रोगियों को डराना-धमकाना, और यहां तक की रोगियों को

ओमिक्रॉन+डेल्टा का कहर, कोरोना की चौथी लहर...

एशिया, यूरोप समेत दुनियाभर में कोरोना की चौथी लहर आने के प्रबल संकेतों के बीच देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को एक एडवाइजरी जारी कर सतर्कता बरतने को कहा है। केंद्र ने कहा है कि कि कोरोना से बचाव को राज्य पूर्व में जारी किए गए दिशा-निर्देश का सख्ती से पालन कराएं।

ओमिक्रॉन+डेल्टा सब-वेरिएंट भारत में ला सकता है चौथी लहर

भारत के कई राज्यों में ओमिक्रॉन, डेल्टा के मेल से बने सब वेरिएंट बीए.2 संक्रमण की पुष्टि के बाद सरकार अलर्ट हो गई है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस बात की काफी संभावना है कि Omicron का BA.2 देश में संभावित COVID-19 चौथी लहर का कारण बन सकता है। Omicron Delta India अत्यधिक पारगम्य और संक्रामक है, इसलिए चौथी लहर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इससे पहले, IIT कानपुर की टीम ने भारत में जून 2022 में कोरोना की चौथी लहर आने की भविष्यवाणी की थी। बताया गया है कि कोरोना की चौथी लहर 4 महीने तक जारी रहेगी। अगस्त 2022 में यह अपने चरम पर पहुंच जाएगा। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 182 करोड़ लोगों का कोरोना टीकाकरण होने के बाद भारत में कोरोना की चौथी लहर आने की संभावना कम है।

ये हैं Omicron Delta BA.2 वेरिएंट के दो सामान्य लक्षण

ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के मेल से बने सब वेरिएंट BA.2 पहले के मुकाबले अधिक संक्रामक है। कोरोना वायरस का BA.2 वेरिएंट मुख्य रूप से श्वसन प्रणाली में कई गुना अधिक होता है। इसके शुरुआती लक्षण फेफड़ों से संबंधित नहीं होते हैं। इस नए वेरिएंट के दो विशिष्ट लक्षण मुख्य रूप से चक्कर आना और थकान हैं। वे ओमिक्रॉन+डेल्टा BA.2 वायरस से संक्रमित होने के दो से तीन दिनों के भीतर प्रकट हो सकते हैं और अधिक समय तक रह सकते हैं।

पाचन संबंधी समस्याएं और BA.2 के दूसरे लक्षण

BA.2 स्टील्थ ओमिक्रॉन नाक के बजाय आंत को प्रभावित करता है। जिससे पाचन तंत्र से संबंधित कई समस्याएं होती हैं। यह आरटी पीसीआर टेस्ट को भी बाईपास कर सकता है। जांच के दौरान यह पकड़ में आए ऐसा जरूरी नहीं है। गलत-नकारात्मक परीक्षण हो तो नाक या मुंह में मौजूद कोरोना वायरस का पता आसानी से नहीं लगाया जा सकता। BA.2 वेरिएंट से मतली, दस्त, उल्टी, पेट में दर्द, नाराजगी, डिप्रेशन और पेट में सूजन जैसी पाचन समस्याएं हो सकती हैं।

Omicron+Delta BA.2 वेरिएंट के अन्य लक्षण

बुखार, खांसी, गले में खराश, सिर का घाव, मांसपेशियों की थकान, उच्च हृदय, गति गंध या स्वाद की कमी, सांस लेने में तकलीफ

केंद्र ने किया अलर्ट, झारखंड में पालन कराएं कोरोना गाइडलाइन

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का आगे भी सख्ती से पालन कराने को कहा है। मुख्य सचिव को संबोधित पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने लिखा है कि केंद्र से कोविड को लेकर जारी दिशा-निर्देश गत माह 25 फरवरी को ही समाप्त हो गया था। इसके बाद नया दिशा-निर्देश तब तक जारी नहीं होगा, जब तक देश में कोरोना की स्थिति फिर विस्फोटक रूप नहीं लेगी। कोरोना संक्रमण का दर बहुत कम हो चुका है, इसलिए सभी राज्य अपने-अपने तरीके से कोरोना को लेकर जारी सामान्य दिशा-निर्देश जैसे दो गज की दूरी, मास्क का इस्तेमाल आदि सख्ती से लागू करवाएं।

एशिया के कुछ देशों में कोविड बढ़ोतरी पर: संक्रमण नियंत्रण और जन-स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार हैं जरूरी

हालांकि एशिया के कुछ देशों में कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या में फिर से बढ़ोतरी होने लगी है, इसके बावजूद अनेक देशों ने कोविड नियंत्रण नियमों में ढिलाई करनी आरम्भ कर दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि महामारी का अंत अभी दूर है, इसलिए संक्रमण नियंत्रण के साथ ही सामान्य जीवन यापन करना सर्वोपरि रहेगा। सरकारों को जन स्वास्थ्य प्रणाली को सशक्त करना चाहिए, और रोग नियंत्रण पर अत्याधिक ध्यान देना चाहिए।

ऑर्गनायज़्ड मेडिसिन ऐकडेमिक गिल्ड (ओएमएजी) की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ सुनीला गर्ग और महासचिव डॉ ईश्वर गिलाडा ने कहा कि एस.एम.एस.वी. अभियान के साथ ही सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां पुनः सक्रिय हों - एस.एम.एस.वी. यानि कि सैनिटेशन, मास्क, सामाजिक दूरी और वैक्सीन। ओएमएजी के वरिष्ठ विशेषज्ञ ग्रेटर नॉएडा में आयोजित बाल रोग विशेषज्ञों के राष्ट्रीय अधिवेशन को सम्बोधित कर रहे थे।

भारत समेत अनेक देशों के आंकड़े देखें तो लगभग हर 10 में से 9 लोग जो कोविड के कारण इस साल अस्पताल में भर्ती हुए थे, उनका टीकाकरण नहीं हुआ था। साफ जाहिर है कि पूरा टीकाकरण करवाए लोगों में कोविड रोग होने पर गम्भीर परिणाम कम होते हैं, अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत कम पड़ती है, वेंटिलेटर या ऑक्सिजन आदि की जरूरत कम पड़ती है और मृत्यु दर भी कम रहता है (टीकाकरण न करवाए लोगों की तुलना में)।

वरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉ ईश्वर गिलाडा ने वही दोहराया जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैज्ञानिक भी कह चुके हैं कि कोविड महामारी का अंत तुरंत न मुमकिन हो पर जो तुरंत मुमकिन है वह यह कि कोविड को महामारी स्वरूप का अंत हो, अस्पताल-वेंटिलेटर या ऑक्सिजन की आवश्यकता न पड़ें, कोई गम्भीर बीमार न पड़े, और न ही मृत हो। कोविड के टीकाकरण से यह काफी हद तक मुमकिन है। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि लोग, विशेषकर कि वह लोग जिन्हें कोविड होने पर गम्भीर परिणाम होने का ख़तरा है, कोरोना वाइरस से संक्रमित ही न हों। कोरोना से बचाव मुमकिन है (मास्क, सामाजिक दूरी, सफाई और टीकाकरण आदि) तो क्यों न संक्रमण नियंत्रण को जीवन यापन में अंगीकार करते हुए हम लोग सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां चालू रखें?

कोविड महामारी का अंत अभी नहीं: डब्ल्यूएचओ

विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेडरोस अधनोम घेबरेएसस ने भी दोहराया कि अनेक हफ़्तों से कोविड से संक्रमित हो रहे लोगों कि संख्या में गिरावट आ रही थी पर पिछले हफ़्ते से एशिया के कुछ देशों में चिंताजनक बढ़ोतरी हो रही है। एक ओर अनेक देशों में कोविड के परीक्षण में बहुत गिरावट आयी है पर दूसरी ओर कुल संक्रमित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। असल में संक्रमित लोगों की संख्या अधिक होगी क्योंकि परीक्षण कम हो रहे हैं। जब कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है तो जाहिर बात है कि अस्पताल में भर्ती, ऑक्सिजन, वेंटिलेटर और मृत्यु दर में बढ़ोतरी होगी। अनेक देशों में टीकाकरण बहुत कम हुआ है जिसका तात्पर्य है कि कोविड होने पर अस्पताल में भर्ती होने का ख़तरा अधिक रहेगा, ऑक्सिजन वेंटिलेटर आदि की जरूरत पड़ने की सम्भावना अधिक रहेगी और मृत्यु का ख़तरा भी अधिक रहेगा। हम सब को याद रखना चाहिए कि कोविड महामारी का अभी अंत नहीं हुआ है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने सभी सरकारों से अपील की कि वह सावधानी बरतें, टीकाकरण को प्राथमिकता दें, कोविड परीक्षण और जीन सीक्वन्सिंग परीक्षण को महत्व दें, जरूरतमंद लोगों को सभी मुमकिन स्वास्थ्य सेवा बिना विलम्ब उपलब्ध करवाएं और जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आबादी को संक्रमण से बचाने का पूरा प्रयास करें।

डॉ ईश्वर गिलाडा ने भारत सरकार की एनटीएजीआई समिति (टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह) को सराहा कि उसने ओएमएजी विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझाव को पारित किया है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय उनको लागू करवा रहा है।

वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा अहम: डॉ सुनीला गर्ग

ओएमएजी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश की वरिष्ठ जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ सुनीला गर्ग ने कहा कि चिकित्सकों समेत सभी जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों के समूह को एकजुट हो कर स्वास्थ्य प्रणाली के सशक्तिकरण का प्रयास करना होगा जिससे कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा का सपना

साकार हो सके। एक-दुनिया-एक-समान-स्वास्थ्य-सुरक्षा का सपना साकार हो। चाहे वह दवा प्रतिरोधकता हो या टीबी या गैर-संक्रामक रोग हों या संक्रामक, सभी के लिए चिकित्सकीय सेवा के साथ-साथ जन-स्वास्थ्य सेवा और सहयोग और सामाजिक सुरक्षा भी अत्यंत जरूरी है।

डॉ सुनीला गर्ग ने कहा कि 7 साल पहले दुनिया की सभी सरकारों ने सतत विकास लक्ष्य को 2030 तक पूरा करना का वादा किया। सतत विकास लक्ष्य में यह बात निहित है कि बिना स्वास्थ्य सुरक्षा के सतत विकास सम्भव ही नहीं है।

डॉ गर्ग ने अपील की कि सभी विभिन्न चिकित्सकीय और जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों के संगठन एकजुट हों और बेहतर समन्वयन के साथ जन स्वास्थ्य सुरक्षा के सपने को साकार करने में अपना योगदान दें।

डॉ ईश्वर गिलाडा ने बताया कि भारत में चौथी कोविड लहर आने का ख़तरा बहुत कम है क्योंकि आबादी के एक बड़े भाग को कोविड होने के कारण प्राकृतिक रूप से प्रतिरोधकता उत्पन्न हो गयी है और आबादी के बड़े भाग का पूरा टीकाकरण भी हो चुका है। शोध से ज्ञात हुआ है कि आबादी के 90 प्रतिशत लोगों में कोविड एंटीबॉडी थीं जिसका तात्पर्य है कि उन्हें कोविड हो चुका है। भारत में 18 वर्ष की उम्र से अधिक लोगों में 97 प्रतिशत को कोविड टीके की पहली खुराक लग चुकी है और 83 प्रतिशत को दूसरी खुराक (पूरा टीकाकरण)।

डॉ गिलाडा ने महत्वपूर्ण बात कही कि भारत सरकार को बिना विलम्ब वैज्ञानिक शोध को तेज करना चाहिए जिससे कि वैज्ञानिक आधार पर यह स्पष्ट हो कि आगामी बूस्टर डोज के संक्रमण नियंत्रण के लिए क्या लाभ रहेंगे, क्या वैक्सीन की मात्रा कम होगी, या विभिन्न वैक्सीन को मिलाजुला के देना लाभकारी रहेगा? बच्चों और युवाओं में टीकाकरण के लाभ पर भी शोध अधिक होने चाहिए। वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित आधार पर यदि जन स्वास्थ्य नीतियां बनेंगी और कार्यक्रम लागू होंगे तो वांछित परिणाम भी होने की सम्भावना अधिक रहेगी। यह शोध न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के सभी सरकारों के लिए लाभकारी रहेंगे।

जितना कोरोना वाइरस हमारी आबादी को संक्रमित करेगा उतना ख़तरा बढ़ेगा कि उसके नए प्रकार उत्पन्न हों। इसीलिए यह और भी जरूरी है कि हम लोग संक्रमण नियंत्रण को तिलांजलि न दें। स्वयं भी संक्रमित होने से बचे और यदि संक्रमित हो जाएं तो हर सम्भव प्रयास करें कि कोई अन्य जन संक्रमित न हों। मास्क सही से पहने, यथासंभव भौतिक दूरी बना के रखें, साफ-सफाई रखें, और टीकाकरण करवाएं।

बॉबी रमाकांत

उनकी अस्पताल शैय्या पर गोली मार देना रिपोर्ट हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच में से चार स्थायी सदस्य देश ही इन हमलों के लिए जिम्मेदार रहे हैं। अब आप ही सोचें यदि वह देश जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं वहीं युद्ध अपराध करेंगे, तो उनकी जवाबदेही कैसे होगी, युद्ध विराम कैसे होगा? संयुक्त राष्ट्र की ऐसे में क्या भूमिका होनी चाहिए?

हम लोग कैसे भूल सकते हैं कि इसराइल ने गाजा पर हमला करके हजारों लोगों को मृत किया था। अमरीका की सेना ने अफगानिस्तान में सरहद बगैर बॉर्डर के अस्पताल पर हमला किया था।

मानवाधिकार के लिए चिकित्सक (फिजिशियंस फोर ह्यूमन राइट्स) के अनुसार, जब से सीरिया विवाद शुरू हुआ है तब से 250 स्वास्थ्य सेवा केंद्रों पर 360 से अधिक हमले हो चुके हैं। 730 से अधिक स्वास्थ्यकर्मी मृत हो चुके हैं। तब यह हालत थी कि बमबारी और हमलों के कारण आधे से अधिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र बंद हो चुके थे या पूरी तरह से सक्रिय नहीं थे। इसी तरह की तबाही और स्वास्थ्य व्यवस्था को चकनाचूर किया गया था येमन में। 600 से अधिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र बंद हो गए थे - या तो हमले के कारण या स्वास्थ्यकर्मी ही पर्याप्त नहीं थे या दवा आदि की कमी थी।

कुछ महीने पहले तक, अफगानिस्तान में यह हालत थी कि जरूरी जीवनरक्षक दवाएं ख़त्म हो गयी थी और स्वास्थ्यकर्मी को उनके पदों पर कार्यरत रखना मुश्किल हो रहा था।

इथियोपिया के टिगरे क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तक को भीतर जाने की अनुमति नहीं मिल रही थी। जुलाई 2021 से वहां विश्व स्वास्थ्य संगठन जरूरी दवाएं और स्वास्थ्य सम्बन्धी राहत सामग्री पहुंचवाने के लिए प्रयासरत रहा है पर उसको अनुमति ही नहीं मिल रही थी। यदि स्वास्थ्य अधिकार सर्वोपरि है तो सरकारों को इस पर खरा उतरना पड़ेगा। सरकारों द्वारा लिए गए निर्णय से कोई भी इंसान अनावश्यक पीड़ा न झेले।

हम लोग यह कैसे भूल सकते हैं कि कोविड महामारी के पहले भी, हमारे देशों में आबादी के एक बड़े भाग को ऐसे हालात में रहने पर मजबूर किया गया था कि न तो साफ पीने का पानी मुहैया था, न स्वच्छता, न पौष्टिक आहार और न ही स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा। समाज में जो गैर-बराबरी और सामाजिक अन्याय व्याप्त है, उसको अंत किए बिना सबका सतत विकास कैसे मुमकिन है?

शांति और युद्ध विराम के बिना न सिर्फ स्वास्थ्य अधिकार बल्कि सतत विकास और मानवाधिकार की सभी बातें बेमायने हैं। संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रभावकारी भूमिका में आना ही होगा जिससे कि युद्ध जैसी वीभत्स स्थिति कहीं भी उत्पन्न ही न हो। ■

जा सकती है इमरान खान की सरकार, पर हौसले बुलंद हैं

● डॉ. वेदप्रताप वैदिक

इमरान खान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बने अभी साढ़े तीन साल ही हुए हैं, लेकिन लगता नहीं कि वह अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे। हालांकि जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता-पलट कर दिया था, मौजूदा सेनापति कमर बाजवा को शायद वैसा न करना पड़े। बहुत संभव है, तख्ता-पलट की जगह वोट-पलट के जरिए इमरान को अपदस्थ किया जाए। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग, जरदारी की पीपीपी और फजलुर रहमान की जमात उलेमा-इस्लाम-तीनों ने मिलकर इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा है, जो कब का पास हो जाता। लेकिन पाकिस्तानी संसद की बैठक नहीं बुलाई जा सकी, क्योंकि अभी उसी भवन में 'इस्लामिक सहयोग संगठन' का सम्मेलन चल रहा है। बहरहाल, अविश्वास प्रस्ताव पर शीघ्र ही मतदान होना है, लेकिन यह भी संभव है कि उसके पहले ही इमरान अपने इस्तीफे की पेशकश कर दें। इमरान के इस्तीफे के आसार इसलिए बढ़ गए हैं कि जिस फौज के दम पर उनका तकिया था, वही अब उन्हें हवा देने लगी है।

फौज से मोहभंग

इमरान की पार्टी 'पाकिस्तान तहरीके-इंसाफ' पार्टी (पीटीआई) 2018 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। संसद की 343 सीटों में से उसे 155 सीटें मिली थीं। लेकिन कई अन्य पार्टियों की 24 सीटें जोड़कर वह सत्तारूढ़ हो गई। इमरान की इस जीत के पीछे पाकिस्तान फौज की शै थी। भुट्टो की पीपीपी और नवाज की मुस्लिम लीग के कई सांसदों को तोड़कर फौज ने उन्हें इमरान की पार्टी का उम्मीदवार बनवा दिया था। नवाज शरीफ को अपदस्थ करने की मांग करने के कारण इमरान पाकिस्तानी फौज के करीबी बन गए थे। लेकिन फौज और इमरान का एक-दूसरे से जल्दी ही मोहभंग हो गया। दोनों एक-दूसरे के विरुद्ध कदम उठाने लगे। 2019 में जब जनरल बाजवा का कार्यकाल बढ़ाया गया तो उस आदेश को इतनी देर से जारी किया गया कि वह सर्वोच्च न्यायालय और जनता में भी विवाद का विषय बन गया। अदालत के आदेश पर उसे संसद से पास करवाना पड़ा। उधर, इमरान खान के भाषण तो जोरदार होते रहे लेकिन विरोधी दलों ने उनके खिलाफ काफी बड़े-बड़े प्रदर्शन सारे देश में आयोजित कर डाले। महंगाई और प्रशासनिक सुस्ती ने इमरान सरकार की हालत खस्ता कर दी। फौज इस बात से भी नाराज थी कि इमरान ने कश्मीर के सवाल को जोर से नहीं उठाया। उन्होंने भारत के साथ ढिलाई बरती।

अमेरिका से भी पाकिस्तान के रिश्तों में कोई सुधार नहीं हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और इमरान के बीच आज तक सीधा संवाद नहीं हुआ है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अभी तक पाकिस्तान को कठघरे में ही रखा है। उसे अब तक छह बिलियन डॉलर की जगह सिर्फ एक बिलियन डॉलर मिले हैं। फौज तो पाकिस्तान की असली मालिक है, लेकिन फौज और इमरान के बीच गंभीर तनाव पैदा हो गया है। जनरल बाजवा का यूं तो इमरान ने कार्यकाल बढ़ाकर 2022 तक कर दिया था, लेकिन बाजवा को यह बात नागवार गुजर रही थी कि इमरान उनके उत्तराधिकारी सेनापति की खोज में जुट गए थे। इमरान ने खुफिया एजेंसी आईएसआई के मुखिया जनरल फैज हमीद की गोटी आगे बढ़ानी शुरू कर दी थी। उन्हें तालिबान से सीधा संपर्क करने के लिए इमरान ने काबुल भी भेजा था। उन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रचार भी खूब मिलने लगा। उन्हें 11वीं कोर का कमांडर बनाकर पेशावर भेज दिया गया, लेकिन उनकी जगह गुप्तचर विभाग के मुखिया के तौर पर जनरल

क्यों मचा बवाल ?

पाकिस्तान की राजनीतिक में अभी उथल-पुथल जारी है और यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी भी खतरे में है। तो जानते हैं किन मुद्दों पर सरकार घिरी हुई है। पाकिस्तान की राजनीति में अभी काफी बदलाव हो रहे हैं।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी पर खतरा बढ़ता जा रहा है। सरकार जनहित के मुद्दों के साथ साथ सहयोगी पार्टियों के विरोध के वजह से दिक्कत में है। हाल ही में इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ है, जिसके बाद से मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पास को लेकर 25 मार्च को वोटिंग हो सकती है। ऐसे में इमरान खान की कुर्सी संकट में दिख रही है और आलू-टमाटर जैसे मुद्दे भी सरकार पर हावी हैं।

ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि इमरान खान की सरकार के खिलाफ कौन-कौन से मुद्दे सबसे अहम हैं, जिसकी वजह से सरकार खतरे में हैं। तो जानते हैं पाकिस्तान की राजनीति से जुड़ी हर एक बात, जिससे आप पाकिस्तान की स्थिति के बारे में जान पाएंगे।

क्या है पाकिस्तान की राजनीति की स्थिति?

पाकिस्तान की राजनीति में अभी काफी बदलाव हो रहे हैं। हाल ही में इमरान खान की पार्टी से कई सांसदों ने पार्टी छोड़ दी है और बताया जा रहा है कि इनकी संख्या 14 है। अब सासंदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अब सरकार का अहम उद्देश्य 25 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव में सरकार बचाना है। बताया जा रहा है कि अभी इमरान खान अपने सांसदों को वापस बुलाने पर और विरोधियों को शांत करने की कोशिश में लगे हुए हैं।

अगस्त 2018 में सत्ता में आने के बाद से पूर्व क्रिकेट स्टार से इस्लामिक नेता बने इमरान खान के लिए यह चुनौती अब तक की सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। पीएम इमरान खान ने दावा किया है कि 342 सीटों वाले सदन में उन्हें अभी भी अधिकांश सांसदों का समर्थन प्राप्त है।

महंगाई बनी आफत

अभी पाकिस्तान में महंगाई सबसे अहम मुद्दा बन गया है। महंगाई ने खासतौर पर गरीब और मध्यम वर्ग का हाल बहुत बुरा कर रखा है और पिछले कुछ सालों में महंगाई की दर सबसे ज्यादा हो गई है और रोजमर्रा से जुड़े हर एक सामान की कीमत लगातार बढ़ रही है। पाकिस्तान के फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स (FBS) के अनुसार अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2021 तक बिजली की दरें 57 फीसदी तक बढ़ी हैं। जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पेट्रोल-चीनी-दूध समेत कई चीजों के बढ़ते दामों से हाहाकार मचा हुआ। पाकिस्तान में महंगाई 70 सालों में अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। पेट्रोल 150 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचने वाला है तो वहीं चीनी भी 100 रुपए प्रति किलो बिक रही है।

क्या है आलू का मुद्दा?

दरअसल, अन्य सामानों की तरह आलू-टमाटर के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान अभी टमाटर 80 रुपये तो आलू करीब 60 रुपये किलो बिक रहे हैं। इसके साथ दूध, आटा, चिकन के दाम आसमान पर हैं। मगर आलू-टमाटर पर चर्चा इसलिए ज्यादा हो रही है, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान सरकार को जब महंगाई को लेकर घेरा गया तो प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, 'मैं आलू और टमाटर के दाम जानने राजनीति में नहीं आया।' इसके बाद महंगाई का मुद्दा और भी ज्यादा बढ़ गया और अब सरकार हर तरफ से घिरी हुई नजर आ रही है।

राजनीतिक संकट के बीच प्रधानमंत्री इमरान खान ने कल सोमवार को जमीनी समर्थकों की ओर रुख किया, गरीबों की पैरवी की और मरीजों के लिए बेहतर अस्पतालों का वादा किया क्योंकि उन्हें संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा है।

नदीम अंजुम को नियुक्त करने में इमरान ने देरी करनी शुरू कर दी। जनरल बाजवा और अन्य फौजियों के कान खड़े हो गए। उनका असंतोष और अविश्वास सार्वजनिक हो गया। फिर क्या था, सारे प्रमुख विरोधी दल मिल गए और उन्होंने संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। इमरान सरकार ने बीच-बचाव करने के लिए पाकिस्तान के पूर्व सेनापति राहिल शरीफ को सऊदी अरब से इस्लामाबाद भी बुलवाया,

इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इमरान खान की सरकार गिरना तय माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान सदन में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। नेशनल असेंबली में विश्वास प्रस्ताव पर सात दिनों के अंदर वोटिंग होगी। असेंबली में प्रस्ताव पर बहस के लिए मंजूरी मिल गई है। इस विश्वास प्रस्ताव पर पाक सदन में 31 मार्च को विस्तार से बहस होगी, जिसमें सत्ता और विपक्ष के नेता अपना-अपना पक्ष रखेंगे।

पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान के गृहमंत्री शेख रशीद ने कहा था कि प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान 3 या 4 अप्रैल को होने की संभावना है, जो इसमें और देरी का संकेत देता है। हालांकि, अविश्वास प्रस्ताव शुक्रवार के नेशनल असेंबली सत्र के एजेंडे में था, लेकिन अध्यक्ष असद कैसर ने सत्र को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया।

इसके बाद विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने कैसर को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव से निपटने की आलोचना की और आरोप लगाया कि अध्यक्ष अविश्वास मत में देरी करके अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे हैं। रशीद ने कहा कि विपक्ष ने वास्तव में PTI सरकार के हाथों में खेला है। उन्होंने दावा किया कि अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद से इमरान की लोकप्रियता बढ़ी है।

पाकिस्तान में चरम पर सियासी संग्राम, अल्पमत में आई इमरान सरकार

पाकिस्तान की गठबंधन सरकार में शामिल एक अहम दल मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान (एमक्यूएम-पी) ने बुधवार को विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में मतदान का एलान कर दिया। इसके साथ ही इमरान सरकार संसद में अल्पमत में आ गई है। सरकार में शामिल एमक्यूएम-पी कोटे के दो मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने आनन-फानन में कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई। इस्तीफे की अटकलों के बीच गृह मंत्री राशिद खान ने दावा किया है कि इमरान आखिरी बाल तक खेलेंगे।

एमक्यूएम-पी प्रमुख खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा, हम सहिष्णुता व सच्चे लोकतंत्र की राजनीति के लिए नई शुरुआत करना चाहते हैं। पार्टी ने गत दिवस सरकार के सामने तीन मांगें रखी थीं। संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली में एमक्यूएम-पी के सात सदस्य हैं। पांच सदस्यों वाली बलूचिस्तान अवामी पार्टी (बीएपी) सोमवार को विपक्ष के साथ जाने का एलान कर चुकी है।

जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम फजल (जेयूआइ-एफ) के मुखिया मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया कि विपक्ष को 175 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। यह भी घोषणा की गई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष शहबाज शरीफ देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे।

शहबाज ने कहा कि यह बहुत अहम दिन है, क्योंकि विपक्ष की सभी पार्टियां पाकिस्तान की समस्याओं का सामना करने के लिए एकजुट हो चुकी हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देते हुए नई परंपरा कायम करनी चाहिए। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि एमक्यूएम के विपक्षी दलों के साथ आने के बाद प्रधानमंत्री के पास इस्तीफे के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने भी दावा किया कि शहबाज जल्द ही देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे।

विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को गिराने के लिए इमरान को 342 सदस्यीय निचले सदन में 172 मतों की जरूरत होगी। पीटीआइ ने अपने 155 व गठबंधन के सहयोगी दलों के 23 सांसदों के समर्थन से सरकार बनाई थी। दो घटक दल विपक्षी पाले में जा चुके हैं, जबकि पीटीआइ के दो दर्जन सांसदों ने भी बगावत कर दी है।

लेकिन उसका भी कोई असर जनरल बाजवा और नदीम अंजुम पर नहीं हुआ।

फौज का संदेश यही है कि इमरान खुद ही इस्तीफा दे दें। पाकिस्तान के विरोधी दलों ने अपने बहुमत की जुगाड़ बिठा ली है और मियां नवाज शरीफ के छोटे भाई शाहबाज शरीफ को भावी प्रधानमंत्री भी घोषित कर दिया है। अपने भाषणों और टीवी भेंटवार्ताओं में विरोधी नेता-मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो इमरान खान का काफी मजाक उड़ाते हैं। इमरान भी ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। वह नवाज शरीफ को गीदड़ और चमगादड़ कहते हैं और शाहबाज शरीफ को हर किसी का बूट पालिश करने वाला बताते हैं। वे तीनों विरोधी पार्टियों के नेताओं-शाहबाज, बिलावल और फजलुर रहमान को भ्रष्ट, देशद्रोही और कमअक्ल बताते हैं। इस समय पाकिस्तानी राजनीति में कटुता चरम पर है।

ऐसी ही स्थिति में इमरान ने यूक्रेन पर भारतीय नीति की तारीफ कर दी और कह दिया कि पाकिस्तान भी किसी गरीब की जोरू नहीं है कि वह आंख मींचकर किसी देश का समर्थन या विरोध करे। पाकिस्तान किसी के आगे झुकेगा नहीं। यह तो ठीक है लेकिन इस्लामिक देशों के सम्मेलन में उस चीन के विदेश मंत्री वांग यी को इमरान ने अपना विशेष अतिथि बनाया है, जिसने शिनच्यांग के दस लाख मुसलमान उइगरों को यातना-शिविरों में डाल रखा है।

अदालती दांव

इमरान के हौसले अभी भी बुलंद मालूम पड़ रहे हैं। हो सकता है पाकिस्तानी संविधान की धारा-63 ए का इस्तेमाल करके वह अपने बागी सांसदों को मतदान के पहले ही अपदस्थ करवाने की कोशिश करें। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में इस आशय की याचिका लगा रखी है। बस, अब अदालत ही उन्हें किसी तरह बचा सकती है। वरना पाकिस्तान के लोग यह मानकर चल रहे हैं कि इमरान के दिन लद गए हैं। लेकिन यह सवाल भी बड़ा है कि जो पाकिस्तानी फौज इमरान को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, वह नवाज शरीफ के भाई को कैसे बर्दाश्त करेगी? ■

बर्बादी की कगार पर पहुंची सोने की लंका

चीनी कर्ज के जाल में फंसकर द्वीपीय देश श्रीलंका में हालत हर दिन के साथ बदतर होते जा रहे हैं। विदेश मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका है तो वहीं महंगाई इतिहास के सभी रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई मुद्रा बुरी तरह से टूट चुकी है। कोविड-महामारी की मार से उबर पाने से पहले ही सोने की लंका दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी है। आइए जानते हैं क्या हैं इस समय देश के हालात और क्या है इनके पीछे की वजह?

इतिहास का सबसे बड़ा वित्तीय संकट

श्रीलंका इन दिनों अपने इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय संकट से जूझ रहा है। कोरोना महामारी से पहले से ही देश के हालात खराब हो चुके थे और उस पर रूस-यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने इन हालातों को और भी खराब कर दिया है। इसके चलते इस द्वीपीय देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। जिसे संभालना भी मुश्किल होता जा रहा है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म होता जा रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के अनुसार, जनवरी में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.36 अरब डॉलर रह गया था। गौरतलब है कि करीब 2.2 करोड़ आबादी वाले देश में पेट्रोल-डीजल समेत अन्य ईंधन की भारी किल्लत हो चुकी है। जबकि, महंगाई बेहिसाब बढ़ रही है। इससे देशवासियों के सामने खाने का विकराल संकट पैदा हो गया है।

महंगाई ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड

देश के विदेशी मुद्रा संकट के बीच पेट्रोलियम की कीमतें आसमान छू गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, श्रीलंका की सरकार के पार पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं बची है जिससे ये संकट और भी गहरा गया है। कुछ दिनों पहले श्रीलंका से ऐसी तस्वीरें आईं कि लोग पेट्रोल खरीदने के लिए पेट्रोल पंप पर टूट पड़े हैं और लोगों को नियंत्रित करने के लिए सेना बुलानी पड़ी। हजारों लोग घंटों तक कतार में इंतजार करके तेल खरीद रहे हैं। देश में डॉलर की कमी ने सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। देश में फरवरी में महंगाई 17.5 प्रतिशत के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई जो कि पूरे एशिया में सबसे ज्यादा है।

45 फीसदी तक टूटा श्रीलंकाई रुपया

श्रीलंका में संकट कितना गहरा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपया सिर्फ मार्च महीने में भी अब तक 45 फीसदी टूट चुका है। एक मार्च से अब तक श्रीलंका की मुद्रा डॉलर की तुलना में टूटकर 292.5 के सर्वकालिक निचले स्तर पर आ चुकी है। देश के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे की मानें तो इस साल देश को 10 अरब डॉलर का व्यापारिक घाटा हो सकता है। वहीं दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके श्रीलंका के हालात पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां बढ़ रही हैं और सरकारी ऋण काफी उच्च स्तर पर पहुंच गया है। आईएमएफ ने गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे देश की अर्थव्यवस्था में तत्काल सुधारों का आह्वान किया।

आयात पर अधिक निर्भरता का असर

गौरतलब है कि श्रीलंका अपनी जरूरत ज्यादातर चीजें आयात करता है। इसमें दवा से लेकर तेल तक सब शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, श्रीलंका के कुल आयात में पेट्रोलियम उत्पादों की हिस्सेदारी पिछले साल दिसंबर में 20 फीसदी थी। लेकिन, विदेशी मुद्रा भंडार में आई कमी के चलते श्रीलंका की सरकार ईंधन समेत जरूरी चीजों का आयात करने में विफल हो रही है। इससे देश में जरूरी सामानों की किल्लत होती जा रही है और इनके दाम दिन-ब-दिन आसमान छूते जा रहे हैं या फिर कहें तो देश के आम लोगों की पहुंच रोजमर्रा के जरूरत के सामानों से दूर होती जा रही है। श्रीलंका पेट्रोलियम, भोजन, कागज, चीनी, दाल, दवाएं और परिवहन उपकरण भी आयात करता है। फिलहाल की बात करें तो देश में कागज की सप्लाई प्रभावित होने की वजह से जहां न्यूजपेपर बंद हो गए तो दूसरी ओर विद्यालय परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो पा रहा है।

पर्यटन उद्योग पर सबसे ज्यादा मार

बता दें कि देश की अर्थव्यवस्था के बर्बादी की कगार पर पहुंचने के लिए एक कारण देश में पर्यटन उद्योग का पतन है। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण देश की जीडीपी में अहम योगदान देने वाला श्रीलंका का पर्यटन क्षेत्र पहले से ही संकट के दौर से गुजर रहा था, जो अब तक उबर नहीं सका है। टूरिज्म इंडस्ट्री का देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लगभग 10 प्रतिशत का योगदान है। 2019 में कोलंबो में हुए सीरियल बम धमाकों के बाद से पर्यटन उद्योग को झटका लगा था और कोरोना महामारी ने इसे इतना बढ़ा दिया कि इसे उबारना भी मुश्किल हो गया। इसका असर भी सीधे तौर पर श्रीलंका की विदेशी मुद्रा आय पर पड़ा। इसके अलावा सरकारी आंकड़ों के अनुसार, श्रीलंका में एफडीआई में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि यदि किसी देश में एफडीआई घटती है, तो उसके भंडार में विदेशी मुद्रा भी कम हो जाती है। ■

क्या 'विश्व व्यवस्था' बदलनी शुरू हो गयी है?

2nd World war के बाद हम Bypolar World में रह रहे थे, जहां एकतरफ स्स्फ था तो दूसरी तरफ अमेरिका था। 90 आते आते SSR बिखर गया और फिर दुनिया में अमेरिका की बादशाहत चलने लगी.....पिछले 30 साल हमने एक Unipolar दुनिया मे गुजारे हैं।

Unipolar दुनिया मे सारे बड़े संस्थान, जैसे N, UNSC, WHO, मीडिया, IMF, World Bank..... सब अमेरिका की मुट्ठी में थे....अमेरिका ने अपना प्रभुत्व बनाने के लिए कई देशों को अपना Protectorate बनाया....उन्हें अपने पाले में रखने के लिए इन देशों को support देने की बात की।

अमेरिका ने NATO को फैलाया और इसका इस्तेमाल किया कई देशों पर आक्रमण करने में.....जब मन किया, कोई भी बहाना बनाया और किसी भी देश को निबटा दिया।

ना कोई सवाल पूछता था, न कोई action होता था.....

लेकिन पिछले 3 दशकों में कुछ बदलाव हुए हैं.....चीन का एक Alternate World Power के रूप में उदय हुआ है। रूस फिर से ताकतवर हुआ है, जिसका श्रेय पुतिन के करिश्माई नेतृत्व को जाता है। वहीं भारत भी एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। वहीं BRICS और SCO जैसे संगठन बने, जिनमे अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों का कोई स्थान नही था। हम धीरे धीरे Multi Polar दुनिया बनते जा रहे हैं।

अब आइये रूस-यूक्रेन के मुद्दे पर रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है। ये सही है या गलत है, इस पर हम फिलहाल बात नही करेंगे। यहां इस घटना को एक Watershed Moment समझिये, और इसके पड़ने वाले प्रभावों को देखिए।

जब रूस ने हमला किया, तो सबसे ज्यादा कड़ी प्रतिक्रिया आयी NATO और अमेरिका से उन्होंने रूस पर हर तरह के Sanctions लगा दिए, और ये उम्मीद लगाई कि दुनिया उनका अनुसरण करेगी, जैसे करती आ रही थी।

लेकिन UNSC, UNGA में उनका ये myth टूट गया। BRICS और SCO देशो ने या तो रूस का समर्थन किया या फिर Abstain किया। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से NATO देश इस युद्ध मे नही उतरे क्योंकि उनके पास अब जनसमर्थन नही है और शायद वो किसी बड़े देश से लड़ने की ताकत भी नही रखते। रूस कोई सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान या इराक़ तो है नही।

यूक्रेन को बलि का बकरा बनाया गया, जिसकी वजह से अब कई देशों की आंखें खुली हैं जिनमे NATO देश, जापान और ताइवान भी हैं। अब इन्हें लगने लगा है कि अमेरिका इन्हें Protect नही कर सकता, और अब इन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। ये देश अब nuclear हथियार भी खरीदेंगे, Missiles भी लेंगे, और अपने Air डिफेंस भी मजबूत करेंगे।

जर्मनी ने अपने डिफेंस बजट में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी की है। उसके अलावा अन्य यूरोपीय देश जैसे स्वीडन, रोमानिया, लातविया, फिनलैंड, नीदरलैंड और च ने भी अपने डिफेंस बजट बढ़ाने की बात की है। इसका अर्थ जानते हैं आप?

इसका अर्थ ये हुआ कि अब दुनिया को अमेरिका पर विश्वास नही रहा। आप जापान का statement पढिये, उन्होंने कहा है कि अमेरिका को अब ये साफ करना चाहिए कि वो किसी

बुरी स्थिति में जापान या ताइवान को कैसे बचाएगा।

इस वजह से यूरोप के जानेमाने डिफेंस Manufacturers BAE Systems(UK), Rheinmetall (Germany) और France के Thales के shares आसमान छू रहे हैं। अब यूरोप के देश और जापान आने वाले सालों में कई सौ Billion USD खर्च करने वाले हैं।

रूस पर लगे sanctions की वजह से एक Alternative Financial System बनाने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। आज ही रूस की बैंकों ने चीन के Unionpay पर switch कर लिया है...क्योंकि अमेरिका के वीसा और मास्टरकार्ड ने रूस में सेवाएं देने से मना कर दिया था।

रूस को Swift से भी बाहर कर दिया है, तो अब जाहिर है कि रूस alternative देखेगा ही.....इसमे चीन का CIPS एक हद तक सहायता कर सकता है लेकिन long Term में एक बड़ा सिस्टम जरूरी होगा। हो सकता है BRICS और SCO देश कोई नया system बना लें। शायद उन्हें बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि Sanctions ने उन्हें एक सबक दिया है, कि आत्मनिर्भरता जरूरी है।

कल को हो सकता है ADB या IMF को टक्कर देने के लिए BRICS की बैंक का scope बढ़ा दिया जाए, और funding दे दी जाए। ताकि इन देशों को Western Financial institutions की तरफ देखना ही ना पड़े। बाकी NGA और UNSC तो वैसे ही बेकार हैं, रूस और चीन के पास वीटो है, ये चाहें तो पत्ता भी ना हिले वहां। WHO पर चीन ने वैसे ही अधिग्रहण कर लिया है।

उन्हें समझ आ गया है, कि हर चीज weaponize की जा सकती है.....आपका ATM कार्ड से लेकर आपका स्मार्टफोन। कुछ भी कभी भी बन्द किया जा सकता है.

यहां ये भी जानना interesting है, कि रूस पर हर तरह की बंदिश लगाने वाले देशो ने उसके तेल और गैस पर कोई sanction नही लगाया है। क्योंकि उन्हें सबसे सस्ता रूस से ही मिलता है। क्या हो अगर रूस अपने तेल और गैस को weaponize कर ले??

वैसे भी रूस पर इतने sanctions लग गए हैं, लेकिन वहां की सरकार ने अभी तक कोई भी Panic नही दिखाया है। अगर आप उनके पिछले 5-7 साल के Financial और strategic कदमो को देखेंगे, तो पाएंगे कि शायद रूस इस दिन की तैयारी कई सालों से कर रहा था। they were waiting and preparing for this day for so long.

आज रूस से हर तरह की कंपनियां पलायन कर रही हैं चाहे IT हो, मीडिया हो, manufacturing हो, Oil एंड एनर्जी हो। सब रूस छोड़ कर जा रही हैं। अब यहां सवाल ये है कि इसमे फायदा किसका होगा? जो जगह western कंपनियों ने खाली कर दी है, वो चीन और भारत भर देंगे। फायदा इन्ही को मिलेगा।

और जब ये सब देश एक parallel system बना लेंगे, उस पर व्यापार करना शुरू कर देंगे तो जाहिर है इनकी currency डॉलर तो नही ही होगी। रूस को अगर चीन या भारत से कुछ directly खरीदना होगा तो डॉलर की जरूरत नही पड़ेगी। ये लोग रूबल के साथ युआन या रुपए का exchange करेंगे और जब ये देश ऐसा करना शुरू कर देंगे, तब सबसे बड़ा नुकसान होगा डॉलर का जिसकी वजह से अमेरिका का प्रभुत्व और टूटेगा।

कुलमिलाकर कहानी ये है कि अगले 5-10 साल बड़े ही interesting होंगे क्योंकि हम दुनिया को बदलते देखेंग। आपको अप्रत्याशित गठजोड़ दिखाई दे सकते हैं। आपको रूस, चीन, भारत एक साथ दिख सकते हैं। वहीं इजराइल, अरब, ईरान भी किसी खास जरूरत के लिए एक ग्रुप में दिखाई दे सकते हैं। आप OIC में भारत का डंका बजते हुए भी देख सकते हैं।

दुनिया मे 3 ही बड़े धंधे हैं.....हथियार, फार्मा और एनर्जी (oil, gas and EV) जो भी इन पर कंट्रोल करता है, वो दुनिया चलाता है। अमेरिका और उसके साथी अब तक इन सभी पर एकाधिकार रखते थे.....लेकिन अब ये कंट्रोल Multiple players के पास जा रहा है। आगे वही चलाएंगे दुनिया।

वैश्विक आर्थिक युद्ध के परिणाम क्या होंगे?

इतना तो तय है कि दुनिया एक दोराहे पर है। इस सब के चलते या तो रूसी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, या फिर इससे एक नयी विश्व आर्थिक व्यवस्था बनेगी, जिसके आसार पहले से बन रहे थे और जिसमें सैन्य व आर्थिक युद्धों की जगह, सहकारात्मक समाधानों को आगे बढ़ाया जाएगा।

क्या यूक्रेन युद्ध और अमरीका, यूरोपीय यूनियन तथा यूके के कदम, दुनिया की सुरक्षित या रिजर्व मुद्रा के रूप में डॉलर के अंत की ओर इशारा कर रहे हैं? रूस तथा यूक्रेन के बीच शांति की बातचीत भले ही 15 सूत्री शांति योजना तक पहुंच गयी हो, जैसी कि फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है, डॉलर पर इस पूरे घटनाविकास का असर होना ही है। आखिरकार, यह पहली ही बार है कि एक बड़ी नाभिकीय ताकत और एक बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ, एक अधीनस्थ देश के जैसा सलूक किया जा रहा है। अमरीका, यूरोपीय यूनियन तथा यूके

डालर के पतन का अनुमान

अमेरिका एक क्षैतिज साम्राज्य के शीर्ष पर बैठा है, पूंजीवाद की आत्म-संगठित, प्रोत्साहन-आधारित संरचना इसके मूल्य की परतों के साथ। यह 'प्रत्येक को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार' का मार्क्सवादी विचार नहीं है। आपको अपना स्थान अर्जित करना होगा। अमेरिकी डॉलर को धागा या यहां तक कि डक्ट टेप के रूप में सोचें जो परतों को एक साथ बांधता है। दुनिया में .12.8 ट्रिलियन का लगभग 60 प्रतिशत- व्यापक मुद्रा भंडार डॉलर हैं। क्या अमेरिका का 'अत्यधिक विशेषाधिकार' दुनिया की प्रमुख आरक्षित मुद्रा के रूप में सर्वशक्तिमान डॉलर खतरे में है? क्या आपको भी परवाह करनी चाहिए?

प्रतिबंधों ने रूस को काट दिया है। इसके 630 अरब डॉलर के विदेशी भंडार का एक बड़ा हिस्सा जम गया है। कुलीन वर्गों की नौकाओं को जब्त कर लिया गया है। वीजा, मास्टरकार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस ने रूस में सेवा निलंबित कर दी। Apple और Google Pay ने मॉस्को की मेट्रो में कैशलेस यात्रियों को रोक दिया। नेटफ्लिक्स से लेकर नाइके तक, स्वैच्छिक प्रतिबंध लागू हैं।

क्या रूस को वैश्विक वित्तीय प्रणाली से बाहर करना सही कदम था? Naysayers को लगता है कि यह आरक्षित मुद्रा के रूप में डॉलर के अंत की शुरुआत है क्योंकि रूस चीन के साथ तालमेल बिठाएगा और युआन या क्रिप्टोकरेंसी के लिए धुरी को अपनाएगा। चीन डॉलर डंप करना शुरू कर सकता है। वास्तव में, 2014 के बाद से चीन और रूस ने द्विपक्षीय व्यापार के लिए डॉलर पर अपनी निर्भरता को गंभीर रूप से कम कर दिया है।

जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के बाद से डॉलर दुनिया की आरक्षित मुद्रा रही है, डॉलर के साथ सोने और अन्य संबद्ध मुद्राओं को डॉलर के लिए आंका गया है। यह कोई नौकरशाही घोषणा नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध में संबद्ध प्रयासों के वित्तपोषण के बाद अमेरिका ताकत की स्थिति में था। 1971 में अमेरिका ने इस विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति को लगभग खो दिया जब युद्ध और कल्याण की कमी के कारण राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने सोने के मानक को गिरा दिया।

आज भी देश अमेरिका के वर्चुअल बेंजामिन को अपने वर्चुअल बैंक वॉल्ट- आधुनिक बैंकिंग के सोने में रखते हैं। चीन के पास कोषागार में .1 ट्रिलियन से अधिक है। रूस के पास तेजी से जमी विदेशी मुद्रा में करीब 500 अरब डॉलर के करीब 100 अरब डॉलर हैं।

लेकिन ये देश डॉलर क्यों रखते हैं? मुद्रा का क्या समर्थन करता है? पारंपरिक उत्तर अमेरिकी सरकार का 'पूर्ण विश्वास और श्रेय' है। हा, वह और 3.65 आपको एक स्टारबक्स ग्रैंड लेटे मिलेगा, हालांकि अब मास्को में नहीं। वास्तव में डॉलर का समर्थन अमेरिका की बढ़ती भविष्य की कर-उत्पादन क्षमता है उत्पादक अर्थव्यवस्था और उस अर्थव्यवस्था की ताकत की रक्षा के लिए एक रक्षा संरचना। इसके बिना, कोई क्षैतिज-बाध्यकारी डक्ट टेप नहीं है।

1990 के दशक के अंत में मुद्रा संकट के दौरान दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और विशेष रूप से रूस ने इसे कठिन तरीके से सीखा। उन्होंने अपनी खुद की मुद्राओं की रक्षा के लिए पर्याप्त विदेशी भंडार नहीं रखा क्योंकि क्रेडिट और डॉलर में मूल्यवर्ग के बैंक ऋण देय थे। अर्जेंटीना, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे ने भी इसे सीखा।

रूस की तरह चीन का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद मेक्सिको से थोड़ा ऊपर है-अमेरिका के चीन के युआन मूल्य का लगभग छठा हिस्सा इसकी आर्थिक वृद्धि पर आधारित है, अब 2022 के लिए केवल 5.5 प्रतिशत का अनुमान है। जबकि चीन को और अधिक iPhones को असेंबल करते रहने की आवश्यकता है वैश्विक ग्राहकों के लिए खिलौने, जूते और ग्रिल, यह उच्च क्षैतिज परतों तक जाने के लिए संघर्ष कर रहा है।

रूसी रूबल में चीन के पास जो कुछ भी है, वह केवल हफ्तों में अपने मूल्य का 40 प्रतिशत से अधिक खो चुका है। आउच। यदि रूस या अन्य देश युआन धारण करते हैं, तो वे इसी तरह के अवमूल्यन का जोखिम उठाते हैं, यदि कहते हैं, चीन ताइवान पर हमला करने के लिए प्रतिबंधों से निचोड़ा जाता है। चीन और रूस को केवल रूबल और युआन के समर्थन के आपसी भ्रम से सावधान रहना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि रूस क्रिप्टो पर लोड करता है, जिसके पतन से 90 के दशक का मुद्रा संकट पिकनिक जैसा लग सकता है।

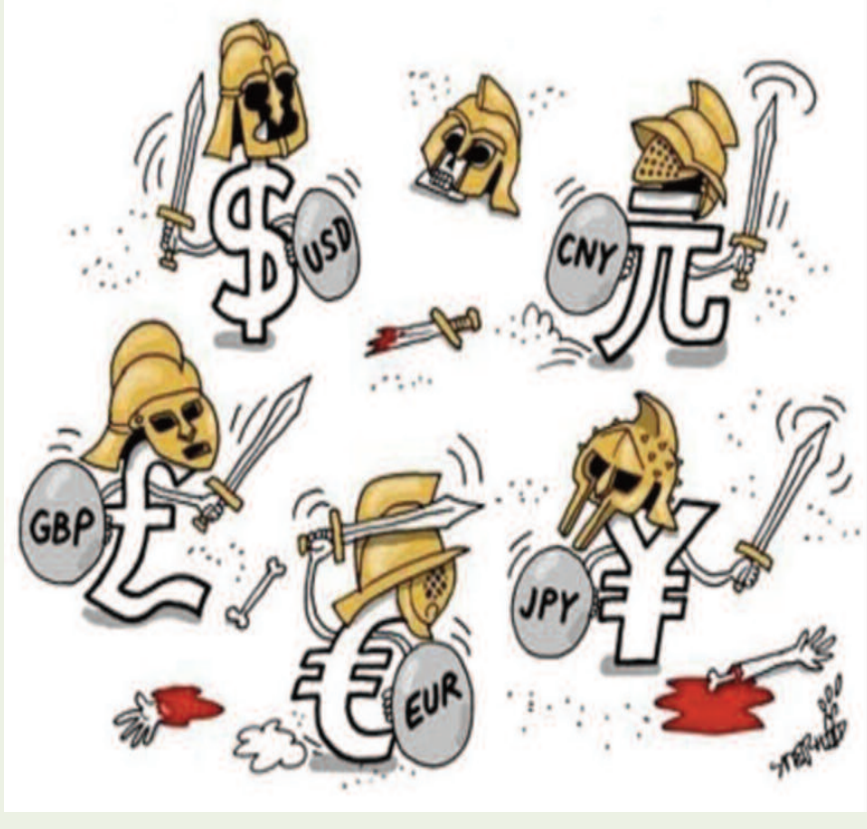

जैसा कि बेन फ्रैंकलिन आज के अमेरिकी नेताओं से कह सकते हैं, 'यदि आप इसे रख सकते हैं तो आपके पास आरक्षित मुद्रा की स्थिति है।' क्या करें? फेडरल रिजर्व को ब्याज दरों को बढ़ाकर डॉलर को मजबूत करना चाहिए। ट्रेजरी सचिव जेनेट येलन को चिल्लाने की जरूरत है 'ए मजबूत डॉलर हमारे राष्ट्रीय हित में है' पहाड़ की चोटियों से। राजकोषीय घाटे को समाप्त करने से बकाया कोषागारों के लिए बोली लगाने की लड़ाई पैदा करने में भी मदद मिलेगी। अमेरिकी कंपनियों को आत्मसंतुष्ट आपूर्ति श्रृंखलाओं को अद्यतन करने की आवश्यकता है। यदि दवाएं और आईफोन जैसे उत्पाद केवल चीन से आते हैं, तो यह एक समस्या है। इस वजह से, बिडेन प्रशासन को संघ-प्रेमी 'अमेरिकी खरीदें' पिच को छोड़ देना चाहिए, जिसे हमने उनके स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में सुना था, जो डोनाल्ड ट्रम्प के 'अमेरिका पहले' को प्रतिध्वनित करता है। Apple यूनियन-भारी मिशिगन में iPhones को असेंबल नहीं कर सकता। अमेरिका की ताकत वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका और पूर्वी यूरोप के देशों जैसे निचले क्षैतिज स्तरों में अपने सहयोगियों से सामान और सेवाएं खरीदने से आती है। इससे खिलवाड़ मत करो।

अमेरिका के लिए यह पता लगाने का समय आ गया है कि चीन या रूस के पास फार्मा, जेनेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वारफेयर की एक छोटी सी बढ़त कहां हो सकती है और इन उद्योगों को ऑर्डर और प्रीपेमेंट के माध्यम से प्रोत्साहित करने के लिए ऑपरेशन वॉर स्पीड जैसे प्रोग्राम बनाएं, हैंडआउट्स नहीं।

रूस पर प्रतिबंध तुरंत डॉलर को खतरे में नहीं डालेंगे, लेकिन युद्ध तब होते हैं जब संक्रमण होता है। अमेरिका को अपनी आरक्षित-मुद्रा स्थिति को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। अगर दूसरे देश डॉलर डंप करना शुरू करते हैं तो मुद्रास्फीति वास्तव में बड़े पैमाने पर चलेगी। अमेरिका का विशेषाधिकार बनाए रखने लायक है कहां से आसान।

में रखे उसके 300 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा संचित कोषों को, जब्त कर लिया गया है।

डॉलर के शस्त्रीकरण के खतरे

बहरहाल, डॉलर के वर्चस्व के लिए खतरा पैदा हो जाना तो, इस घटनाक्रम के परिणामों का एक हिस्सा भर है। इसका एक और हिस्सा यह है कि विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों पर आधारित, एक स्थिर व्यापार व्यवस्था के बने रहने के भरोसे के आधार पर निर्मित जटिल आपूर्ति श्रृंखलाएं भी दरकती नजर आती हैं। अमरीका को भी अब इसका पता चल रहा है कि रूस महज एक पैट्रोलियम-उत्पादक देश नहीं है, जैसा कि वे समझ रहे थे, बल्कि वह तो अमरीकी उद्योगों तथा सेना की जरूरतों के लिए अनेक अति-महत्वपूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति भी करता है। इसके अलावा रूस दुनिया के पैमाने पर गेहूं व उर्वरकों का अति-महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता तो है ही।

इस सब की पृष्ठभूमि में पश्चिमी देशों में जमा रूस के धन के जब्त किए जाने का अर्थ इस भरोसे पर ही सवालिया निशान खड़े करना है कि अमरीका दुनिया का बैंकर है और डॉलर विश्व की सुरक्षित मुद्रा है। अगर पश्चिमी देशों में जमा उनका पैसा ये देश अपनी मर्जी से कभी भी जब्त कर सकते हैं, तो क्यों अन्य देश इन देशों के साथ बचत वाला व्यापार चलाएंगे और अपनी बचत का पैसा इन पश्चिमी देशों की बैंकों में जमा करके रखेंगे? डॉलर के विश्व की सुरक्षित मुद्रा होने का भरोसा इस बात का तो भरोसा था कि डॉलर में जमाकर के रखा जा रहा सारा का सारा पैसा सुरक्षित रहेगा।

लेकिन, चंद महीने पहले अफगान सेंट्रल बैंक के 9.5 अरब डॉलर जब्त करके अमरीका ने दिखा दिया कि वह, अमरीकी सेंट्रल बैंक में दूसरे देशों द्वारा डॉलर में जमा करके रखे जा रहे पैसे को, माल ए गनीमत समझता है, जिसे कभी भी लूट सकता है। हो सकता है कि इस तरह की जमा राशियां, संबंधित देशों के खातों में एक आर्थिक परिसंपत्ति की तरह प्रदर्शित होती हों। लेकिन, वास्तव में तो ये जमा-राशियां इन देशों के लिए एक राजनीतिक कमजोरी ही हैं क्योंकि अमरीकी सरकार इन परिसंपत्तियों को अपनी मर्जी से कभी भी जब्त कर सकती है। इससे पहले ऐसा ही इराक, लीबिया, वेनेजुएला के मामले में भी देखने को मिला था। रूस के विदेशी मुद्रा संचित कोषों के जब्त किए जाने का यही अर्थ है कि तथाकथित नियम-आधारित व्यवस्था अब डॉलर को तथा वैश्विक वित्त व्यवस्था पर पश्चिम के नियंत्रण को हथियार बनाए जाने पर ही आधारित व्यवस्था बनकर रह गयी है।

डॉलर की सुरक्षित विश्व मुद्रा का रुतबा अब खतरे में

अर्थशास्त्रीगण, प्रभात पटनायक, माइकेल हडसन तथा क्रेडिट सुईस जोल्टन पोट्सर जैसे वित्त विशेषज्ञ अब एक ऐसी नयी विश्व वित्त व्यवस्था के अवतरण की भविष्यवाणी कर रहे हैं, जिसमें चीन की मुद्रा युआन या उसका कोई स्वरूप, दुनिया की नयी सुरक्षित मुद्रा बनकर उभर सकता है। और ये भविष्यवाणियां क्यों की जा रही हैं?

दूसरे विश्व युद्ध के बाद, ब्रेटन वुड्स समझौते के चलते, डॉलर को दुनिया की सुरक्षित मुद्रा बनने का मौका मिला था। तभी डॉलर ने ब्रिटिश पाउंड की यह जगह ले ली थी और उसकी कीमत को सोने के साथ बांध दिया गया था। 35 डॉलर यानी एक आउंस सोना! बहरहाल, 1971 में अमरीकी राष्ट्रपति निक्सन ने अमरीकी डॉलर को सोने के मानक से अलग करा दिया यानी अब डॉलर के पीछे सोने की निश्चित मात्रा नहीं, बल्कि सिर्फ अमरीकी सरकार या अमरीकी खजाने की गारंटियों का ही बल था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में, डॉलर के दुनिया की सुरक्षित मुद्रा बनने और बने रहने के पीछे तीन कारक थे। एक तो उसके पीछे अमरीका की ताकत थी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक

उत्पादनकर्ता है। दूसरा, इसके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत थी, हालांकि तब सोवियत संघ इस सैन्य ताकत को चुनौती दे रहा था। तीसरा, इसके पीछे पश्चिम एशिया के तेल की ताकत थी। तेल, अकेला ऐसा माल था जिसका व्यापार दुनिया भर में सबसे बड़ा था और जिसके दाम डॉलर में लगाए जाते थे।

पश्चिम एशिया के तथा खासतौर पर साऊदी अरब के तेल का डॉलर में निर्धारित किया जाना, अमरीका के लिए अति-महत्वपूर्ण था और यह अमरीका की सैन्य शक्ति से ही तय होता था। ईरान में प्रधानमंत्री मुसद्देह के खिलाफ तख्तापलट, इराक में 1963 के तख्तापलट और दूसरी अनेक घटनाओं को समझना कहीं आसान होगा, अगर हम यह याद रखते हैं कि अमरीका के लिए तेल कितना महत्वपूर्ण था। यही तो कार्टर सिद्धांत का आधार था, जो फारस की खाड़ी क्षेत्र तक मुनरो सिद्धांत का एक तरह से विस्तार करता था। या हम इसे उस कार्टर की नजर से समझ सकते हैं जो कहता था: 'हमारा तेल, उनकी रेत के नीचे दबा है!' पश्चिम एशिया के तेल पर अमरीका के नियंत्रण और उसकी औद्योगिक व सैन्य शक्ति ने ही यह सुनिश्चित किया था कि डॉलर, दुनिया की सुरक्षित मुद्रा बना रहे।

विश्व औद्योगिक शक्तिः नीचे खिसकता अमरीका

विश्व औद्योगिक शक्ति के रूप में अमरीका का नीचे खिसकना और चीन का उदय, साथ-साथ चलते आए हैं। चीन की औद्योगिक शक्ति के उभार को, एक सरल से आंकड़े से समझा जा सकता है, जो विश्व व्यापार के आइएमएफ के आंकड़ों का प्रयोग कर के लोवी इंस्टीट्यूट ने निकाला है। 2001 में, 80 फीसद देशों का मुख्य व्यापार सहयोगी अमरीका था। 2018 तक यह आंकड़ा घटकर 30 फीसद से जरा सा ही ऊपर रह गया और 190 देशों में से 128 का मुख्य व्यापार सहयोगी चीन हो गया, न कि अमरीका। यह नाटकीय बदलाव सिर्फ 20 साल में हुआ है! इस बदलाव का कारण है, औद्योगिक उत्पादन। चीन 2010 में ही अमरीका को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक उत्पादक बन चुका था (स्टेटिस्टा.कॉम)। भारत भी 5वां सबसे बड़ा औद्योगिक उत्पादक बन चुका है, लेकिन विश्व औद्योगिक उत्पादन में भारत का हिस्सा 3.1 फीसद ही है, जबकि चीन का हिस्सा 28.7 फीसद है और अमरीका का 16.8 फीसद। हैरानी की बात यह नहीं है कि व्यापार, औद्योगिक उत्पादन के पीछे-पीछे चलता है।

इस संदर्भ में हाल की दो घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। चीन और यूरेशियाई इकॉनमिक यूनियन, जिसमें रूस, कजाखस्तान, किर्गीजिस्तान, बेलारूस तथा आर्मीनिया शामिल हैं, एक नयी अंतर्राष्ट्रीय तथा मौद्रिक प्रणाली की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। भारत और रूस भी, रूसी हथियारों, उर्वरकों तथा तेल के आयात की भारत की जरूरत के आधार पर, रुपया-रूबल विनियम व्यवस्था स्थापित करते लग रहे हैं। भारत इससे पहले ईरान से तेल खरीदने के लिए ऐसी ही व्यवस्था आजमा चुका है। इस तरह की व्यवस्था से रूस के लिए भारत के निर्यातों में बढ़ोतरी को ही उछाला मिल सकता है। साऊदी अरब ने हाल ही में इसका इशारा किया है कि वह भी चीन के लिए तेल की अपनी बिक्री को डॉलर की जगह पर, युवान में प्रदर्शित करना शुरू कर सकता है। इसका मतलब युवान को तत्काल उछाला मिलना होगा क्योंकि साऊदी अरब के तेल का 25 फीसद हिस्सा चीन को ही बेचा जाता है।

छिन्न-भिन्न होतीं आपूर्ति शृंखलाएं

सेवाओं, बौद्धिक संपदा तथा सूचना प्रौद्योगिकी के बाजारों में अमरीका का बोलबाला है। लेकिन, ये सभी क्षेत्र जटिल आपूर्तियों पर और इसलिए जटिल वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं पर निर्भर हैं। अगर पश्चिमी आर्थिक युद्ध का मतलब, रूस की आपूर्तियों को वैश्विक बाजार से बाहर करना है, तो इससे अनेक आपूर्ति शृंखलाएं ही छिन्न-भिन्न हो जाएंगी। मैं पहले ही इस आर्थिक युद्ध के ऊर्जा युद्ध वाले पहलू पर लिख चुका हूं और यह भी कि कैसे यूरोपीय संघ, रूस से पाइपलाइन के जरिए योरप पहुंचायी जा रही गैस पर निर्भर है। बहरहाल, दूसरे भी बहुत से ऐसे माल हैं, जो रूस के खिलाफ पाबंदियां लगाने वाले देशों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं हैं बल्कि जो दूसरे अनेक ऐसे देशों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिनके लिए, पश्चिम की पाबंदियों के चलते रूस के साथ व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा।

काफी विचित्र है कि चिपों के उत्पादन की आपूर्ति शृंखला में काम आने वाला एक कुंजीभूत तत्व, रूस की आपूर्तियों पर ही निर्भर है। ये हैं नीलम सबस्ट्रेट्स, जिनमें कृत्रिम नीलम का उपयोग किया जाता है और जिनका उपयोग चिपों में होता है। इस क्षेत्र में लगता है कि रूस की लगभग इजारेदारी है। दूसरा खतरा, चिप निर्माताओं के लिए नियोन गैस की आपूर्तियों के लिए है। नियोन गैस के मुख्य आपूर्तिकर्ता दक्षिणी यूक्रेन में हैं। एक मरिऊपूल में और दूसरा ओडेस्सा में। दुनिया की नियोन गैस आपूर्ति का करीब 50 फीसद और दुनिया के चिप निर्माताओं के लिए नियोन गैस की आपूर्ति का 75 फीसद, इन्हीं दोनों कारखानों से आता है।

हम पहले ही रेखांकित कर चुके हैं कि यूरोपीय यूनियन की पर्यावरण परिवर्तन से निपटने की योजनाओं के लिए और उसके संक्रमणकालीन ईंधन के तौर पर प्राकृतिक गैस के उपयोग पर जाने के मंसूबों के लिए, आर्थिक युद्ध से कैसा खतरा पैदा हो गया है। इतना ही नहीं, नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा के रास्ते पर बढ़ने के लिए, ऊर्जा के भंडारण की सुविधाओं के मामले में निकल एक कुंजीभूत तत्व है और इस मामले में भी रूस निर्भरता काफी ज्यादा है। बिजली की बैटरियों के निकल बहुत महत्वपूर्ण होता है और रूस ही दुनिया का निकल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। अब जबकि अमरीका तथा यूरोपीय यूनियन ने, रूस के खिलाफ पाबंदियां लगा दी हैं, इसका नतीजा यह भी हो सकता है कि चीन, जो पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी आपूर्तिकर्ता बन चला है, इस मामले में अपनी बढ़त को और भी पुख्ता कर ले।

दोराहे पर है दुनिया

वांग यी की यात्रा का असली अर्थ

चीनी विदेश मंत्री वांग यी की यह भारत-यात्रा बड़ी रहस्यमय है। इसका अर्थ निकालना आसान नहीं है। वे हमारे विदेश मंत्री जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित दोभाल से मिल चुके हैं। वे भारत अपनी मर्जी से आए हैं। उनको बुलावा नहीं दिया गया था। उन्होंने अपनी भारत-यात्रा की घोषणा भी नहीं की थी। वे इसी तरह काबुल भी पहुंच गए थे। काबुल में तालिबान के विदेश मंत्री और अफसरों से तो उनकी बात हुई ही, रूसी प्रतिनिधि काबुलोव से भी उनकी गिटपिट हुई। अब वे श्रीलंका भी जाएंगे। ऐसा लगता है कि इस वक्त चीन अपनी छवि सुधारने में लगा हुआ है। कोरोना महामारी सारे संसार में फैलाने का जो दोष उसके माथे मढ़ा गया है, वह उसकी सफाई में जुटा हुआ है और अपनी महाशक्ति की छवि को चमकाने के लिए कृतसंकल्प है। वांग यी भारत इसलिए नहीं आए हैं कि भारत-चीन सीमांत विवाद शांत हो जाए। यदि वे इसलिए आए होते तो उस मुद्दे पर कोई ठोस प्रस्ताव लेकर आते लेकिन दोभाल और जयशंकर से हुई उनकी बातचीत से लगता है कि उनके भारत आने का खास उद्देश्य यही है कि 'ब्रिक्स' की अगली बैठक का कहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहिष्कार नहीं कर दें। यदि मोदी ने बहिष्कार कर दिया तो चीन की नाक कट सकती है। इसीलिए जब जयशंकर और दोभाल ने सीमा का मुद्दा उठाया और कहा कि उसे हल किए बिना दोनों देशों के संबंध सहज नहीं हो सकते तो वांग ने कह दिया कि वे सहमत हैं और वे इस मुद्दे पर संवाद जारी रखेंगे। उन्होंने दोभाल को चीन आने का निमंत्रण भी दे दिया। यूक्रेन के मुद्दे पर चीन पूरी तरह से अमेरिका के विरोध में है लेकिन भारत की तरह वह तटस्थता का दिखावा भी कर रहा है। ऐसा लगता है कि अब रूस और चीन का एक गुट तथा अमेरिका, नाटो, आकुस और क्वाड का दूसरा गुट बनने जा रहा है। लेकिन भारत को काफी सावधान रहना है। उसे अमेरिका की फिसलपट्टी पर झेलेंस्की की तरह फिसल नहीं जाना है। उसे अपने पांव पर खड़े रहना है। इसीलिए दोनों विदेश मंत्रियों ने युद्ध को रोकने और राष्ट्रीय संप्रभुताओं की रक्षा की बात को दोहराया। वांग यी ने इस्लामाबाद में कश्मीर पर जो कुछ कहा, उस पर भी आपत्ति की गई लेकिन वांग ने कहा कि दुनिया की ज्यादातर समस्याओं पर भारत और चीन का नजरिया एक-जैसा है। यदि वे मिलकर परस्पर सहयोग करें तो दोनों देशों के लिए यह बहुत लाभदायक होगा। चीनी राष्ट्रपति शी चिन फिंग और वांग यी जो कह रहे हैं, यदि वे सचमुच उसका पालन करें तो यह सदी एशिया की सदी बन सकती है।

- डॉ. वेदप्रताप वैदिक

विदेश नीतिः कुछ कमी, कुछ बढ़त

ऐसा लगता है कि तुर्की में चल रहा रूस-यूक्रेन संवाद शीघ्र ही उनका युद्ध बंद करवा देगा लेकिन इस मौके पर भारतीय विदेश नीति की कमजोरी साफ़-साफ़ उभरकर सामने आ रही है। जो काम भारत को करना चाहिए था, वह तुर्की कर रहा है। यह ठीक है कि तुर्की के अमेरिका और रूस दोनों से अच्छे संबंध हैं और वह नाटो का सदस्य भी है लेकिन इस समय अमेरिका और रूस के भारत के साथ जितने घनिष्ट संबंध हैं, किसी देश के नहीं हैं। इसका प्रमाण तो यह ही है कि दोनों के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं, दोनों देशों के राष्ट्रपति भारतीय प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं और दोनों महाशक्तियां भरपूर कोशिश कर रही हैं कि वे भारत को अपनी तरफ झुका लें लेकिन भारत अपनी तटस्थता की टेक पर मजबूती से टिका हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब भी मतदान हुआ है, उसने न तो रूस के समर्थन में वोट डाला और न ही अमेरिका के समर्थन में। लेकिन दुर्भाग्य है कि इसी साहस का परिचय उसने युद्ध बंद करवाने में नहीं दिया। फिर भी इस समय विदेश नीति के क्षेत्र में भारत काफी सफि य है। हर सप्ताह के दो-तीन दिन कोई न कोई विदेशी मेहमान भारत जरुर आ रहा है और भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित दोभाल भी विदेश यात्राएं कर रहे हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेइ लावरोव यदि नई दिल्ली आ रहे हैं तो अमेरिका ने अपने उप-सुरक्षा सलाहकार दलीपसिंह को भारत भेज दिया है ताकि भारत सरकार लावरोव के भुलावे में न फंस जाए। अमेरिका और नाटो राष्ट्रों की भरसक कोशिश है कि भारत किसी न किसी रुप में रूस की भर्त्सना करे और उस पर प्रतिबंधों को भी लागू करे लेकिन रूसी व्यापारिक प्रतिनिधि आजकल दिल्ली में बैठकर यह कोशिश कर रहे हैं कि भारत को बड़ी मात्रा में तेल कैसे बेचा जाए। इस्राइली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भी भारत आनेवाले थे लेकिन अस्वस्थता के कारण उनकी यात्रा अभी टल गई है। इस बीच बिम्सटेक की बैठक के लिए जयशंकर श्रीलंका पहुंचे हुए हैं। बिम्सटेक के सात देशों की बैठक को हमारे प्रधानमंत्री भी संबोधित कर रहे हैं। ये सात देश अपना घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं और आपसी सहयोग का महत्वपूर्ण समझौता भी कर रहे हैं। दक्षेस के निष्फि य होने पर बिम्सटेक की सफि यता विशेष स्वागत योग्य है। इस समय जयशंकर की यह श्रीलंका-यात्रा बहुत सार्थक और सामयिक सिद्ध हो रही है, क्योंकि श्रीलंका के अपूर्व आर्थिक संकट में भारत ने सीधी मदद की घोषणा की है और जफना में चीनियों के प्रस्तावित तीन सौर-केंद्रों को अब भारत चलाएगा। श्रीलंका के साथ दो रक्षा-समझौते भी हुए हैं। इस मौके पर मिली भारतीय सहायता श्रीलंका को चीन का चंगुल ढीला करने का साहस भी प्रदान करेगी।

- डॉ. वेदप्रताप वैदिक

आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व पैलेडियम, प्लेटीनम, टिटीनियम तथा रेयर तत्व हैं। उन्नत उद्योगों में इनकी जरूरत होती है और इससे दुनिया भर में आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाएं पैदा हो रही हैं। ये सभी उन 50 रणनीतिक सामग्रियों की सूची में भी हैं, जिनकी अमरीका को जरूरत होती है। हम यह याद कर लें कि कैसे कोविड-19 के दौरान आपूर्ति श्रृंखलाएं रुंध गयी थीं। आने वाला संकट उससे भी बदतर हो सकता है। इसके अलावा पाबंदियां लगाना तो आसान होता है, पर उन्हें उठाना कहीं मुश्किल होता है। और पाबंदियां उठाए जाने के बाद भी, आपूर्ति श्रृंखलाएं कोई पहले की तरह फिर से सुचारु तरीके से नहीं चल पड़ेंगी। याद रहे कि ये आपूर्ति श्रृंखलाएं, धीरे-धीरे करके दसियों साल में कायम हुई थीं। पाबंदियों के हथौड़े से उन्हें छिन्न-भिन्न करना तो आसान है, लेकिन उन्हें फिर से खड़ा करना काफी मुश्किल होने जा रहा है।

विश्व खाद्य आपूर्तियों पर इस सब के बीच और भी भारी चोट पड़ने जा रही है। यूक्रेन तथा बेलारूस, दुनिया भर के किसानों की जरूरत के उर्वरकों का उल्लेखनीय रूप से बड़ा हिस्सा बनाते हैं। रूस और यूक्रेन, गेहूं के दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से हैं। अगर रूस के गेहूं पर पाबंदी लगा दी जाती है और यूक्रेन की फसल पर युद्ध की मार पड़ती है, तो पूरी दुनिया के लिए खाद्यान्न की गंभीर तंगी से बचना आसान नहीं होगा।

इतना तो तय है कि दुनिया एक दोराहे पर है। इस सब के चलते या तो रूसी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, चाहे यूक्रेन में रूस जल्दी से शांति हासिल करने में कामयाब हो जाए या फिर चाहे नाटो-रूस युद्ध चाहे न भी हो। या फिर इससे एक नयी विश्व आर्थिक व्यवस्था बनेगी, जिसके आसार पहले से बन रहे थे और जिसमें सैन्य व आर्थिक युद्धों की जगह, सहकारात्मक समाधानों को आगे बढ़ाया जाएगा। ■

यूक्रेन में जीत के करीब पुतिन की सेना, यूक्रेन के साथ ही हारेगा अमेरिका-NATO?

● अभिजात शेखर

यूक्रेन युद्ध अब पांचवे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है और रूसी सेना ने युद्ध के चौथे हफ्ते से यूक्रेनी शहरों को हाइपरसोनिक मिसाइलों से निशाना बनाना शुरू कर दिया है और इसका दावा खुद रूसी रक्षा मंत्रालय ने किया है। यूक्रेन में अभी भी बेगुनाहों का खून बह रहा है, लेकिन अभी तक रूसी सेना को कीव पर कब्जा करने में कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन पुतिन ने अपने चार बड़े लक्ष्यों में से तीन को प्राप्त कर लिया है और अब रूस का आखिरी लक्ष्य कीव पर कब्जा करना ही बाकी बचा है। लेकिन, संभावना है कि, कीव पर कब्जे की लड़ाई में अभी कई दिनों का वक्त और लग सकता है। ऐसे में यूक्रेन युद्ध में फिलहाल तौर आने वाले वक्त में पांच बड़ी संभावनाएं बनती दिख रही हैं।

पहली संभावना-1- रूस जारी रखेगा हमले

यूक्रेनी सेना भी लगातार रूसी आक्रमण का विरोध कर रही है और रूसी सेना भी कई बार फंसती दिख रही है, खासकर कीव की लड़ाई रूसी सैनिकों को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है। जिसके बाद रूसी सेना ने अब राजधानी कीव पर डायरेक्ट कब्जे की कोशिश बंद कर दी है और कीव की पूरी तरह से घेराबंदी कर दी है और यूक्रेन के बाकी शहरों पर रणनीतिक नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रही है। जबकि, पश्चिमी देश लगातार एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें और पोर्टेबल एंटी टैंक यूक्रेन सैनिकों को भेज रहे हैं, जिससे रूसी सेना को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं, पिछले एक हफ्ते में रूस ने हमलों में कमी की है और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि, रूस बड़े हमले से पहले एक बार फिर से स्थिति का आकलन कर रहा है और अपनी शक्ति को पुनर्गठित कर रहा है।

पहली संभावना-2- अमेरिकी दावे में कितना दम?

अमेरिकी खुफिया का अनुमान है कि 7,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी खुफिया विभाग की तरफ से ये जानकारी दी है, जबकि यूक्रेनी सेना ने 13 हजार ज्यादा रूसी सैनिकों को मारने का दावा किया है। लेकिन, कई रक्षा विशेषज्ञ अमेरिका और यूक्रेनी दावों को 'इनफार्मेशन वारफेयर' का हिस्सा बताते हुए 'युद्ध प्रोपेगेंडा' बताते हैं। हालांकि, रूस ने भी 'कितने सैनिक मारे गये हैं?' इसकी सही जानकारी नहीं दी है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता के बड़े पैमाने पर नए पैकेज की घोषणा की, जिसमें एस-300 मिसाइल रक्षा प्रणाली, 100 स्विचब्लेड 'कमिकेज' ड्रोन और हजारों और मिसाइल शामिल हैं। यानि, पहली संभावना ये है कि, यूक्रेन की राजधानी कीव की लड़ाई लंबे वक्त तक चलेगी, लेकिन अंतिम हार यूक्रेन की ही होगी और पुतिन के लिए अब 'वापसी' संभव नहीं है।

दूसरी संभावना- शांति वार्ता से युद्ध खत्म

यूक्रेन युद्ध शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद दोनों

यूक्रेन के जैविक हथियार और भारत का मास्टर स्ट्रोक !

भारत ने यूक्रेन में रासायनिक एवं जैविक हथियारों के रूसी दावे की जांच करवाने की बात कहकर पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। अब न तो अमेरिका को कोई उत्तर सूझ रहा है और न नाटो देशों को और न ही यूक्रेन को।

क्योंकि भारत की इस उचित मांग को कोई अनुचित कह भी नहीं सकता। जैविक हथियार मिले तो अमेरिका-यूक्रेन बेनकाब और रूस से दोस्ती और प्रगाढ़। यदि नहीं मिले तो अमेरिका से सम्बन्ध में कोई कटुता नहीं, सबकुछ यथावत ! लेकिन भारत की इस मांग के कई गहरे निहितार्थ हैं।

अब सबको अपनी-अपनी पोल खुल जाने का डर सताने लगा है। अतीत में अमेरिका लोकतंत्र, मानवाधिकार, विश्वशान्ति, परमाणु बम बनाने की क्षमता और जैविक-रासायनिक हथियारों का नाम ले लेकर अनेक देशों में आर्थिक प्रतिबंध से लेकर सैनिक हस्तक्षेप करता रहा है।

वियतनाम से लेकर इराक और ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक वह यही करता रहा है।

यूक्रेन और अमेरिका दोनों ही यूक्रेन में किसी भी जैविक हथियार निर्माण केंद्र के अस्तित्व से इनकार करते रहे हैं जबकि रूस इनके होने का दावा कर रहा है। यूक्रेन पर आक्रमण के अनेक कारणों में से यह भी एक प्रमुख कारण रूस बताता रहा है।

प्रश्न यह है कि अमेरिका और नाटो ने इराक पर इन्हीं हथियारों की बात कहकर ही तो आक्रमण किया था। परंतु अमेरिका के ही नेतृत्व में हुई जांच में ऐसा कुछ भी नहीं मिल पाया !

तो फिर किस अधिकार से अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया था ?

यह ठीक है कि सद्दाम हुसैन के सम्बंध भारत से मैत्रीपूर्ण थे, पर वह कोई दूध का धुला आदमी नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा तानाशाह था। उसने अपने दामाद तक को गोली मार दी थी।

दोहरे मापदण्ड की धंधेबाजी करनेवाला अमेरिका आजतक नहीं बता पाया कि यह अफगानिस्तान में गया क्यों था?? फिर निर्लज्ज कपटी और कायर की भांति सबको मौत के मुंह में डालकर और अपने मुंह में कालिख लगाकर अफगानिस्तान से भागा क्यों ?

क्या तब काबुल में लोकतंत्र की स्थापना का पुनीत कार्य सम्पन्न हो गया था ?

वह आजतक यह भी नहीं बता सका कि सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत को लगातार लहूलुहान करनेवाले और अलकायदा के मुखिया ओसामा बिन लादेन को छुपा कर रखनेवाले आतंकी देश पाकिस्तान की हर प्रकार से मदद वाशिंगटन क्यों करता रहा था ?

कश्मीर से धारा 370 हटाये जाने के बाद संयुक्त जांच दल भेजनेवाले अमेरिका के जांचदल ने अफगानिस्तान में ऐसा कोई दल क्यों नहीं भेजा ?

अब भारत की मांग के बाद यदि जांच होती है.... यदि यूक्रेन में ये घातक हथियार मिलते हैं तो इसके निर्माण का सारा ब्लूप्रिन्ट और साजो सामान उपलब्ध कराने वाला अमेरिका पूरी तरह बेनकाब हो जाएगा।

और तब इराक पर किये गये आक्रमण को, ईरान पर किये गए आक्रमण को, अफगानिस्तान से अपने पतित पीठ दिखाने आदि कलंक को कैसे सही ठहरा पाएगा ?

और तब यूक्रेन को मिल रही सहानुभूति भी समाप्त हो जाएगी। तब रूस को विलेन बनाने की जगह अमेरिका खुद ही विलेन बन जाएगा। और यदि ये हथियार नहीं मिले तो ??

जाहिर है कि बिना रूस से मिले ठोस सबूत के भारत अमेरिका को नङ्गा करने का इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा।

जांच सही पाये जाने पर नाटो भी विघटन की ओर बढ़ जाएगा, जो भारत के लिए अच्छा होगा।

इसी अमेरिका के कारण आज हम तालिबान, पाकिस्तान और चाइनीज वुहान सब से परेशान हैं।

अब वुहान के जैविक हथियार संस्थान को मिली अमेरिकी सहायता की जांच पर बाइडेन प्रशासन ने जैसी लीपापोती की थी उसकी कलई भी खुल जाएगी।

इसके बाद तालिबान पर किसी भी भारतीय सैन्य कार्रवाई के समय पश्चिम से ईरान और उत्तर से रूस के कारण तालिबान अकेला पड़ जाएगा।

रही बात पाकिस्तान की तो रूस के कारण चीन उसे अंकुश में रखते हुए युद्ध में शामिल नहीं होने देगा।

नतीजा यह होगा कि तालिबान पाकिस्तान पर ही हमले शुरू कर देगा, लेकिन इससे वह खुद चारों ओर से घिरकर तबाह हो जाएगा।

भारत, रूस और ईरान का यह नया सम्बन्ध पोलैंड, फ्रांस और जर्मनी को भी भारत के और निकट ला देगा, पहले से तो ये देश हैं ही।

इन सबके कारण तेल से लेकर हथियार तक भारत को कोई कठिनाई नहीं होगी।

लेकिन हां, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हम ही क्या सारा विश्व अभी भी अमेरिका के गूगल, जीमेल, फेसबुक, ट्विटर, मुद्रा विनिमयन के स्विफ्ट आदि पर बहुलांश निर्भर है। यहां असर पड़ेगा ! लेकिन भारत ने चतुराई के साथ सिर्फ जांच कराने की बात कही है, न तो अमेरिका का नाम लिया है, न रूस का और न ही यूक्रेन का।

दावे प्रतिदावे में कोई भी तटस्थ और सम्भावित मध्यस्थ यही बात करेगा।

अतः इससे भारत एक धर्माधिकारी की भूमिका में आ गया है जो केवल सत्यान्वेषी होकर सत्य आधारित न्याय का पक्षधर दिख रहा है बिना किसी का भी पक्ष लेते हुए।

इस प्रकार भारत के इस मास्टर स्ट्रोक से सांप भी मर जायेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी !

थैंक्यू मोदी जी !!

युद्ध का व्यापार और अर्थशास्त्र

कितनी दिलचस्प बात है कि दुनिया के अधिकांश तेल व गैस उत्पादक राष्ट्र ईसाई व मुस्लिम हैं। अमेरिका के नेतृत्व में नाटो देश इन देशों को आपस में लड़ाने का खेल खेलते हैं। माल कमाने के लालच में पहले मुस्लिम देश फिलिस्तीन, इराक़, कुवैत व अफगानिस्तान बर्बाद किए गए तो अब ईसाई देश यूक्रेन को बर्बाद किया जा रहा है। इस बार रूसी ईसाई ही युक्रेनी ईसाई को मार रहे हैं। रुस को जबरदस्ती उकसाकर आक्रामक बना दिया गया है। युद्ध -युद्ध के इस सोचे समझे खेल में तेल गैस की आपूर्ति गड़बड़ा दी जाती है, जिस कारण मांग-आपूर्ति का चक्र बिगड़ जाता है और गैस व तेल के दाम कुछ ही दिनो में आसमान छूने लगते हैं। भ्रम, भय, हिंसा व युद्ध के इस वहशी व पूरे खेल को तेल - गैस उत्पादक देशों के राजनेता, नौकरशाह, अर्थशास्त्री व कारपोरेट चराने बैठ कर तय करते हैं। कितने लोग मारे जाएंगे, कितनी युद्धक सामग्री लगेगी, कितने संसाधन नष्ट होंगे, कितना पुनर्निर्माण में खर्च आएगा और दाम बढ़ने से कितना टर्नओवर बढ़ेगा सब पहले ही अनुमान लगा लिए जाते हैं। क्या बयानबाजी करनी है, कितने प्रतिबंध लगाने के नाटक करने हैं सब स्क्रिप्ट पहले से ही लिख ली जाती है। जिंसो के रेट, हथियारों आदि के सौदे, शेयर व वायदा बाजार के उतार चढ़ाव आदि से क्या फायदे होंगे। पूरे खेल की रचना अपनी जीडीपी बढ़ाने व निर्भर देशों की आमदनी चूसने के गणित पर आधारित होती है। युद्ध के इस व्यापार में आदमी 'मानव संसाधन' होता है जिसका युद्ध में इस्तेमाल कर निबटा दिया जाता है और बाजार के चक्र को आगे बढ़ाया जाता है। बाजार के इस क्रूर खेल में 'मानवाधिकार' और ' ह्यूमनवीइंग' जैसे शब्द बस एक धोखा हैं।

- अनुज अग्रवाल

पक्षों के वार्ताकारों ने बातचीत शुरू कर दी है और पहली बातचीत बेलारूस-यूक्रेन सीमा पर, फिर तुर्की में और बाद में राजधानी कीव में वर्चुअल बैठक के जरिए की जा रही है, ये बातचीत हर दिन हो रही है। युद्ध के मैदान में बढ़ते नुकसान और रूसी अर्थव्यवस्था पर पश्चिमी प्रतिबंधों को पंगु बनाना पुतिन को संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक 'चेहरा' बचाने वाला रास्ता तलाशने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस सप्ताह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के युद्ध विशेषज्ञ रॉब जॉनसन ने लिखा है कि, 'यूक्रेन रूसियों को एक विकल्प चुनने के लिए मजबूर करने में सक्षम हो सकते हैं, अगर वो बीच का रास्ता निकालने पर विचार करते हैं'। वहीं, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बुधवार को कहा कि, दोनों पक्ष एक समझौते पर सहमत होने के करीब आ गये हैं, और इसके तहत यूक्रेन भी स्वीडन और ऑस्ट्रिया की तरह ना अमेरिका का और ना ही रूस के खेमे में जाएगा और न्यूट्रल रहेगा। वहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की पहले ही सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुके हैं कि उनका देश पश्चिमी नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल नहीं होगा, जो क्रेमलिन की एक प्रमुख मांग रही है।

तीसरी संभावना- रूस की घरेलू राजनीति

यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी देशों की मीडिया लगातार दावे कर रही थी, कि यूक्रेन युद्ध से पुतिन की कुर्सी खतरे में पड़ रही है और रूस में ऐसा विद्रोह होगा, कि पुतिन को राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन, ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। रूस के समाज पर पुतिन की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत ही हो रही है। यूं तो रूसी मीडिया पहले भी स्वतंत्र नहीं थी, लेकिन अब रूस में मीडिया को पूरी तरह से फंदे में कस दिया गया है। रूस के सैकड़ों मीडियाकर्मियों ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं, हजारों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर नये कानून के तहत 15 सालों तक जेल में बंद करने की धमकी दी गई है। वहीं, रूस के लोगों को स्वतंत्र तौर पर न्यूज पढ़ने और दूसरे देशों की जानकारियां हासिल करने के सभी रास्ते बंद कर दिए गये हैं और अब लोग न्यूज पढ़ने के लिए 'VPN' का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं, रूस के एक बड़े वर्ग में पुतिन की लोकप्रियता और बढ़ गई है। यानी, पुतिन और भी ज्यादा ताकतवर बनकर उभर सकते हैं। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि, आने वाले वक्त में रूसी अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो जाएगी, कि पुतिन का तख्तापलट हो सकता है।

चौथी संभावनाः रूस की सैन्य सफलता

अब जब युद्ध का चौथा हफ्ता शुरू हो चुका है और रूसी सैनिकों ने बेहतर हथियारों के जरिए यूक्रेनी सैनिकों के प्रतिरोध को कुचलना शुरू कर दिया है, तो पश्चिमी देशों के विश्लेषकों ने मन-मसोसकर कहना शुरू कर दिया है, कि रूस अब यूक्रेन में प्रतिरोध का खात्मा कर सकता है। एक वरिष्ठ यूरोपीय सैन्य अधिकारी ने बुधवार को आगाह करते हुए कहा कि, रूसी सेना अपने आप को फिर से संगठित कर रही है और बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने की प्लानिंग कर रही है। अधिकारी ने कहा कि, ऐसा प्रतीत होता है कि डीजल और यहां तक कि इंजन स्नेहक की आपूर्ति कम होने से उन्हें रसद और मनोबल की समस्या है, जिसे वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं, रूस ने शहरी लड़ाई के लिए सीरियाई लड़ाकों को बुलाया है, जो जल्द ही कीव में घुसने वाले हैं।

पांचवी संभावना- विश्वयुद्ध की आशंका

यूक्रेन की चार पूर्व सोवियत राज्यों के साथ सीमा है जो अब अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो सैन्य गठबंधन के सदस्य हैं, जो एक सदस्य पर हमले को सभी के खिलाफ हमला मानता है। यानी, अगर गलती से भी रूसी सेना ने किसी भी नाटो देश पर हमला किया, तो फिर नाटो को युद्ध में शामिल होने का मौका मिल जाएगा। रूस पोलैंड की सीमा के बेहद पास यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है और पोलैंड पर गलती से अगर एक भी मिसाइल या बम गिरता है, तो विश्वयुद्ध की आग सुलगने में वक्त नहीं लगेगी। वहीं, पुतिन ने रूस के परमाणु निवारक बलों को हाई अलर्ट पर रखने का आदेश दिया है और विदेश मंत्री लावरोव ने भी चेतावनी दी है कि 'तीसरा विश्व युद्ध परमाणु युद्ध का शक्ल

ले सकता है।' पश्चिमी विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह की चेतावनियों को संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप को यूक्रेन पर 'नो-फ्लाई जोन' जैसे विचारों पर विचार करने से रोकने के लिए एक मुद्रा के रूप में लिया जाना चाहिए।

रूस-यूक्रेन युद्ध में सीधे तौर पर नहीं शामिल होगा नाटो

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) ने साफ कर दिया है कि वह रूस-यूक्रेन युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं होगा। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मौजूदगी में नाटो, यूरोपीय यूनियन और जी 7 देशों की महत्वपूर्ण बैठकों यह निर्णय लिया गया।

नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि 30 देशों के संगठन को रूस से कोई खतरा नहीं है लेकिन सतर्कता के चलते रूस के पास के सदस्य देशों- बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया और स्लोवेनिया में लड़ाकू सैन्य दस्तों की तैनाती की जाएगी।

यूक्रेन को अधिक मदद, रूस पर और प्रतिबंध

अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंधों का दायरा और बढ़ाने और यूक्रेन को अतिरिक्त सहायता ऐलान किया है। अमेरिका यूक्रेन से पलायन करने वाले एक लाख लोगों को अपना वीजा देकर उन्हें जीवन यापन में मदद देगा। इसके अतिरिक्त यूक्रेन को एक अरब डालर (करीब साढ़े सात हजार करोड़ रुपये) की मानवीय सहायता दी जाएगी। सैन्य मदद इसके अतिरिक्त होगी। अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो ने यूक्रेन की सैन्य आपूर्ति बढ़ाने का भी फैसला किया है।

इससे पहले यूक्रेन युद्ध में सीधे दखल से नाटो ने पहले ही इन्कार कर दिया था। एक महीने के युद्ध के बाद गठबंधन ने इस बात को गुरुवार को फिर दोहराया। राष्ट्रपति बाइडन ने कहा, यूक्रेन को आत्मरक्षा का अधिकार है। इसलिए हम उसे समर्थन देना जारी रखेंगे और उसकी मदद बढ़ाएंगे।

यूक्रेन को दी जाने वाली मदद बढ़ाएगा नाटो, पूर्वी सदस्य देशों में सैन्य तैनाती भी बढ़ेगी

यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच NATO (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन) सहयोगियों ने अपनी पूर्वी सीमा पर सैन्य तैनाती में इजाफा करने का फैसला किया है।

साथ ही उन्होंने रूस का मुकाबला कर रहे यूक्रेन को दी जाने वाली मदद बढ़ाने का ऐलान किया है।

ब्रसेल्स में अहम बैठक के बाद NATO के महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि एक नई सुरक्षा हकीकत का सामना करने के लिए सभी नेताओं ने प्रतिरोध और रक्षा को बढ़ाने पर सहमति जताई है।

नाटो के बारे में जानिये

NATO अमेरिका और उसके सहयोगियों का एक सैन्य गठबंधन है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 4 अप्रैल, 1949 को एक संधि के जरिए इसका गठन किया गया था।

अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम (UK) समेत कुल 12 देशों ने इसकी स्थापना की थी। अभी इसके सदस्यों की संख्या 30 है।

NATO का सबसे प्रमुख प्रावधान ये है कि अगर कोई इनमें से किसी एक देश पर हमला करता है तो इसे सभी देशों पर हमला माना जाएगा।

'यह युद्ध इस पीढ़ी की सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा'

स्टोल्टनबर्ग ने कहा, 'रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से शुरू किया गया यह युद्ध इस पीढ़ी की सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा है और सहयोगियों को निर्णायक तौर पर इसका जवाब देना होगा। हमें यूक्रेन की हर संभव मदद करनी चाहिए

पूर्वी सीमा की सुरक्षा बढ़ाएगा गठबंधन

NATO के सभी सदस्य देशों ने बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया में चार अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियों की तैनाती का फैसला किया है। ये उन सैनिकों से अलग होंगे, जो पहले से ही पोलैंड और अन्य बाल्टिक देशों में तैनात हैं।

इसके अलावा गठबंधन की पूर्वी सीमा पर लड़ाई विमानों और लड़ाई का जवाब देने वाले दस्तों की तैनाती की जाएगी। साथ ही स्थायी तौर पर पनडुब्बी और युद्धक जहाजों को तैनात करने का निर्णय लिया गया है।

यूक्रेन की मदद रहेगी जारी

NATO ने कहा कि वह रूस के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए यूक्रेन को एंटी-टैंक एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन्स मुहैया कराएगा, जो अभी तक बेहद कारगर साबित हो रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन की साइबर सिक्योरिटी, वित्तीय और मानवीय मदद भी जारी रहेगी।

इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने NATO सदस्यों को संबोधित करते हुए मांग की थी उन्हें रूस का मुकाबला करने के लिए असीमित मदद मुहैया कराई जाए।

चीन से रूस की मदद न करने की अपील

यूक्रेन आंखो देखी .....

अच्छा सुनो

मैंने बताया था कि ये लड़ाई रूस यूक्रेन की दिख रही है लेकिन वास्तव में ये युद्ध रू नाटो के साथ रूस लड़ेगा । यूक्रेन को रूस ने बुरी तरह तबाह कर दिया है लेकिन कब्जा नही कर रहा है । आज बाइडन की यूरोप यात्रा का स्वागत पुतिन ने धमाकेदार अंदाज में किया है । सबसे पहले तो मारियोपोल को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया और उसके बाद उसने यूरो और डॉलर के साथ सभी तरह के लेनदेन पर रोक लगा दिया है । अब होगा ये की जब बिडेन अपने श्व के मित्रो के साथ बैठक करेंगे तो श्व के वो देश जो रूस के तेल और गैस पर निर्भर हैं बाइडन को सबसे पहले उनकी समस्या का समाधान करने को कहेंगे क्योंकि जब रूस यूरो और डॉलर नही लेगा तो वो देश प्रतिबन्ध के कारण रूबल कैसे इस्तेमाल करेंगे ।

बाइडन अपनी ही चाल में फंस रहा है । बात बात पर हथियार और पैसे देने की बात करता है जबकि जेलेन्स्की ने साफ कह दिया है कि उसे सैन्य सहायता भी चाहिये । यूरोपीय देशों को रूस की ओर झुकना पड़ सकता है क्योंकि उन्हें श्रीलंका में अपना भविष्य दिखाई पड़ रहा है जहां, सेना लगी है और एक आदमी को एक लीटर से ज्यादा तेल नही दे रही है । श्व बाइडन की मीटिंग में नाटो का दो फाड़ होना भी सम्भव लग रहा है क्योंकि आज बाइडन ने दो बार एक ही बात दोहराया है – रूस हमें आपस मे नही लड़वा सकता ।

यानी आग लग चुकी है ।

अच्छा सुनो

रूस नें युक्रेन पर जो हमला किया वह उसके राष्ट्रहित के तौर पर एकदम उचित और सही कदम है । भारत नें भी चीन द्वारा पाक क्षेत्र में किये जाने वाले निर्माण पर आपत्ति जताते हुए आक्रामक कदम उठाया था तब चीन वहां से पीछे हटा । ठीक ऐसा ही युक्रेन भी कर रहा था , अंतर इतना ही है की यहां चीन था वहां नाटो ह्य । यदि आप रूस के हमले को गलत मानकर उस पर लगने वाले प्रतिबन्ध का समर्थन करते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नही हो सकता क्योंकि तब आप केवल बिकाऊ मीडिया के दिमाग से ही सोच रहे हैं । यदि आपको रूस पर प्रतिबंध सही लगता है तो आप यमन की राजधानी साना में आज सुबह से जारी रू+च की बमबारी पर कुछ क्यों नही कहते !

क्या युक्रेन में मरने वाले 127 बच्चों की संख्या साना में आज मरने वाले 310 बच्चो की मौत से ज्यादा है ? क्या युक्रेन की मांग जायज और यमन की मांग नाजायज है ?

दरअसल युक्रेन पर हमले के बाद बिकाऊ मीडिया नें रूस को खलनायक बनाने का खेल किया है और कुछ नही । यदि आप तर्कों और सिद्धांतों की कसौटी पर यूक्रेन और यमन को कसेंगे तो यूक्रेन खोटा निकलेगा । आप मानो या न मानो दुनिया पर कब्जे की जंग में रू+च+श्व निकले हुए है ना कि रूस । रूस अपनी सीमाओ की सुरक्षा में लगा हुआ है जबकि अमेरिका के साथी क्यों यमन में लड़ाई कर रहे हैं इसका कोई ठोस जवाब किसी के पास नही मिलेगा । कारण साफ है – यमन के प्राकृतिक संसाधनों को पाने के लिए अपनी समर्थक सरकार तैयार करने के लिये ।

यमन के हूती विद्रोहियों ने कल फिर से सऊदी के आरामको तेल कम्पनी पर हमला किया था जिसके जवाब में सऊदी आज सुबह से विद्रोहियों के ठिकाने पर लगातार बमबारी कर रहा है ।

अब देखो यूक्रेन और यमन में खेल !

यूक्रेन में रूस लड़ रहा है अपने लिए । यमन विद्रोहियों पर सऊदी रूसी सहयोग से हमले कर रहा हैं जबकि अमेरिकी दोस्त विद्रोहियों के समर्थन में यमन की राजधानी पर बम बरसा रहे हैं ।

और हां !

रूस के विरोध में या हताश करने वाली खबरों पर कोई ध्यान मत देना क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसेंगे ।

अच्छा सुनो

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में कल रूस नें यूक्रेन मामले में अपना एक मसौदा प्रस्तुत किया और ह्रस्ट सदस्यों से समर्थन मांगा । उसके प्रस्ताव पर 15 में से 13 सदस्यों ने दूरी बना लिया और उस प्रस्ताव पर केवल 2 वोट पड़े । 1 रूस और दूसरा चीन का । भारत इस बार भी खुद को तटस्थ बताते हुए वोटिंग से दूर रहा ।

अब दुनिया की सारी मीडिया इसे रूस की करारी हार बताते फिर रही है, लेकिन इस हार में रूस की कूटनीतिक जीत पर कोई बात नही करना चाह रहा है । रूस की जीत प्रस्तुत मसौदे में भावी इतिहास लिखेगा । सारी दुनिया जानती है कि अब विश्वयुद्ध कुछ ही कदमों की दूरी पर है इसलिए सभी अपने अपने वर्तमान को इस तरह दर्शाना चाहते है ताकि भविष्य में युद्ध का ठीकरा उन पर न फूटे । द्वितीय विश्वयुद्ध उदाहरण है कि सबसे बड़ा नरसंहार अमेरिका ने किया था जबकि इतिहास जर्मनी जापान को दोष देता है ।

खैर अपने को क्या !

जानिये रूस के किस प्रस्ताव पर उसे किसी का साथ नही मिला है –

प्तयूक्रेन में ह्रस्ट सदस्य मानवीय सहायता पहुंचाने सहयोग करे ।

प्तजहां भी जरूरत होगी सीज फायर करके उस क्षेत्र को सुरक्षित गलियारे में तब्दील किया जाये ।

भोजन पानी दवाओं की सारी खेप जल्द से जल्द पहुंचाया जाये ।

प्तमहिलाओं बच्चों व असहाय लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने के प्रयास किये जाएं।

अब इस प्रस्ताव भले ही गिर गया हो, लेकिन UNSC के रिकॉर्ड में आ गया है । अब भविष्य कहेगा कि देखो रूस ने तो मानवीय सेवा के लिए पूरा प्रयास किया था लेकिन UNSC नें इस प्रस्ताव पर साथ नहीं दिया, इसलिए इस युद्ध का दोष जेलेन्स्की और UNSC के ऊपर ही जाएगा।

और हां !

इतनी दूर की कूटनीति भारत का वर्तमान कौटिल्य ही कर सकता है।

अच्छा सुनो

मैने कहा था कि जो देश दिख रहे हैं वहां नही बल्कि लड़ाई नए मोर्चे पर शुरू होगी । वह नया मोर्चा खुला है आर्मेनिया और अजरबैजान का। अजरबैजान नें अर्मेनियाई सीमा पर जबरदस्त बमबारी शुरू कर दिया है । उसको ये हिम्मत कल मिली जब रूस नें आर्मेनिया से अपने शांति सैनकों की वापसी शुरू किया ।

आज पुतिन ने दो बार अजरबैजान से युद्ध रोकने की अपील किये है लेकिन वह अब भी आक्रमण जारी रखा है ।

लगता है पहला शॉट उद्दर ही पड़ने वाला है क्योंकि युक्रेन पर रूस अपना कब्जा नही कर रहा है ।

रूस इस बात का इंतजार नही करेगा कि कोई हम पर पहले न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करे, तब हम उसके जवाब में अपने हथियार निकालें । हम कभी भी, किसी भी समय , किसी भी देश पर न्यूक्लियर हथियारो का इस्तेमाल करने को स्वतंत्र है । हमारा निर्णय अपने विरुद्ध खड़े होने वाले देशों की ताकत व क्षमता पर निर्भर रहेगा कि किस पर कितना इस्तेमाल करना है - पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, जो देश की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं,

आपको लगता है रूस हार रहा है ?

बिल्कुल नही ! यदि ऐसा हो रहा होता तो यकीन मानिये अमेरिका नाटो अब तक यूक्रेन को हथियार देकर खुद भी रूस पर टूट पड़ते । दरअसल पुतिन की रणनीति अभी तक खुलकर किसी के समझ नही आई है । 2 मार्च को खारकीव पर रूसी कब्जा होने के बाद, रूसी सेना का वापिस होना और अब फिर से चेचन्या लड़ाकों का हमला करना समझ से बाहर का खेल है । हफ्ते भर पहले ओडेसा और मारियोपोल को इस कदर तबाह कर दिया गया था कि वहां आराम से रूसी फौज कब्जा कर चुकी होती और वो छोड़िये, आज सुबह कीव को चारो तरफ से घेरने के बाद फिर से एक हिस्से से पीछे हटना, ये कौन सी युद्धनीति है ।

इसके तीन कारण समझ आते हैं -

पहला - रूस कब्जा करके फिर से पीछे हटकर ये बताना चाहता है कि यदि नाटो यूक्रेन को हथियार दे देगा तो यूक्रेनियन रूस को खदेड़ सकते हैं । नाटो का हथियार आना यानी रूस का पोलेंड पर निशाना ।

दूसरा - रूस पीछे हटकर देखना चाहता है कि यूक्रेन को कौन कौन से देशो के हथियार मिल रहे है और उनकी क्षमता रूसी हथियारो के आगे कितनी है ।

तीसरा - रूस यूक्रेन को तबाह करके पूरी तरह अपने में शामिल करने की तैयारी में है और वह देखना चाहता है कि बड़े युद्ध की स्थिति में नाटो और अमेरिका उस पर कितने मोर्चे से हमला कर सकते हैं । इसके साथ ही वह ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और नार्वे पर अपना विशेष नजरें बनाये रखा है ।

और हां ! रूसी वायुसेना को सबसे ज्यादा नुकसान स्टिंगर और जेवलिन मिसाइल पहुंचा रही है । ये वही मिसाइलें है जिन्हें अमेरिका ने रूस के खिलाफ तालिबानीयों को दिया था जिसके बाद रूसी सेना पीछे हट गई थी ।

1. ओडेसा में रूसी सेना पीछे हटी, यूक्रेनी सेना का फिर से कब्जा ।

नतीजा - 3 दिन बाद ओडेसा पर हुई भारी बमबारी सभी बन्दरगाह तबाह ।

2. यूक्रेनी सेना के बुलंद हौसलों से मारियोपोल में रूसी सेना पीछे हटी, जेलेन्स्की नें कहा हम जीत रहे हैं ।

नतीजा - 2 दिन बाद से लगातार हवाई हमले के बाद 5 दिनों में मारियोपोल शहर खंडहर बन गया, जेलेन्स्की नें कहा हम निःशर्त बातचीत को तैयार ।

3. 2 दिन पहले खारकीव पर लहराया यूक्रेनी झंडा, जेलेन्स्की नें कहा नाटो हमें हथियार दे तो हम रूस जीत लेंगे ।

नतीजा - कल रात से जारी भीषण बमबारी और मिसाइल हमले के बाद आज खारकीव पूरी तरह नेस्तनाबूद हुआ एक भी इमारत साबुत नही बची । जेलेन्स्की नें कहा नाटो हमारा इस्तेमाल करके युद्ध लम्बा करना चाहता है ताकि वह कमजोर रूस पर हमला कर सके । मैं पुतिन से बातचीत करके मसला हल करना चाहता हूं ।

और अभी - इरपीन शहर पर यूक्रेनी सेना नें कब्जा करके अपना झंडा फहरा दिया है और जेलेन्स्की ने कहा है कि हम रूस को झुकाएंगे

अच्छा सुनो

अमेरिका का पांचवी पीढ़ी का सबसे आधुनिक विमान F35 है । इस पर अमेरिका को B2 से भी ज्यादा गुमान है कि पूरी दुनिया मे इसका कोई तोड़ नही हो सकता । अमेरिकी थिंक टैंक तो कहता है कि यदि ये युद्ध मे उतर जाए तो केवल 6 घण्टे में किसी भी पक्ष को जिताने में सक्षम है । वैसे भी US को अपने हथियारो की खूबियां बढ़ा चढ़ाकर बताने की होती है ।

तो क्या ये रूस के विरुद्ध कारगर हो सकता है ?

रूस का 6th जनरेशन का विमान मिग 41 है जिसे 2026 तक मिग 31 की जगह आ जाना है । रूस नें अपने इस घातक हथियार के बारे में खास जानकारी बाहर न भेजकर केवल साधारण जानकारी भेजा है । अब वो साधारण जानकारी क्या है ये पढिये -

इसकी रफ्तार मात्र 5270 km प्रति घण्टे है।

यह पायलट रहित, पुर्णतः स्वचालित प्रक्रिया चलित है ।

हथियार के नाम पर इसमें मासूम सी चार किंजल मिसाइल लगती है जिसका वार हेड न्यूक्लियर से लैस होता है ।

इसकी उड़ान अपने क्रायोजेनिक इंजन के कारण अंतरिक्ष तक सुगम बनाती है ।

अंतरिक्ष में स्थित उपग्रहों को नष्ट करने के लिए इसमें महज लेजर लगी होती है, जो बिना किसी की नजरों में आये उपग्रहों को नष्ट कर सकती है ।

दुनिया की कोई भी राडार या संचार प्रणाली इसे नही देख सकती ।

फिलहाल इतनी ही जानकारी मिग 41 की मिल सकी है । रूस नें पहले ही कह रखा है यदि नाटो यूक्रेन की मदद को आया तो उसे ऐसा सबक सिखाएंगे जो इतिहास में आज तक किसी को नही मिला होगा ।

रूस बिना बोले हथियार निकाल रहा है जबकि अमेरिका हल्ला कर करके अपनी दुर्गति करवा रहा है ।

और हां ! भारत के सहयोग से बनी ब्रह्मोस मिसाइल का नमूना तो दुनिया देख ही चुकी है । अमेरिका अपने जिन आधुनिक विमानों पर इतरा रहा है वह रूस के एयर डिफेंस S-500 की जद में है ।

मैं पहले भी बता चुका हूं कि रूस अपने नई पीढ़ी के कोई भी हथियार नही बेचता । उसके बिकने वाले सारे हथियार एक से दो पीढ़ी पुराने होते हैं । दरअसल US नाटो अभी भी इस भ्रम में हैं कि लड़ाई के मैदान में वो रूस से आगे हैं, सच्चाई ये है कि वो अभी रूस से तीन पीढ़ी पीछे हैं ।

क्या आप जानते हैं ?

रूस नें अमरीकी बमवर्षक B2 को तबाह करने में सक्षम मिसाइलों को अंतरिक्ष में 2011 से तैनात कर रखा है । अंतरिक्ष में रूस इकलौता महाशक्ति है और अगर इसने वहां अपनी जंग छेड़ा तो सारे देश बिन संचार जंग कैसे लड़ेंगे ?

- डब्बू मिश्रा यूक्रेन से

NATO के सदस्यों देशों के प्रमुखों और सरकारों ने चीन को रूस की आर्थिक और सैन्य मदद करने से बचने की अपील करते हुए कहा कि उसे भी दुनिया के बाकी देशों की तरह रूसी आक्रमण की निंदा करनी चाहिए।

रासायनिक हमले को लेकर क्या बोले नाटो महासचिव?

NATO में अपने संबोधन के दौरान जेलेंस्की ने रूस पर यूक्रेन में फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया था।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए स्टोल्टनबर्ग ने युद्ध में रासायनिक, जैविक और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका जताते हुए कहा कि यह संघर्ष का चरित्र ही बदल देगा और इसके यूक्रेन की सीमाओं से परे भी परिणाम देखने को मिलेंगे।

उन्होंने कहा यह NATO सदस्यों को भी प्रभावित करेगा और इसलिए युद्ध को तुरंत रोकने की जरूरत है।

जेलेंस्की ने मांगा सहयोग

नाटो सम्मेलन में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये शामिल हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ युद्ध में दुनिया के लोगों का सहयोग मांगा। जेलेंस्की ने कहा कि अपने घर-कार्यालयों से निकलकर लोग नजदीक के चौराहे-गलियों के नुक्कड़ पर एकत्रित हों और यूक्रेन के समर्थन का एलान करें। यूक्रेन जो लड़ाई लड़ रहा है, वह स्वतंत्रता और शांति की लड़ाई है। इस दौरान जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और नाटो के सदस्य देशों से ज्यादा सैन्य सहायता और समर्थन की मांग की।

इससे पहले जेलेंस्की ने स्वीडन की संसद को संबोधित करते हुए यूरोपीय यूनियन की सदस्यता के दावे को इसलिए भी जरूरी बताया कि वह पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए रूसी हमले का मुकाबला कर रहे हैं। वह और उनके देश की जनता स्वतंत्रता, सुरक्षा और विकास के लिए यूरोप से जुड़ना चाहती है।

बाइडन ने पुतिन को कसाई बता दी धमकी

रूस और यूक्रेन की जंग के बीच अब अमेरिका ने आक्रामक तरीके से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आलोचना की है. पोलैंड दौरे पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन पर निशाना साधते हुए कहा कि 'वो सत्ता में नहीं रह सकते हैं.' बाइडन ने पुतिन को 'कसाई' तक कह दिया. अमेरिका इस युद्ध में यूक्रेन के साथ खड़ा है. अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों के जरिए भी मदद का वादा किया है. बीती 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस की 'विशेष सैन्य कार्रवाई' शुरू होने के बाद अमेरिका ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए हैं. कुछ दिनों पहले बाइडन ने पुतिन को 'युद्ध अपराधी' और 'हत्यारा तानाशाह' भी बता दिया था.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाइडन ने 26 मार्च को पोलैंड की राजधानी वारसा में यूक्रेन के शरणार्थियों से मुलाकात की. इसी दौरान एक संबोधन में बाइडन ने कहा कि रूस लोकतंत्र का गला घोंट रहा है. उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध रूस के लिए 'रणनीतिक असफलता' है. बाइडन ने कहा कि ये लड़ाई कुछ दिनों या महीनों में खत्म नहीं होने वाली है. इसलिए इस संकट के समय वो यूक्रेन के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं. इसी संबोधन के अंत में बाइडन ने पुतिन को लेकर कहा,

भगवान के लिए, यह व्यक्ति सत्ता में नहीं रह सकता है

जो बाइडन के इस बयान का मतलब अलग-अलग तरीके से निकाला जाने लगा. जिसके बाद व्हाइट हाउस को भी सफाई देनी पड़ी। व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर कहा,

'बाइडन मॉस्को में सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कह रहे थे। राष्ट्रपति के कहने का मतलब यह था कि पुतिन अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपने पड़ोसियों या किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं। वो रूस में पुतिन के शासन की बात नहीं कर रहे थे।'

इससे पहले बाइडन ने 26 मार्च को वारसॉ में यूक्रेनी शरणार्थियों से भी मुलाकात की। इसी दौरान पत्रकारों ने बाइडन से शरणार्थियों की दिक्कतों को लेकर उनसे पुतिन के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, 'वो एक कसाई हैं।' बाइडन ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि रूस ने यूक्रेन को लेकर अपनी रणनीति में कोई बदलाव किया है। एक दिन पहले रूस ने कहा था कि यूक्रेन पर उसकी सैन्य कार्रवाई का 'पहला चरण' पूरा हो चुका है और अब वह डोनबास क्षेत्र को 'आजाद' कराने पर फोकस करेगा।

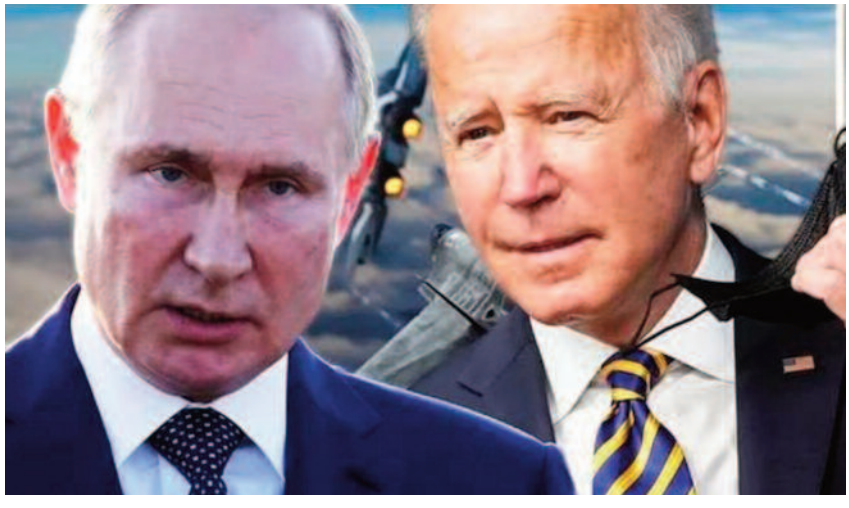

रूस ने बाइडन के बयान को किया खारिज

वहीं दूसरी तरफ, रूस ने जो बाइडन के 'पुतिन के सत्ता में नहीं रहने वाले' बयान की आलोचना की और कहा कि अमेरिका का इस मामले में कोई अधिकार नहीं है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इसका जवाब देते हुए कहा,

'इसका फैसला जो बाइडन नहीं कर सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति को रूसी नागरिकों ने चुना है।'

यूक्रेन पर हमले की शुरुआत के बाद से एक महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। रूस अपनी 'रणनीति' में बदलाव की बात कर

भारत-जापान सार्थक संवाद

जापान के नए प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना, यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। भारत और जापान के बीच कुछ दिन पहले चौगुटे (क्वाड) की बैठक में ही संवाद हो चुका था लेकिन इस द्विपक्षीय भेंट का महत्व इसलिए भी था कि यूक्रेन-रूस युद्ध अभी तक चला हुआ है। दुनिया यह देख रही थी कि जो जापान दिल खोलकर भारत में पैसा बहा रहा है, कहीं वह यूक्रेन के सवाल पर भारत को फिसलाने की कोशिश तो नहीं करेगा लेकिन भारत सरकार को हमें दाद देनी होगी कि मोदी-किशिदा वार्ता और संयुक्त बयान में वह अपनी टेक पर अड़ी रही और अपनी तटस्थता की नीति पर टस से मस नहीं हुई। यह ठीक है कि जापानी प्रधानमंत्री ने अगले पांच साल में भारत में 42 बिलियन डॉलर की पूंजी लगाने की घोषणा की और छह मुद्दों पर समझौते भी किए लेकिन वे भारत को रूस के विरुद्ध बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सके। भारत ने राष्ट्रों की सुरक्षा और संप्रभुता को बनाए रखने पर जोर जरूर दिया और यूक्रेन में युद्धबंदी की मांग भी की लेकिन उसने अमेरिका के सुर में सुर मिलाते हुए जबानी जमा-खर्च नहीं किया। अमेरिका और उसके साथी राष्ट्रों ने पहले तो यूक्रेन को पानी पर चढ़ा दिया। उसे नाटो में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया और रूस ने जब हमला किया तो सब दुम दबाकर बैठ गए। यूक्रेन को मिट्टी में मिलाया जा रहा है लेकिन पश्चिमी राष्ट्रों की हिम्मत नहीं कि वे रूस पर कोई लगाम कस सकें। किशिदा ने मोदी के साथ बातचीत में और बाद में पत्रकारों से बात करते हुए रूस की काफी भर्त्सना की लेकिन मोदी ने कोरोना महामारी की वापसी की आशंकाओं और विश्व राजनीति में आ रहे बुनियादी परिवर्तनों की तरफ ज्यादा जोर दिया। जापानी प्रधानमंत्री ने चीन की विस्तारवादी नीति की आलोचना भी की। उन्होंने दक्षिण चीनी समुद्र का मुद्दा तो उठाया लेकिन उन्होंने गलवान घाटी की भारत-चीन मुठभेड़ का जिक्र तक नहीं किया। भारत सरकार अपने राष्ट्रहितों की परवाह करे या दुनिया भर के मुद्दों पर फिजूल की चौधराहट करती फिरे ? चीनी विदेश मंत्री वांग यी भी भारत आ रहे हैं। चीन और भारत, दोनों की नीतियां यूक्रेन के बारे में लगभग एक-जैसी हैं। भारत कोई अतिवादी रवैया अपनाकर अपना नुकसान क्यों करें? भारत-जापान द्विपक्षीय सहयोग के मामले में दोनों पक्षों का रवैया रचनात्मक रहा।

- डॉ. वेदप्रताप वैदिक

रहा है. लेकिन अब भी यूक्रेन के कई शहरों पर लगातार हमला जारी है। 26 मार्च को भी अमेरिकी राष्ट्रपति के संबोधन से कुछ देर पहले पोलैंड की सीमा से लगे यूक्रेन के लवीव शहर पर हमला किया गया। अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस ने चार रॉकेट से लवीव पर हमला किया। युद्ध के कारण पूर्वी क्षेत्रों से भाग रहे लोगों के लिए लवीव एक सुरक्षित जगह माना जाता रहा है। इस हमले में पांच लोग घायल हुए।

परमाणु हथियारों की धमकी

इधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पोलैंड दौरे के बीच रूस ने एक बार फिर कहा कि वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने से नहीं झिझकेगा। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अगर उनके देश पर कोई संकट आता है, तो परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल करेंगे. मेदवेदेव ने कहा कि अगर रूस या उसके सहयोगी देशों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल का उपयोग होता है, तो वो इसका जवाब जरूर देंगे। उन्होंने कहा कि अगर रूस के खिलाफ कोई आक्रामक कार्रवाई या उसके किसी महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होता है, तो वो उन देशों के खिलाफ भी हमला करेगा, जिनके पास सिर्फ परंपरागत हथियार हैं।

इस बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने हथियार से मदद नहीं करने पर अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश सिर्फ बातचीत कर रहे हैं. जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन मिसाइल के खिलाफ बिना उपयुक्त हथियारों से खुद की रक्षा नहीं कर सकता है. और कब्जे में आ चुके मारिया पोल को टैंक और फाइटर जेट के बिना आजाद नहीं करा सकता है. उन्होंने कहा कि यूक्रेन को NATO के एक एयरक्राफ्ट और टैंकों का सिर्फ 1 फीसदी चाहिए।

वैश्विक आर्थिक युद्ध के परिणाम क्या होंगे?

- प्रबीर पुरकायस्थ

इतना तो तय है कि दुनिया एक दोराहे पर है। इस सब के चलते या तो रूसी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, या फिर इससे एक नयी विश्व आर्थिक व्यवस्था बनेगी, जिसके आसार पहले से बन रहे थे और जिसमें सैन्य व आर्थिक युद्धों की जगह, सहकारात्मक समाधानों को आगे बढ़ाया जाएगा।

क्या यूक्रेन युद्ध और अमरीका, यूरोपीय यूनियन तथा यूके के कदम, दुनिया की सुरक्षित या रिजर्व मुद्रा के रूप में डॉलर के अंत की ओर इशारा कर रहे हैं? रूस तथा यूक्रेन के बीच शांति की बातचीत भले ही 15 सूत्री शांति योजना तक पहुंच गयी हो, जैसी कि फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है, डॉलर पर इस पूरे घटनाविकास का असर होना ही है। आखिरकार, यह पहली ही बार है कि एक बड़ी नाभिकीय ताकत और एक बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ, एक अधीनस्थ देश के जैसा सलूक किया जा रहा है। अमरीका, यूरोपीय यूनियन तथा यूके में रखे उसके 300 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा संचित कोषों को, जब्त कर लिया गया है।

डॉलर के शस्त्रीकरण के खतरे

बहरहाल, डॉलर के वर्चस्व के लिए खतरा पैदा हो जाना तो, इस घटनाक्रम के परिणामों का एक हिस्सा भर है। इसका एक और हिस्सा यह है कि विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों पर आधारित, एक स्थिर व्यापार व्यवस्था के बने रहने के भरोसे के आधार पर निर्मित जटिल आपूर्ति श्रृंखलाएं भी दरकती नजर आती हैं। अमरीका को भी अब इसका पता चल रहा है कि रूस महज एक पैट्रोलियम-उत्पादक देश नहीं है,

जैसा कि वे समझ रहे थे, बल्कि वह तो अमरीकी उद्योगों तथा सेना की जरूरतों के लिए अनेक अति-महत्वपूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति भी करता है। इसके अलावा रूस दुनिया के पैमाने पर गेहूं व उर्वरकों का अति-महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता तो है ही।

इस सब की पृष्ठभूमि में पश्चिमी देशों में जमा रूस के धन के जब्त किए जाने का अर्थ इस भरोसे पर ही सवालिया निशान खड़े करना है कि अमरीका दुनिया का बैंकर है और डॉलर विश्व की सुरक्षित मुद्रा है। अगर पश्चिमी देशों में जमा उनका पैसा ये देश अपनी मर्जी से कभी भी जब्त कर सकते हैं, तो क्यों अन्य देश इन देशों के साथ बचत वाला व्यापार चलाएंगे और अपनी बचत का पैसा इन पश्चिमी देशों की बैंकों में जमा करके रखेंगे? डॉलर के विश्व की सुरक्षित मुद्रा होने का भरोसा इस बात का तो भरोसा था कि डॉलर में जमाकर के रखा जा रहा सारा का सारा पैसा सुरक्षित रहेगा।

लेकिन, चंद महीने पहले अफगान सेंट्रल बैंक के 9.5 अरब डॉलर जब्त करके अमरीका ने दिखा दिया कि वह, अमरीकी सेंट्रल बैंक में दूसरे देशों द्वारा डॉलर में जमा करके रखे जा रहे पैसे को, माल ए गनीमत समझता है, जिसे कभी भी लूट सकता है। हो सकता है कि इस तरह की जमा राशियां, संबंधित देशों के खातों में एक आर्थिक परिसंपत्ति की तरह प्रदर्शित होती हों। लेकिन, वास्तव में तो ये जमा-राशियां इन देशों के लिए एक राजनीतिक कमजोरी ही हैं क्योंकि अमरीकी सरकार इन परिसंपत्तियों को अपनी मर्जी से कभी भी जब्त कर सकती है। इससे पहले ऐसा ही इराक, लीबिया, वेनेजुएला के मामले में भी देखने को मिला था। रूस के विदेशी मुद्रा संचित कोषों के जब्त किए जाने का यही अर्थ है कि तथाकथित नियम-आधारित व्यवस्था अब डॉलर को तथा वैश्विक वित्त व्यवस्था पर पश्चिम के नियंत्रण को हथियार बनाए जाने पर ही आधारित व्यवस्था बनकर रह गयी है।

डॉलर की सुरक्षित विश्व मुद्रा का रुतबा अब खतरे में

अर्थशास्त्रीगण, प्रभात पटनायक, माइकेल हडसन तथा क्रेडिट सुईस जोल्टन पोट्सर जैसे वित्त विशेषज्ञ अब एक ऐसी नयी विश्व वित्त व्यवस्था के अवतरण की भविष्यवाणी कर रहे हैं, जिसमें चीन की मुद्रा युआन या उसका कोई स्वरूप, दुनिया की नयी सुरक्षित मुद्रा बनकर उभर सकता है। और ये भविष्यवाणियां क्यों की जा रही हैं?

दूसरे विश्व युद्ध के बाद, ब्रेटन वुड्स समझौते के चलते, डॉलर को दुनिया की सुरक्षित मुद्रा बनने का मौका मिला था। तभी डॉलर ने ब्रिटिश पाउंड की यह जगह ले ली थी और उसकी कीमत को सोने के साथ बांध दिया गया था। 35 डॉलर यानी एक आउंस सोना! बहरहाल, 1971 में अमरीकी राष्ट्रपति निक्सन ने अमरीकी डॉलर को सोने के मानक से अलग करा दिया यानी अब डॉलर के पीछे सोने की निश्चित मात्रा नहीं, बल्कि सिर्फ अमरीकी सरकार या अमरीकी खजाने की गारंटियों का ही बल था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में, डॉलर के दुनिया की सुरक्षित मुद्रा बनने और बने रहने के पीछे तीन कारक थे। एक तो उसके पीछे अमरीका की ताकत थी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक उत्पादनकर्ता है। दूसरा, इसके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत थी, हालांकि तब सोवियत संघ इस सैन्य ताकत को चुनौती दे रहा था। तीसरा, इसके पीछे पश्चिम एशिया के तेल की ताकत थी। तेल, अकेला ऐसा माल था जिसका व्यापार दुनिया भर में सबसे बड़ा था और जिसके दाम डॉलर में लगाए जाते थे।

पश्चिम एशिया के तथा खासतौर पर साऊदी अरब के तेल का डॉलर में निर्धारित किया जाना, अमरीका के लिए अति-महत्वपूर्ण था और यह अमरीका की सैन्य शक्ति से ही तय होता था। ईरान में प्रधानमंत्री मुसद्देह के खिलाफ तख्तापलट, इराक में 1963 के तख्तापलट और दूसरी अनेक घटनाओं को समझना कहीं आसान होगा, अगर हम यह याद रखते हैं कि अमरीका के लिए तेल कितना महत्वपूर्ण था। यही तो कार्टर सिद्धांत का आधार था, जो फारस की खाड़ी क्षेत्र तक मुनरो सिद्धांत का एक तरह से विस्तार करता था। या हम इसे उस कार्टर की नजर से समझ सकते हैं जो कहता था: 'हमारा तेल, उनकी रेत के नीचे दबा है!' पश्चिम एशिया के तेल पर अमरीका के नियंत्रण और उसकी औद्योगिक व सैन्य शक्ति ने ही यह सुनिश्चित किया था कि डॉलर, दुनिया की सुरक्षित मुद्रा बना रहे।

विश्व औद्योगिक शक्तिः नीचे खिसकता अमरीका

विश्व औद्योगिक शक्ति के रूप में अमरीका का नीचे खिसकना और चीन का उदय, साथ-साथ चलते आए हैं। चीन की औद्योगिक शक्ति के उभार को, एक सरल से आंकड़े से समझा जा सकता है, जो विश्व व्यापार के आइएमएफ के आंकड़ों का प्रयोग कर के लोवी इंस्टीट्यूट ने निकाला है। 2001 में, 80 फीसद देशों का मुख्य व्यापार सहयोगी अमरीका था। 2018 तक यह आंकड़ा घटकर 30 फीसद से जरा सा ही ऊपर रह गया और 190 देशों में से 128 का मुख्य व्यापार सहयोगी चीन हो गया, न कि अमरीका। यह नाटकीय बदलाव सिर्फ 20 साल में हुआ है! इस बदलाव का कारण है, औद्योगिक उत्पादन। चीन 2010 में ही अमरीका को पछाड़कर दुनिया

का सबसे बड़ा औद्योगिक उत्पादक बन चुका था (स्टेटिस्टा.कॉम)। भारत भी 5वां सबसे बड़ा औद्योगिक उत्पादक बन चुका है, लेकिन विश्व औद्योगिक उत्पादन में भारत का हिस्सा 3.1 फीसद ही है, जबकि चीन का हिस्सा 28.7 फीसद है और अमरीका का 16.8 फीसद। हैरानी की बात यह नहीं है कि व्यापार, औद्योगिक उत्पादन के पीछे-पीछे चलता है।

इस संदर्भ में हाल की दो घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। चीन और यूरेशियाई इकॉनमिक यूनियन, जिसमें रूस, कजाखस्तान, किर्गीजिस्तान, बेलारूस तथा आर्मीनिया शामिल हैं, एक नयी अंतर्राष्ट्रीय तथा मौद्रिक प्रणाली की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। भारत और रूस भी, रूसी हथियारों, उर्वरकों तथा तेल के आयात की भारत की जरूरत के आधार पर, रुपया-रूबल विनियम व्यवस्था स्थापित करते लग रहे हैं। भारत इससे पहले ईरान से तेल खरीदने के लिए ऐसी ही व्यवस्था आजमा चुका है। इस तरह की व्यवस्था से रूस के लिए भारत के निर्यातों में बढ़ोतरी को ही उछाला मिल सकता है। साऊदी अरब ने हाल ही में इसका इशारा किया है कि वह भी चीन के लिए तेल की अपनी बिक्री को डॉलर की जगह पर, युवान में प्रदर्शित करना शुरू कर सकता है। इसका मतलब युवान को तत्काल उछाला मिलना होगा क्योंकि साऊदी अरब के तेल का 25 फीसद हिस्सा चीन को ही बेचा जाता है।

छिन्न-भिन्न होतीं आपूर्ति श्रृंखलाएं

सेवाओं, बौद्धिक संपदा तथा सूचना प्रौद्योगिकी के बाजारों में अमरीका का बोलबाला है। लेकिन, ये सभी क्षेत्र जटिल आपूर्तियों पर और इसलिए जटिल वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर हैं। अगर पश्चिमी आर्थिक युद्ध का मतलब, रूस की आपूर्तियों को वैश्विक बाजार से बाहर करना है, तो इससे अनेक आपूर्ति श्रृंखलाएं ही छिन्न-भिन्न हो जाएंगी। मैं पहले ही इस आर्थिक युद्ध के ऊर्जा युद्ध वाले पहलू पर लिख चुका हूं और यह भी कि कैसे यूरोपीय संघ, रूस से पाइपलाइन के जरिए योरप पहुंचायी जा रही गैस पर निर्भर है। बहरहाल, दूसरे भी बहुत से ऐसे माल हैं, जो रूस के खिलाफ पाबंदियां लगाने वाले देशों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं हैं बल्कि जो दूसरे अनेक ऐसे देशों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिनके लिए, पश्चिम की पाबंदियों के चलते रूस के साथ व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा।

काफी विचित्र है कि चिपों के उत्पादन की आपूर्ति श्रृंखला में काम आने वाला एक कुंजीभूत तत्व, रूस की आपूर्तियों पर ही निर्भर है। ये हैं नीलम सबस्ट्रेट्स, जिनमें कृत्रिम नीलम का उपयोग किया जाता है और जिनका उपयोग चिपों में होता है। इस क्षेत्र में लगता है कि रूस की लगभग इजारेदारी है। दूसरा खतरा, चिप निर्माताओं के लिए नियोन गैस की आपूर्तियों के लिए है। नियोन गैस के मुख्य आपूर्तिकर्ता दक्षिणी यूक्रेन में हैं। एक मरिऊपूल में और दूसरा ओडेस्सा में। दुनिया की नियोन गैस आपूर्ति का करीब 50 फीसद और दुनिया के चिप निर्माताओं के लिए नियोन गैस की आपूर्ति का 75 फीसद, इन्हीं दोनों कारखानों से आता है।

हम पहले ही रेखांकित कर चुके हैं कि यूरोपीय यूनियन की पर्यावरण परिवर्तन से निपटने की योजनाओं के लिए और उसके संक्रमणकालीन ईंधन के तौर पर प्राकृतिक गैस के उपयोग पर जाने के मंसूबों के लिए, आर्थिक युद्ध से कैसा खतरा पैदा हो गया है। इतना ही नहीं, नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा के रास्ते पर बढ़ने के लिए, ऊर्जा के भंडारण की सुविधाओं के मामले में निकल एक कुंजीभूत तत्व है और इस मामले में भी रूस निर्भरता काफी ज्यादा है। बिजली की बैटरियों के निकल बहुत महत्वपूर्ण होता है और रूस ही दुनिया का निकल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। अब जबकि अमरीका तथा यूरोपीय यूनियन ने, रूस के खिलाफ पाबंदियां लगा दी हैं, इसका नतीजा यह भी हो सकता है कि चीन, जो पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी आपूर्तिकर्ता बन चला है, इस मामले में अपनी बढ़त को और भी पुख्ता कर ले।

दोराहे पर है दुनिया

आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व पैलेडियम, प्लेटीनम, टिटीनियम तथा रेयर तत्व हैं। उन्नत उद्योगों में इनकी जरूरत होती है और इससे दुनिया भर में आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाएं पैदा हो रही हैं। ये सभी उन 50 रणनीतिक सामग्रियों की सूची में भी हैं, जिनकी अमरीका को जरूरत होती है। हम यह याद कर लें कि कैसे कोविड-19 के दौरान आपूर्ति श्रृंखलाएं रुंध गयी थीं। आने वाला संकट उससे भी बदतर हो सकता है। इसके अलावा पाबंदियां लगाना तो आसान होता है, पर उन्हें उठाना कहीं मुश्किल होता है। और पाबंदियां उठाए जाने के बाद भी, आपूर्ति श्रृंखलाएं कोई पहले की तरह फिर से सुचारु तरीके से नहीं चल पड़ेंगी। याद रहे कि ये आपूर्ति श्रृंखलाएं, धीरे-धीरे करके दसियों साल में कायम हुई थीं। पाबंदियों के हथौड़े से उन्हें छिन्न-भिन्न करना तो आसान है, लेकिन उन्हें फिर से खड़ा करना काफी मुश्किल होने जा रहा है।

विश्व खाद्य आपूर्तियों पर इस सब के बीच और भी भारी चोट पड़ने जा रही है। यूक्रेन तथा बेलारूस, दुनिया भर के किसानों की जरूरत के उर्वरकों का उल्लेखनीय रूप से बड़ा हिस्सा बनाते हैं। रूस और यूक्रेन, गेहूं के दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से हैं। अगर रूस के गेहूं पर पाबंदी लगा दी जाती है और यूक्रेन की फसल पर युद्ध की मार पड़ती है, तो पूरी दुनिया के लिए खाद्यान्न की गंभीर तंगी से बचना आसान नहीं होगा।

इतना तो तय है कि दुनिया एक दोराहे पर है। इस सब के चलते या तो रूसी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, चाहे यूक्रेन में रूस जल्दी से शांति हासिल करने में कामयाब हो जाए या फिर चाहे नाटो-रूस युद्ध चाहे न भी हो। या फिर इससे एक नयी विश्व आर्थिक व्यवस्था बनेगी, जिसके आसार पहले से बन रहे थे और जिसमें सैन्य व आर्थिक युद्धों की जगह, सहकारात्मक समाधानों को आगे बढ़ाया जाएगा। ■

कश्मीर से केरल

सर से लेकर पैर तक एक समान चुनौती

● डॉ विवेक आर्य

उत्तर भारत में रहने वाले लोगों को यह संभवत: यह कम ज्ञात है कि केरल एक ऐसा भूभाग है जहां पर अहिन्दू (मुस्लिम +ईसाई) जनसंख्या हिन्दुओं से अधिक हैं। बहुत कम हिन्दुओं को यह ज्ञात होगा कि उत्तरी केरल के कोझिकोड, मल्लपुरम और वायनाड के इलाके दशकों पहले ही हिन्दू अल्पसंख्यक हो चुके थे। इस भूभाग में हिन्दू आबादी कैसे अल्पसंख्यक हुई? इसके लिए केरल के इतिहास को जानना आवश्यक हैं।

1. केरल में इस्लाम का आगमन अरब से आने वाले नाविकों के माध्यम से हुआ। केरल के राजपरिवार ने अरबी नाविकों की शारीरिक क्षमता और नाविक गुणों को देखते हुए उन्हें केरल में बसने के लिए प्रोत्साहित किया। यहां तक की जमोरियन राजा ने स्थानीय मलयाली महिलाओं के उनके साथ विवाह करवाए। इन्हीं मुस्लिम नाविकों और स्थानीय महिलाओं की संतान मपिल्ला/ मापला/मोपला अर्थात भांजा कहलाई। जमोरियन राजा ने दरबार में अरबी नाविकों को यथोचित स्थान भी दिया। मुसलमानों ने बड़ी संख्या में राजा की सेना में नौकरी करना आरम्भ कर दिया। स्थानीय हिन्दू राजाओं द्वारा अरबी लोगों को हर प्रकार का सहयोग दिया गया। कालांतर में केरल के हिन्दू राजा चेरुमन ने भारत की पहले मस्जिद केरल में बनवाई। इस प्रकार से केरल के इस भूभाग में मुसलमानों की संख्या में वृद्धि का आरम्भ हुआ। उस काल में यह भूभाग समुद्री व्यापार का बड़ा केंद्र बन गया।

2. केरल के इस भूभाग पर जब वास्को दी गमा ने आक्रमण किया तो उसकी गरजती तोपों के समक्ष राजा ने उससे संधि कर ली। इससे समुद्री व्यापार पर पुर्तगालियों का कब्जा हो गया और मोपला मुसलमानों का एकाधिकार समाप्त हो गया। स्थानीय राजा के द्वारा संरक्षित मोपला उनसे दूर होते चले गए। व्यापारी के स्थान पर छोटे मछुआरे आदि का कार्य करने लगे। उनका सामाजिक दर्जा भी कमतर हो गया। उनकी आबादी मुलत तटीय और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता में जीने लगी।

3. केरल के इस भूभाग पर जब टीपू सुल्तान की जिहादी फौजों ने आक्रमण किया तब स्थानीय मोपला मुसलमानों ने टीपू सुल्तान का साथ दिया। उन्होंने हिन्दुओं पर टीपू के साथ मिलकर कहर बरपाया। यह इस्लामिक

साम्राज्यवाद की मूलभावना का पालन करना था। जिसके अंतर्गत एक मुसलमान का कर्त्तव्य दूसरे मुसलमान की इस्लाम के नाम पर सदा सहयोग करना नैतिक कर्त्तव्य हैं। चाहे वह किसी भी देश, भूभाग, स्थिति आदि में क्यों न हो। टीपू की फौजों ने बलात हिन्दुओं का कत्लेआम, मतांतरण, बलात्कार आदि किया। टीपू के दक्षिण के आलमगीर बनने के सपने को पूरा करने के लिए यह सब कवायद थी। इससे इस भूभाग में बड़ी संख्या में हिन्दुओं की जनसंख्या में गिरावट हुई। मुसलमानों के संख्या में भारी वृद्धि हुई क्योंकि बड़ी संख्या में हिन्दू केरल के दूसरे भागों में विस्थापित हो गए।

4. अंग्रेजी काल में टीपू के हारने के बाद अंग्रेजों का इस क्षेत्र पर आधिपत्य हो गया। मोपला मुसलमान अशिक्षित और गरीब तो था। पर उसकी इस्लाम के प्रचार प्रसार के उद्देश्य को वह भूला नहीं था। 1919 में महात्मा गांधी द्वारा तुर्की के खलीफा की सल्तनत को बचाने के लिए मुसलमानों के विशुद्ध आंदोलन को भारत के स्वाधीनता संग्राम के साथ नत्थी कर दिया गया। उनका मानना था कि इस सहयोग के बदले मुसलमान भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ उनका साथ देंगे। गांधी जी के आह्वान पर हिन्दू सेठों ने दिल खोलकर धन दिया, हिन्दुओं ने जेलें भरी, लाठियां खाई। मगर खिलाफत के एक अन्य पक्ष को वह कभी देख नहीं पाए। इस आंदोलन ने मुसलमानों को पूरे देश में संगठित कर दिया। इसका परिणाम यह निकला कि इस्लामिक साम्राज्यवाद के लक्ष्य की पूर्ति में उन्हें अंग्रेजों के साथ साथ हिन्दू भी रूकावट दिखने लगे। 1921 में इस मानसिकता को परिणति मोपला दंगों के रूप में सामने आयी। मोपला मुसलमानों के एक अलीम के यह घोषणा कर दी कि उसे जन्नत के दरवाजे खुले नजर आ रहे हैं। जो आज के दिन दीन की खिदमत में शहीद होगा वह सीधा जन्नत जायेगा। जो काफिर को हलाक करेगा वह गाजी कहलायेगा। एक गाजी को कभी दोजख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। उसके आह्वान पर मोपला भूखे भेड़ियों के समान हिन्दुओं की बस्तियों पर टूट पड़े। टीपू सुल्तान के समय किये गए अत्याचार फिर से दोहराये गए। अनेक मंदिरों को भ्रष्ट किया गया। हिन्दुओं को बलात मुसलमान बनाया गया, उनकी चोटियां काट दी गई। उनकी सुन्नत कर दी गई। मुस्लिम पोशाक पहना कर उन्हें कलमा जबरन पढ़वाया गया। जिसने इंकार किया उसकी गर्दन उतार दी गई। ध्यान दीजिये कि इस अत्याचार को इतिहासकारों ने अंग्रेजी राज के प्रति रोष के रूप में चित्रित किया हैं जबकि यह मजहबी दंगा था। 2021 में इस दंगे के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। अंग्रेजों ने कालांतर में दोषियों को पकड़ कर दण्डित किया मगर तब तक हिन्दुओं की व्यापक क्षति हो चुकी । ऐसे में जब हिन्दू समाज की सुध लेने वाला कोई नहीं था। तब उत्तर भारत से उस काल की सबसे जीवंत संस्था आर्यसमाज के कार्यकर्ता लाहौर से उठकर केरल आये। उन्होंने सहायता डिपों खोलकर हिन्दुओं के लिए भोजन का प्रबंध किया। सैकड़ों की संख्या में बलात मुसलमान बनाये गए हिन्दुओं को शुद्ध किया गया। आर्यसमाज के कार्य को समस्त हिन्दू समाज ने सराहा। विडंबना देखिये अंग्रेजों की कार्यवाही में जो मोपला दंगाई मारे गए अथवा जेल गए थे उनके कालांतर में केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने क्रांतिकारी घोषित कर दिया। एक जिहादी दंगे को भारत के स्वाधीनता संग्राम के विरुद्ध संघर्ष के रूप में चित्रित कर मोपला दंगाइयों की पेंशन बांध दी गई। कम्युनिस्टों ने यह कुतर्क दिया कि मोपला मुसलमानों ने अंग्रेजों का साथ देने धनी हिन्दू जमींदारों और उनके निर्धन कर्मचारियों को दण्डित किया था। कम्युनिस्टों के इस कदम से मोपला मुसलमानों को 1947 के बाद खुली छूट मिली। मोपला 1947 के बाद अपनी शक्ति और संख्या बल को बढ़ाने में लगे रहे। उन्होंने मुस्लिम लीग के नाम से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नाम से अपना राजनीतिक मंच बनाया।

5. 1960 से 1970 के दशक में विश्व में खाड़ी देशों के तेल निर्यात ने व्यापक प्रभाव डाला। केरल के इस भूभाग से बड़ी संख्या में मुस्लिम कामगार खाड़ी देशों में गए। उन कामगारों ने बड़ी संख्या में पेट्रो डॉलर खाड़ी देशों से भारत भेजे। उस पैसे के साथ साथ इस्लामिक कट्टरवाद भी देश ने आयात किया। उस धन के बल पर बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी गई। मस्जिदों और मदरसों का निर्माण हुआ। स्थानीय वेशभूषा छोड़कर मोपला मुसलमान भी इस्लामिक वेशभूषा अपनाने लगे। मजहबी शिक्षा पर जोर दिया गया। जिसका परिणाम यह निकला कि इस इलाके का निर्धन हिन्दू अपनी जमीनें बेच कर यहां से केरल के अन्य भागों में निकल गया। बड़ी संख्या में मुसलमानों ने हिन्दू लड़कियों से विवाह भी किये। इस्लामिक प्रचार के प्रभाव, धन आदि के प्रलोभन में अनेक हिन्दुओं ने स्वेच्छा से इस्लाम को स्वीकार भी किया। केरल से छपने वाले सालाना सरकारी गजट में हम ऐसे अनेक उदाहरणों को पढ़ सकते हैं। इस धन के प्रभाव से संगठित ईसाई भी अछूते नहीं रहा। असंगठित हिन्दू समाज तो इस प्रभाव को कैसे ही प्रभावहीन करता। ऐसी अवस्था में इस भूभाग का मुस्लिम बहुल हो जाना स्वाभाविक ही तो है।

वर्तमान स्थिति यह है कि धीरे धीरे इस इलाके में इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ता गया। इन मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग करती हैं। जी हां वही मुस्लिम लीग जो 1947 से पहले पाकिस्तान के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। हिन्दुओं का केरल में

कश्मीरी पंडितों का पलायन : ये भी जानें ...

विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' भी भारत में बुराई की हद तक जड़ें जमा चुकी Selective Intelegence का शिकार हो गई है।

- 'द कश्मीर फाइल्स' को ज्यादातर स्थापित फिल्म समीक्षकों ने खारिज कर दिया है।
- वैसे हाल के वर्षों में जिस तरह बौद्धिक कर्म में Selectiveness बढ़ा है, उसमें ऐसा होना ही था। लेकिन इस फिल्म को खारिज करने के लिए जो तर्क और तथ्य दिए जा रहे हैं, वे थोथे और आधारहीन हैं।
- 1990 में कश्मीर घाटी से हिंदुओं के पलायन और उनके साथ हुए अत्याचार की कहानी पर यह फिल्म केंद्रित है।
- आलोचकों का कहना है कि कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा से उपजे हिंदू-मुस्लिम तनाव की वजह से हुए।
- सवाल यह है कि कश्मीर जैसे पैमाने पर किसी समुदाय के साथ दूसरे इलाकों में क्यों नहीं हुआ ? कश्मीर से राम रथ यात्रा तो गुजरी भी नहीं और उसे गुजरना भी नहीं था।
- कहा जा रहा है कि यह पलायन भी विश्वनाथ प्रताप सिंह की उस सरकार के दौरान हुआ, जिसे 86 सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी भी समर्थन दे रही थी।
- बहरहाल अब थोड़ा तथ्यों की बात करते हैं।
- वीपी सिंह सरकार ने 2 दिसंबर 1989 को शपथ ली उसे बाहर से 141 सदस्यीय जनता दल की उस सरकार को 86 सदस्यों वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ ही 54 सदस्यों वाला वाममोर्चा भी समर्थन दे रहा था। वाममोर्चे में सीपीएम, सीपीआई, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लाक थे।
- विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपना सेक्युलर चेहरा बनाने के लिए देश को पहला मुस्लिम गृहमंत्री दिया - मुफ्ती मोहम्मद सईद।
- वही सईद, जिनकी बेटी हैं महबूबा मुफ्ती जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री तो रहीं भारतीय राज्य जम्मू-कश्मीर की, लेकिन बात करती रहीं पाकिस्तान की।

आगे बढ़ते हैं..

- 'द कश्मीर फाइल्स' के बहाने भाजपा पर सवाल उठाने वालों को यह जान लेना चाहिए कि कश्मीर घाटी में 1989 में इतने अच्छे हालात थे कि मुफ्ती मोहम्मद सईद कश्मीर की बजाय उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े थे और अमनपसंद धर्मनिरपेक्ष हिंदी पट्टी ने उन्हें संसद जिताकर भेज दिया था।
- इन्हीं मुफ्ती साहब की एक और बेटी हैं रूबिया सईद पेशे से डॉक्टर।
- मुफ्ती देश के गृहमंत्री बने दो दिसंबर 1989 को और इसके ठीक छह दिन बाद ही श्रीनगर से उनकी बेटी रूबिया सईद का अपहरण कर लिया गया।
- अपहरण किया पाकिस्तान समर्थक आतंकियों ने।
- पांच दिन तक इस अपहरण कांड का ड्रामा चला। बदले में पांच आतंकी 13 दिसंबर को छोड़े गए। शाम करीब साढ़े पांच बजे आतंकी छोड़े गए और इसके ढाई घंटे बाद रूबिया सईद को आतंकियों ने रिहा कर दिया।
- इसके लिए पुलिस ने जिन लोगों पर चार्जशीट दायर की थी, उनमें उस यासिन मर्चेंट का भी नाम था, जिसे साल 2008 में इंडिया टुडे ने साल का युवा चेहरा घोषित किया था। वैसे यासिन की पहचान आतंक के कारनामों के ही चलते रही।
- बहरहाल इन आतंकियों की रिहाई के बाद कश्मीर में पहले से ताक लगाए बैठे पाकिस्तान का उत्साह बढ़ गया। उसने अपने नियंत्रण वाले आतंकियों के जरिए कश्मीर में कहर बरपाना शुरू किया। और फिर तो पूरी कश्मीर घाटी में पंडित परिवारों पर हमला होने लगा। चुन-चुनकर उन्हें मारा गया या फिर बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया।
- रही बात आडवाणी की राम रथ यात्रा की तो वह 25 सितंबर 1990 को शुरू हुई और 30 अक्टूबर को समस्तीपुर में तब के डीएम राजकुमार सिंह और अब के केंद्रीय बिजली मंत्री राजकुमार सिंह के हाथों गिरफ्तारी के बाद थम गई थी।
- कश्मीर फाइल की आलोचना करने वालों को इन तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए।

- उमेश चतुर्वेदी

असंगठित होने के कारण कोई राजनीतिक रसूख नहीं हैं। वे कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों के मध्य विभाजित हैं। जबकि ईसाई और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि नेताओं से खूब मोल भाव कर वोट के बदले अपनी मांगें मनवाते हैं। इसलिए केरल की जनसंख्या में आज भी सबसे अधिक होने के बाद भी जाति, सामाजिक हैसियत, धार्मिक विचारों में विभाजित होने के कारण हिन्दू अपने ही प्रदेश में एक उपेक्षित है। यही कारण है कि शबरीमाला जैसे मुद्दों पर केरल की सरकार हिन्दुओं की अपेक्षा कर उनके धार्मिक मान्यताओं को भाव नहीं दे रही हैं।

ये भूमिका रही कांग्रेस की

ये भूमिका रही कांग्रेस की 1990 में हुएं हिन्दूओं के सबसे बड़े नरसंहार में। इस तरह का पोस्ट आजकल खूब वायरल हो रहा है सोचिए किस तरह से तथ्यों को झूठ लिखकर लोगों को बरगलाया जा रहा है और तमाम सेकुलर सूअर बिना सच्चाई जाने इसे खूब शेयर भी कर रहे हैं।

अब आप जरा सच्चाई जानिए।

कश्मीरी पंडितों पर हमले सिर्फ 01 दिन में नहीं हुए बल्कि जैसे ही कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस की यानी फारुख अब्दुल्ला की सरकार बनी फारूक अब्दुल्ला के इशारे पर कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार बलात्कार जुल्म कत्लेआम शुरू हुआ।

जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक डोगरा राजवंश का शासन था और उनके समय में कश्मीरी पंडितों को सरकारी नौकरियों में बड़े बड़े पद पर रखा गया था और जम्मू कश्मीर की काफी जमीन कश्मीरी पंडितों के नाम थी।

1950 में कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों की आबादी में हिस्सेदारी 76 प्रतिशत थी।

फिर आजादी के बाद 1950 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने जम्मू कश्मीर में यह कहकर नए भूमि सुधार कानून लागू किए कि जम्मू कश्मीर में जमीन का बंटवारा उचित नहीं है कश्मीरी हिंदुओं के पास बहुत ज्यादा जमीन है और कश्मीरी मुसलमानों के पास कम जमीन है और फिर नया भूमि एक्ट बनाया गया जिसके तहत कश्मीरी पंडितों से जमीन लेकर उन्हें कश्मीरी मुसलमानों में दिया गया।

इस नए भूमि सुधार कानून से परेशान होकर 55 प्रतिशत कश्मीरी हिंदुओं यानी कश्मीरी पंडितों ने अपनी जमीनें बेच कर कश्मीर घाटी छोड़ दिया।

यानी कश्मीर से हिंदुओं की पलायन की कहानी 1950 में कांग्रेस और शेख अब्दुल्ला द्वारा लिख दी गई थी।

फिर कश्मीर में कांग्रेस की राज्य सरकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस कि राज्य सरकार ने भूमि सुधार कानून को बड़ी सख्ती से लागू किया जिस से प्रताड़ित होकर 1981 तक 15 प्रतिशत और कश्मीरी पंडित यानी कश्मीरी हिंदुओं ने कश्मीर घाटी छोड़ दिया और 1981 तक कश्मीर घाटी के कुल जनसंख्या का सिर्फ 5 प्रतिशत ही कश्मीरी पंडित रह गए।

1981 में केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और जम्मू-कश्मीर में भी कांग्रेस और कभी नेशनल कान्फ्रेंस की सरकार रही।

70 के दशक से 1981 तक कश्मीर का मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला था। जो फारुख अब्दुल्ला का बाप था उसने कश्मीर में सीलिंग एक्ट को बहुत कड़ाई से लागू किया और केंद्र की कांग्रेस सरकार शेख अब्दुल्ला के इस कदम का समर्थन कर रही थी 1970 तक कश्मीर घाटी में 30 प्रतिशत कश्मीरी पंडित बचे थे, लेकिन शेख अब्दुल्ला के भूमि सुधार कानून से तंग होकर 1981 तक सिर्फ 05 प्रतिशत कश्मीरी पंडित ही कश्मीर घाटी में बचे।

उसी समय 1976 में ब्रिटेन में जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की स्थापना यासीन मलिक ने किया इस संगठन के संविधान में लिखा था कि इसके सदस्य सिर्फ मुसलमान होंगे और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है। कश्मीर से सभी हिंदुओं का सफाया कर के कश्मीर को एक अलग में इस्लामिक देश बनाना और इस संगठन के तमाम पदाधिकारियों को केंद्र की कांग्रेस सरकार ने तमाम सुविधाएं दिया यासीन मलिक के तो सैकड़ों फोटो मनमोहन सिंह के साथ हैं। राजीव गांधी के साथ हैं यासीन मलिक जो कुख्यात आतंकवादी था उसकी पूरी फैमिली का खर्चा कांग्रेसी सरकार उठाती थी उसकी किडनी का प्रत्यारोपण भी भारत सरकार यानी मनमोहन सरकार ने एम्स में करवाया।

कश्मीरी पंडितों पर हिंसक हमले और कश्मीरी पंडितों की महिलाओं पर बलात्कार 1989 से शुरू हुए।

यह कांग्रेसी यह नहीं बताते कि 2 दिसंबर 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और तब तक कश्मीर घाटी हिंदुओं के खून से लाल हो चुकी थी तब तक कश्मीर घाटी में हिंदू महिलाओं का बलात्कार शुरू हो गया था और मस्जिदों से कश्मीर घाटी छोड़ने का ऐलान हो चुका था उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी चुप थे और कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी चुप थे।

07 नवंबर 1986 से लेकर 19 जनवरी 1990 तक जम्मू-कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी।

इस दरम्यान यानी 1986 से लेकर 1990 तक जब कुख्यात हिन्दू विरोधी फारुख अब्दुल्ला कश्मीर का मुख्यमंत्री बना तब उसने तमाम आतंकवादी संगठनों जैसे हिज्बुल मुजाहिदीन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट इत्यादि को खुला समर्थन दे दिया कि तुम कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार करो जबकि उस वक्त कश्मीर घाटी में सिर्फ 5 प्रतिशत आबादी ही कश्मीरी पंडितों की थी।

2 दिसम्बर 1989 तक केंद्र में राजीव गांधी सत्ता में थे उन्होंने कश्मीर की फारुख अब्दुल्ला सरकार पर कोई एक्शन नहीं लिया।

फिर सरकार बदली केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने बीजेपी सत्ता को बाहर से समर्थन दे रही थी फिर बीजेपी के दबाव पर 19 नवंबर 1990 को फारुख अब्दुल्ला सरकार को बर्खास्त किया गया जी हां आप फैक्ट चेक कर लीजिए।

लेकिन सत्ता से बर्खास्त होने के पहले फारुख अब्दुल्ला ने कश्मीर से हिंदुओं के सफाई की पूरी भारत लिख दिया था।

फिर 19 जनवरी 1990 को जगमोहन केंद्र में राज्यपाल बने उन्होंने कश्मीरी पंडितों से घाटी में रुकने की अपील किया आतंकवादियों का सफाया किया गया।

ये भूमिका रही कांग्रेस की 1990 में हुएं हिन्दूओं के नरसंहार में।

इतिहास व कथ्य निर्माण व मिथ्या विजय दिवस विशेषः दी कश्मीर फाइल्स फिल्म

इस आलेख को सम्राट अशोक के काल व वर्तमान चीनी युद्ध व भारत पर चीन के ताजा आक्रमण, 'दी कश्मीर फाइल फिल्म' से जोड़कर पढ़ेंगे तो भान होगा किसने हमारे वीर युद्धक प्रजाति को नपुंसक बनाया। मैं झूठे कारगिल विजय दिवस पर लानत भेजता हूं और मैं अपने वीर जवानों को नमन करने में भी शर्मिन्दित अनुभव करता हूं क्योंकि,देश की नपुंसक सरकारों ने उनकी हत्या करवाई है वो शहीद नहीं हुए।उन्हें आर पार की लड़ाई न लड़ने दिया गया कभी भी, चाहे वो 1962, 65, 68, 99 या अब 2020 ही क्यों न हो। एक अपवाद है 1971 और वो भी फील्ड मार्शल जनरल मानेक शॉ की बदौलत हुआ वरना इंदिरा गांधी तो इन सबके खिलाफ ही थीं,तभी तो 90 हजार मुसलमान आक्रांताओं को पाकिस्तान वापस भेज दिया, कम से कम अंग भंग तो करवा कर भेजते।

इस लेख से आपको पता चलेगा कि क्यों हमारी सरकारें दोगली चालें चलती हैं।पुलिस,आर्मी जब चाहे 10 दिन के अंदर,सीमा के आतंकियों,विरोधी सेना,नक्सली, इस्लामिक मुस्लिम आतंकवादियों व बड़े बड़े अपराधियों का जड़मूल विनाश कर सकती है।परंतु स्वार्थ व राजनीति इन्हें रोकती है। अब आलेख पढ़ें

सत्य, तथ्य व कथ्य का मिश्रण होता है इतिहास लेखन। इसमें भी कथ्य सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इतिहास लेखक भी साहित्यकार होता है और कल्पनाशील भी। जब एक इतिहास या साहित्य लेखक की कल्पनाशीलता अतिरेक की सीमा लांघ जाती है तो इतिहास या साहित्य सत्य या तथ्य की बजाय कथ्य निर्माण बन कर रह जाता है।अंततोगत्वा, आप एक इतिहासकार या साहित्यकार से नहीं वरन एक गल्प किस्सागो से रूबरू होते हैं।

प्रमाण बताते हैं कि बिम्बिसार, अजातशत्रु से अशोक महान का काल आते आते भारतवर्ष का भूगोल हिंदुकुश से लेकर जावा,सुमात्रा,फारस की खाड़ी तक प्रखर हो चुका था। ये सारा भूगोल युद्धों से बदला था न कि बुद्धों या अन्तःपुर की दुरभिसंधियों से।

महान विजेता अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो वो अपने प्रौढ़ावस्था से आगे जा चुका था। उसने 'अहिंसा परमो धर्म' को राष्ट्र

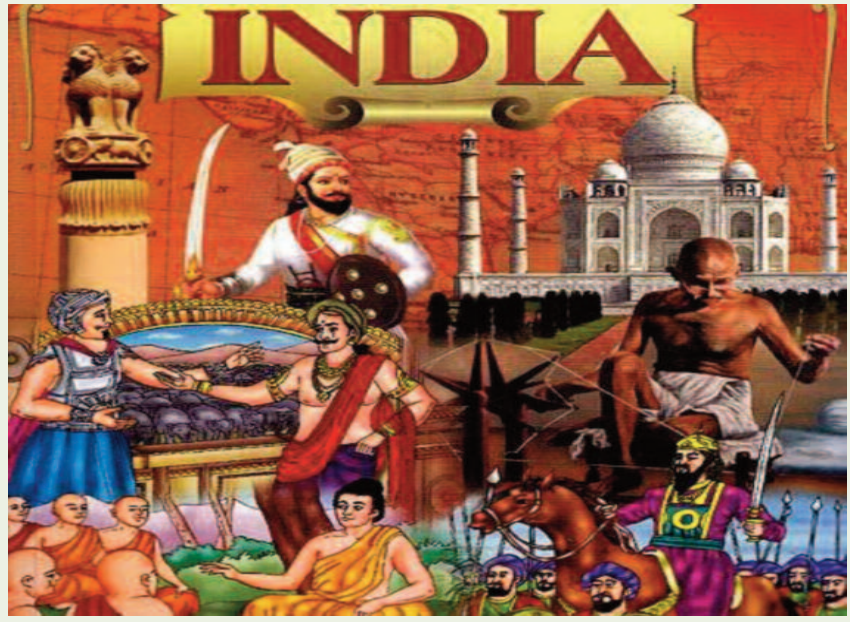

सूक्ति बना दिया। किसी भी प्रकार की हिंसा पर समग्र रोक हो गयी। अशोक के प्रयाण के बाद जो भी युद्ध हुए वो भारतवर्ष की तरफ से नहीं हुए बल्कि आक्रांताओं ने किए, भारत तो सिर्फ सत्य, अहिंसा, न्याय इत्यादि पर आधारित होकर या तो जान बचा कर भागा या फिर बचाव के लिए लड़ते हुए कट मर गया। अर्थात भारत केवल प्रतिकार करता था आक्रमणों का और आज तक वही यथास्थिति बनी हुई है।

9वीं शती के बाद तो चोर,लुटेरे,भारत आते,लाशें बिछाते,धन लूटते,हजारों स्त्रियों को अपने हरम के लिए ले जाते। हम प्रतिकार में सिर्फ अपनी जान बचाते रहे लुक छिप कर, या धर्म परिवर्तन कर। साथ ही साथ भारत का भूगोल भी संकुचित होता चला गया।

आपने कभी सोचा है हम 1000 वर्षों तक गुलाम क्यों रहे? इसलिए नहीं कि भारत में जातीय श्रेष्ठता के लिए लोग लड़ रहे थे बल्कि इसलिए क्योंकि भारत राष्ट्र एक अधूरे श्लोक को अपना जैविक, बौद्धिक, मानसिक डीएनए बना चुका था जो वास्तव में आज भी हमारे जहन को काबू में किये हुए है। वो अधूरी सूक्ति थी- 'अहिंसा परमो धर्म'।पूरा श्लोक है- 'अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च', अर्थात अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है,परन्तु धर्म के लिए हिंसा उससे भी श्रेष्ठ है। कमाल ये था कि हमारा प्रतिकार पीटने में नहीं बल्कि पिटते रहने से पूरा होता था।

अगर आपको लगता है कि आप गांधी के प्रयासों से ही स्वतंत्र हुए तो ये भारी गलतफहमी है। वास्तविकता ये है कि दो विश्वयुद्धों से बरतानिया साम्राज्य क्षत विक्षत हो चुका था और अपने तमाम उपनिवेशों को संभाल पाने में अक्षम।दूसरी तरफ नेताजी ने आजाद हिंद फौज के द्वारा ऐसी त्वरित मारकाट मचाई की बरतानवी हुक्मरानों के होश हवा हो गए। द.अफ्रीका ने गांधी का सत्याग्रह अपनाया और वो सही मायनों में 90 के दशक के पूर्वार्ध में जाकर स्वतंत्र हुआ।

अब आते हैं कथ्य निर्माण पर। 20वीं शती में जो इतिहास लेखन शुरू हुआ,उसमें अतिरंजना भाव ऐसा प्रखर था कि वो गल्प साहित्य की किस्सागोई भर बन कर रह गया। छद्म बुद्धिजीवियों के एक वर्ग ने कमाल का इतिहास लेखन किया।उनके कथ्य निर्माण (Narrative) का ही कमाल था कि भारतवर्ष को मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी,गजनवी से लेकर शेख अब्दुल्लाह तक से अपमानित किये जाने को भी विरुदावली तरह प्रस्तुत किया गया। इन बुद्धिजीवियों की ही देन है कि अंग्रेजों की बनाई सड़कें बाबर, अकबर

के नाम पर तो प्रतिष्ठापित हुई लेकिन राणा सांगा या महाराणा प्रताप के नाम से नहीं। इन महानुभावों की देन है कि,आज भी भगत, आजाद, नेताजी जी जैसे लोग क्रांतिकारी या शहीद नहीं माने गए हैं किसी भी सरकारी दस्तावेज में बल्कि बागी हैं, आतंकी हैं। आज बम्बई को मुम्बई, कलकत्ता को कोलकाता,मद्रास को चेन्नई, बैंगलोर को बंगलुरू, करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इलाहबाद को प्रयाग करते ही इन बुद्धिजीवियों की नानी मर गयी। क्या मोदीजी में हिम्मत है कि कम से कम इन लुटेरे,बलात्कारियों के नाम पर रखे सड़कों व शहरों के नाम अपने महापुरुषों के नाम पर रख सकें?* नहीं।

500 ईसा पूर्व से आज 2022 आ गया और हम आज भी अपने संकुचित भूगोल के प्रति जागरूक नहीं हैं। हम अब भी 'आक्रमणकर्ता' नहीं हैं बस आक्रमण का प्रतिकार करते हैं। ये छद्म बुद्धिजीवी ऐसा कथ्य निर्माण करते हैं जिसका सत्य व तथ्य से कोई लेना देना नहीं होता।ये कहते हैं 'युद्ध कोई समाधान नहीं होता'। अरे कूढ़ मगजों'आक्रमण बचाव का सबसे अच्छा रास्ता होता है' माने 'Offence is best Defence' माने या न माने इन छद्म बुद्धिजीवियों व अहिंसा परमो धर्म ने एक युद्धक व विजेता प्रजाति के राष्ट्र को समूल नपुंसक बना डाला।

भारत वास्तव में सोने की चिड़िया था अपने दम की बदौलत, लेकिन इस एक सूक्ति ने इसे लुटेरों का स्वर्ग बना डाला। डाकू समृद्ध के यहां ही लूट करते हैं, किसी भिखमंगे या कंगाल के घर में नहीं और 1000 वर्षों तक भारत को अनवरत लूटा गया हमारी अकर्मण्यता से और गद्दारों के सहयोग से।

'अहिंसा परमो धर्म' की सूक्ति आज शानदार,जानदार और दमदार भारत वंशियों को भीरु और नपुंसक बना चुकी है। मुस्लिम कौम किसी राष्ट्र के प्रति वफादार हो ही नहीं सकती, क्योंकि जहां भी ये बहुसंख्य होते हैं वहां ये कत्लोगारत मचा देते हैं। इसके लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है बस याद कीजिये *जनवरी 1990 के कश्मीर को।

आज भारत में 700-800 छोटे बड़े कस्बे, गांव व शहर ऐसे हैं जहां हिंदू होली, दीवाली व दशहरा या तो मना नहीं पाते या फिर भारी पुलिस बल के साये में निश्चित समयसीमा तक ही मना सकते हैं। आज 40 सालों के बाद एक आदमी ने दी कश्मीर फाइल के नाम से फिल्म बनाया तो इस देश के नेताओं,लेफ्ट लिबरल्स छद्म बुद्धजीवियों, बॉलीवुड के इस्लामिक पुरोधाओं के पेट में मरोड़ उठ गया।यहां तक कि इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक की मांग की याचिका उच्चतम न्यायालय में डाली गई परन्तु खारिज हो गयी।

आज रूस,अमेरिका,चीन जब तब किसी की भी गर्दन मरोड़ देते हैं और खास तौर पर मुस्लिम आतंकवादियों का। चेचेन मुस्लिम, उइगर मुस्लिम और इराक, सीरिया, लेबनान, अफगानिस्तान में कैसे इन्होंने आतंकियों को घुस कर मारा और पूरा विश्व बस दीदे फाड़ कर देखता रहता है।

तो मान्यवर, क्षमाशीलता,दया,न्याय व थोथी अहिंसा को तरजीह देना छोड़े भारत सरकार। कश्मीरी हिंदुओं को तुरत उनकी सम्पत्ति उनको हस्तांतरित करे और 1990 की कश्मीर फाइल खोल कर इन्हें 72 हूरों के पास पहुंचाए।न्याय की बात कीजिये परन्तु अन्याय पर आक्रमण कीजिये। चीन व पाकिस्तान को शत्रु राष्ट्र घोषित कीजिये या फिर फुद्दूओं की तरह ज्ञान बांटना बन्द कीजिये।

दिनकर जी ने कहा था-

क्षमा शोभती उस भुजंग के जिसके पास गरल हो!!
वो क्या जो दंतहीन, विषरहित, विनीत सरल हो!!

- संतोष पांडेय

मंदिर संकुल और कश्मीर फ़ाईल्स

मंदिर केवल मूर्तिपूजा के केंद्र होते और तोड़े जाते तो वजह समझ आती पर हमारे मंदिर तो हमारे लिए नृत्य कला को, ललित कला को, चित्र कला को, मूर्ति कला को, वास्तु कला को, रोजगार को, प्रकृति को, संस्कार और संस्कृति को संरक्षण देने के केंद्र भी थे।

मुल्तान का भव्य सूर्य मंदिर, कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर, महोबा का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, सूदूर पूर्वोत्तर के भुवन पहाड़ी पर बसे शिव मंदिर, 52 शक्तिपीठ, चार धाम और द्वादश ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु और दक्षिण के हम्पी आदि क्षेत्रों के भव्य मन्दिर से लेकर जावा, सुमात्रा, अंकोरवाट और बोरोबदूर के भव्य मंदिर ये सब केवल मूर्तिपूजा के केंद्र नहीं थे बल्कि विश्व के सर्वोत्कृष्ट सभ्यता के हस्ताक्षर थे।

ये हिंदू एकात्मता और सहभागिता के भी सेंटर थे क्योंकि इनके निर्माण के लिये क्षत्रिय राजाओं ने लिए भूमि और संरक्षण दिये थे, ब्राह्मण देवताओं ने इसमें प्रतिष्ठित ईश्वर के लिए स्तुति और वंदनायें रची थी और कठोरता से शुचिताओं का पालन करते हुए इसकी पवित्रता को अक्षुण्ण रखा था। वैश्यों ने इसके निर्माण के लिए धन दिया था और आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाई, प्याऊ लगवाए और शूद्रों ने इन मंदिरों को वो वास्तु दी थी कि दुनिया आज भी विस्मित होकर दांतों तले अंगुली दबाए हैरान खड़ी है।

इसीलिए जब TheKashmirFiles फिल्म्स का एक पात्र कृष्णा पंडित मार्तंड सूर्य मंदिर के टूटने की व्यथा कहता है तो वो केवल मंदिर टूटने की व्यथा नहीं थी बल्कि वो व्यथा थी स्थापत्य के एक बेजोड़ नमूने के टूटने की जिसके पीछे उस समय के अभियंताओं का श्रेष्ठ मस्तिष्क और कारीगरों की श्रेष्ठ कला सम्मिलित थी। वो व्यथा थी उस मन्दिर में प्रांगण में उकेरी कर मूर्ति और चित्रों को रौंदे जाने की जो किसी मूर्तिकार और चित्रकार के जीवन भर का समर्पण था। वो व्यथा थी ज्ञान के उस केंद्र के ध्वंस का जिसे भारत भर के न जाने कितने ही ब्राह्मणों ने अपने तप और अनुष्ठान से सींचा था। वो व्यथा थी उस अर्थ तंत्र के तोड़े जाने की जो उस मन्दिर के कारण वहां बना हुआ था। वो व्यथा थी उस स्थल के ध्वंस की जो भारत की सांस्कृतिक एकबद्धता का प्रमाण था। वो व्यथा थी कृतज्ञता ज्ञापन के उस प्रतीक के ध्वंस का जिसे हमारे पूर्वजों ने सृष्टि के संचालक और प्रकृति के रक्षक सूर्य नारायण की आराधना के लिए बनाया हुआ था।

वी एस नायपॉल ने भारत को एक 'आहत सभ्यता' नाम दिया था तो उसकी वजह यही थी कि बर्बर आक्रांताओं के हमलों ने भारत की सभ्यता को ही लहूलुहान कर दिया था जिससे अब विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग ऐसी फिल्में बनाकर उबार रहे हैं।

कश्मीर फाइल्स देखना अपनी सभ्यता के उन्हीं जख्मों और घावों पर मरहम लगाना है।

इसलिए जब तक ये फिल्म कम से कम सौ करोड़ की कमाई तक न कर ले हममें से किसी को भी रुकना नहीं है। -

स्वामी यतींद्रानंद

इस्लामिक कट्टरपंथ पर कुछ ज़रूरी सवाल

पिछले दिनों कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये कहते हुए शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी कि हिजाब इस्लामी परम्परा का हिस्सा नहीं है। फैसले के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी को जान से मारने की धमकी दी गई। इस बारे में एक वीडियो सामने आया जिसमें धमकी देने वाले बता रहे थे कि उन्हें पता है कि जज सुबह घूमने किस पार्क में जाते हैं। धमकी के बाद तीनों तीनों जजों को Y श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई। लेकिन ये धमकी एक बार फिर इस्लामिक कट्टरपंथियों को लेकर बहुत से सवाल खड़े करती है।

सवाल खड़ा होता है कि जब भी चीजें इन कट्टरपंथियों के मुताबिक नहीं होती तो वो सीधे मरने-मारने पर उतारू क्यों हो जाते हैं।

फ्रांस में कोई मैगजीन कोई कार्टून बनाती है तो आप उसके पूरे स्टाफ की हत्या कर देते हैं। कोई तस्लीमा नसरीन किताब लिखती है तो उसे देश छोड़ना पड़ जाता है। कोई सलमान रशदी मजहब पर टीका करता है तो उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है, अदालत में केस चलने के बावजूद किसी कमलेश तिवारी का दिनदहाड़े गला रेत दिया जाता है और जब फैसला तुम्हारे पक्ष में नहीं आता, तो सीधे जज को ही मारने की धमकी दे दी जाती है।

मतलब, या तो तुम मेरी बात मानो, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। बीच में संवाद, सुधार या माफी की गुंजाइश ही नहीं! और फिर आप शिकायत करते हैं कि मेरे मजहब को लेकर 'फोबिया' क्यों बढ़ रहा है। फोबिया कोई हवा में पैदा नहीं होता। न ही कोरोना की तरह किसी की छींक से फैलता है। फोबिया असल, जायज और कड़वे अनुभवों से पैदा होता है।

कुछ वक्त पहले मैं ओशो का एक ऑडियो टेप सुन रहा था जिसमें पाकिस्तान से आए एक शख्स फिरोज ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है कि दुनिया का सबसे नया धर्म होने के बावजूद इस्लाम सबसे पुराना लगता है। इस पर रजनीश का जो जवाब था वो आज भी बहुत से लोगों के लिए सोचने का विषय है। रजनीश ने कहा, सबसे नया होने के बावजूद इस्लाम सबसे पुराना इसलिए लगता है क्योंकि उसमें टीका की इजाजत नहीं है। दुनिया के हर धर्म ने अपने मानने वालों को ये छूट दी कि वो उसकी धार्मिक मान्यताओं पर बहस करें, उसकी धार्मिक किताबों में लिखी बातों पर तर्क करें, और हो सके तो उसमें सुधार भी करें, लेकिन इस्लाम ऐसी कोई छूट नहीं देता।

रजनीश ने आगे कहा कि यही वजह है कि मैं हर मजहब और सम्प्रदाय पर टिप्पणी करता हूं लेकिन इस्लाम पर बहुत कम, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिन लोगों से मैं मुखातिब हो रहा हूं उनका रवैया क्या है।

हिजाब विवाद के दौरान एक दलील अक्सर दी गई कि बच्चियों पर हिजाब कोई थोप थोड़ा रहा है। अगर कोई अपनी मर्जी से पहनना चाहता है, तो उसे रोका क्यों जा रहा है! 'अपनी मर्जी' क्या आप मजाक कर रहे हैं।

सोचिए, जब मर्जी का फैसला न आने पर आप जजों तक को जान से मारने की धमकी दे देते हैं। अबू आजमी जैसे जनप्रतिनिधि तक जजों की समझ पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। मौलानाओं द्वारा जजों की लानत-मलानत हो रही है। तो आपको लगता है कि इन लोगों के दायरे में जो औरतें आती होंगी ये उन्हें 'अपनी मर्जी' से कुछ करने की छूट मिलती होगी?

दो दिन पहले बरेली में एक मुस्लिम महिला ने मीडिया में आकर बताया कि यूपी चुनावों में बीजेपी को वोट करने के कारण उसके तलाक की नौबत आ गई है। महिला ने बताया कि बीजेपी सरकार ने महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई हैं उससे प्रभावित होकर वोट दिया था। लेकिन उसके ससुरवालों का ये बात पसंद नहीं आई और आज उसके तलाक की नौबत आ गई है।

ईरान में तो महिलाओं ने हिजाब के खिलाफ इतने कैंपेन चलाए। इसके लिए उन्होंने अपनी मूल 'आर्यन पहचान' तक हवाला दिया। इतने विरोध सहे। जेल गईं। सार्वजनिक तौर पर जलील हुईं। पर हुआ क्या? क्या इस सबसे कट्टरपंथी झुक गए। उन्हें अपनी मर्जी चलाने दी?

और यही बड़ा सवाल है कि आप अपनी मजहबी नाइत्तेफाकी से कैसे डील करते हैं। जो आपके हिसाब से धर्म सम्मत नहीं है उससे कैसा सुलूक करते हैं। खुद से जो अलग है, उससे कैसे एडजस्ट करते हैं। यही बताता है कि एक बहुधर्मी समाज में रहने के लिए आप कितने फिट हैं। एक बहुसांस्कृतिक समाज में रहने के लिए आप कितने तैयार हैं?

एक ऐसा समाज जहां लोगों की आपसे सांस्कृतिक असहमतियां भी होंगी, सुधार का दबाव भी होगा, आधुनिक होने का आग्रह भी होगा। लेकिन हर बार अगर आप इन असहमतियों, दबावों और आग्रहों पर हिंसक हो जाएंगे, तो सवाल पर उस समाज पर नहीं, न बदलने की आपकी ही ढिठाई पर उठेंगे।

कश्मीर को लेकर एक वर्ग अक्सर ये बात बार-बार दोहराता है कि वहां जनमत संग्रह करवा लो। लोगों से पूछ लो कि उनकी मर्जी क्या है? वो भारत के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं या खुद को आजाद मुल्क बनाना चाहते हैं? इस दलील का

सबसे बड़ा Selling Point यह है कि हम 'लोगों की बात' कर रहे हैं। 'उनकी मर्जी' से फैसला लेना चाहते हैं!

अब इस मर्जी की हकीकत जान लीजिए। 80 के दशक में जब कश्मीर में चुन-चुनकर पंडितों को निशाना बनाया गया तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थे कि वहां इस्लामी निजाम कायम करने की हसरत पालने वाले लोगों को पंडितों का 'भारत प्रेम' पसंद नहीं था। कश्मीरी पंडित उन्हें भारत सरकार के मुखबिर लगते थे।अपनी इस्लामी निजाम की हसरत में वो उन पंडितों को सबसे बड़ा रोड़ा मानते थे।

मैं कहता हूं कि आप हिंदुस्तानी सरकार को भाड़ में जान दीजिए। उसे अपना दुश्मन मानिए। लेकिन जब आप दिन-रात कश्मीरियों की ही मर्जी की दुहाई देते हैं, दिन-रात कश्मीरियत की बात करते हैं, तो क्या वो 'पंडित' कश्मीरी नहीं थे। और जब आपने एक बार उनको कश्मीर से भगा दिया, तो फिर उस 'जनमत संग्रह' या कथित 'जनता की मर्जी' या 'कश्मीर के लोगों' की राय के क्या मायने रह गए ?

इसी महीने की दो तारीख को कश्मीर के कुलगाम के सरांदू इलाके में आतंकियों ने मोहम्मद याकूब नाम के एक कश्मीरी मुस्लिम की गोली मारकर हत्या कर दी। जानते हैं उसका कसूर क्या था ? उसका कसूर था कि वो पंचायत चुनाव लड़कर मुख्यधारा का हिस्सा बनना चाहता था। और कश्मीर में पंचायत चुनाव लड़ते ही मारे जाने वाले मोहम्मद याकूब कोई पहले कश्मीरी मुस्लिम और न ही आखिरी। याकूब की हत्या से एक दिन पहले ही आतंकियों ने बटमालू में मस्जिद के बाहर खड़े एक पुलिसवाले को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। इससे पहले पिछले साल 7 नवम्बर को बटमालू में ही आतंकियों ने गोली मारकर एक पुलिसवाले की हत्या कर दी थी।

मतलब साफ है। चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे चुनाव लड़कर मुख्यधारा का हिस्सा बनने वाले कश्मीरी मुसलमान हो या फिर कश्मीर के ही पुलिसवाले. ऐसा हर वो शख्स, ऐसा हर वो वर्ग, जो कश्मीर में इस्लामी निजाम की स्थापना में रोड़ा बनेगा, वो मार दिया जाएगा। फिर इस देश के बुद्धिजीवी, कश्मीर के अलगाववादी, अरुंधति राय जैसे पेशेवर असंतुष्ट, कश्मीर में जनमत संग्रह करवाकर वहां की आवाम की राय जानने का दावा करते हैं। अरे भाई, ऐसे हर इंसान को तो आप चुन चुनकर मार डालते हैं जो आपसे नाइत्तेफाकी रखता है तो फिर इस 'जनमत संग्रह करवा लो' वाले ढोंग का क्या मतलब ?

एक बात आपको समझनी होगी कि किसी भी फिल्म या राजनीतिक पार्टी की इतनी हैसियत नहीं होती कि वो लोगों को आपस में बांट पाए। आम से आम आदमी किसी भी कौम या वर्ग को लेकर अपनी राय अपने खुद के अनुभवों पर बनाता है। वो अनुभव जो उसने उन लोगों के साथ रहकर First hand हासिल किए हैं, अलग-अलग मुद्दों पर उनकी राय, प्रतिक्रिया जान सुनकर बनाए हैं। इसलिए बार-बार ये बचकानी दलील देकर आम आदमी की कॉमन सेंस और उसकी निष्ठा पर सवाल मत खड़े कीजिए कि वो इतना गधा है कि एक फिल्म देखकर अपने असल अनुभवों को ताक पर रखकर खुद को ख्वामख्वाह जहर से भर लेगा।

ये समझना होगा कि कश्मीर से लेकर ईरान तक. और बरेली से लेकर कर्नाटक तक जिन तमाम घटनाओं का जिक्र मैंने ऊपर किया है ये मंगल ग्रह पर नहीं, इसी धरती पर घटी हैं। यहां के लोगों के बीच घटी हैं। यहीं के लोगों ने उसे देखा है और उस आधार पर अपने अनुभव बनाए हैं।

अंत में यही कहूंगा कि लोग बदलें, तो उनसे जुड़े अनुभव भी बदल जाते हैं। पर सवाल यही है, क्या वो बदलेंगे ? शायद ये बदलाव देखने के लिए हमें ओशो से तो ज़्यादा आशावादी होना पड़ेगा!

- विनोद बार्ष्णेय

सेंसर बोर्ड के नियम एवं निर्देशानुसार

' The kashmir files ' में न न करते हुए भी सात कट लगाये गए हैं...*

1) तिरंगा गिरने और जलाने वाला सीन हटाया गया।
2) यासीन मलिक से मनमोहन सिंह की मुलाकात वाला दृश्य हटाया गया।

3) कश्मीरी पंडितों के नाम लेकर जो गालियां बकी जाती थीं, उन्हें भी हटाया गया।
4) छोटी बच्चियों से रेप।
5) हिंदू महिला से गैंगरेप।
6) जिंदा हिन्दू को बांधकर मोटरसाइकिल से खदेड़ खदेड़ कर मार डाला गया।
7) मरे हुए हिंदू को थूक थूक कर तथा पत्थर मार मार कर उसके चारों ओर से घूम घूम कर अल्लाह हू अकबर के नारे लगाने वाला दृश्य।

फिर भी चलो हक़ीक़त सामने तो आई...

हादिया जो पूर्व में हिन्दू अखिला के नाम से जानी जाती थी। उसने 2016 में जहान के साथ इस्लाम में धर्मान्तरण कर विवाह कर लिया। अखिला के पिता ने कोर्ट में उसके जबरन धर्म परिवर्तन पर याचिका थी। केरल की पूरी मुस्लिम लॉबी एकत्र हो गई। क्या वकील, क्या नेता, क्या पत्रकार, क्या मौलवी, क्या वामपंथी। सभी अखिला को वापिस जाने से रोकने में लग गये। इस प्रकरण की आवाज खाड़ी देशों तक गई। अंत में कोर्ट ने फैसला अखिला के पति के पक्ष में दिया। मायूस मां-बाप अपनी बेटी तक को जिसे उन्होंने बड़े लाड-प्यार से बड़ा किया था। अपनी आंखों के सामने खो देते हैं। यह प्रकरण यहां ही नहीं रुका। केरल की विधान सभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ कि ऐसे धर्मान्तरण करने वालों को अब राजकीय गजट परिवर्तन की सुचना नहीं देनी होगी। इससे तात्पर्य यही निकलता है कि जितना भी परिवर्तन हो किसी को पता ही नहीं चलेगा। सोचिये कैसे स्थिति है ?

जिन अरबी मुसलमानों को केरल के हिन्दू राजा ने बसाया था। उन्हें हर प्रकार से संरक्षण दिया। उन्हीं मोपला की संतानों ने हिन्दुओं को अपने ही प्रदेश के इस भूभाग में अल्पसंख्यक बनाकर

शांतिप्रिय कश्मीरी हिंदुओं के नृशंस हत्याकांड और उनके निर्वासन के दर्द पर केजरीवाल की राजनीति

विधानसभा में बहस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने शांतिप्रिय कश्मीरी हिंदुओं के नृशंस हत्याकांड और उनके निर्वासन पर बनी फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' पर कहा कि इसको टैक्स फ्री करने के लिए कह रहे हैं। 'इसे यूट्यूब पर अपलोड कर दो फ्रीफ्री हो जाएगा। टैक्स फ्री क्यों करवा रहे हो। इतना ही तुम्हें शौक है तो विवेक अग्निहोत्री को बोलो कि इस फिल्म को यूट्यूब पर डाल दे सभी लोग एक ही दिन में ये फिल्म देख लेंगे। केजरीवाल उन लाखों कश्मीरी हिंदुओं के बर्बर हत्याओं और उनके निर्वासन के दर्द पर अट्टहास कर रहे हैं। 1990 के दशक में हुए कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार और पलायन को झूठा कह रहे हैं। जनता सब जानती है इसलिए जनता का भरपूर प्यार इस फिल्म को और विवेक अग्निहोत्री को मिल रहा है जिसके कारण यह फिल्म 2 सौ करोड़ से अधिक की कमाई कर चुकी है लेकिन लगता है सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाले कुछ लोगों को यह रास नहीं आ रही है। इनमें से एक नाम केजरीवाल का भी है। इसलिए विधानसभा में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ लोग कश्मीरी पंडितों के नाम पर करोड़ों कमा रहे हैं और तुम लोग (बीजेपी) फिल्म के पोस्टर चिपका रहे हो। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि कश्मीरी हिंदूओं के इस नरसंहार पर सियासत हो रही है।

केजरीवाल के इस शर्मनाक बयान के बाद, अनुपम खेर ने पलटवारकरते हुए ट्वीटर पर अपने किरदार की अलग-अलग फोटो के कोलाज को शेयर करते हुए लिखा है कि अब दोस्तों TheKashmirFiles सिनेमा हॉल में ही जाकर देखना। आप लोगों ने 32 साल बाद KashmiriHindus के अत्याचार को समझा है। उनके साथ हुए अत्याचार को समझा है। उनके साथ सहानुभूति दिखाई है। लेकिन जो लोग इस Tragedy का मजाक उड़ा रहे हैं। कृपया उनको अपनी ताकत का एहसास कराएं। Shame

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं ने इस फिल्म को देखा है और इसकी तारीफ करते हुए

इस फिल्म को आम लोगों को देखने की अपील भी की है। इतना ही नहीं कई राज्यों ने फिल्म को टैक्स फ्री भी किया है। जिस पर केजरीवालसदन में टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि 'हम आपसे झूठी फिल्मों के पोस्टर नहीं लगवाएंगे। जो भी करना हो कम से कम ये फिल्मों का प्रमोशन तो करना बंद करो,गंदे लगते हो तुम लोग, सोभा नहीं देती है, आप राजनीति में कुछ करने आए थे, कहां झूठी फिल्मों के पोस्टर लगा रहे हो'। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विशेष रूप से आलोचना करते हुए केजरीवाल कहते है कि 8 साल सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया, बताओ विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़ रही है बचा लो बचा लो जैसे आरोप लगा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करना उन्हें क्या शोभा देती है।केजरीवाल देश की जनता के जनादेश पर सवाल उठा रहे है क्योंकि देश की जनता ने बहुमत से मोदी को दूसरी बार देश का प्रधानमंत्री चुना है उनके काम को देख कर और जहां तक फिल्म की बात है वोतो अब बनी है जनता ने उन्हें पहले से ही चुन लिया था। केजरीवाल जी शायद भूल गए हैं कि वो फिल्मों के कितने शौकीन है। बींसयों ऐसी फिल्में होंगी जिसे आपने देखा और उस फिल्म का प्रमोशन किया। हिंदू विरोधी और एक वर्ग को खुश करने जैसी कई फिल्मों को आपने टैक्स फ्री भी किया है जिसमें से जिस 83 फिल्म को आपने टेक्सफ्री किया था उसमें क्या दिखाया गया कि पाक सेना ने भारतीय सेना को फाइनल मैच का स्कोर सुनाने के लिए फायरिंग रोक दी थी? क्या ऐसा हुआ था नहीं इस झूठ को फैलकर आप तुष्टिकरण की राजनीति कर सकते। परंतु हिंदुओं की पीड़ा को जग जाहिर होने से आपको दिक्कत हो रही है। इसके अलावा कई फिल्में है जिसे आपने अपने ट्वीटरहैंडल से ट्वीट करके प्रमोट किया है जैसै- 83, सांड की आंख, निल बटे सन्नाटा, मसान, मॉम, आर्टिकल 15, सीक्रेटसुपरस्टार, गब्बरइजबैक

और वन्सअपॉन ए टाइम इन बिहार जैसी कई फिल्मों के नाम इनमें शामिल है।तब आप राजनीति में क्या फिल्मों का प्रमोशन करने और रिव्यू देने आए थे। खुद की करनी भूल गए और मोदी देश में हुए उन कश्मीरी हिंदूओं पर बनी एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म को अच्छा बताया तो आपकी हिंदू विरोधी छवि उभर कर जनता के सामने आ गई ऐसे बड़े हिंदू बने घूमते थे परन्तु जब बात आई कश्मीरी हिंदूओं का साथ देने की तो तुष्टीकरण की राजनीति खतरे में आ गई और विधानसभा में ठहाके लगाने लगें।

सियासत की सहूलियत के मुद्दे को समर्थन और विरोध का सामना करना पड़ता है परंतु इस फिल्म को झूठी फिल्म बताकर उन सभी कश्मीरी हिंदूओं के सामूहिक नरसंहार का मजाक बनाया देश के हिंदू इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। इस बयान के बाद बीजेपी सड़कों पर उतर गई है। केजरीवाल के घर के पास धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और उन सभी कश्मीरी हिंदूओं से केजरीवाल को माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में पोस्टर लगा रहे है। वही दूसरी ओर,बीजेपी नेता अमित मालवीय ने केजरीवाल के यूट्यूब पर फिल्म को डालने जैसे बयान पर जवाब देते हुए कहा कि 'केजरीवाल जी ने उपर्युक्त(जिन फिल्मों को केजरीवाल ने टैक्स फ्री किया है उसका हवाला देते हुए) फिल्मों को यूट्यूब पर डालने की सलाह क्यों नहीं दी? दिल्ली में टैक्स फ्री क्यों किया? केजरीवाल किन किन के चरणों में गिरा होगा? क्योंकि द कश्मीर फाइल्सहिंदुओं के नरसंहार की दास्तान दिखा रही है, इसलिए इस अर्बन नक्सल के पेट में दर्द हो रहा है?'

इस तरह ये साफ-साफ दिख रहा है कि केजरीवाल किस तरह हिंदू विरोधी कार्यों को प्रोत्साहन देते हैं। द कश्मीर फाइल्सफिल्म के जरिए, केजरीवालकी मानसिकता पूरी तरह उजागर हो चुकी है जो जेएनयू मेंभारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारों का समर्थन करती है, सर्जिकलस्ट्राइक पर सवाल उठाती है ऐसे इंसान से भारत वासी और क्या अपेक्षा कर सकते हैं।कश्मीरी हिंदूओं को बस उन्हें न्याय चाहिए और कुछ नहीं।

प्रेरणा कुमारी
(स्वतंत्र लेखन एवं अनुवाद में सक्रिय हैं।)

उपेक्षित कर दिया। समस्या यह है कि वर्तमान में इस बिगड़ते जनसंख्या समीकरण से निजात पाने के लिए हिन्दुओं की कोई दूरगामी नीति नहीं हैं। हिन्दुओं को अब क्या करना है। इस पर आत्मचिंतन करने की तत्काल आवश्यकता है। अन्यथा जैसा कश्मीर में हुआ वैसा ही केरल में न हो जाये।

यह भी जाने -

- कृष्ण-गंगा नदी जिसमें असुरों से छुपाकर अमृत रखी गई थी वो जिन भूभागों में सबसे अधिक बहती है वो पाकिस्तान के कब्जे में है और अब पाकिस्तानी उसे नीलम नदी कहते हैं।
- कृष्णगंगा की बेहद खूबसूरत ढ़ाई सौ किलोमीटर लंबी घाटी जिसे हम कृष्ण-गंगा घाटी कहते थे वो अब नीलम घाटी कही जाती है।
- जम्मू-कश्मीर के डल झील के किनारे की एक पहाड़ी पर आदि शंकराचार्य आये थे और लोगों ने उनके नाम पर उस पहाड़ का नाम 'शंकराचार्य पर्वत' रख दिया था और उनके सम्मान में राजा गोपादित्य ने 371 ई. पूर्व में एक मंदिर का निर्माण करवाया था और नाम दिया था शंकराचार्य मंदिर। आज उस मंदिर का नाम बदल कर तख्त-ए-सुलेमानी कर दिया गया है।
- वराहमूल को बारामूला कर दिया गया।
- कनकवाहिनी नदी (जिसके बारे में कहा जाता था कि ये लक्ष्मी देवी का रूप है) को बदलकर अब कनकई नदी कर दिया गया है।
- पुराणों में वर्णित चंद्रभागा नदी अब चेनाब है।
- पंचाल धर को बदलकर पीर पांचाल किया गया।
- दुग्धधर तीर्थ को दुदुकंत कर दिया गया।
- बुद्धगम को बड़गाम कर दिया गया।
- शिवजी के बारात पथ 'गौरीमार्ग' को गुलमर्ग कर दिया गया।
- विध्वंस लीला का आलम तो ये है कि श्रीनगर के पुलवामा से करीब 17 किलोमीटर दूर खरेव में माता ज्वालादेवी का मंदिर है जिसे अभी हाल में ही अग्नि के हवाले करके खंडहर में बदल दिया गया था।
- दक्षिण कश्मीर के मार्तंड प्राचीन सूर्य मंदिर जो लगभग 1400 वर्ष पुराना है, उसे अब हैदर जैसी फूहड़ फिल्मों की शूटिंग स्थली में बदलकर 'शैतान की गुफा' कहा जा रहा है।
- जम्मू में स्थित 'रघुनाथ मंदिर' पर आतंकी हमला कर उसे भी नष्ट करने की कोशिश हुई थी।
- 2000 साल पुराना श्रीनगर स्थित 'शीतलेश्वर मंदिर' अब खंडहर है।
- पाक अधिकृत भारत में स्थित 'शारदापीठ' की करूण कथा सभी जानते ही हैं
- घाटी के कुलगाम जिले के देवसर क्षेत्र में स्थित मां 'त्रिपुरसुन्दरी मंदिर' के अब केवल निशान ही बाकी हैं।
- 1988-89 तक कश्मीर में 583 मंदिर थे, इनमें से 532 मंदिर ऐसे हैं जिनको आतंकवादियों ने कई बार निशाना बनाया और 52 मंदिरो का तो अब अस्तित्व ही नहीं है।

और इतना करके भी वो नहीं रुके हैं और अब वो अनंतनाग, अवन्तिपोरा, जम्बुपुरा (जम्मू), रामबन, पद्म, सांबा आदि स्थानों के नाम बदलकर कश्मीर के मूल के सारे चिन्ह को मिटाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं।

विवेक अग्निहोत्री ने तो कश्मीर फाइल्स के अनगिनत क्रूर पन्नों में से अभी केवल पहला पन्ना ही खोला है। अभी तो हजारों विवेक आने हैं और हजारों कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म बनने बाकी हैं। ■

हिजाब पर फैसले में बाबा साहेब की राय कितनी अहम

● आर.के. सिन्हा

बाबा साहेब डॉ बी0 आर0 अम्बेडकर किसी गंभीर और संवेदनशील मसले पर भी अपनी राय बेबाकी से ही रखते थे। उनकी मुस्लिम समाज की औरतों के हिजाब और बुर्का पहनने पर प्रगट किये गए सार्वजनिक विचार 75 सालों के बाद भी समीचिन और स्पष्ट हैं। इसलिए ही कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य के स्कूलों में हिजाब पहनने या ना पहनने को लेकर चल रही बहस पर अपना फैसला सुनाते हुए बाबा साहेब के विचारों का भी विस्तार से हवाला दिया। बाबा साहब ने अपनी मशहूर किताब 'पाकिस्तान ओर द पार्टिशन ऑफ इंडिया (1945)' में लिखा था, 'एक मुस्लिम महिला सिर्फ अपने बेटे, भाई, पिता, चाचा ताऊ और शौहर को देख सकती है या फिर अपने वैसे रिश्तेदारों को जिन पर विश्वास किया जा सकता है। वो मस्जिद में नमाज अदा करने तक भी नहीं जा सकती। मुसलमानों में भी हिंदुओं की तरह और कई जगह तो उनसे भी ज्यादा सामाजिक बुराइयां हैं।' उन्होंने एक तरह से पर्दा प्रथा का खुलकर विरोध किया था। हैरानी इसलिए हो रही है कि जो मुस्लिम नेता देश में मुसलमान और दलितों के बीच सियासी तालमेल बनाने की हर वक्त वकालत करते हैं, वे हिजाब के मसले पर बाबा साहेब के विचारों को या तो जानते नहीं या फिर जानकर भी अंजान बने हुए हैं। अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को ही लें। आप गूगल करके देख सकते हैं कि वे बार-बार दलित-मुस्लिम एकता का आहवान करते हैं। वही ओवैसी हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का पुरजोर तरीके से विरोध भी कर रहे हैं। वे इससे पहले भी ले तीन तलाक और अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर चुके हैं। इसके बावजूद वे संविधान और दलित-मुसलमान गठबंधन पर प्रवचन देते रहते हैं। क्या उन्हें मालूम नहीं है कि भारत के संविधान को तैयार करने में बाबा साहेब की क्या भमिका थी? क्या उन्हें पता है कि हिजाब जैसी कुप्रथा पर बाबा साहेब की राय किस तरह की थी? दरअसरल कहने का अर्थ यह है कि ओवैसी जैसे नेता जो मुसलमानों की राजनीति करते हैं, वे अपनी कौम के साथ-साथ दलितों को भी छलने का काम करते हैं। ये किसी के भी सगे नहीं हैं। ये जान लें कि आज के दलित जाग चुका है। वे बाबा साहेब जैसे रोशन ख्याल नेता को अपना आदर्श मानते हैं। ओवैसी और उनके जैसे मुसलमान नेता यह भी जान लें कि हाल के उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनावों में दलित उसी भाजपा के साथ खड़े थे जिसने उनके बारे में सही ढंग से सोचा और किया भी। आगरा को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की दलित सियासत का किला समझा जाता था। वहां की सभी सातों विधानसभा सीटों पर भाजपा को विजय मिली है। इस चुनाव ने उस गलतफहमी को ध्वस्त कर दिया है कि प्रदेश में बसपा की सरकार बने या नहीं बने, लेकिन; उसका वोट बैंक तो बना का बना रहेगा।

एक बार फिर से अपने मूल विषय पर लौटूंगा। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद एक और गंभीर बात सुनने में आ रही है कि कुछ मुसलमान नेता अंदर ही अंदर अपनी कौम के बीच में यह आहवान कर रहे हैं कि वे अपनी बेटियों को सरकारी स्कूलों- कॉलेजों से निकाल कर उन शिक्षण संस्थानों में दाखिला दिलवा दें, जिनका प्रबंधन मुसलमानों के हाथों में है। यह एक बेहद गंभीर और खतरनाक पहल है। इस खुराफात के पीछे जिन शातिर लोगों का दिमाग चल रहा है, जाहिर है कि उन्हें मुसलमान जल्दी ही पहचान लेंगे। इस तरह के देश विरोधी तत्वों को तुरंत बेनकाब करना होगा। क्या इन्हें मालूम नहीं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंतर्गत चलने वाले स्कूलों-कॉलेजों की फीस और जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी की फीस में कितना अंतर है? जामिया मिल्लिया इस्लामिया सरकारी

हिंदुओं की मॉब लींचिंग पर चुप्पी क्यों ?

पिछले कई दिनों में हिंदुओं की मॉब लींचिंग की जो घटनाएं हुई हैं उनमें तीन बातें विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं -

1. पहला, इन घटनाओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। पहले ऐसी घटनाएं हर कुछ महीने पर होती थीं, अब हर कुछ दिन में होने लगी हैं। पहले आप एक को भूलते थे तब अगली होती थी, आज आप एक पर outrage कर रहे होते हैं तबतक अगली हो जाती है।
2. दूसरा, इन घटनाओं के लिए प्रोवोकेशन का लेवल कम होता जा रहा है। इसके लिए किसी को कमलेश तिवारी की तरह नेशनल नेटवर्क पर कुछ बोलना जरूरी नहीं रह गया, आज एक फेसबुक पोस्ट पर, सरस्वती पूजा के विसर्जन पर, स्कूलों में यूनिफार्म लागू करने का समर्थन करने पर यह हत्याएं होने लगी हैं।
3. और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज ये घटनाएं डॉ नारंग वाली घटना की तरह रैंडम नहीं रह गयी हैं, बल्कि बहुत फोकस्ड हो गयी हैं। हजारों लोगों ने स्कूलों में मजहबी लिबास के खिलाफ प्रदर्शन किया, उनमें से एक विजिबल और सक्रिय लड़के की हत्या कर दी। यानि एक संदेश देना है, जो भी प्रतिकार करेगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। यह हिन्दू समाज का प्रतिकार करने का मनोबल तोड़ने का एक लो कॉस्ट तरीका है। यह पेरिफेरी से घेरने की तकनीक है।

पर अगर आप दूसरे पॉइन्ट को भविष्य में प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका लॉजिकल कॉन्क्लूजन यह है कि इन घटनाओं के लिए प्रोवोकेशन आगे जाकर और कम होगा। आप उनसे जरा सी भी असहमति व्यक्त करेंगे, यहां तक कि सिर्फ असहमति रखेंगे तो भी उनके निशाने पर आ जाएंगे। इसे और आगे प्रोजेक्ट करें तो अगर आप उनकी ओर से नहीं बोलेंगे तो सिर्फ चुप रहने के लिए भी निशाने पर आ जाएंगे। फिर कल को वही होगा जो होना है।।।आप अगर उनकी ओर से नहीं लड़ेंगे, उनकी फौज में नहीं होंगे, यानि कन्वर्ट नहीं होंगे तो फिर भी उनके निशाने पर होंगे। यानि आप जिस लड़ाई से बचना चाहते हैं, वह तो आपको लड़नी ही है।।।अगर इधर से ना लड़े तो आप या आपके बच्चे उधर से लड़ेंगे।

और आखिर में पॉइंट नंबर एक।।। इन हमलों की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, कल को मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। जो हत्याएं आज हर कुछ दिन पर हो रही हैं, वे हर रोज कई होंगी। और फिर एक दिन बहुत सारी होंगी, जैसा डायरेक्ट एक्शन डे को हुआ था। यानि हम उनके नियत D-DAY के नजदीक, और नजदीक पहुंच रहे हैं।

हर खेल के अपने नियम होते हैं। क्रिकेट का नियम है रन - जिसने ज्यादा रन बनाए वह जीता। फुटबॉल का नियम है गोल। जिसने ज्यादा गोल किये वह जीता। आपकी ड्रिब्लिंग स्किल, आपकी स्क्वायर कट की टेक्निक मायने नहीं रखती।

हम युद्ध में हैं। दुर्भाग्य से हमारा #JusticeForHarsha कहना हमें युद्ध जीतकर नहीं देगा। फिर भी हमारा outrage महत्वपूर्ण है, वह हमारे संघर्ष को वैधता देता है। जो तटस्थ हैं, निरपेक्ष हैं उन्हें शत्रुबोध कराता है, पर युद्ध जीत कर नहीं देता है। युद्ध का नियम है हिंसा। यहां जो अधिक हिंसा करने में सक्षम होता है वह जीतता है।

यूनिवर्सिटी है और जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी प्राइवेट। स्पष्ट कर दें कि जामिया हमदर्द को भी सरकार की तरफ से खासी मदद मिलती है। फिर भी उसकी फीस कई गुना ज्यादा है। यह तो बस एक उदाहरण था।

खैर,कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि, इस्लाम में हिजाब पहनना कतई अनिवार्य नहीं है। स्कूलों-कॉलेजों में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। देखिए भारत में कोई यह नहीं कह रहा है कि आप हिजाब मत पहनिए। लेकिन, हरेक शिक्षण संस्थान की अपनी एक मर्यादा है। उसकी एक वेशभूषा है।

विनीत
नारायण

मुसलमानों का क्या करें?

सुजलाम, सुफलाम, मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम, भारत माता इतनी उदार हैं कि हर भारतवासी सुखी, स्वस्थ व सम्पन्न हो सकता है। पर स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी अधिकतर आबादी पेट पालने के लिए भी दान के अनाज पर निर्भर है। कई दशकों तक 'गरीबी हटाओ' के नाम पर उसे झुनझुना थमाया गया। पर उसकी गरीबी दूर नहीं हुई। आज गरीबी के साथ युवा बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बन गयी है । जिसका निदान अगर जल्दी नहीं हुआ तो करोड़ों युवाओं की ये फौज देश भर में हिंसा, अपराध और लूट में शामिल हो जाएगी। हर राजनैतिक दल अपने वोटों का ध्रुवीकरण के लिए जनता को किसी न किसी नारे में उलझाए रखता है और चुनाव जीतने के लिए उसे बड़े-बड़े लुभावने सपने भी दिखाता है।

पिछले कुछ वर्षों से अल्पसंख्यक मुसलमानों का डर बहुसंख्यक हिंदुओं को दिखाया जा रहा है। आधुनिक सूचना तकनीकी की मदद से 'इस्लमोफोबिया' को घर-घर तक पहुंचा दिया गया है। लगभग 30 फीसदी हिंदू आबादी ये मान चुकी है कि भारत की हर समस्या का कारण मुसलमान है, जो सही नहीं है। आर्थिक समस्याओं के कारण दूसरे हैं और सामाजिक समस्याओं के कारण दूसरे।

जहां तक भारत में मुस्लिम आबादी का प्रश्न है वे आज 17 करोड़ हैं और हम हिंदू 96 करोड़ हैं। अपनी आबादी के इतने बड़े हिस्से को अगर हम अपनी हर समस्या का कारण मानते हैं तो इसका निदान क्या है? क्या उन्हें मार डाला जाए? क्या उन्हें एक और पाकिस्तान बना कर भारत से अलग कर दिया जाए? या उनके और हमारे बीच चले आ रहे विवाद के विषयों का समाधान खोजा जाए?

उल्लेखनीय है कि सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी मुसलमानों के विषय में कई बार कह चुके हैं कि उनके और हमारे पुरखे एक ही थे, कि उनका और हमारा डीएनए एक है, कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। 80 बनाम 20 फीसदी का नारा देकर चुनाव लड़ने वाले योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी एक सभा में कहा, 'वह मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूं'।

संघ और भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए इस सब से बड़े असमंजस की स्थितियां पैदा होती रहती हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि क्या करें ? अगर भागवत जी की यही बात सही है तो फिर मॉबलिंचिंग, लव जिहाद, टोपी-दाढ़ी का विरोध, रेहड़ी वालों को पीट कर उनसे जय श्री राम कहलवाना या मुसलमानों के साथ हर तरह का व्यावसायिक व सामाजिक व्यवहार ख़त्म करने जैसे अभियानों का रात दिन सोशल मीडिया पर इतना प्रचार क्यों किया जाता है ?

अगर भागवत जी या योगी जी या फिर मोदी जी भी यही मानते हैं कि मुसलमान ही हर समस्या की जड़ हैं तो इस अभियान को लम्बा खींचने के बजाय एक बार में इसका समाधान ढूंढ कर उसे कड़ाई से लागू क्यों नहीं करते? अगर वे ऐसा कर देते हैं तो समाज में नित्य नए उठने वाले विप्लव शांत हो जाएंगे। जो समाज और राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए अत्यावश्यक हैं। क्योंकि अशांत समाज में आर्थिक गतिविधियां ठहर जाती हैं। अगर इन राष्ट्रीय नेताओं को ये लगता है कि ऐसा करना सम्भव नहीं है तो जो अभियान अभी चल रहे हैं उनको रोकने और उनकी दिशा मोड़ने का कार्य उन्हें करना चाहिये। जो उनके लिए असम्भव नहीं है। हां इससे अपेक्षित राजनैतिक लाभ नहीं प्राप्त होगा किंतु समाज में शांति जरूर स्थापित हो जाएगी।

इस सबसे अलग एक प्रश्न हम सब सनातन धर्मियों के मन में सैंकड़ों वर्षों से घुट रहा है। भारत की सनातन संस्कृति को गत हजार वर्षों में राजाश्रय नहीं मिला। कई सदियों में तो उसका दमन किया गया। जिसका विरोध सिख गुरुओं व शिवाजी महाराज जैसे अनेक महापुरुषों ने किया। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका विरोध उस राज सत्ता से था जो हिंदुओं का दमन करती

थीं। सामाजिक स्तर पर इन्हें मुसलमानों से कोई बैर नहीं था। क्योंकि इनकी सेना और साम्राज्य में मुसलमानों को महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया गया था।

बंटवारे से पहले जो लोग भारत और पाकिस्तान के भोगौलिक क्षेत्रों में सदियों से रहते आए थे, उनके बीच भी पारस्परिक सौहार्द और प्रेम अनुकरणीय था। बंटवारे के बाद इधर से उधर या उधर से इधर गए ऐसे तमाम लोगों के इंटरव्यू यूट्यूब पर भरे पड़े हैं। ये बुजुर्ग बताते हैं कि बंटवारे की आग फैलने से पहले तक इनके इलाक़ों में साम्प्रदायिक वैमनस्य जैसी कोई बात ही नहीं थी।

एक तरफ सनातन धर्म के मानने वाले वे संत और हम जैसे साधारण लोग हैं जिनका यह विश्वास है कि सनातन धर्म ही मानव और प्रकृति के कल्याण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसीलिए हम इसका पालन राष्ट्रीय स्तर पर होते देखना चाहते हैं। वैसे भी दुनिया के सभी सम्प्रदाय वैदिक संस्कृति के बाद पनपे हैं। पर ऐसा होता दीख नहीं रहा। चिंता का विषय यह है कि हिंदुत्व का नारा देने वाले भी वैदिक सनातन संस्कृति की मूल भावना व शास्त्रोचित सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए अति उत्साह में अपने मनोधर्म को वृहद् हिंदू समाज पर जबरन थोपने का प्रयास करते हैं। जबकि हमारे सनातन धर्म की विशेषता ही यह है कि इसका प्रचार-प्रसार मनुष्यों की भावना से होता है तलवार के जोर से नहीं।

रही बात मुसलमानों की तो इसमें संदेह नहीं कि मुसलमानों के एक भाग ने भारतीय संस्कृति को अपने दैनिक जीवन में काफी हद तक आत्मसात किया है। ऐसे मुसलमान भारत के हर हिस्से में हिंदुओं के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में जीवन यापन करते हैं। किंतु उनके धर्मांध नेता अपने राजनैतिक लाभ के लिए उन्हें गुमराह करके ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जिससे बहुसंख्यक हिंदू समाज न सिर्फ असहज हो जाता है बल्कि उनकी ओर से आशंकित भी हो जाता है। हिंदू समाज की ये आशंका निर्मूल नहीं है। मध्य युग से आजतक इसके सैंकड़ों उदाहरण उपलब्ध हैं। ताजा उदाहरण अफगानिस्तान के तालिबानों का है जिन्होंने सदियों से वहां रह रहे हिंदुओं और सिक्खों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में अब समय आ गया है कि शिक्षा, क़ानून और प्रशासन के मामले में देश के हर नागरिक पर एक सा नियम लागू हो। धार्मिक मामलों को समाज के निर्णयों पर छोड़ दिया जाए। उनमें दखल न दिया जाए। ऐसे में मुसलमानों के पढ़े-लिखे और समझदार लोगों को भी हिम्मत जुटा कर अपने समाज में सुधार लाने का काम करना चाहिए। जिससे उनकी व्यापक स्वीकार्यता बन सके । वैसे ही जैसे हिंदुत्व का झंडा उठाने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को गम्भीरता से सनातन धर्म के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, न कि उसमें घालमेल। तभी भारत अपनी 135 करोड़ जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप खड़ा हो सकेगा। ■

क्या आप उसे भी नहीं मानेंगे ?

पड़ोसी देश श्रीलंका में कुछ साल पहले हुए दिल-दहलाने वाले बम धमाकों के बाद सरकार ने बुर्का पहनने पर रोक लगा दी थी। इस्लामिक देश मोरक्को बुर्के के पहनने पर प्रतिबंध लगा चुका है। जाहिर है कि यदि वहां की सरकार ने बुर्के पर रोक लगाई है तो उसकी तरफ से यह कदम बहुत सोच-विचार के बाद ही लिया गया होगा। इस्लाम को बुर्का प्रथा से जोड़ना भी कतई सही नहीं है। फ्रांस भी बुर्के और हिजाब के पहनने पर पहले ही रोक लगा चुका है।

फ्रांस में मुसलमानों की आबादी का हिस्सा 9 फीसदी है। ये अधिकतर उत्तरी अफ्रीकी मूल के हैं, जहां अल्जीरिया, मोरक्को या ट्यूनीशिया में पहले फ्रांसीसी उपनिवेश हुआ करते थे। फ्रांस में धार्मिक आधार पर कतई भेदभाव नहीं होता, यह बात आप फ्रांस की फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों के नामों को पढ़कर समझ सकते हैं। लेकिन वहां अंधकार युग के चिन्हों को स्वीकार नहीं किया जाता।

मुसलमानों को यह समझना होगा कि उन्हें अकारण दलदल में रखने की चेष्टा उन्हीं के ओवैसी जैसे कथित रहनुमा करते रहते हैं। उन्हें धार्मिक मसलों में फंसाए रखने की कोशिशें भी निरंतर चलती रहती हैं। वे जब तक अपने इन बदबूदार नेताओं से दूरी नहीं बनाएंगे इनका कल्याण नहीं होगा।

याद कीजिए कि ये ही मुसलमानों में ट्रिपल तलाक और हलाला की परम्परा को बनाए और बचाए रखने के लिए लड़ते रहे हैं। इनकी घनघोर महिला विरोधी सोच को जहां से भी चुनौती मिलती है, तो वे अनाप-शनाप बकने लगते हैं। इस सारी बहस का बेहद कड़वा सच यह भी है कि मुसलमानों का शिक्षित मध्यवर्ग भी हिजाब, बुर्का, ट्रिपल तलाक को खत्म करने को लेकर दिल से चाहते हुए भी खुलकर सामने नहीं आता। अपने को मुसलमानों का शुभचिंतक बताने वाली तीस्ता सीतलवाड़ भी सामने नहीं आतीं। हैं। वे तमाम लेखक और कैंडल मार्च निकालने वाले बुद्धिजीवी भी दीन-हीन मुसलमान औरतें का साथ देने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन भारत तो उस संविधान के अनुसार ही चलेगा, जिस पर उदारवादी बाबा साहेब की अमिट छाप है। ■

राष्ट्रिय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अंतर्गत अल्पसंख्यको को अधिसूचित करने की केंद्र सरकार की शक्ति के खिलाफ एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने जब केंद्र सरकार से जवाब मांगा तो उस पर केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र देकर कहा है कि राज्य अपने यहां की जनसख्या के आधार पर हिंदुओं को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकते हैं। संविधान के अनु0 29,30 में अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिये गए हैं जो हिंदुओं पर लागू नहीं होते हैं। संविधान के द्वारा प्रदत्त समता का अधिकार तब महत्वहीन दिखाई देता है जब लक्षादीप का 97 प्रतिशत मुसलमान अल्पसंख्यक और 2 प्रतिशत हिन्दू बहुसंख्यक कहलाता है। कश्मीर में 70 प्रतिशत मुसलमान अल्पसंख्यक एवं 28 प्रतिशत हिन्दू बहुसंख्यक कहलाता है।

अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक

अब हिन्दू भी हो सकते हैं अल्पसंख्यक

● **अमित त्यागी**

अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक की बहस के बीच उच्चतम न्यायालय में केंद्र सरकार का एक शपथ पत्र अहम मोड़ लेकर आया है। केंद्र सरकार ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि राज्य अपने यहां की जनसंख्या के आधार पर हिंदुओं को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकते हैं। भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए अलग से प्रावधान दिये गए हैं किन्तु अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। 1992 तक देश में अल्पसंख्यक विषय पर संवैधानिक रूप से सामान्य प्रक्रिया चल रही थी। 1992 में पहली बार तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस विषय को उभार दिया और अल्पसंख्यक आयोग बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। कानून बना दिया गया। पर इतने महत्वपूर्ण विषय पर न तो कोई विस्तृत चर्चा की गयी न ही अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया गया। इस कानून में सिर्फ यह प्रावधान कर दिया गया कि अल्पसंख्यक को निर्धारित करना केंद्र सरकार के मापदण्डों के अनुसार होगा। केंद्र सरकार किस मापदंड के अनुसार अल्पसंख्यक को परिभाषित करेगी यह इसमे स्पष्ट नहीं किया गया। कितनी प्रतिशत आबादी होने पर कोई वर्ग अल्पसंख्यक माना जाएगा यह भी इस कानून में स्पष्ट नहीं है। इस तरह से राष्ट्रिय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर दिया गया जिसकी धारा-2 में प्रदत्त असीमित शक्तियों का उपयोग करते हुये तत्कालीन केंद्र सरकार ने 23 अक्तूबर 1993 को मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित कर दिया। अब बिना किसी शोध, जनगणना, विस्तृत चर्चा, राष्ट्रिय विमर्श और विधि विशेषज्ञों की सलाह के इसका आधार क्या था यह आज भी समझ से परे हैं।

इसके बाद वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। अन्य धर्म के लोग अल्पसंख्यक का दर्जा पाने के लिए हाथ पैर मानने लगे। जैन समुदाय ने इसके लिए न्यायलय में याचिका दायर कर दी। 2002 में बॉम्बे उच्च न्यायालय से जैन समुदाय को निराशा हाथ लगी। इसके बाद 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अल्पसंख्यक की पहचान प्रदेश स्तर पर होनी चाहिए। 2005 में उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से मना कर दिया। न्यायालय का तर्क इस बारे में रोचक रहा। 'देश का बंटवारा एक बार पहले ही धर्म के आधार पर हो चुका है और भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, इसलिए अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की अवधारणा ठीक नहीं है'। न्यायालय ने हालांकि, अल्पसंख्यक शब्द को खारिज नहीं किया किन्तु सरकार से आशा की कि वह धीरे धीरे अपनी नीतियों से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच का फासिला अवश्य खत्म कर देगी। इस फैसले के एक साल के बाद ही जो काम पहले समाज कल्याण मंत्रालय के आधीन होता था, उसके लिए अलग से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बना दिया गया।

यदि न्यायालय के पूर्व निर्णय के आधार पर 'अल्पसंख्यक' पर गौर करते हैं। केरल शिक्षा बिल, 1958 में उच्चतम न्यायालय ने मुद्दा

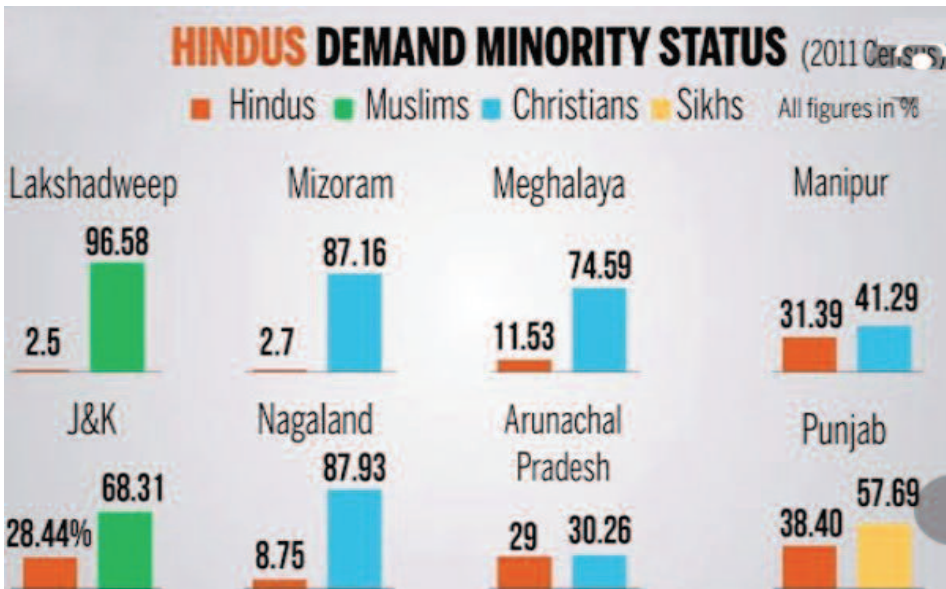

उठाया कि अल्पसंख्यक समुदाय उसे माना जाएगा जिसकी आबादी 50 प्रतिशत से कम होगी। लेकिन यह नहीं कहा कि यह 50 प्रतिशत पूरे देश की आबादी है या किसी राज्य विशेष की। इस सवाल का जवाब गुरुनानक यूनिवेर्सिटी पंजाब के वाद में मिलता है। इसमे न्यायालय ने कहा कि भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय को पूरे देश की आबादी के अनुपात में अल्पसंख्यक नहीं मानकर क्षेत्र के कानून के हिसाब से अल्पसंख्यक माना जाये। 2002 में टीएम पाई फाउंडेशन मामले में उच्चतम न्यायालय की आठ न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि कोई भी समुदाय जो उस राज्य की आबादी के पचास प्रतिशत से कम है उसे अल्पसंख्यक माना जाये। इस निर्णय के अनुसार नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, लक्षदीप, जम्मू कश्मीर और पंजाब में हिन्दू अल्पसंख्यक माने जाने चाहिए।

देश के संविधान के अनुसार भारत का हर नागरिक समान अधिकार रखता है। धर्म, लिंग और संप्रदाय के आधार पर उनमे किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 1947 के विभाजन के बाद संविधान निर्माताओं के मन में एक भय था कि कहीं ऐसा न हो कि आने वाली सरकारें धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा न कर सकें। चूंकि भारत की ज़्यादातर आबादी हिन्दू होने के कारण ईसाई और मुसलमान जैसे धर्मों के हित प्रभावित हो सकते थे इसलिए संविधान में अनु0-29,30 के प्रावधान रखे गए। संविधान में तो सिर्फ एक बार धार्मिक अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग किया गया था किन्तु 1992 में कांग्रेस सरकार ने अलग से अल्पसंख्यक आयोग का गठन करके हिन्दू एवं अन्य धर्मों में विभेद की नींव रख दी।अब एक रोचक आंकड़ा देखिये जो सारी स्थिति को बयान कर देता है। लक्षदीप में 97 प्रतिशत, कश्मीर में 70 प्रतिशत, असम में 35 प्रतिशत, बंगाल में 28 प्रतिशत, केरल में 27 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 20 प्रतिशत और बिहार में लगभग 19 प्रतिशत मुसलमान हैं। इन प्रदेशों की यह बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक कही जाती है। इसके साथ ही ईसाई का आंकड़ा भी रोचक है। नागालैंड में 88 प्रतिशत, मिजोरम में 87 प्रतिशत, मेघालय में 75 प्रतिशत, मणिपुर में 42 प्रतिशत, अरुणाचल प्रदेश में 31 प्रतिशत, गोवा में 26 प्रतिशत, अंडमान और केरल में 21 प्रतिशत जनसंख्या ईसाई है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद इन सबको अल्पसंख्यक के नाम पर वह अधिकार मिल रहे हैं जो हिंदुओं को नहीं मिल रहे हैं। इसके विपरीत लक्षदीप में 2 प्रतिशत, मिजोरम में 3 प्रतिशत, नागालैंड में 8 प्रतिशत, मेघालय में 11 प्रतिशत होने के बावजूद हिन्दू बहुसंख्यक माने जाते हैं और अधिकारों से वंचित हैं।

विडम्बना देखिये कि आजादी के सत्तर साल बाद भी हम अल्पसंख्यक को परिभाषित करने वाला फॉर्मूला नहीं ढूंढ पाये हैं। केंद्र सरकार के उच्चतम न्यायालय में जवाब के बाद अगर अल्पसंख्यक शब्द परिभाषित होता है तो यह देश की एकता के लिए अच्छा संदेश होगा। जब हर राज्य में अलग अलग धर्मों के लोग भिन्न भिन्न अनुपात में हैं तो अल्पसंख्यक की परिभाषा केंद्र सरकार के स्थान पर राज्य सरकार के द्वारा क्यों नहीं तय होती है। संविधान के द्वारा प्रदत्त समता का अधिकार तब महत्वहीन दिखाई देता है जब लक्षदीप का 97 प्रतिशत मुसलमान अल्पसंख्यक और 2 प्रतिशत हिन्दू बहुसंख्यक कहलाता है। कश्मीर में 70 प्रतिशत मुसलमान अल्पसंख्यक एवं 28 प्रतिशत हिन्दू बहुसंख्यक कहलाता है। अब क्या इन आंकड़ों के बाद भी किसी और तथ्य को सार्वजनिक करने की आवश्यकता है ? क्या अल्पसंख्यक शब्द के राजनीतिक इस्तेमाल की इससे पुष्टि नहीं होती है। क्या इस तरह की असमानता और इस असमानता की पैरवी करने वालों से देश की एकता और अखंडता की भावना को खतरा नहीं है, आप स्वयं विचार करिए। ■

उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत

● डॉ कामिनी वर्मा

यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से,
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी

यह 'कुछ बात' विश्व में विशिष्टतम स्थान से विभूषित हमारी संस्कृति में निहित है। जिसने संपूर्ण विश्व को 'वसुधैव कुटुंबकम' का मंत्र देकर इसे अपना परिवार मानने का संदेश दिया है। संस्कृति का ही आश्रय लेकर मानव जाति अनादि काल से निरंतर विकास की ओर उन्मुख रही है। मनुष्य की नैतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियां संस्कृति की संज्ञा से अभिहित की जाती हैं। इसी के चलते भाषा, साहित्य, लिपि, कला, तकनीक, विज्ञान एवं धर्म का उद्भव एवं विकास होता है । सोचने, समझने एवं विचार विमर्श करने की विवेकमय प्राकृतिक शक्ति मनुष्य को संस्कृति की ओर से उन्मुख करती है। और उसे पशुओं से पृथक करती है।

राष्ट्र मात्र भौगोलिक और राजनीतिक स्तर पर निर्धारित भूखंड नहीं होता, बल्कि यह अपने आप में विचार और भाव समाहित किए होता है । जो वहां के स्त्री, पुरुषों, जाति, धर्म, दर्शन, कला, तकनीक, ज्ञान और संस्कार में परिलक्षित होता है। और यही राष्ट्र की आत्मा होती है ।भारतवर्ष का नाम लेते ही समस्त ज्ञान, धर्म और दर्शन का भाव मन में प्रतिविम्बित होने लगता है । जिसमें वैदिक ऋचाओं से लेकर शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन का सार समावेशित हो जाता है। इस आध्यात्मिक ज्ञान और दर्शन का केंद्र उत्तर प्रदेश है। जो हिंदुस्तान के हृदय स्थल के रूप में विराजमान है।

राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश का जन्म 24 जनवरी सन 1950 को भारत के गवर्नर जनरल द्वारा 'यूनाइटेड प्रोविंसेस आर्डर' पारित करने के साथ हुआ जिसके अंतर्गत यूनाइटेड प्रोविंसेस को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। 2,38,566 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत यह भूभाग अपनी विशाल जनसंख्या से भी समृद्ध है। सांस्कृतिक धरोहर की मेरुदंड पतित,पावनी गंगा और यमुना नदियों की जलोढ़ मिट्टी इस भूखण्ड को उपजाऊ बनाने

के साथ-साथ सांस्कृतिक एवं धार्मिक नगरी के रूप में भी वैभव प्रदान करती हैं।

हिंदुस्तान की प्राचीन सभ्यता का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश है। वैदिक काल में इसे ब्रह्मर्षि देश या मध्य देश के नाम से जाना जाता था आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व आर्य सर्वप्रथम यही आए थे। और इनके ही नाम पर इस देश का नाम आर्यावर्त, और आर्यों के एक राजा भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। संपूर्ण विश्व को ज्ञान और अध्यात्म की रोशनी देने वाले चारों वेद रामायण, महाभारत, श्रीमद्भगवद्गीता जैसे ग्रंथ इसी प्रदेश में लिखे गए। श्रीमद्भागवत गीता में उल्लिखित 'धर्मो रक्षति रक्षत:' भारत की न्यायपालिका का प्रेरणा वाक्य बना। नृत्य, संगीत आदि समस्त कलाओं के अधिष्ठाता, लोक कल्याणार्थ गरल पान करके,विश्व को 'सत्यम शिवम सुंदरम' का संदेश देकर नीलकंठ के रूप में सुशोभित, आदिदेव भारतीय सभ्यता संस्कृति में सेंधव काल से अद्यतन काशी में, बाबा विशेश्वर के रूप में विराजित हैं । इन्हीं के त्रिशूल पर मोक्षदायिनी काशी बसी है। जो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है।

लोक को मर्यादा और कर्तव्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाने वाले राम,लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इसी प्रांत की उर्वर धरती से प्रसूत हैं। आज जब भाई भाई का हिस्सा हड़पना चाहता है तब राम जिन का राज्याभिषेक होने जा रहा था, वह माता कैकेई एवं पिता दशरथ के वचन को सर्वस्व मानकर राज्य सिंहासन त्याग कर वन चले जाते हैं। तो वहीं पर भरत जिनको संपूर्ण राज सिंहासन मिल जाने के बाद भी उसे न स्वीकार करके राम की खड़ाऊ सिंहासन पर रखकर उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन व्यवस्था संचालित करते हैं। यह संस्कार सिर्फ उत्तर प्रदेश की संस्कृति में ही दृष्टिगोचर होते हैं। नारी स्वाभिमान का साक्षात्कार कराने वाली सीता का समाहित स्थल इसी प्रदेश में है। तथा विश्व को राजनीति से परिचित कराने वाले कृष्ण यहीं की विभूति हैं।

छठी शताब्दी ईसा पूर्व से भारत और उत्तर प्रदेश का क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित इतिहास प्राप्त होने लगता है। जब महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की कर्म स्थली के रूप में इसके गौरव में संवर्धन होता है। 'सब्बम दुखम' कहकर संसार को दुखमय मानकर बुद्ध उस दुख से निजात पाने के लिए मध्यम मार्ग का अनुसरण करने की शिक्षा देते हैं। जिसका आशय है जीवन में न तो अत्यधिक कठोरता होनी चाहिए और न ही सरलता। अर्थात संतुलित आचरण करके व्यक्ति हर प्रकार के दुखों से छुटकारा पा सकता है। आज जब हम तृतीय विश्वयुद्ध की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तब संसार के लिए बुद्ध का शांति उद्घोष समस्त संसार को युद्ध की विभीषिका से बचाने में नितांत उपयोगी है। सारनाथ के निकट ऋषि पत्तन अथवा चौखंडी नामक स्थान पर बुद्ध का स्तूप है। यहीं पर उन्होंने अपना प्रथम उपदेश देकर ऐसे धर्म की नींव रखी जिसका विस्तार न सिर्फ भारत अपितु विश्व के अन्य देशों जैसे चीन,जापान में भी हुआ। उनका प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध है। धर्मचक्र प्रवर्तन के प्रतीक अशोक के एकाश्मक स्तंभ के शीर्ष भाग पर स्थित चौकी पर चार सिंह बने हैं, जो चारों दिशाओं में मुंह किये हैं।तथा 32 तीलियों वाला चक्र धारण किये हुए हैं।यह विश्व में मूर्ति विन्यास में अप्रतिम होने के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन हैं। धर्मचक्र प्रवर्तनाय को भारतीय संसद द्वारा प्रेरणा वाक्य के रूप में स्वीकार किया है। तथा स्वतंत्रता के उपरांत भारत सरकार ने राजकीय चिन्ह के रूप में भी इसे स्वीकार किया। आदि गुरु शंकर के वेदांत की परीक्षा भी इसी काशी में हुई थी।

मौर्य और गुप्त शासकों ने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधकर राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक एकता की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया। 12 वीं सदी में मुस्लिम शासन की स्थापना के बाद उत्तर भारत में महान शक्तिशाली सम्राटों का शासनकाल रहा। जिन्होंने स्थापत्य और वास्तुकला में रुचि लेते हुए विश्व विख्यात इमारतों का निर्माण करवाया। इनमें फतेहपुर सीकरी,आगरा में ताजमहल, एत्माद्दौला का मकबरा कला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। मुगल काल में साहित्य, संगीत, कला का विकास हुआ। हिंदी और उर्दू भाषा यहीं पर फली फूली। और हिंदी को भारत की राजकीय भाषा होने का गौरव मिला। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में तुलसीदास, कबीर दास, रैदास, सूरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिलीशरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञेय, महादेवी वर्मा जैसे लेखकों ने अपनी रचनाओं से देश को समृद्ध किया। उर्दू साहित्य में रहीम, रसखान, फिराक गोरखपुरी, जोश मलीहाबादी, अकबर इलाहाबादी, नजीर, वसीम बरेलवी,चकबस्त प्रमुख रहे।

संगीत का विकास गुप्त काल में हुआ। एक मुद्रा पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। सितार और तबले का विकास भी यही हुआ। तानसेन और बैजू बावरा जैसे विश्व प्रसिद्ध संगीतज्ञ मुगल बादशाह अकबर के समय में थे। भारत के प्रमुख मंदिरों के समीप निर्मित मस्जिद तथा उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर मछली का चित्र भारत की गंगा जमुनी तहजीब एवं सभी धर्मों में आपसी समन्वय व मेल मिलाप की भावना का सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। कालक्रम में भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई। तब औपनिवेशिक शासन के विरोध में वृहद स्तर पर प्रथम क्रांति 10 मई 1857 में मेरठ में हुई। जिसमें रानी लक्ष्मीबाई,झलकारी बाई, उदा देवी, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे और नाना साहब की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी।

उत्तर प्रदेश, भारत की सांस्कृतिक धरोहर की आत्मा है। जिसकी संस्कृति के संवहन में तत्युगीन महापुरुषों, आचार्यों, ऋषियों तथा विचारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो न सिर्फ भारत अपितु विश्व में इसे उत्कृष्ट स्थान प्रदान करता है। ■

अनुदान राशि के लिए भटकते राजस्थानी फिल्म निर्माता

● रामस्वरूप रावतसरे

राजस्थान कांग्रेस ने 2018 के विधान सभा चुनावों में अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण करने वाले निर्माताओं को प्रोत्साहन स्वरूप 25 लाख रूपये का अनुदान देगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के तीन बजट पेश किये लेकिन चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार राजस्थानी भाषा में निर्मित फिल्मों के लिए किसी प्रकार के अनुदान बजट की घोषणा नहीं की। जब फिल्म निर्माताओं ने उन्हें चुनावी घोषणा पत्र की याद दिलाई तब जाकर चौथे बजट में राजस्थानी भाषा फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान राशि दिये जाने की घोषणा की गई । मुख्यमंत्री की बजटीय घोषणा को अमल में लाने के लिए जिस प्रशासनिक तन्त्र को नियुक्त कर रखा है। वह अपनी कुण्डली ही नहीं खोल रहा है।

फिल्म निर्माता राजेन्द्र सिहं शेखावत के अनुसार राजस्थानी भाषा, कला, संस्कृति को लेकर बनने वाली फिल्मों के प्रोत्साहन लिए प्रदेश में मंत्री, मंत्रालय और अफसर नियुक्त हैं, ये सभी सरकार से मोटा वेतन पाते हैं, राजस्थानी फिल्मों के लिए प्री व्यू कमेटी भी बनी हुई है, फिर भी राजस्थानी फिल्मों को समय पर अनुदान नहीं मिल रहा है। फिल्म निर्माता निर्देशक शेखावत के अनुसार उनके द्वारा चन्द्र फिल्म्स प्रोडक्शन के बैनर तले बनाई गयी राजस्थानी भाषा की फिल्म ''बावळती'' को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से यू प्रमाण पत्र मिला हुआ है। इस फिल्म को 22 सितंबर 2021 को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ कला एवं संस्कृति विभाग सचिवालय जयपुर में जमा करवा दी थी। कला एवं संस्कृति मंत्री बी डी कल्ला ने नवंबर माह में उप समिति का गठन करके 11 दिसंबर 2021 तक फिल्मों का प्री व्यू देखने के निर्देश भी दिए थे।

इतना सब होने के बाद भी आज तक अनुदान मिलना तो दूर, उप समिति द्वारा फिल्मों का प्री व्यू तक नहीं देखा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कला एवं संस्कृति मंत्री बी डी कल्ला के सभी आदेश व निर्देशो पर अफसरशाही कुण्डली मार कर बैठी है। राजस्थानी फिल्म निर्माताओं द्वारा बार बार मुख्यमंत्री और मंत्री को निवेदन करने पर आदेश तो दिये पर उन आदेशों का आगे क्या हुआ इसकी कोई सुध नहीं ली है। यदि मुख्यमंत्री और मंत्री इस ओर ध्यान देते तो राजस्थानी फिल्मों को दिसंबर 2021 में ही अनुदान राशि जारी हो जाती।

इस संबंध में कला एवं संस्कृति विभाग के अनुभागाधिकारी से फिल्म निर्माता मिले तो उन्होंने इतना कह कर बात को समाप्त कर दिया कि समिति की बैठक नहीं हो रही है। ये ही बात उप समिति के मेंबर के सी मालू कह रहे हैं कि प्री व्यू समिति की बैठक नहीं हो रही है। बैठक कौन कराएगा यह भी समझ में नहीं आ रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और मंत्री के आदेश के बाद भी समिति, उप समिति की बैठक नहीं होना भी कई प्रकार के प्रशन खडे करता है। इनकी नकारात्मक कार्य प्रणाली से इस बात को भी बल मिलता है कि राजस्थानी भाषा, कला व संस्कृति को लेकर प्रशासनिक एवं राजनीतिक स्तर पर जिम्मेदार लोग कैसी मनोवृति को पाले हुए है।

राजस्थान में राजस्थानी भाषा को सरकारी कामकाज की भाषा बनाने के लिए बरसों से प्रयासरत संगठनों को आज तक सफलता नहीं मिलने के पीछे भी हमारा शासन तन्त्र है जो राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति के मुद्दे पर आंखें मूंदने के साथ साथ कानों को भी बन्द कर लेता है। चुनावों के समय इस प्रकार के मुद्दे उठाये जाते है। लेकिन सत्ता में आने के बाद ऐसे मुद्दे गोण कर दिये जाते है।

राजस्थानी फिल्मों को समय पर अनुदान राशि जारी नहीं होने से फिल्म निर्माता बहुत परेशान हैं। उनके सामने आर्थिक संकट की विकट स्थिति है। साथ ही सरकार की घोषणाएं भी झूठ का पुलंदा साबित हो रही हैं। निर्माता निर्देशक राजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी राजस्थानी फिल्मों को प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान देने के नाम पर 10 लाख की घोषणा की थी। भाजपा शासन में प्रशासनिक स्तर पर लम्बी जद्दोजहद के बाद 3 लाख का अनुदान मिला। पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे की अनुदान देने की घोषणा 70 प्रतिशत झूठी निकली, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई 25 लाख की घोषणा अभी तक 100 प्रतिशत झूठ है। क्या इनकी नीति और नीयत जनता को झूठे आश्वासन देने की ही रह गई है।

अब जानकारी में आया है कि कला एवं संस्कृति मंत्रालय राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थानी फिल्मों को अनुदान देने के लिए नई नीति बनाई है उसके अनुसार कार्य होगा। राजेन्द्र सिहं शेखावत के अनुसार यह सरकार नीति और नियम बनाने में ही अपना समय पूरा कर देगी। जैसा कि पहले होता आया है। तीन साल बीत ही चुके है। ये सरकार में बैठे लोग किसी प्रकार के अनुदान को देने में नियम, उप नियम का ऐसा मकड़ जाल बनाते है कि अनुदान लेने वालों की हिम्मत टूट जाती है, पर अनुदान नहीं मिलता। पाश्चात्य आबोहवा के चलते स्थानीय भाषा में फिल्म का निर्माण बहुत बड़ा जोखिम होता है। लेकिन अपनी भाषा एवं सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण रखने के लिए राजेन्द्र सिहं शेखावत जैसे कुछ उत्साही व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर होते हुए भी ये जोखिम उठाते है। ऐसे में प्रदेश गहलोत सरकार को चाहिए कि बिना किसी राजनीतिक लाभ हानि के ऐसे लोगों का समय समय पर उत्साहवर्धन के साथ आर्थिक सहयोग भी करें।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2022 के बजट में प्रदेश की जनता के लिए बहुत सी घोषणाएं की है, उसमें एक घोषणा राजस्थानी भाषा की फिल्मों को अनुदान देने की भी है। उम्मीद की जा सकती है कि इस घोषणा पर भी सकारात्मक रूप से प्रशासन द्वारा जल्द ही फिल्म निर्माताओं के पक्ष में निर्णय होगा। ■

फिर एक बार भगवा लहर

भाजपा ने अपने राष्ट्रवादी एजेंडे के साथ अपनी राजनीति को जो स्वरूप प्रदान किया है उसे समझने के लिए विपक्ष को अब उसकी गहराई में जाने की आवश्यकता है। भाजपा को सांप्रदायिक बताकर विपक्ष भारत की संस्कृति को नकार देता है जबकि भारत का सांस्कृतिक स्वरूप सनातन परंपरा से जुड़ा है और भाजपा ने इसी को अपनी राजनीति का आधार बनाया है। जो डीएनए भाजपा के अंदर दिखाई देता है वास्तव में वह भारत की सनातन संस्कृति का संस्कार है। जैसे ही कोई राजनीतिक दल इस संस्कृति को नकारता है तो जनता में उसकी प्रतिक्रिया होती है। केजरीवाल की सफलता में इस बात का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होने भारत के इस डीएनए के साथ छेड़छाड़ नहीं की। उन्होने अपनी राजनीति में भाजपा पर तो हमला किया किन्तु मंदिर जाने के साथ साथ सनातन परंपरा को नहीं भूले। केजरीवाल की छवि हिन्दू विरोधी नेता की न होना उनमे और अन्य विपक्षी नेताओं में मूलभूत अंतर पैदा करता है। केजरीवाल ने इसी आधार पर स्थानीय मुद्दों से समीकरण बैठाते हुये पंजाब में एक विशाल जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में वापसी कर 37 साल पुराना मिथक तोड़ा है। उत्तराखंड में भी यह धारणा खंडित हुयी है कि वहां हर चुनाव में सत्ता परिवर्तन हो जाता है। उत्तराखंड में पुष्कर धामी हालांकि स्वयं चुनाव हार गये हैं किन्तु उन्होने कांग्रेस की बदहाली का भरपूर फायदा उठाते हुये भाजपा की वापसी करा दी है। कांग्रेस की निर्णयहीनता और हरीश रावत के बुजुर्ग चेहरे की घटती लोकप्रियता ने उत्तराखंड में भाजपा को सीधा फायदा पहुचाया है। राज्यों के संदर्भ में देखें तो पिछले कुछ सालों से कांग्रेस नेतृत्व अब बेहद संकीर्ण दिख रहा है। चुनाव के पहले राहुल गांधी पंजाब में अमरिंदर सिंह पर भरोसा नहीं कर सके और न ही उत्तराखंड में हरीश रावत पर उनका विश्वास रहा। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस का कमजोर होना आप और भाजपा को मजबूत कर गया। उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत योगी की साफ सुथरी प्रशासनिक व्यवस्था और पिछली सरकारों की दंगों की छवि के कारण हुयी है। उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रबंधन न सिर्फ जीत की भूमिका निभा गया है बल्कि 2024 की विजय का आधार भी तैयार कर गया है। भाजपा का हर सूरत में विरोध करने वाला समूह भी उत्तर प्रदेश की हार से हताश है। भाजपा विरोधी यह खेमा इस जीत को लोकतन्त्र विरोधी बताकर अपने समर्थकों को उकसाने का कार्य करने लगा है। इस खेमे के शीर्ष पर बैठे लोगों का तो कुछ नही बिगड़ेगा किन्तु निचले स्तर के लोग उनके बहकावे में निश्चित तौर पर नुकसान उठाएंगे। 2022 में हारे हुये दल अगर 2024 में मोदी को परास्त करना चाहते हैं तो उन्हे मोदी की तर्ज पर पूरे पांच साल काम करना होगा। चुनाव के पहले सिर्फ छह महीने जनता के बीच का दिखावा लोगों को छलावा दिखता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी लगातार राष्ट्रियता का बोध जनता को करा रहे हैं। उनका हर सम्बोधन राष्ट्र को सबल बनाने और नये भारत के निर्माण पर होता है। जबकि विपक्षी दल अभी भी परिवारवाद से बाहर नहीं आ सके हैं। सिर्फ मोदी विरोध के द्वारा आत्ममुग्ध होकर मोदी विरोधियों को प्रसन्न तो किया जा सकता है किन्तु जीत के लिए जिस निरंतरता और समर्पण की राजनीति आवश्यक होती है, विपक्ष में उसका अभाव दिखाई दे रहा है।

● **अमित त्यागी**

पाँच राज्यों में हुये चुनाव के परिणाम व्यापक असर डालने वाले हैं। यह मोदी और भाजपा का जनता पर प्रभाव दर्शाते हैं। पंजाब को छोडकर बाकी चार राज्यों में भाजपा ने चुनाव प्रबंधन, कौशल, राजनीतिक समीकरण और कार्यकर्ताओं के बेहतर समन्वय के द्वारा जीत दर्ज की है। वैश्विक परिदृश्य जिस तरह से बदल रहा है उसमे पूरे विश्व में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता दिखने लगा है। उक्रेन और रूस की जंग ने पूरे विश्व को लगभग दो भागों में विभक्त कर दिया है। अमेरिका में ट्रम्प के जाने के बाद जिस तरह के समीकरण बने थे उसमे भारत में मोदी विरोध अचानक से तेज हो गया था। विपक्ष को लगने लगा था कि वह ट्रम्प की तर्ज पर मोदी को भी भारत में सत्ता से हटा सकता है। इस बीच जब 2021 में अप्रैल मई में कोरोना की दूसरी लहर आई तब जिस तरह से हाहाकार मचा उसमे सत्ता विरोधी भावना बलवती होने लगी। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल सपा को इसमे अपने लिए एक आशा की किरण दिखलाई दी। पूरे देश के विपक्षी दल एकजुट होकर 2022 में उत्तर प्रदेश से भाजपा को हटाने के क्रम में एकजुट हो गए। इस बीच किसान आंदोलन भी चल रहा था तो मोदी का वहां विरोध चल ही रहा था। यह विपक्षी दल योगी की मुस्लिम विरोधी छवि के द्वारा मुस्लिम वोट बैंक पर नजरें गड़ाए थे तो किसान आंदोलन के नाम पर जाटों और किसानो पर। इसके बाद ब्राह्मण विरोधी होने की हवा भी विपक्षियों द्वारा खूब उड़ाई गयी। लखीमपुर कांड भी प्रचारित

क्रांतिकारी व आमूलचूल बदलाव लाने वाले हैं विधानसभा चुनावों के परिणाम

छद्म हिंदुत्ववादियों, पत्तलकारों, कुबुद्धिजीवियों और अल्पसंख्यकवाद व जाति की राजनीति करने वाले दलों के प्रपंच और षड्यंत्रों को धता बताकर अंतत पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में सनातन संस्कृति, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, डबल इंजन की सरकार, लाभार्थी जाति के समर्थन और विकास के एजेंडे पर काम कर रही भाजपा चार राज्यों में फिर से अपनी सरकार बनाने में सफल हो गयी है तो दूसरी ओर सत्तारूढ़ कांग्रेस की अंतर्कलह, कुशासन, अकाली दल के सिरमौर बादल परिवार के भ्रष्टचार से तंग, भाजपा के देर से सक्रिय होने के कारण व किसान आंदोलन और खालिस्तान आंदोलन व मुफ्त योजनाओं के लालच में पंजाब की जनता नए चेहरों वाली आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से सरकार की डोर थमा बैठी।

सन 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए लिटमस टेस्ट माने जाने वाले इन चुनावों के परिणामों ने कोरोना संकट के कारण अतिशय दबाव व चुनौती झेल रही केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार को नई संजीवनी दी है।सन 2019 के लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद से ही विपक्षी दलों के साथ ही नौकरशाही, न्यायपालिका, मीडिया, अल्पसंख्यक समुदायों व बुद्धिजीवियों का एक वर्ग खुले और व्यापक स्तर पर मोदी सरकार के अनेक नीतिगत निर्णयों का हर सीमा से परे जाकर विरोध कर रहा था। विरोध के लिए विरोध को राजनीति के इस खेल का ये चुनाव परिणाम अंत कर देंगे ऐसी आशा है। क्रांतिकारी व आमूलचूल बदलावों वाले इन विधानसभा चुनावों के प्रभावों को आइए इन बिंदुओं से समझते हैं -

1) यह चुनाव परिणाम मोदी सरकार की नीतियों व नीतिगत फैसलों पर जनता की मुहर है और विपक्ष की अंधे विरोध की राजनीति को एक बड़ा तमाचा। अगर विपक्ष ने अपनी रणनीतियों में सकारात्मक बदलाव नहीं किया तो वह अप्रासंगिक होता जाएगा और सन 2024 में मोदी फिर से प्रचंड बहुमत से आ जाएंगे। अगर विपक्ष मोदी की नीतियों का समर्थन कर सकारात्मक व रचनात्मक भूमिका में आता है तो भी वह मोदी सरकार की नीतियों पर विपक्ष की मुहर लगने जैसा होगा और इसका लाभ भी मोदी को ही मिलेगा। निहितार्थ यह है कि अब लंबे समय तक देश में विपक्ष हाशिए पर ही रहेगा और अनेक राज्यों में भी सिकुड़ता जाएगा।

2) ये चुनाव धर्मनिरपेक्ष व अल्पसंख्यकवाद की राजनीति के सिमटने व सिकुड़ने का संकेत दे गए हैं। भारत में किसी भी दल को आगे बढ़ने के लिए बस अस्मिता,राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकास के साथ ही योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन और अति सक्रियता व संवेदनशीलता का मंत्र अपनाना होगा। ऐसे में मन मसोस कर नरम व छद्म हिंदुत्व अपनाने वाले दलों को प्रखर हिंदुत्व की ओर बढ़ना होगा और अल्पसंख्यकों को कट्टरवाद की राजनीति से निकल मुख्यधारा में आना होगा।

3) योगी सरकार का पुन चुना जाना संघ परिवार की नीतिगत जीत है और हिंदुत्व की प्रयोगशाला बने पच्चीस करोड़ की आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के प्रारूप को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होने पर जनता की मुहर है। संघ परिवार को मोदी के बाद योगी एक भविष्य के स्वाभाविक विकल्प के रूप में मिल गए हैं। बस अब आवश्यकता मोदी और योगी को आपसी संयम और सौहार्द बनाकर एक इकाई के रूप में आगे बढ़ने की है तो अमित शाह को चेक-बैलेंस के खेल से दूर रहने की है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाजपा व संघ परिवार गुटबाजी का शिकार जो बिखर सकता है।

4) दुनिया व प्रकृति व्यापक बदलावों से दो चार है । इन बदलावों ने उद्योग-व्यापार के परंपरागत तरीकों को बदलकर रख दिया है। तकनीक की बढ़ती दखल रोजगार काम कम कर रही है । ऐसे में जनकल्याणकारी योजनाओं व मुफ़्त बांटने के खेल राजनीति की आवश्यकता नहीं मजबूरी बन गए हैं। इस सच्चाई को समझकर जिस भी राजनीतिक दल ने इन योजनाओं को ईमानदारी से जमीन पर क्रियान्वित किया है वे दल ही अब सफल हो सकते हैं यह भी इन चुनाव परिणामों का निहितार्थ है।

5) इस चुनाव परिणामों के यह भी निहितार्थ हैं कि कांग्रेस पार्टी अब डूबता जहाज नहीं रही वरण डूब चुकी है और अगले लोकसभा चुनावों तक पूरी तरह समाप्त और अप्रासंगिक हो जाएगी।

6) भगवंत मान के पूर्ण राज्य पंजाब का मुख्यमंत्री बनते ही वे अधूरे राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी की जगह प्रतिद्वंदी बन जाएंगे। मनीष सिसोदिया भी दिल्ली के मुख्यमंत्री की गद्दी पर नजर गड़ाए है। अगर केजरीवाल पार्टी का विस्तार राष्ट्रीय स्तर पर करने के लिए भागदौड़ करेंगे तो उनकी पकड़ दिल्ली व पंजाब दोनो पर काम होती जाएगी और विपक्षी नेता मोदी के मुक़ाबले उनके नेतृत्व को स्वीकार करेंगे इसकी संभावना भी काम ही है। देखना दिलचस्प होगा कि वे इस चुनौती का सामना किस प्रकार कर पाएंगे।

7) अनेक राज्यों में त्रिकोणीय मुकाबले व सहयोगी दलों के साथ से सरकार बनाने वाली भाजपा अब दोतरफा लड़ाई में भी जीत रही है

और बिना सहयोगियों के भी । यह नई भाजपा है जो नए प्रकार के संगठन व सूत्रों से संचालित है और हिंदुत्व पर खुलकर मुखर हो चुकी है । ऐसे में आरएसएस की भूमिका व स्वरूप सिमटता जा रहा है।

8) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर द्रुत गति से हो रहे परिवर्तनों का भी भारतीय राजनीति पर प्रभाव पड़ना तय है। आने वाले समय में नाटो देशों की भूमिका भारत की राजनीति व आंतरिक मामलों में सीमित जो जाएगी। भारत रूस व चीन से भी संतुलन बनाएगा या फिर तटस्थ राष्ट्रों का गुट बनाएगा। ये परिवर्तन देश की राजनीति व समीकरणों को बदल कर रख देंगे।

9) सन 2024 के लोकसभा चुनावों में मोदी के खिलाफ ममता, केजरीवाल, राहुल। व पावर के साथ ही अब स्टालिन, केसीआर, तेजस्वी व अखिलेश भी दावेदारी ठोकेंगे। अगर ये नेता संयुक्त मोर्चा बनाने व स्पष्ट नेतृत्व का चयन करने में विफल रहे तो अपने अपने राज्यों में भी बड़ा नुकसान झेलेंगे।

10) अति आत्मविश्वासी भाजपा अब झारखंड व महाराष्ट्र में जोड़तोड़ या गठबंधन से अपनी सरकार बनाने की पूरी कोशिश करेगी। आगामी हिमाचल व गुजरात चुनावों में भी उसकी वापसी तय है।

11) राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव भाजपा के मिशन - 2024 व चप्पा चप्पा भाजपा के नारे को जमीन पर उतारने का उपकरण बन सकते हैं। नीतीश को राष्ट्रपति बना बिहार में भाजपा नेतृत्व वाली सरकार बनाने और मायावती को उप राष्ट्रपति बना यूपी में दलित वोट दिलवाने व आगे दलित वोटों को अपने पक्ष में करने का दांव भी चला जा सकता है। समीकरण बदलने पर इन पदों के लिए थावर चंद गहलोत व आरिफ मोहम्मद खान के नाम आगे बढ़ाए जा सकते हैं।

12) केंद्र व भाजपा शासित राज्यों में संघ अजेंडे से जुड़े बड़े नीतिगत व प्रशासनिक निर्णय लिए जाएंगे जिससे हिंदुत्व व सुशासन के एजेंडे को धार दी जा सके। ये बदलाव लोकसभा के पुनर्गठन, नए राज्यों का गठन, समान नागरिक संहिता, नए रूप में सीएए व एनआरसी, संशोधित कृषि कानूनों, एक राष्ट्र एक चुनाव, केंद्र व राज्यों में व्यापक प्रशासनिक व न्यायिक सुधार, जनसंख्या नियंत्रण नीति, किसान सम्मान निधि में भारी बढ़ोतरी, शिक्षा,स्वास्थ्य व कृषि नीतियों में भारत परक बदलाव, निजीकरण,आत्मनिर्भर भारत अभियान की तीव्रता से लागू करने के क्षेत्र में हो सकते हैं।

- अनुज अग्रवाल

हुआ। दिल्ली के किसान आंदोलन की आड़ में खलिस्तान समर्थक भी मैदान में कूद पड़े। कनाडा से मिली मदद से पंजाब में आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ा। यहां तक की कनाडा के प्रधानमंत्री टुडो ने भी किसान आंदोलनकारियों का समर्थन किया। किसान आन्दोलन का फायदा आप को पंजाब में हुआ और उसने वहां विशाल बहुमत से सरकार बनाई। अपनी फ्री स्कीम से सत्ता में आई आप ने हास्यास्पद तरीके से आते ही केंद्र सरकार से वित्तीय मदद मांगी है ताकि वह अपनी योजनाएं पूर्ण कर सके।

उधर कनाडा के प्रधानमंत्री टूड़ों भी कनाडा में हड़ताल में फंसे हुये हैं। यानि कि विरोध के स्वर के द्वारा पंजाब में तो सत्ता आ गयी है किन्तु कनाडा में प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में आ गयी है। राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जिस तरह सपा को परास्त किया है उसका ज़्यादा महत्व है। उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा था जैसे भाजपा को सत्ता विरोधी बड़ी लहर का सामना करना पड़ेगा। इसका आधार किसान आंदोलन, लखीमपुर की घटना, हाथरस प्रकरण, ब्राह्मण विरोधी मानसिकता, खुशी दुबे प्रकरण आदि को बनाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में कोविड महामारी के दौरान उपजी परिस्थिति के बीच भाजपा को मिली जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ माह के भीषण दौर पर विपक्ष पांच साल के कार्यकाल को फ्लॉप साबित करना चाह रहा था। जनता ने पांच साल जो कानून व्यवस्था में सुधार और सुशासन को महसूस किया उस पर वोट दिया और भाजपा को इसका सीधा लाभ मिला। किसान आंदोलन के नाम पर विरोध भी विपक्ष को फायदा नहीं पहुंचा सका। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट बाहुल्य इलाकों में भी भाजपा विरोधी कथित लहर नहीं दिखी। सपा और रालोद का गठबंधन न सीटें जीत सका न भविष्य के लिए एकजुट दिख सका। मोदी द्वारा कृषि कानून की वापसी, किसानों से माफी और सम्मान निधि के नाम पर किसानों को दिया गया धन किसानों को यह भरोसा दिलाने में कामयाब रहा कि मोदी किसानों के लिए लगातार सोच रहे हैं।

लचर विपक्ष एवं परिवारवाद की असफल राजनीति

परिवारवादी राजनीति में परिवार प्राथमिकता होती है। यहां राष्ट्रहित उपेक्षित रहता है।चूंकि, परिवार के हित को साधकर ही मुद्दों का निर्धारण होता है इसलिए चुनाव आधारित व्यवस्था दोषपूर्ण हो जाती है। संविधान सभा में 15 जून 1949 के दिन पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था कि दोषपूर्ण चुनाव से लोकतन्त्र विषाक्त होगा। आज भी अगर देखें तो आमजन चुनाव में परिवार आधारित दलों की संख्या से निराश हैं। परिवारवादी दलों में राष्ट्रिय अध्यक्ष के चुनाव नहीं होते हैं। वह आजीवन अध्यक्ष बने रहते हैं। जैसे कांग्रेस ने हार के बाद अपने सभी प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा ले लिया है। यानि कि हार की जिम्मेदारी राष्ट्रिय नेतृत्व ने न लेकर प्रदेश नेतृत्व पर डाल दी है। सपा में कांग्रेस से बेहतर हालात हैं। वहां

अखिलेश यादव के सपने और वायदे !

के. विक्रम राव

अपने चुनाव अभियान के दौरान गत तीन महीनों में अखिलेश यादव ने यादगार, तीखे, व्यंगात्मक और नुकीले बयान दिये थे। इसे संकलित कर किसी प्रकाशक को पुस्तक के रुप में छापना चाहिये। एक दस्तावेज होगा। यह पूर्व मुख्यमंत्री अपरिमित आत्मविश्वास से आप्लावित थे, जब वे बोले थे (25 नवम्बर 2021) कि : 'भाजपा अपनी ऐतिहासिक पराजय की साक्षी बनने जा रही है।' मगर अब बनारसी (मोदी के) वोटर भोजपुरी में कह रहे हैं कि : 'खेला हो गइल बा !' मोदी के लोकसभा क्षेत्र में ममता बनर्जी ने घोषणा की थी, 'खेला होबे' और फुटबाल फेंका था सभा में। मगर गोल मोदी ने मार दिया। योगी ने भी। अखिलेश को एक और आशा थी। उन्होंने सांसद मोदी को धार्मिक आचार का बोध भी कराया (14 दिसम्बर 2021) कि मनुष्य अपने अंतिम दिवस काशी में बिताना चाहता। यह सुझाव मोदी के काशी प्रेम की बावत था।

अपने नामांकन पत्र के साथ योगी ने जो लेखाजोखा दर्ज कराया था कि उनके पास मोटर कार नहीं है। सांसद की पेंशन से ही खर्च चलता है। उनकी संपत्ति में गत पांच वर्षों में 61 प्रतिशत वृद्धि हुयी है। मोबाइल, हथियार तथा कुंडल वही पुराने है। जबकि अखिलेश की कुल संपत्ति चालीस करोड़ और चार लाख है। इनोवा तथा फार्चुनर मोटरे हैं। वे पांच साल बिना किसी पगार के रहे।

अपनी अयोध्या यात्रा (5 दिसम्बर 2021) पर अखिलेश ने कहा था : 'मेरे घर में भगवान राम का मंदिर है, वहां मैं दर्शन करता हूं। जब अयोध्या में मंदिर बन जाएगा, तो वहां भी जाऊंगा और दक्षिणा भी दूंगा।' अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि, 'ये चंदा मांगने की जो व्यवस्था है वह हिन्दू धर्म में नहीं थी। ऊपर से उस चंदे में भी लोगों ने चोरी कर ली।'

हालांकि यह लोहियावादी नेता लोहिया के जन्मस्थान के निकट अयोध्या गया। चुनावी रैली भी की। हनुमानगढ़ी में भी गया। गदा लहरायी। किन्तु जन्मभूमि के दर्शन करने नहीं गये। इतने नजदीक फिर भी कितने दूर ? वहां कभी जहीरुद्दीन बाबर की मस्जिद थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक निर्णय के बाद विवाद खत्म हो गया था। धन्नीपुर में नयी मस्जिद बन रही है। सरकारी कोष से भूभाग तथा राशि दी जा चुकी है। फिर भी वोट बैंक के फिसलने की आशंका से रामलला की जन्मभूमि को नहीं देखा। इतने सेक्युलर ? पर चाचा रामगोपाल यादव ने कहा था (3 जनवरी 2022) कि सपा सरकार बेहतर राममंदिर बनवायेगी।

अखिलेश का दावा रहा कि अयोध्या और मथुरा के विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशी नामित करने के बजाये भाजपा ने योगी को उनके मठ गोरखपुर क्षेत्र को भेजा (16 जनवरी 2022)। व्यंग था कि 'योगी को घर में बैठा दिया।'

अपने पूर्वज मथुरावासी श्रीकृष्ण पर अखिलेश ने कहा था (3 जनवरी 2022) मेरे सपने में श्रीकृष्णजी आते हैं। कल भी आये थे। रोज आते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हारी सरकार बनने जा रही है।

मगर कृष्णभक्त लोहिया के इस चेले ने यह नहीं बताया कि कृष्ण ने उनसे सपने में शर्त रखी थी कि : मुख्यमंत्री बनते ही औरंगजेबी मस्जिद की जगह मेरा भव्य मंदिर बनवा देना।

अखिलेश अपनी विभिन्न चुनावी रैलियों में पुकार-पुकार कर कहते रहे कि चुनाव हारने के बाद बाबा अपने बुल और डॉग से खेलेंगे, (4 फरवरी 2022)। रामगोपाल यादव ने तो शुद्ध देसी टिप्पणी की थी : योगी अब मठ में गुल्ली-डंडा खेलेंगे। उनका कथन था कि स्थलों के नाम बदलने वालों को जनता ही बदल देगी (26 नवम्बर 2021)।

अखिलेश ने यह भी कहा कि योगी सरकार ने कुछ काम नहीं किया। वह पूरी तरह फेल हो चुकी है और उसे पास कराने के लिये दिल्ली से आ रहे लोग चुनाव में कामयाब नहीं होंगे।

विजय के प्रति पूर्णतया आश्वस्त अखिलेश ने क्रमशः कहा था : मतदान के दो चरणों के बाद (19 फरवरी 2022) सपा गठबंधन के विजयी (विधायक) प्रत्याशियों की संख्या का पार्टी सैकड़ा लगा देगी। चौथे चरण तक दोहरा शतक होगा। (19 फरवरी 2022) हालांकि 10 मार्च को सपा सिर्फ 111 पर ही जम गयी।

अखिलेश को यकीन था कि चुनावी हार के पश्चात अलीगढ़ी ताला भाजपा कार्यालय में लग जायेगा। मगर भाजपा कार्यालय में विशाल भीड़ ने होली खेली। उधर करहल विधानसभा क्षेत्र में अखिलेश के डेढ़ लाख वोटरों से विजय अपेक्षित थी । पर केवल आधे से ही जीते। मगर उधर योगी की जीत गोरखपुर से सवा लाख वोटों से भी अधिक रही।

जब पत्रकार समूह लिख रहे थे कि मुफ्त राशन तथा सुशासन के कारण भाजपा बहुमत पायेगी तो अखिलेश ने भी घोषणा कर दी थी कि उनकी सरकार पांच वर्षों तक पांच किलो मुफ्त राशन तथा बिजली देगी (1 मार्च 2021)। खैर इसकी नौबत ही नहीं आयी।

तो आखिर सपा हारी क्यों ? अगर नरेन्द्र मोदी की माने (22 फरवरी 2022) तो अखिलेश ने मुस्लिम बेटी और महिलाओं पर ध्यान नहीं दिया। तलाक, हलाला और बुर्का से पीड़ित स्त्रियों को मोदी ने खुली सांस दिलायी। निजात भी।

माना कि मुसलमानों ने एक मुश्त वोट साइकिल को दिये। मगर यादवों ने एक तबके ने कमल खिलवाया। अतिपिछड़ी जातियां भाजपाइयों के साथ आ गयीं। अर्थात MY वाला नियम भाजपा पर लागू हुआ M अर्थात मोदी तथा Y मतलब योगी।

जो कसर बाकी थी वह अखिलेश ने मोहम्मद अली जिन्ना तथा सरदार पटेल को एक साथ स्वाधीनता सेनानी वर्णित कर डाला, (1 नवम्बर 2021)। भारत के खूनी विभाजन तथा लाखों निर्दोष हिन्दुओं का संहार करने वाले जिन्ना को हर भारतीय हेय दृष्टि से देखता है। वोटरों ने शायद इसीलिये अखिलेश को भी देख लिया।

- के विक्रम राव

अनुपम मिश्रा

योगी सरकार के लिए 10 बड़ी चुनौतियां

1. छुट्टा जानवर से निजात दिलवाना : 2017 में सरकार बनते ही योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी अवैध स्लॉटर हाउस को बंद करने आदेश दिया। सरकार की सख्ती का असर भी दिखा और देखते ही देखते सभी बड़े स्लॉटर हाउसों पर ताला पड़ गया। हालांकि, इसकी वजह से सड़कों पर गो-वंश छुट्टा घूमने लगे। सरकार के पास इनके पालन-पोषण के लिए कोई उचित प्लान नहीं था। गांवों में किसानों की फसलें चौपट होने लगीं। शहरों में सांड के चलते सड़क हादसे होने लगे। भूख और प्यास से बौखलाए कई छुट्टा पशु लोगों पर हमला करने लगे। विपक्ष ने चुनाव में इसे मुद्दा बनाया। इसी वजह से सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम और सभी मंत्रियों को सार्वजनिक मंच से कहना पड़ा कि अबकी सरकार में आएंगे तो इसका उचित प्रबंध करेंगे। प्रधानमंत्री ने गो-वंश से कमाई का प्लान पेश करने तक की बात कही।

2. सरकारी भर्ती : सरकारी भर्तियां योगी सरकार के लिए चुनौती बन सकती हैं। पिछली सरकार में कुछ भर्तियों के पेपर आउट हुए तो कुछ में देरी होने से युवाओं ने कई जगह प्रदर्शन किए। विपक्ष ने युवाओं के रोष को देखते हुए अपने चुनावी घोषणा पत्र में सरकारी नौकरी को लेकर कई वादे किए। हालांकि, इसके बाद योगी सरकार सत्ता में वापसी करने में सफल रही। योगी नई सरकार में इस मुद्दों का हल निकालने की पूरी कोशिश करेंगे।

3. सड़कों का गड्ढा : बीते पांच साल में राज्य में कई फ्लाईओवर, अंडरपास, हाईवे बने हैं। हालांकि, गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा पूरा नहीं हो पाया। शहरों के अंदर की सड़क की हालात भी खराब रहीं। इस बार चुनाव में ये मुद्दा भी खूब विपक्ष ने उठाला। नई सरकार में योगी गड्ढा मुक्त सड़क का वादा पूरा करने की कोशिश करेंगे।

4. स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना : यूं तो कोरोना ने दुनिया के बड़े-बड़े देशों को नुकसान पहुंचाया। स्वास्थ्य मामलों में टॉप पर रहे देश भी कोरोना के दंश को नहीं झेल पाए। यूपी में भी इसका काफी असर देखने को मिला। कोरोना की दूसरी लहर में अस्पतालों में बेड की कमी, डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की कमी, ऑक्सीजन की कमी ने सरकार को काफी परेशान किया। चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा खूब उठा। सरकार ने 2017 में वादा किया था कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे। काफी हद तक इसपर काम भी हुआ, लेकिन अभी काफी बाकी है। दोबारा सरकार बनने पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की काफी बड़ी चुनौती है।

5. प्रदेश को कर्ज से उबारना : यूपी पर इस वक्त आठ लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। कोरोनाकाल में ये कर्ज बढ़ा है। अब इस कर्ज से प्रदेश को उबारने की चुनौती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे पर होगी। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस बार भाजपा ने कई बड़े चुनावी वादे किए हैं। इसमें कॉलेज जाने वाली छात्राओं को मुफ्त स्कूटी, दो करोड़ युवाओं को मुफ्त लैपटॉप-टैबलेट, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, संविदा कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी जैसे वादे शामिल हैं। इन्हें पूरा करने के लिए सरकार को भारी-भरकम वित्तीय मदद की जरूरत होगी। पहले से ही यूपी पर आठ लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। ऐसे में इन वादों को पूरा करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना पड़ेगा।

6. महंगाई को काबू करना : पेट्रोल-डीजल, गैस के दाम तो लगातार बढ़ ही रहे हैं, लेकिन यूपी में भी बिजली, पानी के दाम सातवें आसमान पर हैं। चुनाव में भी इसका बड़ा असर देखने को मिला। इसी वजह से भाजपा ने सस्ती बिजली, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली जैसे वादे किए। अब योगी सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती होगी कि वो अपने वादे पर अमल करें।

7. बेरोजगारी दूर करना : बेरोजगारी का मुद्दा भी चुनाव प्रचार के दौरान हावी था। कोरोना के दौर में प्रदेश में बेरोजगारी का दर भी बढ़ी है। अब योगी सरकार के सामने बेरोजगारी दूर करके वापस सभी को रोजगार मुहैया कराने की बड़ी जिम्मेदारी है।

8. गठबंधन दलों को संतुष्ट रखना : 2017 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। ओम प्रकाश राजभर मंत्री भी बनाए गए, लेकिन दो साल में ही वह बगावत पर उतर आए। भाजपा सरकार पर कई तरह के आरोप लगाने लगे। 2019 से पहले वह भाजपा से अलग भी हो गए। इस बार अपना दल (एस) और निषाद पार्टी के साथ भाजपा गठबंधन को साधे रखने की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर होगी।

9. विपक्ष को काउंटर करना : 2017 के मुकाबले इस बार विपक्ष मजबूत हुआ है। इसके चलते वो ज्यादा आक्रमक भी होगा। विधानसभा में खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे। मजबूत विपक्ष भाजपा सरकार के सामने लगातार चुनौती पेश करेगा।

10. कानून व्यवस्था दुरुस्त करना: अगर ये कहा जाए कि विपक्ष के सारे वादे भाजपा के इस इकलौते मुद्दे ने ध्वस्त कर दिया तो गलत नहीं होगा। पूरे पांच साल योगी आदित्यनाथ सरकार ने डंका बजाकर कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की बात कही। खुले मंच से योगी कहते रहे कि या तो अपराधी यूपी छोड़कर भाग जाएं, या फिर उन्हें यूपी पुलिस ऊपर पहुंचा देगी। इस बार भी योगी सरकार के कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की चुनौती होगी।

- लेखक आईबीएन-7 यूपी-उत्तराखंड न्यूज चैनल के संपादक हैं

केजरीवाल के करोड़पति अपराधी प्रेम की राजनीति

जनता से अरविन्द केजरीवाल का एक और वायदा खिलाफी, आम जनता से एक और झूठ का पर्दाफाश। अब केजरीवाल आम आदमी के पैरवीकार नहीं रहे, अब वे खास और पैसे वाले के पैरवीकार हो गये हैं। आम आदमी पार्टी में गरीब और फटेहाल तथा संघर्षशील व्यक्ति की अब जगह शायद नहीं होगी। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो फिर पंजाब का करोड़पति और अपराधी मानसिकता के विधायकों की सूची देख लीजिये, आम जनता का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले अरविन्द केजरीवाल के करोड़पति और अपराधी प्रेम के तथ्य देख लीजिये। पंजाब में आम आदमी के 92 विधायकों में से 63 विधायक करोड़पति हैं। आम आदमी पार्टी का एक विधायक कुलवंत सिंह घोषित तौर पर 238 करोड़ का स्वामी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित 11 में से 9 मंत्री भी करोड़पति हैं। इसके साथ ही साथ पंजाब के आम आदमी के 50 प्रतिशत विधायकों पर किसी न किसी तरह का मुकदमा जरूर दर्ज है।

पंजाब में हुआ सत्ता परिवर्तन और आम आदमी पार्टी की मिली सफलता के शोर में अरविन्द कजेरीवाल के करोड़पति और अपराधी प्रेम की कहानी दब गयी, इस पर कोई गभीर बहस नहीं हुई। जबकि निश्चित तौर पर करोड़पति और अपराधी प्रेम पर गंभीर बहस होनी चाहिए थी। अरविन्द केजरीवाल भी अन्य पार्टियों की तरह ही राजनीति शुरू कर दी है, वैकल्पिक राजनीति, ईमानदार और नैतिक राजनीति देने का उनका वायदा अब छलावा साबित हुआ है। झूठ के बल पर सत्ता हासिल करना और मुफ्त में कुछ रियायतें बांट कर सत्ता हासिल करने के मामले केजरीवाल चैम्पियन साबित हो रहे हैं।

करोडपति और अपराधी मानसिकता के राजनीतिज्ञ कभी भी जनपक्षीय नहीं होते हैं, ऐसे किस्म के राजनीतिज्ञों का सीधा मतलब अपनी तिजोरी को और भी भरना तथा राजनीति को समाज सेवा की जगह पैसे कमान का हथकंडा बना देना होता है। पंजाब सीमावर्ती प्रदेश है, पंजाब पाकिस्तान के निशाने पर है, पंजाब में पाकिस्तान की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। खालिस्तानी आतंकवाद लौटने की कोशिश में है। पंजाब एक बार फिर से आतंकवाद और हिंसा की ज्वालामुखी पर बैठा हुआ प्रतीत हो रहा है। पंजाब कर्ज में भी डूबा हुआ है। पंजाब के किसानों की समस्याएं भी बहुत गंभीर है, इसके अलावा पंजाब नशे के व्यापार में भी डूबा हुआ है, नशे में पंजाब के

युवकों की जवानी समाप्त हो रही है, नशे पर उड़ता पंजाब नामक फिल्मी बनी थी और यह फिल्म बहुत ही धमाल मचायी थी। पंजाब को निश्चित तौर पर एक ईमानदार राजनीतिक सरकार चाहिए जो पंजाब को विकास और उन्नति के मार्ग पर ले जाये।

सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि लोग करोड़पति कैसे बनते हैं? क्या खून और पसीने की कमाई से करोड़ति बनते हैं? क्या कोई ईमानदारी से करोड़ति बनते हैं? क्या कोई नैतिकता से करोड़पति बनते हैं? क्या कोई करोड़पति राजनीति में आने के बाद अपनी तिजोरी और भी भरने का हथकंडा नहीं अपनाता है? सच कौन नहीं जानता है। सच यह है कि कोई खून और पसीने की कमाई से करोड़पति नहीं बनता है, कोई नैतिकता और ईमानदारी से करोड़पति नहीं बनता है? करोड़पति और अरबपति बनने वाले निश्चित तौर पर भ्रष्टचार का सहारा लेते हैं, सरकारी राजस्व चोरी करने का अपराध करते हैं, नैतिकता और ईमानदारी को हाशिये पर रखकर करोडपति बनते हैं। अपराध के जरिये भी करोड़पति बनते हैं। अपराधों में सिर्फ लूट-डकैती ही शामिल नहीं होती है बल्कि हत्या और अपहरण भी शामिल है। शराब की तस्करी और शराब का अवैध कारोबार से भी लोग करोड़पति बनते हैं। सरकारी बैंकों की लूट से भी करोड़पति बनते हैं। बहुत सारे लोग सरकारी बैंको के कर्ज लेकर बैठ जाते हैं और बैकों के कर्ज को दूसरे कारोबार में ट्रान्सफर कर मालोमाल बन जाते हैं। देश में बड़े पैसे वाले जैसे अडानी और अंबानी पर भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। विजय माल्या सरकारी बैंकों का अरबों रूपये डकार गया। विजय मल्या पैसे के दम पर विधायकों को खरीदकर राज्य सभा में पहुंच गया। राज्य सभा में पहुच कर विजय मल्या अपनी संपत्ति को बढ़ाने और सरकारी धन के लूट से बचने के लिए केन्द्रीय सरकार से जुगाड़ भिड़ाने का काम किया।

एक प्रश्न यह है कि करोड़पति और अपराधी मानसिकता के लोग राजनीतिक पार्टियों से चुनाव लड़ने का टिकट कैसे प्राप्त कर लेते हैं? आम तौर पर माना जाता है कि चुनाव लड़ने का टिकट उसी कार्यकर्ता को मिलता है जिसकी संघर्ष की कहानी प्रेरक होती है, जिसने जनता के लिए संघर्ष कर अपना और अपने परिवार की जिंदगी आग में फूंक देता है। पर ऐसी परम्परा का अब अवसान हो चुका है। करोड़पति और अपराधी मानसिकता के लोगों के पास इतना समय ही नहीं होता है कि वे जनपक्षीय राजनीति का हिस्सा बन सके, जनता के लिए संघर्ष करें। सीधे तौर पर अपराधी और करोड़पति मानसिकता के लोग राजनीतिक पार्टियों से टिकट खरीद लेते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान ही आम आदमी पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगा था, हंगामा भी हुआ था। आम आदमी पार्टी के प्रभारी राघव चड्ढा की पिटाई भी हुई थी।

केजरीवाल वैकल्पिक राजनीति के चेहरे थे। भ्रष्टचार विरोधी चेहरे थे। इन्होंने देश के युवाओं को ईमानदार और नैतिक राजनीति का एक सपना दिखाया था। राजनीति को आम आदमी के करीब लाने का सपना दिखाया था। इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखा था। ईमानदारी और नैतिकता के नाम पर ही इन्हें दिल्ली में सत्ता मिली थी। प्रारंभिक दौर में दिल्ली में आम आदमी इनकी प्राथमिकता में थे। आम आदमी की इनकी पार्टी पर आधिपत्य था। पर दिल्ली में सरकार बनने के साथ ही साथ अरविन्द केजरीवाल ने गिरगिट की तरह रंग बदला। सबसे

पहले तो उन्होंने उस अन्ना को भूला दिया, जिस अन्ना के बल पर इन्होंने सत्ता हासिल की थी। फिर अपने संघर्ष के साथियों जैसे कुमार विश्वास और योगेन्द्र यादव जैसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। कुमार विश्वास और योगेन्द्र यादव जैसे नेता केजरीवाल पर लोकतांत्रिक ढंग से काम करने के लिए दबाव डालने का काम करते थे। दो ऐसे लोगों को इन्होने राज्यसभा में भेज दिया जो आम आदमी पार्टी के कैडर कभी नहीं थे, जिनकी गिनती साधारण और आम आदमी में नहीं होती थी, ये खास आदमी थे, धनपशु थे। इस पर बवाल खड़ा हुआ था और राज्यसभा का टिकट बेचने का आरोप भी लगा था। जब किसी धनपशु को राज्य सभा में भेजा जाता है तो यह मान लिया जाता है कि इसमें पैसे का खेल हुआ होगा।

अरविन्द केजरीवाल ने जितनी वादाखिलाफी की है, जिस तरह के रंग बदले हुए हैं उसकी मिसाल भारतीय राजनीति में मिलनी मुश्किल है। बिना प्रमाण के इन्होंने नितिन गडकरी पर आरोप लगाये,अरूण जेटली पर आरोप लगाये। शीला दीक्षित पर आरोप लगाये। उस समय अरविन्द केजरीवाल ने कहा था कि शीला दीक्षित के खिलाफ उसके पास सैकड़ों पन्ने के भ्रष्टाचार के आरोप है। पर उन्होंने शीला दीक्षित के तथाकथित भ्रष्टाचार के तथ्य कभी जाहिर नहीं किये। जब मामला अदालत में गया और तथ्य प्रस्तुत करने की बात सामने आयी तो फिर अरविन्द केजरीवाल ने बेशर्म की तरह माफी मांगने की फेहरिस्त अपनायी। उसने नितिन गडकरी से माफी मांगी, अरूण जेटली से भी माफी मांगी। उसने नशे के व्यापार संबंधित आरोपों पर भी माफी मांगी। इसलिए राजनीति में केजरीवाल द्वारा आम आदमी के दमन और करोड़पति-अपराधी प्रेम को कई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए।

करोड़पति और अपराधी प्रेम के सहारे पंजाब का विकास नहीं हो सकता है। दिल्ली की तरह पंजाब की राजनीति आसान नहीं है। दिल्ली का अधिकतर खर्च केन्द्र सरकार वहन करती है। दिल्ली कोई राज्य नहीं है। राज्य का दर्जा है। इसके अलावा चुनावी योषनाओं के अनुसार अतिरिक्त राजस्व की जरूरत होगी? अतिरिक्त राजस्व कहां से जुटायेंगे? सरकारी राजस्व का भी बंदरबांट हो सकता है। करोड़पति और अपराधी मानसिकता के विधायक सरकारी राजस्व का बंदरबांट करेंगे, लूटमार करेंगे, गैर कानूनी धंधों को बढ़ावा देंगे। जिन करोड़पति विधायकों का कारोबार है वे करोड़पति विधायक अपने कारोबार का संरक्षण देने के लिए सरकारी कानूनों को उल्लंघन करेंगे।

-आचार्य श्री विष्णुगुप्त

पंजाब में आप सरकार के आगे हैं कई चुनौतियां

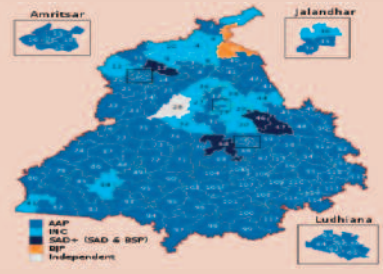

प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आयी आम आदमी पार्टी ने जनता से वादे तो बहुत बड़े कर दिये हैं किन्तु उसके लिए धन उसके पास नहीं है। पंजाब पर 3 लाख करोड़ रुपये का कर्ज सबसे बड़ी चुनौती है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा सरकार को प्रदेश का खर्च और योजनाएं चलाने के लिए 2025 तक 3.73 लाख करोड़ एवं 2028-29 तक 6.33 लाख करोड़ का कर्ज लेना होगा। पंजाब सरकार ने विधायकों की पेंशन बंद करके एक बड़ा प्रशासनिक फैसला ले भी लिया है। इसके द्वारा आप के विधायकों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप पहली बार सत्ता में आयी है। अब मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार से प्रदेश की जनता की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। चुनाव के दौरान आप के वादे परिकल्पना पर आधारित है जिसके अनुसार भ्रष्टाचार, शराब और रेत माफिया खत्म करके जो राजस्व आएगा, उससे वादे पूरे किए जाएंगे। हर साल राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व का 40 फीसदी हिस्सा कर्ज और उसका ब्याज चुकाने में चला जाएगा। वहीं, पिछली कांग्रेस सरकार पावरकॉम को दिए जाने वाले बिजली सब्सिडी के 9600 करोड़ रुपये भी नई सरकार के सिर छोड़ गई है, जिसका भुगतान करने के अलावा आप सरकार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली के अपने वादे के लिए 5000 करोड़ रुपये सब्सिडी राशि के तौर पर देने होंगे।

इसके अलावा अब तक की गई घोषणाओं के तहत 35000 युवाओं को नियमित नौकरी से भी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। अब तक सरकार के कुल राजस्व का 35 फीसदी हिस्सा वेतन-भत्ते और पेंशन पर खर्च हो जाता है। नई नियमित भर्ती इस खर्च में भी इजाफा करेगी। पंजाब में शिअद-भाजपा गठबंधन सरकार 10 साल के शासन के बाद 2017 में 1.82 लाख करोड़ का कर्ज छोड़ गई थी। इसमें सीसीएल का 11000 करोड़ भी शामिल था, जिसे गठबंधन सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में केंद्र से माफ कराने के बजाय पंजाब के खाते में डलवा दिया था। मार्च, 2017 से कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान पंजाब पर चढ़ा कर्ज बढ़कर 2.82 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। अब इस कर्ज का निपटारा या भावी रूपरेखा भगवंत मान सरकार को तैयार करनी है। नीति आयोग के आर्थिक व सामाजिक संकेतकों के अनुसार 2003 के बाद पंजाब में प्रति व्यक्ति आय घटकर 1,15,882 रुपये आंकी गई है, जो राष्ट्रीय औसत (1,16,067 रुपये) से कम है। वहीं पंजाब का कर्ज भी जीडीपी का करीब 50 फीसदी तक है। नई सरकार ने अप्रैल, मई और जून के लिए लेखानुदान प्रस्ताव पेश कर गुजारे लायक व्यवस्था तो कर ली है, लेकिन इस अवधि के लिए भी जुटाई गई राशि में राज्य का कर्ज 5,442 करोड़ रुपये आंका और कुल कर्ज पर ब्याज का भुगतान 4,788.20 करोड़ रुपये (कुल 10230.20 करोड़ रुपये) खर्च हो जाएंगे। फिलहाल राज्य सरकार तीन माह के दौरान कृषि क्षेत्र पर 2,356 करोड़ रुपये, शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति पर 4,643 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर 1,340 करोड़ और बिजली क्षेत्र पर 1,097 करोड़ रुपये खर्च करेगी। पहले तीन महीने के लिए 37120 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया।

हार की जिम्मेदारी लोकतन्त्र के लुटेरे कहकर भाजपा और मोदी पर डाली गयी है। पर इन दोनों दलों के अंदर किसी की भी राष्ट्रिय नेतृत्व के सामने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है। यदि सपा के हिसाब से देखें तो उन्होने इकलौते विपक्ष के रूप में भाजपा को अच्छी चुनौती दी। अपनी सीटें बढ़ायीं और वोट प्रतिशत में भी इजाफा किया।

भारत में सत्ता परिवर्तन नहीं विपक्ष परिवर्तन की आवश्यकता

लोकतान्त्रिक देश में संवैधानिक प्रक्रिया की मजबूती के लिए मजबूत सत्ता पक्ष के साथ ही मजबूत विपक्ष की भी आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में में पूरी तरह से असफल दिख रहा है। देश को इस समय सत्ता परिवर्तन की नहीं विपक्ष परिवर्तन की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सहित अगर पांच राज्यों के चुनाव परिणामों को देखें तो विपक्ष सत्ता को चुनौती देने में नाकाम दिख रहा है। सिर्फ पंजाब में आप ने विपक्ष में रहते हुये सत्ता परिवर्तन किया है। बाकी राज्यों में विपक्ष इतना लचर, आधारहीन और निकम्मा साबित हुआ है कि सत्ता विरोधी लोग भी विपक्ष पर दांव खेलने से बचते रहे। केंद्र की मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें बौद्धिक तर्कों से पिछड़ती दिख रही है। जो काम उसे खुद करना चाहिए उसे वह नेपथ्य में रहकर अन्य संगठनों से करवा रही है। क्या भारत में विपक्ष अपनी भूमिका ठीक से निर्वाह कर पा रहा है ? यह एक ऐसा प्रश्न है जो आजकल एक सामान्य राजनीतिक समझ वाले व्यक्ति के मन में भी कौंध रहा है। विपक्ष कमजोर होने की स्थिति में सत्ताएं निरंकुश हो जाती हैं। चूंकि, सत्ता तो हमेशा ही पूंजीपति व्यवस्था की समर्थक रहती है इसलिए विपक्ष की मुखरता ही सत्ता को संतुलित रखती है। जिस देश ने कई बार सत्ता परिवर्तन देखा है अब उस देश में वर्तमान में विपक्ष परिवर्तन की आवश्यकता ज़्यादा दिखने लगी है। निरंकुश विपक्ष के कारण ही नोटा जैसा विकल्प जनता को रास आने लगता है।

यदि थोड़ा पीछे लौटे तो सर्वोच्च न्यायालय के सितम्बर 13 के आदेश के बाद वर्ष 2014 से जैसे ही नोटा चुनावी राजनीति में एक विकल्प बनकर आया वैसे ही नोटा का प्रदर्शन टॉप 5 में हो गया। नोटा ने तब आप, सीपीआई जैसी पार्टियों को पछाड़ते हुये सीधे एनसीपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी को चुनौती दे दी। लगभग 55-60 लाख मतदाताओं ने 2014, 2019 दोनों लोकसभा चुनावों में नोटा का प्रयोग किया। सरकार विरोधी लोगों का यह समूह विपक्ष की तरफ क्यों नहीं गया यह विपक्ष के लिए चिंतन का विषय है। भारत में 85 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से लगभग 30 करोड़ मतदाता वोट ही नहीं डालते हैं। यह एक ऐसा व्यवहार है जो लोकसभा चुनाव में भी दिखता है और विधानसभा चुनाव में भी। इतने बड़े वर्ग की चुनावी उदासीनता भी अच्छा संकेत नहीं है। ये काफी चिंताजनक परिस्थिति है कि लगभग एक तिहाई जनसंख्या को मौजूदा किसी भी पक्ष या विपक्ष में कोई अंतर नहीं नजर आ रहा है। कुछ पार्टियां बदलाव के नाम पर आती भी हैं तो वह पुरानी पार्टियों के साथ सांठगांठ कर अपने आप को उसी श्रेणी में खड़ा कर लेती हैं। लोगों से बातचीत के आधार पर ऐसी बातें सामने आयी हैं कि एक अच्छे विकल्प की जगह अभी भी खाली है जिसे मौजूदा कोई भी पार्टी शायद भरती नहीं दिख रही है।

भारत मे पक्ष हो या विपक्ष, राष्ट्रवादी पार्टी हो या धर्मनिरपेक्ष पार्टी, या इसके अतिरिक्त भी कोई दल हो। ज़्यादातर के वोट मजबूरी वाले वोट हैं। अगर कैडर का वोट छोड़ दिया जाए तो पांच राज्यों के चुनावों में देखने को मिला है कि आम जनता का वोट किसी के विरोध का वोट है न कि समर्थन का। और जैसे-जैसे किसी भी दल की नीतियों से पर्दा हटता जाता है तब पता चलता है कि पक्ष हो या विपक्ष, नीतिगत आधार पर लगभग सब एक ही हैं। तब आम जन मानस का मन और ज़्यादा खराब होता है। फिलहाल भाजपा को परिवारवाद से लबरेज विपक्ष होने का भरपूर फायदा मिल रहा है। भाजपा तो ऐसे कमजोर विपक्ष को हमेशा संजो कर रखना चाहेगी। सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर भी। परन्तु ये परिदृश्य जनतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। खासकर के तब जब अपने लोकतांत्रिक तरीकों में आम जनता के एक तिहाई से भी ज्यादा लोग भाग लेना बंद कर दे। नोटा के वोट हर चुनाव में टॉप 3 या 5 में आए। ऐसे में पक्ष से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है विपक्ष को बदलना। लोग जब भी विकल्प की बात करते हैं तो वो उसे पक्ष की तुलना में देखने लगते हैं। जबकि वास्तविकता में तुलना विपक्ष से होनी चाहिए। जैसे ही एक मजबूत विपक्ष आयेगा। जो न परिवारवाद से ग्रसित होगा और न ही भ्र्ष्टाचार का आरोपी होगा, तब अपने आप पक्ष की नीतियों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। वरना एक पार्टी के भ्रष्ट लोग अवसर पाते ही दूसरी पार्टी में जाते ही राष्ट्रवादी होते चले जाएंगे। इस तरह सिर्फ दल परिवर्तन करके सत्ता में में रहने की शृंखला आम होती रहेगी और आम जन मानस का भारतीय राजनीतिक तंत्र पर से भरोसा उठता रहेगा।

-अमित त्यागी

सपा सिर्फ यादव-मुस्लिम गठजोड़ और सत्ता से नाराज लोगों का समीकरण बनाती रह गयी। सपा ऐसा कोई खाका नहीं पेश कर सकी जिस पर आम मतदाता उसकी तरफ उत्साहित होकर आता। सपा का मुस्लिम तुष्टीकरण भी उसे भाजपा से छिटकने वाले हिन्दू वॉटर से दूर करता रहा। चूंकि, सपा का पूरा चुनाव हवा में था और जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दे पर वह नहीं लड़ रही थी इसलिए लखीमपुर खीरी सहित 23 जिलों में सपा का खाता भी नहीं खुल सका। लखनऊ में बैठे सपा के आधारहीन सलाहकार अखिलेश यादव को डुबाने का काम करते रहे। इनमे से कुछ तो स्वयं चुनाव हार गए तो कुछ ने हार के बाद एमएलसी के टिकट को ही मना कर दिया। सपा का थिंक टैंक इस बात को समझने में नाकाम रहा कि ध्रुवीकरण की प्रतिक्रिया स्वरूप भी एक ध्रुवीकरण होता है।

सपा जैसे परिवारवादी दल में स्वस्थ राजनीतिक परम्पराएं नहीं होती हैं। एक लोकतान्त्रिक दल की एक सामाजिक और राष्ट्रिय नीति होती है। राष्ट्रिय और अन्तराष्ट्रिय पर्श्नो पर एक दृष्टिकोण होता है। संगठन को चलाने के लिए एक नियमावली होती है। परिवार वादी दलों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं पायी जाती है। इनमे पिता, पुत्र, भाई, बहन और रिश्तेदार ही संसदीय बोर्ड होते हैं। परिवार के फैसले ही दल के फैसले बन जाते हैं। सपा के पारिवारिक झगड़े तो सार्वजनिक तौर पर होते रहे हैं। जनता के मन पर उन झगड़ों की छाप अभी तक मौजूद है। इसी कारण यादव, मुस्लिम और भाजपा विरोधी मतदाता को छोडकर अन्य सामान्य मतदाता सपा की तरफ जाने से कतराता रहा। सिर्फ सपा ही नहीं परिवार आधारित अन्य कई दल हैं जो एक दो जिलों तक सीमित हैं। इन परिवारवादी दलों को भी मुंह की खानी पड़ी है। लोकदल और सपा का बेमेल गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हवा हवाई साबित हुआ। लोकदल भी एक परिवारवादी दल है। चरण सिंह और अजीत सिंह के बाद जयंत सिंह जाटों

जातिगत नहीं समावेशी राजनीति से लगातार विजयी

सुरेश खन्ना

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले को शहीदों की नगरी कहा जाता है। एतेहासिक काकोरी कांड के महानायक राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक़ उल्लाह खान और रोशन सिंह इसी भूमि से आते हैं। फिल्म जगत में राजपाल यादव ने शाहजहांपुर का नाम रोशन किया है। स्काउट गाइड की शुरुआत भी इसी जिले से हुयी है। शाहजहांपुर की भूमि दशकों से राजनेताओं से भरी पूरी रही है। राजीव गांधी और नरसिंह राव के प्रधानमंत्रित्व काल में उनके राजनीतिक सलाहकार रहे कुंवर जितेंद्र प्रसाद उर्फ बाबा साहब, अटल जी की सरकार में मंत्री रहे स्वामी चिन्मयानन्द एवं बाबू सत्यपाल सिंह यादव, मोदी जी के पहले कार्यकाल में मंत्री रहीं कृष्णाराज भी इसी जिले से हैं। शहीदों की इस भूमि की नगर सीट से सुरेश कुमार खन्ना लगातार 1989 से अपना परचम लहराए हुये हैं। सुरेश खन्ना की लगातार जीत इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इस सीट पर न तो उनका कोई जातिगत वोटबैंक है और न ही सुरेश खन्ना किसी राजनीतिक विरासत से आते हैं। सामान्य परिवार से आने वाले खन्ना अपने आरंभिक दिनों में वकालत करते थे और उसके बाद वह राजनीति में आ गए। सुरेश खन्ना हिन्दू और मुसलमान, दोनों में लोकप्रिय हैं। नगर में मुस्लिम आबादी बहुतायत में है किन्तु सुरेश खन्ना भाजपा से होने के बावजूद मुस्लिम वोट भी प्राप्त करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्षेत्रीय दलों की सरकारों में उत्तर प्रदेश में कई जिलों में अक्सर दंगे हुआ करते थे। यह सुरेश खन्ना का शक्ति संतुलन साधने का हुनर ही है कि शाहजहांपुर में तीन दशकों से कभी कोई दंगा ही नहीं हुआ। सबको साथ लेकर चलने की जिस राजनीति पर मोदी सरकार वर्तमान में चल रही है उस पर सुरेश खन्ना तीन दशक से चल रहे हैं। हनुमान भक्त खन्ना ने नगर में खन्नौत नदी के तट पर एक टापू पर हनुमान जी की 108 फिट ऊंची प्रतिमा का निर्माण करवाया है जो अब पर्यटन मानचित्र पर भी उपलब्ध है। आप पर हनुमान जी की विशेष कृपा मानी जाती है।

-अमित त्यागी

उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना की इस जीत पर मौलिक भारत ने उनको शुभकामनाएँ प्रेषित की। मौलिक भारत की तरफ से उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अमित त्यागी ने सुरेश कुमार खन्ना को गुलदस्ता देकर उनका अभिनंदन किया।

किसी अल्पसंख्यक से ज्यादती नहीं होगी - सुरेश खन्ना

योगी सरकार के प्रथम कार्यकाल में प्रशासनिक सुधार पर तेजी से कार्य शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। वर्तमान में 95 विभागों का पुनर्गठन कर उन्हें 54 विभागों में समायोजित करने की सिफारिश पर विचार भी शुरू कर दिया गया है। विभागों के पुनर्गठन से न सिर्फ उनकी संख्या कम होगी, बल्कि काम में भी तेजी आने की उम्मीद है। इस बारें में जब डाइलॉग इंडिया के विशिष्ट संपादक अमित त्यागी ने उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना से बात की तो उन्होने बताया कि योगी सरकार में संसाधनों पर पहला हक़ गरीबों का है। सरकार में नयी ऊर्जा के साथ साथ अनुभव की भी आवश्यकता है। पिछली सरकार में जो काम रह गए थे उसे इस कार्यकाल में पूरा करेंगे। 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की व्यवस्था हमने तीन महीने के लिए बढ़ा दी है। अब उत्तर प्रदेश को एक नंबर का प्रदेश बनाने का संकल्प हमने लिया है। इस कार्यकाल में नए रोजगार सृजन पर हमारा ध्यान रहेगा। बेहतर प्रशासन के कारण उत्तर प्रदेश में लगातार निवेश बढ़ रहा है और कई नयी औद्योगिक इकाइयां लगने जा रही हैं।

न खंजर उठेगा न शमशीर इनसे, ये बाजू मेरे आजमाये हुये हैं - सुरेश खन्ना

सुरेश खन्ना नगर के चप्पे चप्पे से वाकिफ नेता हैं। उनका बूथ मैनेजमेंट जबरदस्त है। हर चुनाव में मतदान के बाद वह जब अपनी जीत के अंतर का अनुमान बताते हैं तो वह अनुमान अमूमन सटीक बैठता है। सुरेश खन्ना की याददाश्त भी बहुत तेज है। भरी भीड़ में वह लोगों को पहचान लेते हैं। बरसो बाद भी उसे नाम से बुलाकर सबको चौंका देते हैं। उनकी पहली जीत 1989 में हुयी थी और उसके बाद पैदा हुये लोग भी आज दो दशक से उनके वोटर हैं। अपने विरोधियों पर सुरेश खन्ना अक्सर इस शेर से कटाक्ष करते हैं। न खंजर उठेगा न शमशीर इनसे, ये बाजू मेरे आजमाये हुये हैं।

के नए मसीहा बन कर परिवारवादी दल बनाए बैठे हैं। मोदी ने उत्तर प्रदेश के चुनावों के दौरान जब कहा कि सपा में 25 वर्ष की आयु के सभी पारिवारिक लोग चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त कर चुके हैं तो इसका व्यापक असर दिखा। वैसे भी देखा जाये तो लोकतन्त्र में कोई भी पार्टी किसी की जागीर नहीं हो सकती है। कांग्रेस के परिवारवादी चरित्र के कारण ही समय समय पर उससे तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी

उत्तर प्रदेश में बड़े प्रशासनिक सुधारों की तैयारी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। वर्तमान में 95 विभागों का पुनर्गठन कर उन्हें 54 विभागों में समायोजित करने की सिफारिश पर विचार भी शुरू कर दिया गया है। विभागों के पुनर्गठन से न सिर्फ उनकी संख्या कम होगी, बल्कि काम में भी तेजी आने की उम्मीद है। गौरतलब है कि विभागों के पुनर्गठन के लिए तत्कालीन अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गयी थी जिसमे विभागों की संख्या 95 के बजाय 57 करने का सुझाव दिया गया था। इस व्यवस्था पर अमल हो इसके पहले पिछले वर्ष रेरा के चेयरमैन व पूर्व मुख्य सचिव राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक नई समिति का गठन किया गया। इस समिति को कर्मचारियों की संख्या के युक्तिकरण, प्रभावशीलता व दक्षता में सुधार तथा उनके उद्देश्यों के आकलन की व्यवस्था पर सुझाव देने को कहा गया। इस समिति ने भी अपनी संस्तुतियों में विभागों के पुनर्गठन संबंधी संजय अग्रवाल समिति की संस्तुतियों पर अतिशीघ्र निर्णय लेकर कार्यवाही किए जाने की सिफारिश की है। राजीव कुमार समिति ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। शासन स्तर से समिति के सुझावों व संस्तुतियों पर अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों की राय मांगी गई है। नयी व्यवस्था में समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का एकीकरण, अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम को एससी-एसटी वित्त एवं विकास निगम में एकीकृत करने की कार्यवाही समाज कल्याण विभाग करेगा।

वित्त विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालयों व निदेशालयों, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग के पुनर्गठन व सुदृढ़ीकरण की जिम्मेदारी वित्त विभाग को दी गई है। सिंचाई व जल संसाधन तथा जल शक्ति विभागों का नए सिरे से निर्धारण सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग करेगा। नियोजन विभाग के अंतर्गत प्रभागों का पुनर्गठन नियोजन विभाग करेगा। जिस तेजी से इस पुनर्गठन की कवायद शुरू हुई है, इसका असर भविष्य में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार पर भी पड़ सकता है। कई ऐसे विभागों का एक दूसरे में विलय का प्रस्ताव है जिनके वर्तमान में अलग-अलग मंत्री हैं। इन सुझावों पर प्रशासकीय विभागों से मांगी गयी है। चकबंदी, हथकरघा,

पंचायतीराज, रेशम विभाग का विलय प्रस्तावित है। चकबंदी विभाग को राजस्व विभाग में, हथकरघा विभाग को उद्योग विभाग में, रेशम विभाग को उद्यान विभाग में तथा पंचायतीराज विभाग को ग्राम्य विकास विभाग में विलय करने की योजना बन रही है। समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व दिव्यांगजन विभाग एक होंगे। इसी तरह अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम में एकीकृत करने को कहा गया है। वित्त विभाग के कई निदेशालय अप्रसांगिक होने जा रहे हैं। बचत निदेशालय की अब आवश्यकता न बताते हुए इसके जिला स्तरीय पदों का समायोजन कोषागार व अन्य कार्यालयों में करने की सिफारिश है। बजट निदेशालय व फिजिकल प्लानिंग एवं रिसोर्सेज निदेशालय का आपस में विलय कर पदों का नए सिरे से निर्धारण करने को कहा गया है। वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय को कोषागार निदेशालय में तथा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा निदेशालय व मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां व पंचायतें को आपस में विलय कर पदों का पुनर्गठन करने की सिफारिश है।

राज्य योजना आयोग द्वारा दैनिक प्रकृति के कार्य किए जा रहे हैं। संस्था में नीति अनुसंधान करने तथा विभागों के साथ वैचारिक आदान-प्रदान के लिए केंद्र सरकार के नीति आयोग की तरह राज्य नीति आयोग का गठन की संस्तुति की गई है।

विकास अन्वेषण व प्रयोग प्रभाग को समाप्त किया जाएगा। राज्य नियोजन संस्थान में स्थापित मूल्यांकन प्रभाग, योजना अनुश्रवण व मूल्य प्रबंधन विभाग तथा जनशक्ति नियोजन प्रभाग का आपस में विलय होगा। प्रदेश में कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए कार्मिक विभाग नोडल विभाग है। नियोजन विभाग के प्रशिक्षण प्रभाग को समाप्त कर कार्मिक विभाग के नियंत्रण में लाने का प्रस्ताव है। इसी तरह नियोजन विभाग के अधीन कार्यरत भूमि उपयोग परिषद को राज्य योजना आयोग में, यूपी राज्य जैव ऊर्जा बोर्ड को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत विभाग तथा गिरि विकास अध्ययन संस्थान को उच्च शिक्षा विभाग में हस्तांतरित होना है। भविष्य में एकीकृत व समग्र रूप से जल संसाधन की मांग व आपूर्ति का प्रबंधन करने के लिए प्रदेश की सभी मुख्य आठ नदियों के लिए एक-एक बेसिन जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन, जल प्रबंधन से संबंधित सभी विभाग को बेसिन स्तर पर उप बेसिक इकाइयोंसे जोड़ना शामिल है। जिला स्तर पर एकीकृत जल प्रबंधन कार्य जिलाधिकारी के नेतृत्व में जल से संबंधित अधिकारियों को देने तथा विकास खंड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी एकीकृत जल प्रबंधन की तैनाती का प्रस्ताव भी प्रस्तावित है।

-अमित त्यागी

का उदय हुआ। विडम्बना यह रही कि ये दोनों पार्टी भी बाद में परिवारवादी होती चली गईं।

परिवारवादी दलों में दो तरह के परिवारवाद होते हैं। पहला दल का संचालन सिर्फ परिवार के द्वारा किया जाता है। दूसरा दलों के कार्यकर्ता अपने परिवार के लिए टिकट मांगते हैं। ऐसे पुत्र पुत्रियों को अक्सर जनता नकार भी देती है। अब सपा को देखें तो यहां यादव के नाम पर तुष्टीकरण भी जम कर होता रहा है किन्तु टिकट परिवार के लोगों को ही मिलता है। ऐसे में यादव वर्ग का एक बड़ा मतदाता सपा से दूर छिटक जाता है। 2019 में लोकसभा चुनाव में युवा यादवों का झुकाव भाजपा की तरफ हुआ था। 2022 में यादव अपनी अस्मिता के कारण सपा से जुड़ा। मुस्लिम भी भाजपा विरोध के कारण सपा से जुड़ा किन्तु अपनी प्रचंड ताकत के बाद भी सपा 111 पर सिमट गयी। यह सपा का सर्वोच्च प्रदर्शन है।

अप सपा के लिए वापसी के सारे रास्ते बंद है। हो सकता है यह सपा के लिए आखिरी चुनाव हो और वह बसपा की राह पर खत्म होती चली जाये। अब उत्तर प्रदेश में भाजपा के सामने अगला विकल्प आम आदमी पार्टी या कांग्रेस बन सकती है। उसकी वजह मुस्लिम वॉटर है। मुस्लिम वॉटर का मानना है कि 2024,17,19,22 में सपा भाजपा को हराने में विफल रही है इसलिए मुस्लिमों को नए विकल्प तलाशने होंगे।

क्षेत्रीय और धार्मिक अस्मिताएं बनाम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद :

इन चुनावों में धार्मिक और जातीय अस्मिता का विषय बेहद महत्वपूर्ण विषय रहा है। पंजाब में धार्मिक, पंथिक, क्षेत्रीय एवं जातीय अस्मिताओं के विषय सर चढ़कर बोले हैं। आम आदमी पार्टी ने अस्मिता की राजनीति को अच्छा भुनाया। सिर्फ उनकी फ्री स्कीम उनकी जीत का आधार नहीं हैं बल्कि मालवा और दोआबा क्षेत्र की अस्मिताओं पर उनका काम भी प्रभावी कारण रहा है। मणिपुर में क्षेत्रीय आबादी का विमर्श और हिन्दू-ईसाई की धार्मिक अस्मिताएं महत्वपूर्ण कारक बनकर उभरी हैं। उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र अस्मिता का प्रतीक बनते हैं। ब्राह्मण और ठाकुर भी इस चुनाव में एक प्रमुख कारक रहा। अस्मिता के विषय क्षेत्रीय दलों द्वारा अच्छे से भुनाये जाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इसे जातिगत राजनीति कहा जाता है। अस्मिता बोध जैसे ही लघुता के रूप में आता है, उस पर राष्ट्रवाद हावी हो जाता है। यहीं पर मोदी सब पर भारी पड़ जाते हैं। विधानसभा चुनाव परिणामों में भी यही हुआ है। मोदी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद सभी अस्मिताओं के ऊपर भारी पड़ा। राम मंदिर निर्माण, 370 का हटना, काशी कॉरीडोर का निर्माण और हिन्दुत्व का उत्थान ऐसे विषय बन कर उभरे जिसने क्षेत्रीय और दलगत अस्मिताओं को ध्वस्त कर दिया।

नरेंद्र मोदी जबसे प्रधानमंत्री बने हैं तबसे वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर तेजी से काम कर रहे हैं। 2021 का साल इस दौरान उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला साल रहा है। पहले बंगाल चुनाव के दौरान उन पर कोविड के कारण उंगलियां उठीं फिर इसके बाद उन्हे बंगाल में हार का मुंह देखना पड़ा। यह वह दौर था जब अन्तराष्ट्रिय मीडिया भारत की नकारात्मक छवि दिखा रहा था। अर्थव्यवस्था संकट में थी। वैक्सीन के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां दवाब बना रही थी। यह वह समय था जब राष्ट्रवाद पर समस्याएं हावी थीं। अस्मिता का प्रश्न उठाकर विपक्ष सरकार पर दवाब बना रहा था। इसके बाद भाजपा ने अस्मिता की राजनीति के मिथक को तोड़कर समवेशी राजनीति की ओर कदम बढ़ाया। इसी कारण उसे 2017 में जाति संप्रदाय से ऊपर उठाकर 41 प्रतिशत वोट मिले थे। शुरू में भाजपा ने जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर विभिन्न वर्गों को अपना लक्ष्य बनाया। महिलाओं, गरीबों और किसानों पर ध्यान केन्द्रित किया। यह एक नयी प्रकार की राजनीति थी जिसमे जाति आधारित व्यवस्था नहीं बल्कि एक नयी किस्म की नीतियों का निर्माण किया जा रहा था। उज्जवला योजना और शौचालय योजना से महिला अस्मिता का विषय लक्ष्य साधित हुआ। इसके बाद महिला सशक्तिकरण के क्रम में महिला सुरक्षा का विषय महत्व पूर्ण विषय बना। मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना तीन तलाक का कानून भी मुस्लिम महिलाओं की अस्मिता को बढ़ाने वाला विषय बना। महिलाओं को आधी आबादी कहकर संबोधित किया जाता है। यह आधी आबादी जातिगत अस्मिताओं से इतर व्यक्तिगत अस्मिता को पसंद कर गयी।

पिछड़े और दलितों में बहुत सी जातियां ऐसी रहीं जिनमे पुरुषों ने भाजपा को वोट नहीं दिया किन्तु इस वर्ग की महिलाओं ने अस्मिता के प्रश्न पर मोदी को वोट दिया। इन चुनावों में देश की आधी आबादी का भाजपा के पक्ष में मौन ध्रुवीकरण हुआ है। यह किसी भी चुनावी अध्ययन या सर्वे में पकड़ में नहीं आ रहा था। इसके साथ ही छोटे और सीमांत किसानों को एकमुश्त 2 हजार रुपये मिलना और वह भी बिना किसी बिचौलिये का मिलना भी किसानों की अस्मिता से जुड़ा। गरीबों को मिलने वाला मुफ्त खाद्यान्न भी महत्वपूर्ण कारक रहा। इन सबके साथ ही राष्ट्रवाद का विषय तो सर चढ़कर बोल ही रहा था। विपक्ष सिर्फ विरोध तक सीमित था। उसके पास न कोई विकास का रोड मैप था न ही कोई स्पष्ट नीति। बाकी कसर उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति ने पूरी कर दी। मुस्लिम समाज की तरफ रुझान के कारण प्रतिक्रिया स्वरूप हिन्दू एकजुट होता चला गया। चूंकि बहुत से ऐसा वोटर जो भाजपा से नाराज था जब उसने धार्मिक ध्रूवीकरण देखा तो उसे स्वयं को मिलने वाली योजनाएं और मोदी, विपक्ष से बेहतर दिखे। बस यही अंतर भाजपा और सपा की जीत और हार का अंतर बन गया।

गुजरात मॉडल के बाद योगी का उत्तर प्रदेश मॉडल

एक समय था देश में मोदी का गुजरात मॉडल चर्चित रहता था। अब देश में योगी का मॉडल चर्चित है। गुजरात मॉडल में विकास मुख्य था तो योगी माडल में त्वरित निर्णय और सुरक्षा की भावना प्राथमिकता में है। अब योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में बड़े प्रशासनिक सुधार करने जा रही है। बहुत से विभागों को एक दूसरे में जोड़े जाने की तैयारी चल रही है। कई गैर जरूरी मंत्रालयों को हटाया जा रहा है। मंत्रियों की संख्या सीमित की जा रही है। अब जिस तरह से कई देश अपना निवेश लेकर भारत में आ रहे हैं उसके अनुसार इन देशों का रुझान उत्तर प्रदेश की तरफ ज़्यादा है। जापान और आस्ट्रेलिया से एक बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है। यूएई भी भारत में एक बड़ा निवेश करने जा रहा है और उसका प्रारम्भिक झुकाव उत्तर प्रदेश की तरफ ही है। उत्तर प्रदेश में कई नए राजमार्ग विकसित किए गए हैं। यमुना एक्स्प्रेस वे और गंगा एक्स्प्रेस वे हैं। इन मुख्य मार्गों के इर्द गिर्द बड़े निवेश होने पर रोजगार बढ़ेंगे। योगी के चेहरे के कारण हिन्दुत्व का विषय इस समय आत्मविश्वास से लबरेज दिखता है। भाजपा का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिस तरह से विरोधियों पर भारी पड़ा है उसको अब हलका या क्षीण भाजपा को नहीं होने देना है। 2024 में जीत की राह उत्तर प्रदेश से होकर जाने वाली है, जिस पर योगी खरे उतरे हैं। अब मोदी और उनकी टीम को नए भारत के निर्माण की गति और तेज करने में कोई बाधा नहीं दिखाई दे रही है। ■

ललित गर्ग

समान आचार संहिता समूचे देश में लागू हो

समान नागरिक आचार संहिता का मुद्दा आज एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल यह मुद्दा आज का नहीं है, यह अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नजरिये से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित में चिन्तन, निर्णय एवं क्रियान्वयन की अपेक्षा है। भले ही भाजपा के लिये यह चुनावी मुद्दा रहा हो, लेकिन इसको लागू करने की अपेक्षा सभी जाति, धर्म, वर्ग, भाषा के लोगों के हित में हैं। हां, इसे लागू करने का साहस एवं दूरदर्शिता भाजपा और उसके नेता प्रदर्शित कर रहे हैं, यह स्वागतयोग्य है। इसे मजहब या साम्प्रदायिकता की राजनीति से ऊपर उठ कर पूरे देश की सामाजिक समरसता के नजरिये से देखा जाना चाहिए। संवैधानिक दृष्टि से भी यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है क्योंकि भारत का संविधान धर्म या जाति-बिरादरी अथवा स्त्री-पुरुष या क्षेत्रीय पहचान की परवाह किये बिना प्रत्येक नागरिक को एक समान अधिकार देता है। उत्तराखंड के पुन: मुख्यमन्त्री बने श्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह राज्य में एक समान नागरिक आचार संहिता को लागू करने के अपनी पार्टी भाजपा के चुनावी फैसले को लागू करने का इरादा जाहिर किया है उसका देश के सभी राज्यों में बिना आग्रह, पूर्वाग्रह एवं दुराग्रह के स्वागत किया जाना चाहिए।

भारत विविधताओं से भरा देश है। यहां विभिन्न पंथों व पूजा पद्धतियों को मानने वाले लोग रहते हैं। इन सबके शादी करने, बच्चा गोद लेने, जायदाद का बंटवारा करने, तलाक देने व तलाक उपरांत तलाकशुदा महिला के जीवनयापन हेतु गुजारा भत्ता देने आदि के लिए अपने-अपने धर्मानुसार नियम, कायदे व कानून हैं। इन्हीं नियमों, कायदे व कानूनों को पर्सनल लॉ कहते हैं। अंग्रेज जब भारत आए और उन्होंने यह विविधता देखी, तो उस समय उन्हें लगा पूरे देश को सुचारुरूप से चलाने के लिए एक समान नागरिक आचार संहिता बनानी आवश्यक है। जब उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो हर धर्मों के लोगों ने इसका विरोध किया। ऐसे में उन्होंने लम्बे समय तक यहां अपने पांव जमाये रखने के लिए किसी से उलझना ठीक नहीं समझा। इन परिस्थितियों में 1860 में उन्होंने इंडियन पैनल कोड तो लागू किया पर इंडियन सिविल कोड नहीं। यानि एक देश-एक दंड संहिता तो लागू की, लेकिन एक देश-एक नागरिक संहिता लागू करने का जिम्मेदारी एवं साहसपूर्ण काम नहीं किया। उसके बाद बनी सरकारों ने तो अंग्रेजों की सोच एवं नीतियों का ही अनुसरण किया, इसलिये वे भी अपने राजनीतिक हितों के लिये इसे लागू नहीं किया। जबसे नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने साहसिक निर्णय लेते हुए ऐसे राष्ट्रहित के निर्णय लेकर राष्ट्र को नया उजाला एवं सांसें दी है। भले ही वह कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने का साहसिक एवं सूझबूझभरा निर्णय हो या तलाक का मुद्दा।

कांग्रेस ही सरकारों ने हिन्दू एवं अन्य धर्मों को कमजोर करने एवं मुस्लिमों को संख्याबहुल बनाने के लिये अपने हित को सर्वोपरि माना। अपनी इन्हीं गलत नीतियों एवं संकीर्ण राजनीति के कारण कांग्रेस लगातार कमजोर होते होते अब एकदम रसातल में जा चुकी है। आजादी के बाद जिस तरह मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों को उनकी मजहब की पहचान के आधार पर उनके धार्मिक कानूनों को मान्यता देने का प्रावधान किया गया वह देश की आन्तरिक एकता व समरसता में व्यवधान पैदा करने वाला था। सभी मत-मजहब वालों के लिए तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, विवाह की आयु, बच्चों को गोद लेने और विरासत संबंधी नियम एक समान बनाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि इन सभी मामलों में एक जैसे नियम बन जाते हैं तो समान नागरिक संहिता का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। इसकी शुभ शुरुआत देवभूमि से हो रही है, यह सुखद संकेत है।

तथ्य यह भी है कि गोवा में समान नागरिक संहिता पहले से ही लागू है और वहां सभी समुदायों के लोग रहते हैं। आखिर जो व्यवस्था गोवा में बिना किसी बाधा के लागू है, वह शेष देश में क्यों नहीं लागू हो सकती? प्रश्न यह भी है कि जब अन्य कई लोकतांत्रिक देशों में तुर्की, सूडान, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, इजिप्ट और पाकिस्तान में समान नागरिक संहिता लागू है तो भारत में उसका विरोध क्यों होता है? देश के अनेक मुस्लिम संगठनों ने आजादी के आन्दोलन में सहयोग एवं सहभागिता ही नहीं की, बल्कि भारत के बंटवारे का विरोध भी किया था। लेकिन आजाद भारत में इन संगठनों ने भी कभी मुसलमानों को भारत की राष्ट्रीय धारा में मिलने की प्रेरणा नहीं दी और उनकी मजहबी पहचान को खास रुतबा दिये जाने की ही कोशिशें करते हुए सर्वाधिक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी को इसके उपाय सुझाये। सबसे दुखद यह है कि 1947 में मजहब के आधार पर ही मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान बनाये जाने के बावजूद हमने अपनी राष्ट्रीय नीति में परिवर्तन नहीं किया और इसके उलट उन्हीं प्रवृत्तियों व मानसिकता को मुल्ला-मौलवियों व मुस्लिम उलेमाओं की मार्फत संरक्षण दिया गया जिन्होंने भारत के बंटवारे तक में अहम भूमिका निभाई थी। जिसकी वजह से भारत में मुसलमानों की राजनैतिक पहचान एक 'वोट बैंक' के रूप में बनती चली गई और

धामी : उत्तराखंड की जीत के बाज़ीगर

उत्तराखंड में पुष्कर धामी ने अपनी मेहनत और युवाओं के मध्य लोकप्रियता के चलते लगातार दूसरी बार भाजपा को सत्ता में पहुंचाया है। उत्तराखंड में किसी भी दल की सरकार की पुनरावृत्ति इसके पहले नही हुई है। यह धामी का जादू ही था जो उन्होंने आठ महीने पहले लगभग डगमगा चुकी भाजपा की कश्ती को न सिर्फ भंवर से बाहर निकाला बल्कि जीत के मुहाने तक पहुंचा दिया। भाजपा की इस जीत में धामी की खुद की खटीमा सीट भी कुर्बान हो गयी। भाजपा के अंदर चलने वाले घमासान एवं नेताओं के द्वारा रचित आंतरिक षड्यंत्र की बू खटीमा में साफ नजर आती है। खैर, उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार सत्तासीन होने का इतिहास रचने वाली भाजपा के अगुवा पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट हारने के बावजूद एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर बाजीगर साबित हुए हैं।

गौरतलब है कि 46 साल के युवा धामी को विधायक दल का नेता चुने जाने का ऐलान स्वयं केंद्रीय पार्टी पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी ने किया था। राजनाथ सिंह विधानसभा चुनाव से पहले धामी को धोनी की तरह 'मैच फिनिशर' तक बता चुके हैं। अब जीत के बाद धामी को पांच साल का समय मिला है। उनकी कार्यशैली को देखकर लगता है कि वह राजनीति की पारी में टेस्ट मैच की तरह खेलते नजर आएंगे।

केंद्र की राजनीति में एक दिन उत्तराखंड का चेहरा होंगे धामी

उत्तराखंड राज्य के कमोबेश दो दशक के राजनैतिक इतिहास को देखते हुए इस पहाड़ी राज्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जब धामी का मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव हुआ था तब हालांकि यह एक सामान्य घटना दिखी हो किंतु पुष्कर सिंह धामी का चयन भाजपा का एक दूरदर्शी निर्णय था। युवा धामी उत्तराखंड का देश मे चेहरा अभी से दिखने लगे हैं। उत्तराखंड का नाम लेते ही जैसे कभी नारायण दत्त तिवारी का चेहरा सामने आता था, वैसा ही कुछ आकर्षण पुष्कर सिंह धामी के व्यक्तित्व में दिखता है। नौकरशाही पर काबू करके, संगठन के साथ संतुलन बैठाना और जनता की नब्ज पकड़ना धामी को बहुत आगे लेकर जायेगा।

- अमित त्यागी

'मुस्लिम तुष्टीकरण' का अघोषित एजेंडा चल पड़ा। देश में मुसलमान लगातार बहुसंख्य बनने की ओर अग्रसर होता रहा और बहुसंख्य हिन्दू लगातार अल्पसंख्य होने की कगार पर अग्रसर होता रहा। सोचने वाली बात तो यह है कि कांग्रेस ने भी मुसलमानों को वोट बैंक से अधिक नहीं समझा और अपने स्वार्थ के लिये उनका इस्तेमाल किया। इससे इस समुदाय के लोगों का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक परिवेश हमेशा पिछड़ा ही रहा। अब मोदी सरकार न केवल इस वर्ग के लोगों का जीवनस्तर ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है, बल्कि उन्हें उन्नत जीवनशैली भी दे रही है।

इंडियन पेनल कोड 1860 की धारा 494 के अनुसार कोई भी स्त्री या पुरूष एक विवाह के रहते दूसरा विवाह नहीं कर सकता। दूसरी ओर मुस्लिम पुरुष 4 शादियां कर सकता है। सीआरपीसी 1973 की धारा 125 के अनुसार तलाकशुदा पत्नी पति से आजन्म गुजारा भत्ता लेने की हकदार है। मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐसा नहीं है। शाहबानो केस इसका उदाहरण है। इसी तरह बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 के अनुसार बाल विवाह अपराध है, परन्तु मुस्लिम समाज के लिए यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ईसाई विवाह अधिनियम 1872, ईसाई तलाक अधिनियम 1869 भी पुराने हैं व हिन्दू विवाह अधिनियम से अलग हैं। ये विषमताएं देश की धर्मनिरपेक्षता पर प्रश्नचिन्ह हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सर्वोच्च प्रमुख श्री मोहन भागवत का समान आचार संहिता पर बहुत ही तर्कसंगत दृष्टिकोण हैं। इस मुद्दे को लेकर संघ और भाजपा पर अत्यंत संकीर्ण, सांप्रदायिक और समाज-विरोधी दृष्टिकोण का आरोप लगता रहा है। जबकि मोहन भागवत का दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट है कि जो भारत में पैदा हुआ और जो भी भारत का नागरिक है, वह हिंदू है। हिंदू होने और भारतीय होने में कोई फर्क नहीं है। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर भी मोहन भागवत की राय है कि सर्वसम्मति के बिना इसे लागू करना उचित नहीं होगा।

उत्तराखंड पूरे देश में 'देवभूमि' के नाम से जाना जाता है, यह अध्यात्म की अलौकिक भूमि है, जहां सद्भावना एवं सौहार्द इंसानों में ही नहीं, जीव-जंतुओं एवं पशु-पक्षियों तक में व्याप्त है। संकीर्णता से ऊपर उठ कर जो किसी भी व्यक्ति में ईश्वर की सर्व व्यापी निरंकार सत्ता का बोध कराती है। ईश्वर की पृथ्वी पर इस निकटता को केवल सनातन या हिन्दू दर्शन अथवा इस धरती से उपजे अन्य धर्म दर्शन ही बताते हैं। अत: बहुत आवश्यक है कि इस देवभूमि में सभी नागरिकों का आचरण एक समान ही हो और सभी के लिए सामाजिक नियम एक समान हों। वैसे गौर से देखा जाये तो 2000 में उत्तराखंड बनने से पहले और बाद में भी इसकी पर्वतीय जनसंख्या में खासा परिवर्तन आया है और पहाड़ों पर मुस्लिम जनसंख्या में खासा इजाफा हुआ है। उत्तराखंड में मदरसों की संख्या तक में अभिवृद्धि हो रही है। जब धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा तो देश सही मायने में धर्मनिरपेक्ष बनेगा। विभिन्न समुदायों के बीच एकता की भावना पैदा होगी। एक ही विषय पर कम कानून होने से न्यायतंत्र को भी फैसले देने में आसानी होगी। कई मुस्लिम देशों जैसे टर्की व ट्यूनिशिया आदि ने भी शरीयत से हटकर नागरिक कानून बनाये हैं। मुस्लिम समाज को मुख्य धारा में आने व अपने सामाजिक उत्थान के लिए सरकार पर समान नागरिक आचार संहिता लागू करने के लिए दबाव बनाना चाहिए। राजनीतिक दलों एवं विभिन्न राज्य सरकारों को भी मुस्लिम समाज को केवल वोट बैंक ना मानते हुए तुष्टीकरण की नीतियों से ऊपर उठ कर सामाजिक समरसता व हर वर्ग के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। ■

सशक्त लोकतंत्र के लिये सशक्त विपक्ष जरूरी

● ललित गर्ग

उत्तरप्रदेश सहित पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों परिणामों के बाद एक बात विशेष रूप से उभर कर सामने आयी है कि सशक्त लोकतंत्र के लिये सशक्त विपक्ष बहुत जरूरी है। पंजाब में दिल्ली की ही भांति आम आदमी पार्टी की जो आंधी चली और नगण्य विपक्ष के रूप में आप की सरकार बनने जा रही है, उस तरह की सरकारें बनना एवं प्रचंड बहुमत मिलना लोकतंत्र के लिये गंभीर खतरा है। देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाये रखना है तो जितना आवश्यक सत्ता धारी दल का स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाना है, उतना ही आवश्यक है सशक्त विपक्ष का होना ताकि सरकार के कामों पर निगरानी रखी जा सके एवं उसकी गलत नीतियों का विरोध किया जा सके। मजबूत विपक्ष होने से ही सत्तारूढ़ दल भी अपने कार्यों को मर्यादा में रहते हुए जनता के हित में कार्य करता रहेगा अन्यथा सत्ताधारी पार्टी कितनी भी परम उद्देश्य के साथ कार्य करने वाली हो, उसको कमजोर विपक्ष के रहते पथभ्रष्ट होने से रोक पाना मुश्किल होता है। सत्ता की राजनीति को प्राथमिकता देने वाले हमारे नेता यह भूल गये कि जनतंत्र में राजनीति सत्ता के लिए नहीं, जनता के लिए, जनता की रक्षा के लिये होनी चाहिए। यह अच्छी बात है कि विपक्ष जागरूक हो रहा है। अपने बिखरावों, गलत नीतियों, परिवारवादी सोच तथा लचर क्रियाकलापों पर विराम देने की कोशिश अगर वह करता है, तो लोकतंत्र के लिए यह शुभ एवं श्रेयस्कर होगा। देश के लिए सशक्त विपक्ष की आवश्यकता है।

लोकतंत्र के सफल संचालन में जितनी सत्ता पक्ष की भूमिका होती है, उतनी ही विपक्ष की भी। देश में जबसे भारतीय जनता पार्टी अपनी राष्ट्र निर्माणकारी विकास योजनाओं के साथ सरकारें बनाने लगी है, विपक्ष का लगभग सफाया हो गया है। इसका मुख्य कारण विपक्षी दलों की विसंगतिपूर्ण नीतियां एवं स्वार्थ की राजनीति है। एक कारण इन विपक्षी दलों का परिवारवादी होना भी है। विपक्षी पार्टियों के लिए अपने अस्तित्व को बनाये रखना है, तो उन्हें अपने स्वार्थ को छोड़ कर देश और देश की जनता के हितों के लिए सोचना ही होगा, राजनीति में आने का तात्पर्य समाज सेवा होना चाहिए न की अपनी और अपनों की तिजोरियों भरने का, या परिवार का पीढ़ियों से दलों पर एकाधिकार होना।

विपक्ष ने हमेशा गलत का साथ दिया, देश के सम्मुख खड़े संकट को कम करने की बजाय बढ़ाने में ही भूमिका निभाई। किसान आन्दोलन एवं कोरोना महामारी ने विपक्ष दलों की स्वार्थ एवं संकीर्ण सोच को ही प्रकट किया। कोरोना महामारी में लोग मर रहे थे और विपक्षी दल तथाकथित राजनीतिक स्वार्थों के नाम पर किसानों की गलत मांगों का समर्थन कर रहे थे। ऐसी ही अनेक राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में साथ देकर विपक्ष क्या जताना चाहता है? जब विपक्ष के लिए जानलेवा विपदा भी सत्ता हथियाने एवं सरकार को नाकाम साबित करने का एक मौका मात्र हो तो लोकतंत्र कैसे मजबूत हो सकता है?

कांग्रेस पार्टी ने सबसे लम्बे समय तक देश पर शासन किया, पर प्रश्न है कि विपक्ष की भूमिका में वह नकारा एवं निस्तेज क्यों है? यह अत्यन्त दुर्भाग्य का विषय है कि विरोधी पार्टी के रूप में नायकत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी अपने अपरिपक्व केन्द्रिय नेतृत्व, अन्तर्कलहों, गलत नीतियों, अन्दरूनी भ्रष्टाचार और अराष्ट्रीय सोच के कारण प्रभावहीन होती जा रही हैं, जबकि उससे सशक्त और सार्थक भूमिका की आवश्यकता है। अन्य कोई राजनीतिक दल ऐसे प्रभावी विपक्ष के रूप में दिखाई नहीं देता। यह हो सकता है कि वर्तमान सत्तासीन पार्टी सही राह पर है, विकास की प्रभावी योजनाओं को लागू कर रही है, देश की सुरक्षा एवं रक्षा में भी उसने प्रभावी उपक्रम किये हैं, विदेशों में भारत की छवि को चार चांद लगाये हैं। लेकिन इतना सब होने पर भी सशक्त एवं आदर्श लोकतंत्र के लिये सशक्त विपक्ष होना नितान्त अपेक्षित है। शक्तिशाली विपक्ष के अभाव में संसद के दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त, जिसकी संभावना है, सत्तासीन दल के हाथों सत्ता का दुरुपयोग भी हो सकता है। लोकतंत्र में यह स्थिति अवांछित है। अतः भारत की राजनीतिक संरचना में सशक्त विपक्ष की आवश्यकता है। जनता में भरोसा उत्पन्न कर विपक्ष को अपनी छवि का निर्माण करने की आवश्यकता है। विपक्षी पार्टियां जो अपनी भूमिका के प्रति सचेत भी हो रही हैं, लेकिन भ्रष्टाचार, परिवारवादी संकीर्ण सोच एवं अराष्ट्रवादी नीतियों के कारण अपनी छवि बिगाड़ने की ही अधिक कोशिश कर रही हैं।

हम हिन्दुस्तानी अक्सर इस बात पर गर्व करते हैं कि हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है और नागरिकों की आशा-आकांक्षाओं के अनुरूप प्रशासन देने वाला, संसदीय प्रणाली पर आधारित इसका मजबूत संविधान है। पर इसके बावजूद राजनीतिक प्रक्रिया में विपक्षी दलों की लगातार साख गिरने, उनमें भ्रष्टता, परिवारवाद एवं अराष्ट्रीय सोच को लेकर आम लोगों में अरुचि और अलगाव बहुत साफ दिखाई देता है, खासतौर से मध्यवर्ग, कामकाजी प्रफेशनल्स

कांग्रेसी कब करेंगे राहुल प्रियंका गांधी के खिलाफ विद्रोह

पांच राज्यों की विधान सभा चुनाव के नतीजों का गंभीरता से आकलन करने के बाद कांग्रेस का समाधि लेख लिखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में कांग्रेस को मतदाताओं ने सिरे से खारिज कर दिया। इन नतीजों के बाद किसी को शक नहीं रहना चाहिए कि यदि गांधी परिवार से कांग्रेस का पीछा नहीं छुड़ाया गया तो 2024 तक इसका कोई नामलेवा भी नहीं रहेगा। चुनाव आयोग ने 9 जनवरी को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी, उसके बाद प्रियंका गांधी ने 42 जगह रोड शो और घर-घर सम्पर्क का अभियान किया। उन्होंने नुक्कड़ सभाओं, वर्चुअल रैलियों आदि के जरिये 340 विधान सभा क्षेत्रों में सम्पर्क किया, इसमें उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर के दौरे भी शामिल हैं। राहुल गांधी ने भी उत्तर प्रदेश में काफी वक्त बिताया पर अपनी बहन की तुलना में थोड़ा कम। छतीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सचिन पायलेट, दीपेन्द्र हुड्डा, शायर और कांग्रेस के मिनोरिटी सेल के चीफ इमरान प्रतापगढ़ी आदि जमीन पर दिखे। इमरान प्रतापगढ़ी ने अकेले छह दर्जन सभाएं की। पर इन सभाओं और प्रयासों के नतीजे सिफर निकले। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के सामने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, जे.पी. नड्डा, राजनाथ सिंह जैसे शिखर नेता थे। जैसी उम्मीद थी वही हुआ। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में फिर करारी शिकस्त मिली। अब आप समझ लें कि 1989 से कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर है। वहां उसके अंतिम मुख्यमंत्री वीर बाहदुर सिंह थे। यह वही उत्तर प्रदेश है जो कि कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था और नेहरू परिवार का निवास भी।

अगर अब भी कांग्रेस के अनुभवी नेताओं ने नेहरू-गांधी परिवार की गुलामी नहीं छोड़ी तो उनकी पार्टी बहुत जल्दी इतिहास की किताबों में आ जाएगी। अब कांग्रेस को जिन्दा रखना है तो उसकी कमान ऐसे नेता को देनी ही होगी जिसमें निर्णय लेने की क्षमता के साथ साथ दूरदृष्टि भी हो। कांग्रेस के लिए अभी उम्मीद की एक ही किरण है अशोक गहलोत। पर क्या वे मुख्यमंत्री की कुर्सी को त्याग कर पार्टी की कमान अपने हाथ में लेंगे? इस बात की उम्मीद भी कम ही है। याद करें कि इन पांच राज्यों के चुनावों से पहले राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनावों में जहां पर भी रैलियां की वहां पर कांग्रेस को मतदाताओं ने नकारा। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में अपना खाता भी नहीं खोला। जिस पार्टी से पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल और चितरंजन दास जैसे जन नेताओं का संबंध रहा है, वह पार्टी अंतिम सांसें ले रही है। यह दुखद स्थिति है। उसका वजूद समाप्त हो रहा है। उसे बचाने की कहीं कोशिश होती नजर तक नहीं आ रही। कांग्रेस की हार के लिए गांधी परिवार के साथ-साथ पार्टी के कुछ दूसरे नेताओं को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। कांग्रेस में कपिल सिब्बल, पी.चिदंबरम, अभिषेक मनु सिंघवी समेत दर्जनों तथाकथित नेता हैं जिनका जनता से कोई संबंध तक नहीं है। ये लुटियन दिल्ली के बड़े विशाल सरकारी बंगलों में रहकर कागजी राजनीति करते हैं। इनमें से अधिकतर बड़े मालदार कमाऊ वकील हैं। वकालत से थोड़ा बहुत वक्त मिल जाता है, तो ये टाइम पास करने के लिये और खबरों में बने रहने के लिये सियासत भी करने लगते हैं। ये मानते हैं कि खबरिया चैनलों की डिबेट में आने मात्र से ही वे पार्टी की महान सेवा कर रहे हैं।

प्रियंका गांधी बार-बार कहती रहीं कि वो उत्तर प्रदेश में रहकर ही काम करेंगी। तो फिर उन्होंने चुनाव क्यों नहीं लड़ा। वो चुनाव लड़ने से क्यों भागती हैं? वो नेता ही क्या, जिसे चुनाव लड़ने से डर लगता हो। याद करें जब हिजाब विवाद चल रहा था, तो उन्होंने एक जगह कहा था- 'लड़कियों को हिजाब पहनने का अधिकार है। अगर कोई बिकिनी पहनना चाहे तो वह भी पहन सकता है।' क्या राष्ट्रीय दल की नेता को इतना सड़क छाप बयान देना चाहिए? प्रियंका गांधी किस आधार पर स्कूलों में हिजाब पहनने के हक में बोल रही थीं? उन्हें बताना चाहिए। क्या भारत में कोई बिकिनी पहनकर स्कूल में आएगा? प्रियंका गांधी को समझ होनी चाहिए कि देश का मतदाता सब कुछ देखता है। पिछले साल सितंबर में राहुल और प्रियंका गांधी के आशीर्वाद से जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता कन्हैया कुमार की कांग्रेस में एंट्री हुई थी। ये वही कन्हैया कुमार थे जो कहते थे कि भारतीय सेना के जवान कश्मीर में बलात्कार जैसे घिनौने कृत्य कर रहे हैं।क्या कांग्रेस भी कन्हैया कुमार के बेतुके और बेहूदगी भरे आरोपों के साथ खड़ी थी? प्रियंका गांधी ने कभी बताया नहीं कि कन्हैया कुमार किसलिए और किस आधार पर सरहदों की रक्षा करने वाली भारतीय सेना पर आरोप लगाते रहे हैं? आप अगर देश विरोधी तत्वों का साथ दोगे तो फिर आपको चुनावों में जनता जवाब तो देगी ही।

दरअसल न तो राहुल जनता का मिजाज और राजनीति जानते हैं और न ही प्रियंका। इनकी किसी भी अहम सवाल पर कोई धीर-गंभीर राय नहीं होती। राहुल गांधी की चाहत है कि वे नरेंद्र मोदी का स्थान ले लें। प्रियंका की भी इच्छा है कि वह दूसरी इंदिरा गांधी बने। लेकिन दोनों भारत को अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं। यही वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति बेहद शर्मनाक हो गई है। अगर ये दोनों पार्टी में बरकरार रहते हैं तो कांग्रेस के अंतिम संस्कार की राख भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। लगता है कि दोनों ने कांग्रेस की कपाल क्रिया करने का पूरी तरह मन बना लिया है। दोनों अपने मकसद की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। पंजाब में भी सब ठीक ठाक ही चल रहा था। इन दोनों ने राजनीति के धाकड़ कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नॉन सीरियस मसखरे इंसान को पार्टी का मुखिया बन दिया। इनके फैसलों का नतीजा सबके सामने है। पिछले यानी 2019 के लोकसभा चुनाव को जरा याद कर लेते हैं। तब ही केरल और पंजाब को छोड़कर कहीं भी कांग्रेस का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा था। पंजाब में कांग्रेस पूर्व पटियाला नरेश कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व के कारण ही जीती थी। उसी कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ राहुल गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को खड़ा किया। सिद्धू राहुल गांधी का प्रिय है। कैप्टन के न चाहने के बाद भी सिद्धू को कांग्रेस में एंट्री मिली थी। राहुल गांधी ने सिद्धू को सारे देश में प्रचार के लिए भेजा था। सिद्धू ने सभी जगहों में जाकर भाजपा और मोदी जी के खिलाफ अपनी गटर छाप भाषा का इस्तेमाल किया। यह सब जनता देख रही थी। सिद्धू जहां भी गए वहां पर उनकी पार्टी परास्त ही हुई। वैसे लोकतंत्र में वाद-विवाद-संवाद तो होते ही रहना चाहिए। संसद में भी खूब सार्थक बहस होनी चाहिए। यह लोकतंत्र की मजबूती के लिए पहली शर्त है। पर लोकतंत्र का यह कब से अर्थ हो गया कि आप अपने राजनीतिक विरोधी पर लगातार टुच्चे किस्म के निराधार आरोप लगाते रहें।

कांग्रेस में केन्द्रीय नेतृत्व लगातार कमजोर हो रहा है। वह पार्टी को कहीं विजय नहीं दिलवा पा रहा है। केन्द्रीय नेतृत्व तब ताकतवर होता है जब उसकी जनता के बीच में कोई साख होती है। लेकिन हैरानी होती है कि कांग्रेस में केन्द्रीय नेतृत्व यानी सोनिया गांधी और उनके बच्चों के खिलाफ विद्रोह क्यों नहीं होता है।

- आर.के. सिन्हा

हरीश रावत ने पंजाब और उत्तराखंड में कांग्रेस को तापा

सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने सलाहकारों की राजनीतिक करतूतों और उनकी नासमझी की भयंकर कीमत चुका रहे है। राजनीतिक कीमत इतनी खतरनाक और आत्मघाती है कि कांग्रेस के नीचे की जमीन खिसक रही है और उन्हें इसकी न तो चिंता है और न ही वे अपने सलाहकारों के समूह को चाकचौबंद करने की कोई प्रयास कर रहे हैं। सोनिया गांधी परिवार का एक राजनीतिक सलाहकार हैं, जिनका नाम है हरीश रावत है। हरीश रावत अभी-अभी उत्तराखंड विधान सभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार थे पर वे चुनाव हार गये, वे कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष भी थे। आमतौर पर यह माना जाता है कि जो चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष होते हैं वहीं पार्टी की ओर से मुख्य चेहरा होते हैं और पार्टी की हार-जीत उन्हें की काबिलियत पर निर्भर करती है।

गंभीर बात यह है कि जो हरीश रावत खुद चुनाव नहीं जीत पाये तो वह कांग्रेस को किस प्रकार से उत्तराखंड में सत्ता दिलाते? चुनाव परिणामों के पूर्व तक यह उम्मीद की जा रही थी कि उत्तराखंड में कांग्रेस का न केवल प्रदर्शन अच्छा रहेगा बल्कि कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है, भाजपा की सत्ता छीन सकती है। लेकिन यह उम्मीद नाउम्मीदी में तब्दील हो गयी और कांग्रेस की उत्तराखंड में सरकार बनाने की इच्छा जमींदोज हो गयी। अब एक और पांच साल कांग्रेस उत्तराखंड में हाशिये पर खड़ी रहेगी। निश्चित तौर पर उत्तराखंड की स्थिति और हार कांग्रेस के लिए एक सबक है और कांग्रेस की हार के लिए सिर्फ और सिर्फ हरीश रावत की अति महत्वाकांक्षा, पुत्री-परिवार प्रेम, मुस्लिम प्रेम और चमचा प्रेम जिम्मेदार हैं।

आप अगर यह सोच रहें होंगे कि हरीश रावत ने सिर्फ उत्तराखंड में ही कांग्रेस तापा है या फिर कांग्रेस की लूटिया डूबोयी है तो फिर आप गलतफहमी में हैं। हरीश रावत ने पंजाब में भी कांग्रेस को तापा है, पंजाब में कांग्रेस की हार के लिए बुनियाद रखने वाले हरीश रावत ही हैं। वह कैसे? आपको याद होना चाहिए कि पंजाब में कांग्रेस के अंदर वर्चस्व की लड़ाई शुरू कराने वाले और कोई नहीं बल्कि हरीश रावत ही हैं। हरीश रावत पंजाब में कांग्रेस के प्रभारी थे। हरीश रावत के बारे में प्रचारित यह है कि वे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अति विश्वासपात्र हैं। जब कोई नेहरू खानदान का अतिविश्वासी बन जाता है तो फिर उसकी कांग्रेस में चमक-धमक, वर्चस्व बढ़ जाते है, उसका खेला सिर चढ़ कर बोलता है। हरीश रावत के सिर पर चमक-धमक, वर्चस्व और खेला दो तरह से चढ़कर बोल रहा था। एक तो हरीश रावत उत्तराखंड के सर्वेसर्वा नेता हो गये, उनकी इच्छा के बिना उत्तराखंड में पत्ता तक नहीं हिलने लगा, कांग्रेस की सभी नियुक्तियों में उनकी इच्छा सर्वोत्तम मानी गयी। दूसरे में वे कांग्रेस के केन्द्रीय कमिटी में भी शक्तिमान बन गये। उन्हें पंजाब में कांग्रेस का प्रभारी बना दिया गया। हरीश रावत उस पंजाब में कांग्रेस के प्रभारी बना दिये गये जिस पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और अमरिंदर सिंह कांग्रेस सरकार के मुख्यमत्री थे। अमरिन्दर सिंह की खासियत और विश्वसनीयता कौन नहीं जानता है?

अमरिंदर सिंह ही वह शख्त थे जो अपने दम पर कांग्रेस को पंजाब में स्थापित और गतिशील करते रहे थे। अकालियों से कांग्रेस ने जो सत्ता छिनी थी उसके पीछे भी अमरिन्दर सिंह की शख्सियत रही थी। अकालियो से सत्ता छिनना कोई आसान काम नहीं था, बहुत ही कठिन काम था। लेकिन वह कठिन काम भी अमरिंदर सिंह ने कर दिखाया था। पंजाब में अमेरिन्दर सिंह की सहजता और कार्यकुशलता के लोग बहुत ही दिवाने रहे हैं। वे हर कोई को मदद करने का काम करते रहे थे। पांच साल का उनका कार्यकाल कोई बहुत बुरा नहीं था, उन पर भ्रष्टचार और निरंकुशता का कोई प्रभावकारी शिकायतें नहीं थी। राजनीतिक हलकों में यह उम्मीद भी नहीं थी कि अमरिन्दर सिंह को इस तरह से कांग्रेस अपमानित करेगी और उन्हें मुख्यमंत्री के पद से अपमानित कर हटा देगी?

हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस के प्रभारी के रूप में कोई एक नहीं बल्कि कई करतूतों को अंजाम देने का काम किया। सबसे पहले तो उन्होंने अमरिन्दर सिंह को हटवाने और उनके खिलाफ साजिश रचने के काम किये। नवजीत सिंह सिद्धु को हथकंडा बनाया। नवजोत सिंह सिद्धु की महत्वाकांक्षा की आग में हरीश रावत ने घी डाला। आग में जब घी पड़ती है तो आग भयानक हो जाती है। ठीक इसी प्रकार सिद्धु की अति महत्वाकांक्षा भयानक हो गयी। मंत्री के रूप में नौटंकी करने वाले सिद्धु को एकाएक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के साथ ही साथ सिद्धु की मुख्यमंत्री बनने की इच्छाएं अति हो गयी। सिद्धु को हरीश रावत का साथ मिला। हरीश रावत और सिद्धु की साजिश से विधायकों ने बगावत की। हरीश रावत ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को समझा दिया कि अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस नहीं जीतेगी, इसलिए सिद्धु को मुख्यमंत्री बना दिया जाये। अमरिंदर सिंह के कारण सिद्धु मुख्यमंत्री नहीं बन पाये। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बन गये। चरणजीत सिंह और सिद्धू के बीच कैसी राजनीतिक लड़ाई हुई, यह भी जगजाहिर है।

अगर अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ती तो फिर कांग्रेस की पंजाब में इतनी बूरी स्थिति नहीं होती और न ही आम आदमी पार्टी की इतनी बड़ी जीत मिलती। लेकिन हरीश रावत की करतूत का खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। अब पंजाब में भी कांग्रेस बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, आंध्रप्रदेश की तरह कभी भी सत्ता के लायक नहीं समझी जायेगी और चौथे-पाचवें नंबर की पार्टी बन कर रहेगी। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी, अकाली दल और भाजपा ही मुख्य सत्ता के दावेदार बने रहेंगे। असम में भी प्रभारी के रूप में उनकी भूमिका नकारात्मक थी।

उत्तराखंड में भी विधान सभा चुनाव के पूर्व हरीश रावत की जगह किसी दूसरे के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट हुई थी। कांग्रेस का चुनाव प्रभारी देवेन्द्र यादव भी हरीश रावत पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहे थे। देवेन्द्र यादव किसी अन्य कांग्रेसी को पार्टी का मुख्य चुनावी चेहरा बनाने के समर्थक थे। लेकिन हरीश रावत ने कांग्रेस को ब्लैकमेल करने का काम किया। प्रचारित यह कराया कि अगर उनके नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव नहीं लडेगी तो फिर कांग्रेस सत्ता में नहीं आयेगी। कुछ विद्राही ट्विट कर चुनौती भी दी। जिसके कारण सोनिया गांधी और प्रियंका-राहुल का मौन समर्थन हरीश रावत को मिल गया।

उत्तराखंड में टिकट वितरण में हरीश रावत

विपक्ष होता है। आज आम आदमी महंगाई, व्यापार की संकटग्रस्त स्थितियां, बेरोजगारी, महिला असुरक्षा, पर्यावरण आदि समस्याओं से परेशान है, ये स्थितियां विपक्षी एकता के उद्देश्य को नया आयाम दे सकती है, क्यों नहीं विपक्ष इन स्थितियों का लाभ लेने को तत्पर होता। बात केवल सशक्त विपक्ष की ही न हो, बात केवल मोदी को परास्त करने की भी न हो, बल्कि देश की भी हो तो आज विपक्ष इस दुर्दशा का शिकार नहीं होता। वह कुछ नयी संभावनाओं के द्वार खोलता, देश-समाज की तमाम समस्याओं के समाधान का रास्ता दिखाता, सुरसा की तरह मुंह फैलाती महंगाई, अस्वास्थ्य, बेरोजगारी, आर्थिक असंतुलन और व्यापार की दुर्दशा पर लगाम लगाने का रोडमेप प्रस्तुत करता, कोरोना से आम आदमी, आम कारोबारी को हुई परेशानी को उठाता तो उसकी स्वीकार्यता बढ़ती। व्यापार, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, ग्रामीण जीवन एवं किसानों की खराब स्थिति की विपक्ष को यदि चिंता है तो इसे उनके कार्यक्रमों एवं बयानों में दिखना चाहिए।

लोकतंत्र का मूल स्तम्भ विपक्ष मूल्यों की जगह कीमत की लड़ाई लड़ता रहा है, तब मूल्यों को संरक्षण कौन करेगा? सत्ता हासिल करने एवं मोदी विरोध का एक खामोश किस्म का 'सत्ता युद्ध' देश में जारी है। एक विशेष किस्म का मोड़ जो हमें गलत दिशा की ओर ले जा रहा है, यह मूल्यहीनता और कीमत की मनोवृत्ति, अपराध प्रवृत्ति को भी जन्म दे सकता है। हमने सभी विधाओं को बाजार समझ लिया। जहां कीमत कद्दावर होती है और मूल्य बौना। सिर्फ सत्ता को ही जब विपक्ष या राजनीतिक दल एकमात्र उद्देश्य मान लेता है तब वह राष्ट्र दूसरे कोनों से नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तरों पर बिखरने लगता है। क्या इन विषम एवं अंधकारमय स्थितियों में विपक्षी दल कोई रोशनी बन सकते हैं, अपनी सार्थक भूमिका के निर्वाह के लिये तत्पर हो सकते हैं? ■

और युवा आबादी में। शायद यही वजह है कि आज मुश्किल से ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, जिसकी राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने में कोई दिलचस्पी हो। इस वर्ग का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए विपक्षी दलों में जोरदार होड़ मची हुई है। लेकिन विसंगतिपूर्ण विपक्षी राजनीति सोच और उनके नेताओं के बारे में शिक्षित और मध्यवर्गीय आबादी के नजरिए में अंतर न लाया जा सका है।

स्वतंत्र विचारों वाले जागरूक नागरिकों द्वारा हर सरकार के कामकाज और विपक्ष की भूमिका निभाने वाले नेता एवं पार्टी का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यह उन्हें अपनी चुनावी घोषणाओं या जीतने के बाद किए गए वायदों के प्रति उत्तरदायी बनाएगा। हमें ऐसे मंच तैयार करने चाहिए जो भारत के उन युवाओं, प्रफेशनल्स और ऊर्जावान नागरिकों को एक साथ लाएं और आपस में जुड़ने का अवसर दें, जो इस देश की तस्वीर बदलना तो चाहते हैं लेकिन ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि उनके पास मंच नहीं है। मजबूत विपक्षी नेतृत्व को तैयार करने के लिए हमें उनकी ऊर्जा को सही चैनल देने की पहल करनी होगी। यही युवा, सक्रिय नागरिक और प्रफेशनल अपने पेशे, अपने तौर-तरीकों और नागरिकों मूल्यों की वजह से दूसरों के लिए रोल मॉडल की भूमिका निभाते हुए प्रभावी विपक्ष या नयी सोच वाले राजनीतिक दल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तभी देश वास्तविक रूप से विकास की ओर उन्मुख हो सकेगा और विश्व में देश को गौरव दिला सकेगा।

विपक्षी दलों और उनके गठबंधनों ने वैचारिक, राजनीतिक और आर्थिक आधार पर सत्तारूढ़ दल भाजपा की आलोचना तो व्यापक की, पर कोई प्रभावी विकल्प नहीं दिया। किसी और को दोष देने के बजाय उसे अपने अंदर झांककर देखना चाहिए। लोकतंत्र तभी आदर्श स्थिति में होता है जब मजबूत

की इच्छा ही सर्वोपरि रही थी। हरीश रावत पर आरोप है कि उन्होंने पैसे वाले और चमचे टाइप के लोगों को टिकट दिलवाये। हरीश रावत ने अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को कांग्रेस से बाहर जाने के लिए मजबूत कर दिया। किशोर उपाध्याय भाजपा में शामिल होकर विधायक बन गये।

उन्होंने कुछ दलबदलुओं को भी टिकट दिलवाये और कांग्रेस में शामिल कराये। वे खुद चुनाव लड़ रहे थे फिर अपनी बेटी को भी कांग्रेस का टिकट दिलवा दिया। जनता के बीच संदेश यह गया कि जो हरीश रावत अपने साथ ही साथ बेटी को भी चुनाव लड़वा रहा है, वह मुख्यमंत्री बनने के बाद भी परिवारवादी ही बना रहेगा। इसके अलावा जो कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता थे उनकी घोर उपेक्षा हुई।

हरीश रावत का घोर और आत्मघाती मुस्लिम प्रेम कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा। उत्तराखंड देव भूमि है। इस देवभूमि में आम जनता की आस्थाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हरीश रावत ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात की थी। जैसे ही मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापित कराने की बात उजागर हुई वैसे ही उत्तराखंड में राजनीतिक उफान मच गया। भाजपा इसका लाभ उठाने की उठायी। देवभूमि हिन्दू वाहिणी के डीडी पांडेय और जगदीश भट्ट ने चुनाव के दौरान इसे मुद्दा बना दिया और पूरे प्रदेश में जमकर अभियान चलाया। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि भाजपा से खफा लोग भी कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम के विरोधी हो गये। यह एक राजनीतिक नासमझदारी का प्रसंग है। मुस्लिम भाजपा को कभी वोट करते नहीं हैं। उत्तराखं डमें भाजपा के खिलाफ कांग्रेस ही मैदान में थी। मुसलमानों के सामने कांग्रेस एक मात्र विकल्प थी। अगर ऐसी घोषणा नहीं भी करते तो भी मुसलमान कांग्रेस को ही वोट देते। एक बार पूर्व भी कांग्रेस को इसी तरह हरीश रावत ताप चुके हैं। हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे और सरकार कांग्रेस की थी तब उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को नमाज पढ़ने के लिए दो घंटे की छुट्टी दी थी। इसके कारण भी कांग्रेस का नुकसान हुआ था। उस समय भी मुख्यमंत्री के पद पर रहते हरीश रावत विधान सभा का चुनाव हार गये थे।

कांग्रेस आलाकमान अनुभवों और युवाओं की परिभाषा समझ नहीं पा रही है। अनुभव के नाम पर हरीश रावत, पी चिदम्बरम जैसे चूके हुए नेताओं को ही आगे बढ़ाता है, युवाओं के नाम पर सिर्फ बड़े घरानों के खानदानी युवाओं को ही संगठन मे जिम्मेदारी मिलती है। जिसके कारण कांग्रेस की यह दुर्गति हो रही है। अगर कांग्रेस आलाकमान ने हरीश रावत की ऐसी राजनीतिक करतूतों पर लगाम लगायी होती तो फिर पंजाब और उत्तराखंड में कांग्रेस की ऐसी दुर्गति और फजीहत नहीं होती।

- आचार्य श्री विष्णुगुप्त

पुणे रेल्वे स्टेशन बना लूट का अड्डा

● स्वाति, रेणुका साहू
एवं सुरेशचंद्र अवस्थी

आये दिन नये कारनामे पुणे रेल्वे स्टेशन पर होते ही रहते हैं. पुने जीआरपी पुलिस की मिलीभगत और इसके साथ ही रेल्वे के अधिकारी भी मिले हुए लगते हैं. फिर एक नये कंप्लेंट की कॉपी संलग्न की गयी है। मामला है –

पुना रेल्वे स्टेशन पर गैर कानूनी सेनिटाइजर की खरीद बिक्री

कोरोना ने बीते साल 2 – 3 सालों से पुरी दुनिया का हाल – बेहाल कर रखा है. लाखो लोगो कों विश्व व्यापी मंदी के चलते कम्पनी बंद होने के वजह से नौकरी से निकाल दिया गया. वहीं छोटे – बड़े कारोबारियों का कारोबार भी पुरी तरह से ध्वस्त हो गया है. आवक न होने से किराया न देने की वजह से कई लोगों को सड़क पर आना पड़ा है। जहां कोरोना की मार झेलते – झेलते सारी दुनिया त्राही – त्राही हो गयी। वहीं कुछ लोगों ने इस विश्वव्यापी त्रासद का भी फायदा उठाया है। इस संकट की घड़ी में भी कुछ लोगो ने न कि सिर्फ अपना गोरखधंदा जारी रखा बल्कि पुरजोर गैरकानूनी रुप से कमाया भी है। यूं तो इस तरह की घटना देश के कई जगहो पर घटित हुई होगी, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं, पुना स्टेशन पर चलने वाले गैरकानूनी सेनिटाइजर के खरीद – बिक्री की। इन दिनों पुना रेल्वे स्टेशन गैर कानूनी सेनिटाईजर की खरीद बिक्री का अड्डा बना हुआ है।

घटना तारीख 11. 12. 2021 की है। हमारे रिपोर्टर द्वारा complaint 11. 12. 2021 को GRP थाना पुना मे अर्जी की जिसमें आज तारीख तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

जहां एक ओर कुछ लोगों से कोरोना जैसी गम्भीर संक्रमित बिमारी ने उनका सबकुछ छिन लिया वहीं इसने लोगों को माला – माल बनाने का काम भी किया है. सेनिटाइजर और मास्क कोरोना से निपटने के महत्त्वपूर्ण साधन बने, लेकिन लोगों ने इनकी कालाबाजारी करके भी अमानवीयता फैला दी. लेकिन अफसोस इस बात का है, कि इस गैरकानूनी गोरखधंधे के विरुध कोई गम्भीर कदम नहीं उठाया गया है।

कोरोना महामारी की इस विश्वव्यापी आपदा में वैश्विक कम्पनीयों ने भी वैश्विक कालाबाजारी करके खूब पैसा कमाया है। सेनिटाइजरर्स की विश्वस्तरिय कालाबाजारी के विषय में कहें, तो अमेरिका की भी बहुत सी कम्पनीज ने गैरकानूनी को वैश्विक बाजार में बेचा है।

लेकिन इन गैरकानूनी रुप से हो रहे सेनिटाइजर के व्यापार को रोकने के लिये पूना रेल्वे स्टेशन में कोई रोकथाम नहीं हो पा रहा है। क्योंकि रेल्वे अधिकारी और सेनिटाइजर डीलर्स के बीच सांठ – गांठ बहुत पक्की चल रही है। इसलिये इस भ्रष्टाचार का तोड़ निकल पाना मुश्किल हो गया है। पुना रेल्वे स्टेशन पर सेनिटाइजर को लेकर यह गैरकानूनी खरीद – बिक्री अत्यंत अमानवीय क्रत्य है। प्रशासन और कानून से यह सवाल है, कि क्या पुना रेल्वे स्टेशन को इस प्रकार के कालाबाजारी से निजात मिल पायेगा ?

पुना रेल्वे स्टेशन पर जनता खाना विलुप्त

हम सभी जानते हैं, कि जनता खाना हर रेल्वे स्टेशन पर आम जनता की भुख मिटाने के लिये केवल 15 रुपये की थाली होती है, जिसमें पूरी और आलु की सब्जी के साथ आचार होता है। इसकी शुरुआत आमजन यात्रियों की जेब और सुविधा को ध्यान में रख कर की गयी थी। लेकिन जनता खाना स्टाल मालिकों और रेल्वे अधिकारीयों की मिली भगत ने जनता खाना योजना को ध्वस्त कर दिया है. जनता खाना स्टोल पर लोग घंटों खड़े – खड़े जनता खाना मांगते रह जाते हैं। लेकिन यह आम जनता स्टाल के कर्मचारी आम लोगों की बड़ी ही बेबाकी से अनदेखी कर देते हैं। और सर्वप्रथम ज्यादा पैसे देनेवाले ग्राहकों को टेस्टी खाना उपलब्ध

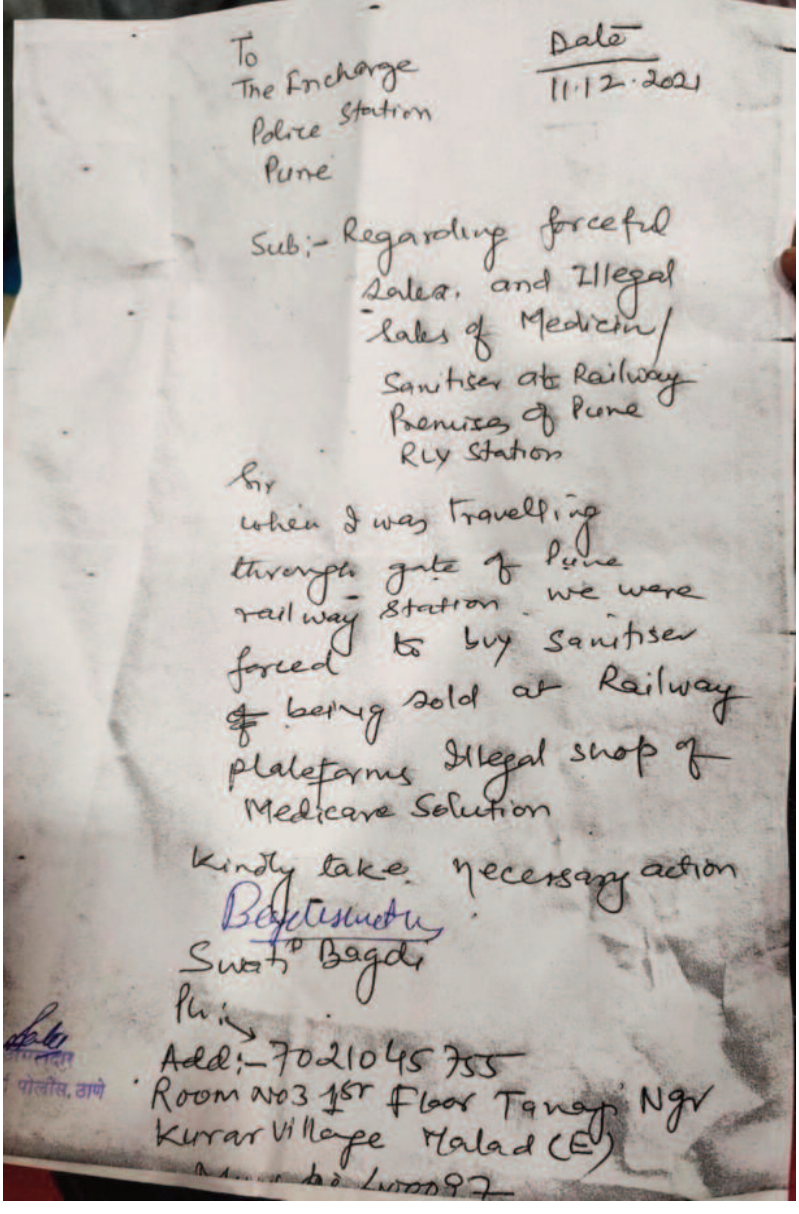

To
The Incharge
Police Station
Pune

Date
11.12.2021

Sub:- Regarding forceful sales, and Illegal sales of Medicine/ Sanitiser at Railway Premises of Pune Rly Station

Sir
when I was travelling through gate of Pune railway station we were forced to buy sanitiser & being sold at Railway platforms Illegal shop of Medicare Solution

Kindly take necessary action

Swati Bagdi
Ph:-
Add:- 7021045755
Room No3 1st Floor Tanaji Ngr
Kurar Village Malad (E)
Mumbai-400097

करवाया जाता है। और जनता खाना मांगने वाले आम जन उपेक्षित महसूस कर के लौट जाते हैं. इस प्रकार पुना रेल्वे स्टेशन में जनता खाना योजना फैल होती नजर आ रही है। और कुछ स्वार्थी, भ्रष्टाचारी लोगों की वजह से पूना रेल्वे स्टेशन पर जनता खाना योजना होती जा रही है।

पुना रेल्वे स्टेशन पर बढ़ता क्राइम

पूणे रेल्वे स्टेशन पर आये दिन कोई – न – कोई घटना घटती ही रहती है। पता नहीं ये गुनाहों का सिलसिला कहां जाकर रुकेगा। इन्हीं गम्भीर गुनाहों में से कुछ गुनाहों पर हम यहां प्रकाश देगें।

पुणे रेल्वे स्टेशन, एक पोलिस इंस्पेक्टर ने गोली खाई

2018 से पुना रेल्वे स्टेशन लगातार गुनाहों में सुर्खियों में रहा है।

बताया गया, कि 22.2018 पुणे रेल्वे स्टेशन पर एक संदिग्ध व्यक्ति ने इंस्पेक्टर गजानन पवार को दिन दहाडे गोली मार दी।

मामला था, एक महिला की हत्या का. महिला एकता भाटि की हत्या कर दी गई थी, जिसकी जांच इंस्पेक्टर गजानन पवार कर रहे थे। इसी मामले को लेकर पुणे रेल्वे स्टेशन के नम्बर 2 प्लेट फार्म पर कुछ संदिग्ध लोगों ने इंस्पेक्टर गजानन पवार पर 2-3 गोलियां चला दी। यह गोलियां इंस्पेक्टर पवार के पेट पर लगी और वे गम्भीर रुप से घायल हो गये। बताया गया है, कि इंस्पेक्टर गजानन पवार पुणे क्राइम ब्रांच के यूनिट 2 में पोस्टेड थे।

16:52

Early on Wednesday morning, Ekta Bhati, 37, who runs her own catering business, was shot dead by two persons at her home in Chandannagar. The assailants shot her dead while she was climbing down the staircase of her housing society.

Forensic experts gather evidence from platform number 3 of the Pune railway station where inspector Gajanan Pawar was shot at on Wednesday evening. (HT)

Updated on Nov 22, 2018 04:38 PM IST

OPEN APP

Hindustan Times, Pune | By Shalaka Shinde, Pune

Pune witnessed three incidents involving guns being fired on Wednesday, two of which were linked. One woman was shot dead and a police …

16:48

THE TIMES OF INDIA

… abducted and raped in Pune; 8 held

PTI | Updated: Sep 6, 2021, 17:09 IST

Representative image

PUNE: A 14-year-old girl was allegedly abducted from the Pune railway station area and raped at multiple places in the city in Maharashtra, police said on Monday.

ELECTION
Watch Now

NEWS CITY TOI+ ETIMES VIDEOS

14 साल की नाबालिग के साथ हुआ पुणे रेल्वे स्टेशन पर अत्याचार

यह दर्दनाक घटना सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जायेगे। बता दे कि बीते दिनों पुणे रेल्वे स्टेशन से एक 14 साल की नाबालिग बच्ची को अगवा कर लिया गया था। और 31 सेप्टेम्बर से लेकर लगभग 8 लोग कई दिन तक बच्ची का बलात्कार करते रहे।

इस प्रकार पुना रेल्वे स्टेशन पर घटित घटनाऐं पुना रेल्वे स्टेशन की कमजोर प्रशासन प्रणाली और गैरजिम्मेदारी की ओर ईशारा करती है।

अगर अब भी प्रशासन इसके खिलाफ जागरूक होकर कार्यवाही नहीं करेगा तो ये जुर्म का सिलसिला चलता ही रहेगा। और गुनाहों की घटना भी बढ़ती रहेगी।

फसल की बर्बादी ने बढ़ाई खाने की थाली की कीमत

● रिचर्ड महापात्र एवं शगुन कपिल

दुनियाभर में खाद्य मुद्रास्फीति अप्रत्याशित ऊंचाई पर पहुंच गई है। चरम मौसम की घटनाओं से फसलों को पहुंचा नुकसान इसके मूल में है। इस दुष्चक्र को तभी तोड़ा जा सकता है जब किसानों के पास मौसम के पूर्वानुमान का मजबूत तंत्र और फसलों का प्रभावी बीमा हो।

कर्नाटक के मांड्या जिले के मालावल्ली तालुका में रहने वाले वेंकटेश और धर्मप्पा को बीमा कंपनियों और स्थानीय कृषि विभाग से मदद नहीं मिलती।

भारत की थोक मुद्रास्फीति दर नवंबर 2021 में 14.23 प्रतिशत के साथ तीन दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। 14 जनवरी 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार, अगले महीने यानी दिसंबर 2021 में 1.95 की प्रतिशत के मामूली गिरावट के साथ यह दर 13.56 प्रतिशत रही।

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) हमेशा चिंता का विषय रहता है, क्योंकि इससे खुदरा (रिटेल) मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाती है। महंगाई का लगातार बढ़ना वास्तव में चिंताजनक है। दिसंबर 2021 लगातार नौंवा महीना था जब डब्ल्यूपीआई में वृद्धि दहाई के आंकड़ों में हुई। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह स्थिति वित्त वर्ष के आखिर यानी मार्च तक रह सकती है।

दिसंबर में मुद्रास्फीति का बढ़ना अप्रत्याशित था, क्योंकि सरकार ने मुद्रास्फीति के बड़े कारक ईंधन पर टैक्स घटा दिया था। तो अब सवाल उठता है कि इसके बाद भी मुद्रास्फीति क्यों अधिक थी? इसके पीछे यह कारण उभरकर आया है कि खाद्य महंगाई, खासकर सब्जियों और अनाज की कीमत में वृद्धि इस मुद्रास्फीति की जड़ में है।

भारत में थोक मुद्रास्फीति नवंबर 2021 में प्राथमिक खाद्य पदार्थों की महंगाई के कारण 13 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। बहुत से राज्यों में मौसमी सब्जियों के भाव आसमान पर पहुंच गए। फसलों को पहुंचे इस नुकसान के मूल में चरम मौसम की घटनाएं रहीं और यह प्रवृत्ति केवल भारत तक सीमित नहीं थी।

दुनियाभर में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ रही है। 17 जनवरी को खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा जारी खाद्य मूल्य सूचकांक बताता है कि खाद्य महंगाई दशक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। यह पिछले वर्ष के मुकाबले औसतन 28 प्रतिशत अधिक हो गई है।

एफएओ के अनुसार, अगर खाद्य मुद्रास्फीति को समायोजित कर दिया जाए तो 2011 के 11 महीने में मुद्रास्फीति पिछले 46 वर्षों में सबसे अधिक थी। मौजूदा हालात की तुलना 2011 की खाद्य महंगाई से की जाती है, जब एशिया खासकर पश्चिम एशिया और अफ्रीका में अरब स्प्रिंग नामक सरकार विरोधी प्रदर्शनों के चलते तख्तापलट हुए थे।

एफएओ के वरिष्ठ अर्थशास्त्री एब्दोलेजा एब्बासियन मौजूदा खाद्य महंगाई को मुख्य रूप से जलवायु परिस्थितियों से जोड़ते हैं। वह कहते हैं, 'कीमतों में सामान्य वृद्धि उत्पादन बढ़ाने, लागत में वृद्धि का रास्ता साफ करती है और अप्रत्याशित जलवायु परिस्थितियां 2022 में भी स्थायी बाजार के लिए बहुत कम उम्मीद छोड़ती हैं।'

1956 से 2010 के बीच दोहरी संख्या में मुद्रास्फीति की नौ श्रृंखलाएं रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, इनमें से सात श्रृंखलाएं सूखे के कारण पैदा हुईं। पिछले छह दशकों में दुनियाभर में 1970 के दशक, 2007-08 और 2010-14 में खाद्य महंगाई की तीन प्रमुख श्रृंखलाएं रहीं।

ये तीनों श्रृंखलाएं मुख्यत: जलवायु के झटकों की देन थीं। इसके बाद अन्य कारक जैसे तेल की कीमतों में वृद्धि, व्यापार नीति में दखल और बायो ईंधन का उपभोग जिम्मेदार थे। मौजूदा श्रृंखला पूर्ण रूप से असामान्य मौसम की देन प्रतीत हो रही है।

ऐसी परिस्थितियां वर्ष 2019-20 में भी बनी थीं। खाद्य पदार्थों की महंगाई, खासकर सब्जियों के ऊंचे दाम के चलते जनवरी 2020 में खुदरा मुद्रास्फीति 68 महीने के उच्चतम स्तर यानी 7.59 प्रतिशत पर पहुंच गई थी। तब खाद्य पदार्थों की महंगाई सुर्खियां बनी थी लेकिन इसके पीछे के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया।

चरम मौसम की घटनाओं ने फसलों को नुकसान पहुंचाया था जिससे सब्जियों की आपूर्ति श्रृंखला नष्ट हो गई थी। इससे सब्जियां बाजार में नहीं पहुंच पाई। वर्षवार तुलना में हम पाएंगे कि जनवरी 2019 के मुकाबले सब्जियों के दाम 50.19 प्रतिशत बढ़ गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों और बाजार में यह वृद्धि 45.56 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 59 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। छह श्रेणियों में बांटे गए उपयोग उत्पादों में सबसे अधिक वृद्धि खाद्य और पेय पदार्थों में हुई है जिससे समग्र मुद्रास्फीति में इजाफा हो गया। 2014 में जब मुद्रास्फीति एक भावनात्मक मुद्दा था, तब आरबीआई ने कहा, 'खाद्य महंगाई का परंपरागत कारण सूखा या बाढ़ से आपूर्ति में बाधा रही है।'

विश्व की मौजूदा खाद्य महंगाई मुख्य रूप से गेहूं के कारण है। इसकी कीमत सूखे और गेहूं उत्पादक देशों में अत्यधिक गर्मी के चलते बढ़ी है। 2021 में बहुत सी रिपोर्ट बताती हैं कि अमेरिका में स्प्रिंग गेहूं का उत्पादन 40 प्रतिशत तक कम हुआ है।

हिमयुग के बाद से हिमालय के ग्लेशियरों का 40 फीसदी हिस्सा हुआ गायब

पिछले कुछ दशकों में हिमालय के ग्लेशियर औसतन 10 गुना अधिक तेजी से पिघल रहे हैं

पिछले 400 से 700 वर्षों में, हिमालयी क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में ग्लेशियरों का लगभग 40 फीसदी हिस्से का नुकसान हो गया है। यह 28,000 वर्ग किलोमीटर से सिकुड़कर लगभग 19,600 वर्ग किलोमीटर रह गया है। ग्लेशियरों के तेज दर से पिघलने के ताजे जल संसाधनों और महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ सकते हैं।

संसद में इस बात की जानकारी देते हुए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लीड्स विश्वविद्यालय के एक हालिया अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि पिछले कुछ दशकों में हिमालय के ग्लेशियरों ने पिछले बड़े ग्लेशियर के विस्तार के बाद से औसतन 10 गुना अधिक तेजी से बर्फ खो दी है।

अध्ययन में विश्वविद्यालय की शोध टीम ने 14,798 हिमालय के ग्लेशियरों के आकार और बर्फ की सतहों का पुनर्निर्माण किया था, क्योंकि वे हिमयुग या लिटिल आइस एज के दौरान थे, जो कि 400 से 700 साल पहले का समय था।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि, पिघलने वाले ग्लेशियरों का हिमालयी नदियों के जल संसाधनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सिंह ने कहा ग्लेशियर बेसिन जल विज्ञान में परिवर्तन, नीचे की ओर तेजी से बहने वाले पानी, फ्लैश फ्लड और गाद की वजह से होने वाले बदलाव का जल विद्युत संयंत्रों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त जानकारी डॉ जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में सांसद दुष्यंत सिंह के एक प्रश्न के उत्तर में दी।

डॉ सिंह ने कहा ग्लेशियर से बनने वाली झीलों की संख्या और मात्रा में वृद्धि हो रही है।

फ्लैश फ्लड और ग्लेशियर की झीलों के फटने से बाढ़ और ऊंचे हिमालयी इलाकों में खेती के प्रभावित होने आदि के लिए तेजी से पिघलते ग्लेशियर जिम्मेवार हैं।

भारत के जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में ग्लेशियर मौजूद हैं। तिब्बत और नेपाल के ग्लेशियरों का भी भारत में बहने वाली कई सहायक नदियों और नदियों पर प्रभाव पड़ता है।

डॉ सिंह ने बताया कि मंत्रालय विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के माध्यम से हिमालय के ग्लेशियरों की निगरानी करता है। इसमें विभिन्न भारतीय संस्थान, विश्वविद्यालय और संगठन जैसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर), राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच), अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एसएसी) आदि शामिल हैं। जो ग्लेशियरों के पिघलने और ग्लेशियरों में तेजी से होने वाले नुकसान की समय-समय पर जानकारी देते हैं।

हिंदू कुश हिमालय के ग्लेशियरों की औसत पीछे हटने की दर 14.9 से 15.1 मीटर प्रति वर्ष (एम/ए) है, जो सिंधु में 12.7 से 13.2 मीटर/ए, गंगा में 15.5 से 14.4 मीटर/ए और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में 20.2 से 19.7 मीटर/ए से अलग-अलग है। हालांकि, काराकोरम क्षेत्र के ग्लेशियरों ने तुलनात्मक रूप से लंबाई में मामूली बदलाव दिखा है, शून्य से 1.37 - 22.8 मीटर / ए, जो स्थिर स्थिति का संकेत देता है।

मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न विश्वविद्यालयों और अन्य शोध संगठनों द्वारा हिमालय के ग्लेशियरों के लिए किए गए मास बैलेंस अध्ययनों से यह भी पता चला है कि हिमालय के अधिकांश ग्लेशियर अलग-अलग दरों पर पिघल रहे हैं या पीछे हट रहे हैं।

बढ़ती संवेदनशीलता

आपदाओं से दुनियाभर में आर्थिक क्षति लगातार बढ़ रही है

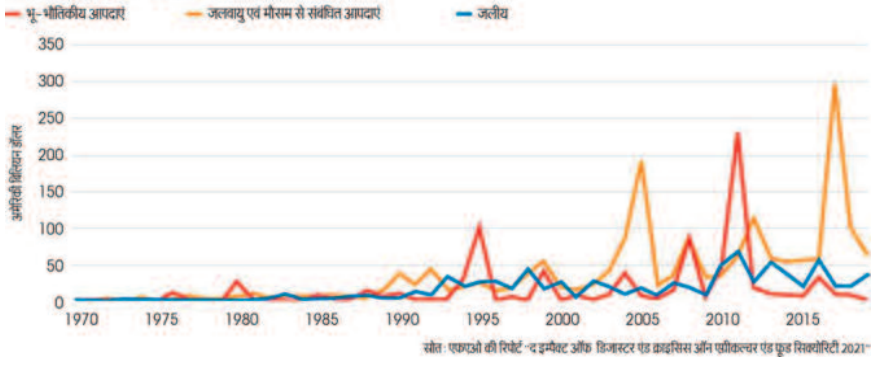

स्रोत: एफएओ की रिपोर्ट "द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर एंड क्राइसिस ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी 2021"

दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक रूस में इसकी पैदावार कम हुई है और उसने घरेलू उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इसके निर्यात पर टैक्स लगा दिया है। ब्राजील के कॉफी बीन उत्पादन क्षेत्र में जुलाई 2021 में अप्रत्याशित फॉस्ट (पाला) के कारण उत्पादन में 10 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। अंतरराष्ट्रीय कॉफी संगठन के अनुमान के मुताबिक, जलवायु के उतार चढ़ाव के चलते दुनिया के प्रमुख कॉफी उत्पादक अगले दो वर्षों में कीमतों में उछाल का सामना करेंगे।

ब्रिटेन स्थित वार्विक विश्वविद्यालय में ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के सीनियर टीचिंग फेलो एलिस्टर स्मिथ ने सितंबर 2021 में द कन्वरसेशन में लिखा, 'वर्ष 2000 से अनिश्चित और प्रतिकूल मौसम की घटनाओं को एफएओ ने बहुत बार रिपोर्ट किया है। इन घटनाओं ने उत्पादन की उम्मीदों और मौसमी उत्पादन को झटका दिया है।'

उन्होंने एफएओ के मुद्रास्फीति समायोजित खाद्य मूल्य सूचकांक का अध्ययन किया और पाया कि वैश्विक खाद्य मूल्य 2011 से अधिक है। यह वह दौर था जब महंगे भोजन के लिए हुए दंगों के चलते लीबिया व मिस्र में तख्तापलट हुआ था।

गैर-लाभकारी संस्था ऑक्सफैम ने खाद्य कीमतों पर प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के प्रभाव का आकलन किया है। 2012 में इसके अनुमानों से पता चलता है कि 2010 की तुलना में 2030 तक गेहूं के लिए औसत विश्व बाजार निर्यात मूल्य में 120 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

प्रसंस्कृत चावल के निर्यात मूल्य में यह वृद्धि 107 प्रतिशत और मक्का में 177 प्रतिशत होगी। तथ्य यह है कि जलवायु परिवर्तन बारिश और उसके वितरण को बदलकर कृषि चक्र को बदल रहा है।

सीधा संबंध

चरम मौसम की घटनाओं व घटती कृषि उपज के बीच सीधा संबंध है और खाद्य महंगाई की तस्वीर भी पहले से अधिक साफ हो चुकी है

गोभी के 40,000 पौधे और 15,000 फूलगोभी पूरी तरह नष्ट हो गई है। यह दर्द झारखंड के रांची जिले के मंदार गांव के किसान रमेश कुमार सिंह का है। 12 जनवरी 2022 को मंदार सहित कम से 9 जिलों के गांवों में भयंकर ओलावृष्टि हुई। इस समय फसल कटाई के लिए तैयार थी। सिंह कहते हैं, 'इस नुकसान से मेरी संभावित कमाई की उम्मीदें खत्म हो गईं और निवेश भी।'

पिछले साल का सितंबर महीना 27 वर्षों में भारत का सबसे नम महीना था। क्षेत्र के किसान अक्टूबर में बुवाई कर पाए लेकिन नवंबर-दिसंबर में हुई बेमौसम बरसात ने उनकी फसलों का चौपट कर दिया। सब्जी उगाने वाले रमेश जैसे किसानों ने इतना कुछ झेलने के बाद बड़ी उम्मीदों के साथ मौसम की आखिरी बुवाई की लेकिन जनवरी की ओलावृष्टि ने इस उम्मीद पर भी पानी फेर दिया।

मध्य प्रदेश निवाड़ी जिले में भी रबी की खड़ी फसलें 9 जनवरी को हुई ओलावृष्टि से जमीन पर बिछ गई। सुबह 8 बजे शुरू हुई ओलावृष्टि आधा घंटे तक जारी रही और करीब दर्जनभर गांवों में गेहूं, मटर, सरसों, ज्वार व अन्य फसलों को नुकसान पहुंचाती रही।

कलोथरा गांव के किसान संजीव प्रजापति बताते हैं, 'ओलों का वजन 10-50 ग्राम था और शाम तक नहीं गले। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी ओलावृष्टि नहीं देखी।' 25 दिसंबर के बाद से राज्य के 52 में से नौ जिलों में बारिश हुई है।

हाल के वर्षों में देश में चरम मौसम की घटनाओं ने किसानों को तबाह कर दिया है। यह 2021 में अति गंभीर थी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 20 नवंबर को लोकसभा में बताया, भारत ने 25 नवंबर 2021 तक चक्रवाती तूफान, अचानक बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से 5.04 मिलियन हेक्टेयर फसल क्षेत्र खो दिया है।

डाउन टू अर्थ के विश्लेषण से पता चलता है कि दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक 12 राज्यों के 80 जिलों में करीब 45 ओलावृष्टि की घटनाएं हुईं। इससे पहले इन राज्यों में भारी बारिश हुई थी, जब खरीफ की खड़ीं फसलों की कटाई की जा रही थी और किसान उन्हें बेचने के लिए तैयार थे। साथ ही, खेत सब्जियों जैसी नकदी फसलों के लिए भी तैयार थे।

भारत के सबसे गरीब जिलों में से एक ओडिशा के नुआपाड़ा में इस साल जनवरी में सामान्य से पांच गुना अधिक बारिश हुई। इसने किसानों के साल भर के निवेश को खत्म कर दिया क्योंकि रबी की हजारों हेक्टेयर फसल जैसे हरा चना, आलू, मसूर, बंगाल चना, लीमा बीन्स और प्याज में पानी भर गया है।

बेंद्राबहल गांव के एक छोटे आदिवासी किसान केदार सबर ने अपने 1.2 हेक्टेयर में गोल चना बोया था। इसे धान की कटाई से कुछ दिन पहले तराई में बोया जाता है। सबर कहते हैं, 'जब धान की कटाई के दौरान चने के पौधे पैरों के नीचे कुचले जाते हैं, तो वे तेजी से बढ़ते हैं और मिट्टी के सूखने पर फूलने लगते हैं।' अब बेमौसम बरसात से फूल झड़ रहे हैं।

बारिश ने उन किसानों का इंतजार भी बढ़ा दिया है जो अपनी फसल बेचने को तत्पर थे। नुआपाड़ा के बुदिकोमना गांव में रहने वाले आशीष पाढ़ी के पास 5 हेक्टेयर के उपजाऊ खेत हैं। वह बताते हैं, 'मैं 18 दिसंबर को छह टन धान मंडी ले गया।

मंडी में मिलर के न पहुंचने पर मेरे धान की खरीद नहीं हो सकी और धान खुले में पड़ा रहा। 11-12 जनवरी को हुई बारिश से धान गीला हो गया। इसके बाद बिचौलियों ने मुझसे 1,200 रुपए प्रति क्विंटल के भार से धान बेचने को कहा। यह भाव सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य से 760 रुपए कम था।'

ब्रेंदाभाई गांव के एक अन्य किसान संजय

बढ़ा हुआ खतरा

मौसम पर निर्भरता के कारण कृषि विशेष रूप से चरम मौसम की बढ़ती घटनाओं के प्रति संवेदनशील है

उद्योग वाणिज्य और पर्यटन के सापेक्ष में कृषि को नुकसान (2008-18)

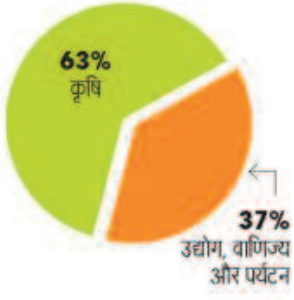

सभी क्षेत्रों में कुल क्षति के अनुपात में कृषि में नुकसान (2008-18)

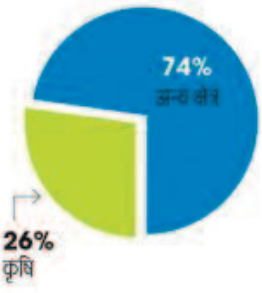

स्रोत: एफएओ की रिपोर्ट "द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर एंड क्राइसिस ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी 2021"

प्रभावित क्षेत्र

फसल और पशुधन उत्पादन में हानि का क्षेत्रीय वितरण, 2008-18

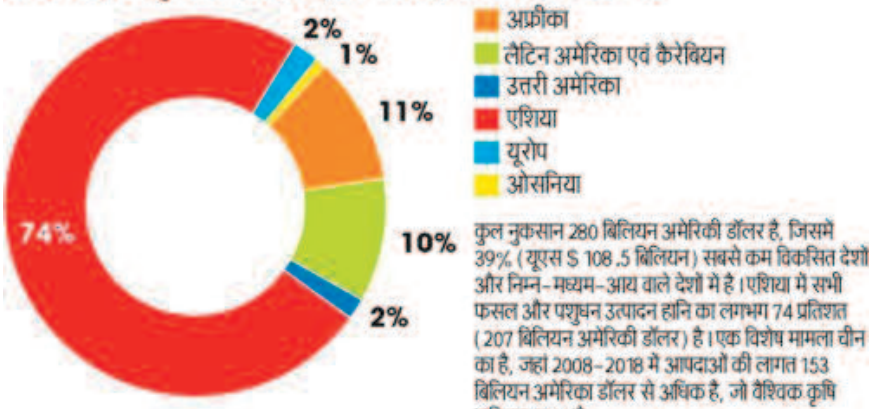

स्रोत: एफएओ की रिपोर्ट "द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर एंड क्राइसिस ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी 2021"

तिवारी ने बताया कि पूरे नुआपाड़ा के 1,000 किसानों का 5,000 टन धान खुले में पड़ा रहा। जैसे ही ओलावृष्टि और असामान्य रूप से अत्यधिक वर्षा की खबरें फैलीं, देशभर के उपभोक्ताओं ने तकलीफ महसूस की।

उनकी चिंता सब्जियों की ऊंची कीमतों को लेकर थी। रांची में फूलगोभी और टमाटर जैसी मौसमी सब्जियों की कीमतें 30 रुपए प्रति किलो से ऊपर पहुंच गईं। सामान्य वर्ष में इन सब्जियों की कीमत 5-10 रुपए प्रति किलो रहती है। डाउन टू अर्थ ने सर्वेक्षण के दौरान पाया कि 25 बाजारों में सब्जियों, गेहूं और धान की कीमत असामान्य रूप से अधिक थी।

प्राकृतिक आपदाओं के चलते खतरे में पड़ी खेती

ऐसे समय में जब एक औसत भारतीय परिवार अपनी कमाई का लगभग 50 प्रतिशत और गरीब 60 प्रतिशत से अधिक भोजना पर खर्च करते हैं, तब मूल्य वृद्धि देश में सबसे बुरे संकट को जन्म देगी

बर बिहार के मोकामा क्षेत्र में खेत में जमा पानी। मोकामा क्षेत्र दाल की खेती के लिए मशहूर है। फाइल फोटो: उमेश कुमार राय

बेमौसमी घटनाओं के चलते एक ओर जहां फसल बर्बाद हो रही है, वहीं खाने-पीने के चीजों के दाम बढ़े हैं। दुनिया भर में यही ट्रेंड दिख रहा है। डाउन टू अर्थ की इस खास सीरीज में इसे गहराई से समझने का प्रयास किया गया है। इस सीरीज की पहली कड़ी में आपने पढ़ा - फसल की बर्बादी ने बढ़ाई खाने की थाली की कीमत । पढ़ें अगली कड़ी -

चरम मौसम की घटनाओं और आपदाओं से कृषि अब तक सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र रहा है। पिछले दो दशकों में इस नुकसान में काफी इजाफा हुआ है। एफएओ के अनुसार, 1970 के दशक में एक वर्ष में केवल 100 आपदाएं आईं। 2000 के दशक में उनकी संख्या बढ़कर 360 और 2010 के दशक में 440 हो गई। सबसे कम विकसित देश (एलडीसी) और निम्न और मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) को इसका सबसे अधिक खामियाजा भुगतना पड़ा। एफएओ के अनुसार, 2008-18 में फसल और पशुधन उत्पादन में आपदा से गिरावट के कारण इन देशों को 108.5 बिलियन डॉलर (8.2 लाख करोड़ रुपए) का नुकसान हुआ (देखें, नुकसान का पैमाना)।

भारत में आपदा से हुई फसल क्षति के कारण मौद्रिक नुकसान पर कोई व्यापक डेटा उपलब्ध नहीं है। हालांकि, हाल के वर्षों में फसल के नुकसान पर संसद में सरकारी उत्तरों से एकत्रित आंकड़ों से पता चलता है कि 2016 से भारी बारिश और बाढ़ सहित मौसम संबंधी आपदाओं के कारण 36 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई है। 2016 में 6.65 मिलियन हेक्टेयर, 2017 में 5.08 मिलियन हेक्टेयर, 2018 में 1.70 मिलियन हेक्टयेर, 2019 में 11.42 मिलियन हेक्टेयर, 2020 में 6.65 मिलियन हेक्टेयर और 2021 में 5.04 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

केंद्र सरकार ने 17 सितंबर, 2020 को लोकसभा को बताया कि 2016 में 6.65 मिलियन हेक्टेयर पर फसलों को पहुंचे नुकसान का अनुमान 4,052.72 करोड़ रुपए था। यदि इसे 2016 से 36 मिलियन हेक्टेयर फसली क्षेत्र पर लागू कर दिया जाए तो यह 29,939 करोड़ रुपए के भारी नुकसान के रूप में परिलक्षित होता है। हालांकि, यह महज सांकेतिक आंकड़ा होगा। 2017 में 2016 की तुलना में कम फसल क्षति का क्षेत्र प्रभावित था, लेकिन नुकसान दोगुने से अधिक 8,761.39 करोड़ रुपए था। वर्षा की प्रकृति में बदलाव वर्षा आधारित कृषि के लिए बड़ा जोखिम है। इस खेती पर भारत की बड़ी गरीब आबादी जीवनयापन के लिए निर्भर है। यह खेती वैश्विक खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है।

हाल ही में यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) के वरिष्ठ प्रमुख अर्थशास्त्री माइल्स पार्कर और ईसीबी के उप महानिदेशक लिवियो स्ट्रैका ने 48 उन्नत और उभरते देशों में कीमतों पर मौसम के प्रभावों, विशेष रूप से तापमान के उतार-चढ़ाव

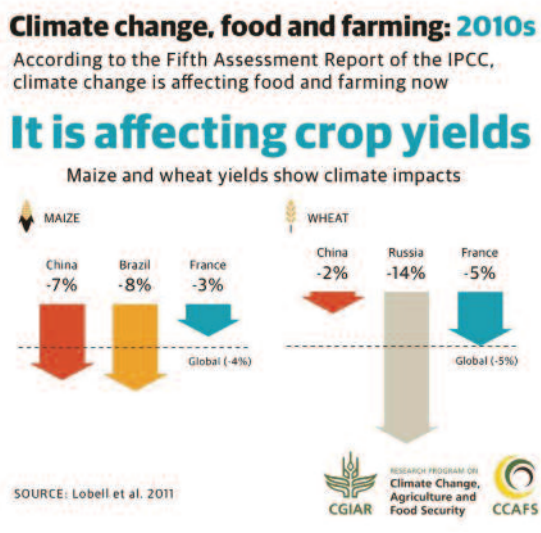

का अध्ययन किया। उन्होंने पाया है कि तेज गर्मी के दौरान खाद्य कीमतों में 0.38 प्रतिशत की वृद्धि होती है। ज्यूरिक में स्थित पुनर्बीमा कंपनी स्विस रे का अनुमान है कि बढ़ते तापमान से कृषि उत्पादन में गिरावट आएगी। अप्रैल 2021 में जारी बयान में उसने कहा, 'उच्च तापमान और चरम सूखे की घटनाएं श्रम उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। ये घटनाएं हीट स्ट्रेस का कारण बनेंगी और स्वास्थ्य पर बुरा असर डालेंगी।'

जलवायु का दुष्चक्र

एफएओ का कहना है कि आपदाओं के कारण दुनिया पहले ही 4 प्रतिशत संभावित फसल और पशुधन उत्पादन गवां चुकी है। यह नुकसान प्रतिवर्ष 6.9 ट्रिलियन किलो कैलोरी अथवा 70 लाख वयस्कों की वार्षिक कैलोरी सेवन के बराबर है। अगर इस नुकसान की व्याख्या गरीब, निम्न और मध्यम आय वाले देशों के संदर्भ में की जाए तो यह रोजाना 22 फीसदी कैलोरी की कमी है। इस लिहाज से देखें तों जलवायु परिवर्तन से जुड़ी आपदाएं न केवल किसानों की आय को प्रभावित करती हैं, बल्कि भोजन की उपलब्धता भी कम करती हैं। उत्पादन में कमी से कीमतों में वृद्धि होती है, जो अंतत: लोगों के भोजन ग्रहण की क्षमता पर असर डालती है।

यह जलवायु का ऐसा दुष्चक्र है जो हर किसी को अपनी जद में ले लेता है।2001-10 के दौरान 63 देशों में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि खाद्य मुद्रास्फीति में 1 प्रतिशत की वृद्धि से शिशु व बाल मृत्यु दर में 0.3 प्रतिशत और कुपोषण में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। गरीब देशों में ये प्रभाव गंभीर हैं। ऐसे समय में जब एक औसत भारतीय परिवार अपनी कमाई का लगभग 50 प्रतिशत भोजन पर खर्च करता है और गरीब 60 प्रतिशत से अधिक खर्च करते हैं, तब मूल्य वृद्धि देश में सबसे बुरे संकट को जन्म देगी। गरीबों को दोहरी मार का सामना करना पड़ेगा। एक, वे भोजन पर अधिक खर्च करने के लिए मजबूर होंगे और दूसरा, उनका स्वास्थ्य और खराब होगा।

भारत में गरीबी का स्तर तेजी से बढ़ सकता है और देश बाल मृत्यु दर और कुपोषण के खिलाफ अपनी लड़ाई में विफल हो सकता है। एडीबी के सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि जन स्वास्थ्य पर खाद्य मुद्रास्फीति का प्रभाव उन देशों में कम है, जहां सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अधिक योगदान है। ऐसे में समझदारी भरे उपायों की जरूरत जो कृषि को इन बदले हालात में अनुकूल बनाने में मदद कर सकते हैं। पहला उपाय कृषि विज्ञान की सलाह पर फसल पैटर्न को नए रास्तों पर ले जाना है। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि किसानों को मौसम संबंधी सलाह देने से उनकी आय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय मॉनसून मिशन (एनएमएम) और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सुविधाओं (एचपीसी) पर भारत के निवेश के आर्थिक प्रभाव को मापने के लिए किया गया था। किसानों को मौसम संबंधी सलाहों के आधार पर नौ महत्वपूर्ण कृषि पद्धतियों में संशोधन करने को कहा गया था।

एनसीएईआर के अनुमानों के अनुसार, जिस किसान परिवार ने कृषि पद्धतियों में बदलाव नहीं किया उसकी औसत वार्षिक आय 1.98 लाख रुपए लाख थी। लेकिन एक किसान जिसने 1-4 बदलाव किए, उसकी आय बढ़कर 2.43 लाख रुपए हो गई। पांच से आठ बदलावों के साथ किसानों की आय बढ़कर 2.45 लाख रुपए प्रतिवर्ष हो गई। जिन लोगों ने सभी नौ परिवर्तनों को अपनाया उनकी सालाना आय 3.02 लाख रुपए थी। रिपोर्ट में कहा गया है, 'बीपीएल व मछली पालन करने वाले परिवारों द्वारा एनएमएम और एचपीसी सुविधाओं में 1 रुपए का निवेश 50 गुना वृद्धि आर्थिक लाभ देता है।'

इस तरह के उपायों के बावजूद अप्रत्याशित मौसम की घटनाएं जैसे चक्रवाती तूफान, अचानक बारिश या भीषण गर्मी कृषि पर कहर बरपा सकती हैं। यहां फसल बीमा नुकसान की भरपाई में मददगार साबित हो सकता है और किसान को अगली फसल के लिए तैयार कर सकता है। लेकिन यह भी तभी कारगर है, जब नीतियां मजबूत हों। ■

नुकसान का पैमाना

कम विकसित देशों और निम्न-मध्यम आय वाले देशों में कुल फसल और पशुधन उत्पादन में हानि (यूएस डॉलर में), 2008-2018

मौलिक भारत विचार श्रृंख्ला-8

अजय सिंह 'एकल'

हर हाथ को काम-रोजगार के लिए रणनीतियां

● अजय सिंह 'एकल'

भारत की जनसंख्या देश की ताकत बन सकती है अगर हर काम करने में सक्षम व्यक्ति के पास उसकी क्षमता के हिसाब से काम हो। रोजगार पिछले कई दशकों से देश की ज्वलंत समस्या बना हुआ है । पिछली सरकारों ने इसके लिए बहुत काम किया है। पहले नेशनल स्किल डेवलपमेंट कार्पोरेशन की स्थापना की गई, इसको सहयोग करने के लिए 38 सेक्टर स्किल काउन्सिल बनाई गई जिनका काम बाजार की जरूरत के लिए उचित कौशल को चिह्नित करके, उसका पाठ्यक्रम तैयार करना फिर नौजवानों को प्रशिक्षण देकर काम के लिए तैयार करना था। जब इतने से बात नहीं बनी तो इसको गति देने लिए एक अलग कौशल विकास और उद्यमशीलता का मंत्रालय बनाया गया जिससे तहत नौजवानों को उद्यमों की आवश्यकता के लिए अलग- अलग तरह के कौशल विकास का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई साथ ही उद्यमशीलता को बढ़ावा देने का काम भी किया गया । मोदी सरकार ने इस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा की है । इसके तहत घोषित मुद्रा योजना, आत्म निर्भर भारत, लोकल फॉरवोकल, एक जिला एक उत्पाद इत्यादि योजनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इतना सब कुछ होने के बाद भी बड़ी तादाद में नवयुवक पढ़ लिख कर भी रोजगार के लायक नहीं बन पाए यह बड़ी चिंता का विषय है। देश के रणनीतिकार इस के संबंध में निश्चित ही चिंता और चिंतन करके इसका समाधान करने में लगे होंगे मैं ऐसा मानता हूं। अभी-अभी सम्पन्न हुए पांच विधानसभाओं के चुनावों में भी यह गंभीर और उत्तेजक चुनावी मुद्दा रहा है । अगर समस्या का संतोष जनक हल शीघ्र नहीं निकाला गया तो भविष्य में होने वाले चुनावों में यह मुद्दा और अधिक गंभीर होने वाला है। इतने प्रयासों के बावजूद समस्या का कारगर हल नहीं निकल पा रहा है तो इस पर हमे नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है जितनी जल्दी हो सके इसका प्रयास किया जाना चाहिए । ताकि समाज में बहुजन सुखाय का दर्शन हो सके।

देश में फैली हुई बेरोजगारी के लिए शिक्षा नीति को पांच दशकों से भी ज्यादा समय से दोषी माना जा रहा है लेकिन इसके लिए जो अलग- अलग प्रयत्न किए गए उनका परिणाम ज्यादा कुछ कर नहीं सका। मोदी सरकार 1.0 के कार्य काल में नई शिक्षा नीति में अमूल चूल परिवर्तन करके इसे रोजगार पूरक बनाने की बात कही गई परंतु इसको अंतिम स्वरूप मोदी सरकार के दूसरे कार्य काल की शुरुवाती वर्ष 2020 में ही जाकर मिल पाया । शिक्षा नीति 2020 लागू किए जाने में लगभग दो वर्षों का विलंब करोना महामारी के कारण हो गया, अब इसे जुलाई 2022 से लागू किया जाना प्रस्तावित है । इस नई शिक्षा नीति को रोजगार पूरक और उद्यमशीलता को बढ़ाने वाला बताया

जा रहा है। नीति की तार्किक समीक्षा करने से ऐसा ही महसूस होगा। लेकिन इसको लागू करने में कुछ कठिनाइयां भी है। पहली यह की शिक्षा राज्य का विषय है। अनेक राज्यों ने नीति की कई बिंदुओं पर आपत्ति की है। दूसरा इसको तेजी से लागू करने में अधिकारियों की कुशलता इत्यादि भी आड़े आएगी । सब कुछ यदि तय समय में हो जाए तो भी नई शिक्षा नीति के अपेक्षित परिणाम दस वर्षों के बाद ही दिखना शुरू होंगे। समस्या अति गंभीर है अत: अगले दस वर्षों तक परिणाम की प्रतीक्षा के साथ ही इस समयावधि में और क्या कुछ किया जा सकता है इस पर गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। तथा इस दिशा में अतिरिक्त प्रयास किए जाए तो समस्या से निजात पाने में सहायता मिलेगी।

बाजार में नौजवानो के लिए उचित अवसर उतने उपलब्ध नहीं है जितने होने चाहिए ताकि हर एक को काम मिल सके यह जितना सत्य है उतना ही सत्य यह भी है कि देश के नौजवान थोड़े समय और श्रम में ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर लेने के लिए अति महत्वाकांक्षी और अधीर है। बाजारवाद और उपभोक्तावाद की वजह से यह आधुनिक सोच का हिस्सा बन गया है। इसलिए एक तरफ तो लोग बेरोजगार है और दूसरी ओर व्यापार और उद्यमों के लिए काम करने में कुशल लोग नहीं मिल रहे है। नौजवान बड़े पैकेज की बात करते है और उद्यमी कम से कम पैसे में काम कैसे करवा ले इसकी जुगत करने में लगे है। सरकारों ने भी अकुशल एवं अर्ध कुशल कामगारों के लिए पारिश्रमिक तय किए है और उसका पालन न करने पर कानूनी कार्यवाही होने का प्रावधान है, परंतु इंजीनियर, डाक्टर तथा ऐसे ही अन्य कुशल लोगों के पारिश्रमिक को बाजार के भरोसे छोड़ देने का नतीजा यह हो रहा है की आपको ड्राइवर और राज मिस्त्री बारह हजार से बीस हजार प्रति माह में मिल जाएंगे जबकि कालेज से पढ़ कर निकले हुए इंजीनियर बारह हजार प्रति माह से पच्चीस हजार प्रति माह तक मिलेंगे। इतने पैसों में इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए उधार लिए पैसों का ब्याज और किश्त चुकाना और जीवन यापन करना मुश्किल है इसलिए जरूरतें पूरी करने के लिए बच्चों के जल्दी-जल्दी नौकरी बदलने से बेरोजगार या अर्ध रोजगार जैसी स्थित उत्पन्न हो जाती है।

करोना काल और उसके बाद यूक्रेन रूस युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों ने आत्म निर्भर भारत जैसे अभियान को और पुष्ट करने और तेजी से आगे ले जाने की महत्ता सिद्ध की है। सरकार ने अपने वित्तीय बजट में रक्षा क्षेत्र में 68 प्रतिशत तक अपनी जरूरते भारत में बने समान से पूरी करने पर बल दिया है इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यहां पर विचारणीय बात यह है अवसर बढ़ने के साथ इसमे काम आने वाले कौशल विकास को भी साथ साथ करना चाहिए । ताकि इस अवसर का पूरा लाभ उद्यमों और नौजवानों दोनों को मिले और विन -विन की स्थित बन सके।

नवजवानों के पास कौशल नहीं इसलिए उद्यमी कम पैसे दे और कौशल की कमी के कारण उद्यम का मुनाफा कम हो यह मुर्गी पहले कि अंडा पहले की स्थिति पैदा करता है। यदि उद्यमी अपने कर्मचारियों को संतुष्ट रखे तो कर्मचारी भी अपने कौशल को विकसित कर भरपूर उत्पादन करने के लिए प्रयासरत रहेगा यह दोनों के लिए सुखद स्थिति होगी। उद्यमी को इसपर विचार करना चाहिए और मालिक के बजाए माली की तरह व्यहारकरे, यानी जो कमजोर फूल या फल देने वाले पेड़ हो उन्हे उखाड़ फेकने के बजाय उन्हे पुष्ट करके उनसे बेहतर उत्पादन लेने से बात बन जाएगी।

केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को अपने प्रदेश की युवा नीतिओ को बनाते समय नवयुवकों के लिए रोजगार और समाज सेवा के अवसरों को चिह्नित करना और इसके लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वास्तव में देश में रोजगार की कमी है इसलिए नवयुवकों को काम नहीं मिल रहा है मैं इस विचार का समर्थक नहीं हूं । अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है की कोई भी आदमी एक मुहं और दो हाथ लेकर पैदा होता है इसलिए कोई भी बिना काम के रह ही नहीं सकता है। गलती जहां हुई है वह यह की वोटों के लिए सरकारों ने नवजवानों में सरकार नौकरी की व्यवस्था करेगी ऐसी आशा जगा दी जिसके कारण रोजगार देना सरकार के कामों में शामिल हो गया है। सरकार को अपनी गलती सुधारने के लिए रोजगार के अवसरों को चिह्नित करने के लिए अंतर मंत्रालय सहयोग करके अपनी नई योजनाएं बनाते समय ही उस काम में उपयोगी कौशल के लिए नवजवानों को कुशल बनाने की योजना को भी शामिल करना चाहिए और रोजगार आयोग बना कर इन योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।

दूसरी महत्वपूर्ण बात है नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा होना है और इसके लिए तैयारी पढ़ाई खतम करने के बाद होगी इसके बजाय इसकी तैयारी छोटे क्लास में पढ़ते समय होनी चाहिए । साथ ही इसकी तैयारी कुछ खास स्कूल या लोग करवाएंगे इसका इंतजार करने के बजाय समाज के लोगों को आगे आकर सहयोग करने से बात आसानी से बन जाएगी । आजकल समाज में परिवार छोटे होने के कारण बुजुर्गों के पास समय बिताने की समस्या से उनका स्वास्थ भी खराब कर रहा है और सेवनिवृत हुए लोग नवजवानों से अपने व्यवसाइक अनुभव साझा करके मार्गदर्शक और सलाहकार बने और बदले में नवयुवक

हुनर सीखने और कमाई करने के साथ बुजुर्गों का ध्यान रखे और उनके लिए सेवा भाव रखे तो दोनों के लिए सुखद स्थिति बन जाएगी। सरकार अपनी नीतियों द्वारा ऐसे बुजुर्ग जो नवजवानों के साथ समय लगा कर उनका जीवन बेहतर करने की कोशिश करेउन्हे आयकर इत्यादि में छूट देकर और नवजवान जो समाज में बुजुर्गों के साथ सेवा भाव के साथ काम करे उनके बच्चों के दाखिले इत्यादि में वरीयता देने का नियम बना कर प्रोत्साहन दे तो कार्य का प्रतिफल तुरंत मिलने से समाज के ताने बने को मजबूत किया जा सकता है।

एक समस्या जो नवयुवकों की है कि उन्हे काम करना नहीं आता अर्थात काम करने के लिए कौशल नहीं है। लेकिन मैं इसे बड़ी समस्या नहीं मानता क्योंकि यदि इच्छा शक्ति हो तो किसी भी काम में निपुणता मेहनत और लग्न से सीखी जा सकती है । इससे ज्यादा बड़ी समस्या है काम करने की इच्छा न होना। बिना काम या कम मेहनत से लाभ कमाने की इच्छा। इस समस्या का आसान उपाय है की पढ़ते समय ही काम करने की आदत बनाना। इस का जो माडल चार्टर्ड एकाउंटसी या मेडिकल की पढ़ाई का तरीका है उसी को इंजीनियरिंग और दूसरे व्यसायिक कोर्स के लिए भी अपनाना एक रास्ता हो सकता है। अर्थात पढ़ते समय काम करने की आदत पद जाए। साथ ही जैसे मेडिकल कालेज खोलने के लिए सम्बद्ध अस्पताल आवश्यक है वैसे ही इंजीनियरिंग कालेज का भी उद्यमों के साथ सम्बद्ध होना उद्यमियों को कालेज के मैनेजमेंट मैं ऐक्टिव रहना आवश्यक करने की नीति बनाई जानी चाहिए। प्रत्येक व्यसाइक कालेज के साथ उद्यमों का सम्बद्ध होना अनिवार्य हो। इतना है नहीं प्रति 100 छात्रों पर कमसे काम 100 करोड़ रुपये के टर्नओवर की एक या कई उद्यम मिलकर सम्बद्ध होना चाहिए। ताकि कुशल नौजवानों की लगातार उपलब्धि सुनिश्चित हो सके। सरकार इसके लिए ष्ह्यहके माध्यम से उद्यमों को प्रोत्साहित और आर्थिक लाभ की भरपाई की व्यवस्था कर सकी है।

नई शिक्षा नीति 2020 में सभी ग्रैजुएशन कोर्स की अवधि चार वर्षों की किए जाने का प्रस्ताव है। चार वर्षों के कोर्स में 2 वर्ष की पढ़ाई करने के बाद अगले दो वर्षों लगातार इंडस्ट्री या बिजनेस में काम करना आवश्यक होना चाहिए। इंडस्ट्रीइसमे सहयोग करे इसके लिए सरकार आय कर में छूट देकर या ऐसी दूसरी नीतियों को बना कर प्रोत्साहित किया जाने से बच्चों में काम करने की आदत और पढ़ाई पूरी होने के बाद इंडस्ट्री में काम करने की आदत बन जाएगी। यह नवयुवकों को रोजगारोन्मुख तो बनाएगा ही साथ ही कौशल युक्त कामगार उद्यमों में उत्पादन बढ़ाने में सहायक होंगे, उत्पादन बढ़ने से लागत कम होगी इससे उद्यमी का मुनाफा बढ़ेगा और ज्यादा टैक्स मिलने से सरकार की भी कमाई बढ़ जाएगी।

सरकारी नौकरी के लाभ जब तक उद्यमी बनने से ज्यादा आकर्षक रहेगे उद्यमी बनने का पारिस्थितिक तंत्र (इकोसिस्टम) कमजोर रहेगा । समाज के निर्माण में उद्यमी का रोल ज्यादा है इसलिए उसे नीतियां बनाते समय उसे महत्व दिया ही जाना चाहिए। उदाहरण के लिए नौकरी करने वाला व्यक्ति केवल अपने और परिवार के लिए काम करता है जबकि एक उद्यमी कुछ लोगों को रोजगार मुहैया करवाता है, करो के रूप में सरकार को रेवेन्यू देता है, उत्पादन और खपत में संतुलन बनाकर बाजार के तंत्र को सुचारु चलने में मदद करता है। इस पर भी उसका व्यापार खराब होने पर किसी प्रकार की सुरक्षा समाज या सरकार की तरफ से नहीं होती है। इसलिए पढ़ने के बाद नौकरी करने की लालसा रहती है। शादी ब्याह में भी नौकरी वाले नौजवानों और युवतियों को प्राथमिकता मिलती है। अत: नौकरी के लाभार्थियों की तरह उद्यमियों को भी आर्थिक सुरक्षा व्यवस्था मुहाईया करवाने से उद्यमियों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी और यह नीति देश के नवजवानों के लिए रोजगार भी पैदा करने में सहायक होगी।

नैसकाम और फिक्की द्वारा प्रकाशित एमपलॉयबिल्टी रिपोर्ट में जिन योग्यताओं का जिक्र है उसमे प्रमुख है, सम्प्रेषण कौशल (Communication Skill), वृतिक कौशल (Professional Skills), विशिष्ट कौशल (Specific Skill)। इन योग्यताओं में केवल विशिष्ट कौशल के लिए पढ़ाई पूरी करने या ग्रेजुएशन इत्यादि तक इंतजार की जरूरत हो सकती है बाकी दो योग्यताओं को प्राप्त करने की तैयारी कक्षा छै से ही की जानी चाहिए, क्योंकि इनका संबंध मनोभाव और नजरिए से है और यह एक दो वर्षों मैं नहीं बल्कि लंबे समय तक अभ्यास से आती है। अत: आवश्यक है इन योग्यताओं की छोटी आयु से ही धीरे-धीरे आदत बन जाए और विशिष्ट कौशल प्राप्त करते हुए यह व्यवहार में शामिल हो जाए। यह योग्यता नवजवानों को नौकरी में नहीं जीवन में भी सफल बना देगी।

भारत तेजी से 5 ट्रिलियनडालर अर्थ व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है। इसमे सेवा क्षेत्र का बड़ा योगदान रहने वाला है। देश में बड़ी जनसंख्या प्रगति में रोड़ा बनने के बजाय इसमे सहायक बन सकती है यदि हम अपने प्रयासों से हर हाथ के लिए काम की व्यवस्था कर दे । नीतियों में थोड़ा परिवर्तन और पिछली गलतियों से सबक सीख कर उन्हे सुधारने से बात बन सकती है । इस तैयारी के लिए अमृत महोत्सव वर्ष से ज्यादा उपयुक्त समय और क्या हो सकता है । वैसे भी मन में एक बात तो आती ही है की अभी नहीं तो कब? पिछत्तर वर्ष तो हमने निकाल ही दिए है तो क्या अगले पचहत्तर वर्ष भी हम ऐसे ही अस्तव्यस्तता में बिताने के लिए तैयार है? यदि नहीं तो समस्या के निदान के लिए सुझाओ पर अमल करके अगले दस वर्षों में इस स्थिती में परिवर्तन ला कर सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन के भागीदार बन कर देश की और अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करे । ■

'आत्म निर्भर महिला, आत्म निर्भर भारत' विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार

सम्मानित किये गये नेशनल वूमेन अचिवर्स 2022 के अवॉर्डी

● सम्यक अग्रवाल

समाजसेवी संस्था दीप वेलफेयर आर्गेनाईजेशन ने 25 मार्च 2022 को नई दिल्ली के कांस्टीट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया, रफी मार्ग में एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार और नेशनल वूमेन अचीवर्स अवॉर्ड 2022 का आयोजन किया।

समारोह के प्रमुख अतिथियों में जाने माने शिक्षाविद एवं वरिष्ठ समाजसेवी प्रो. विक्रम दत्त, डॉ. रश्मि सिंह (विशेष निदेशक और सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग व समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार), डॉ. अजय कुमार (चैयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर फॉक्स कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, फॉक्स रूबिकन कैपिटल पार्टनर्स, फॉक्स पेट्रोलियम ग्रुप ऑफ कंपनीज), सुरेश शर्मा पूर्व आई. जी.पंजाब पुलिस, नीलिमा शर्मा एल. आई.सी.इंडिया एवं नीतू सिंह (एक वूमेन एंटरप्रेन्योर और एमडी और फाउंडर सिनी डिजाइन्स प्रा. लिमिटेड) ने भाग लिया। समानित अतिथियों ने भारत के विकास में महिलाओं के योगदान की आवश्यकता बताते हुए सभी प्रतिभागियों के बीच अपने विचार साझा किए। दीप संस्था के अध्यक्ष अजय प्रकाश ने अपने स्वागत भाषण में सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का प्रति कृतज्ञता ब्यक्त करते हुए संस्था के 17 वर्ष कार्यो का विवरण सभा के सामने उल्लेख किया। इसके साथ ही साथ सेमिनार के मूल उद्देश्य की जानकारी भी प्रदान की ।

इस राष्ट्रीय सेमिनार में नेशनल वूमेंस अवॉर्ड 2022 भी आयोजित किया गया था। जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली 15 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इनमें 2018 में ऑल इंडिया रैंक 42 हासिल करने वाली आईएएस नंदिनी महाराज को लोक सेवा में योगदान देने के लिए, विनीता बक्शी को महिला सशक्तीकरण हेतु, पूनम श्रीवास्तव को महामारी के दौरान दिए गए योगदानों के लिए कोविड वॉरियर के रुप में सम्मानित किया गया, मालविका सहगल (डाइटीशियन), को पोषण आहार पर काम करने के लिए, मधुर शर्मा को सोशल एंटरप्रेन्योर, गीतांजलि त्रिपाठी को सी एस आर में योगदान के लिए, अल्का चौधरी को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए, अनुराधा पांडेय को राष्ट्रीय भाषा को बढ़ावा देने और साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान के लिए, अंशु मुदगल को महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने हेतु, अनीता पांडेय को कानूनी क्षेत्र में काम करने के लिए, अनिला शुक्ला को समाज सेवा के क्षेत्र में, सारिका अग्रवाल को पर्यावरण संरक्षण एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, तारा अपाचू शर्मा को सतत विकास पर

करियर प्लस की उपाध्यक्ष शिक्षाविद डॉ. सारिका अग्रवाल को मिला 'नेशनल वुमन अचीवर्स अवार्ड -2022'

नोएडा निवासी शिक्षाविद व समाजसेवी डा. सारिका अग्रवाल को दिनांक 25 मार्च 2022 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित एक समारोह में ' नेशनल वुमन अचीवर्स अवार्ड -2022' से सम्मानित किया गया। दीप वेलफेयर सोसाइटी, मेट्रिक्स सोसाइटी व शोध संस्था द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री श्रीमती पूर्णिमा भौमिक मुख्य अतिथि थीं।

पिछले पच्चीस वर्षों से आईएएस, पीसीएस व अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं आदि की कोचिंग के क्षेत्र में देश की अग्रणी संस्था करियर प्लस एजुकेशनल सोसाइटी की उपाध्यक्ष डा सारिका अपनी संस्था के माध्यम से दलित, गरीब, दिव्यांग व पिछड़े हजारों छात्र छात्राओं को निशुल्क कोचिंग उपलब्ध करा उनको सफलता के शिखर पर पहुंचा चुकी हैं। उनकी संस्था भारत सरकार व अनेक राज्य सरकारों के साथ मिलकर भी कार्य करती है। डा सारिका अपने पति अनुज अग्रवाल के साथ मिलकर मौलिक भारत संस्था व डायलॉग इंडिया प्रकाशन के माध्यम से भी सुशासन, चुनाव सुधार, राष्ट्रपरक वैकल्पिक नीतियों, धर्म संस्कृति के उत्थान व समाज सुधार के लिए निरंतर कार्य करती रहती हैं।

काम करने हेतु और एडवोकेट सारिका वर्मा को कानूनी जागरूकता पैदा करने हेतु एवं निशा जैन (दिव्यांग) दिव्यांग जनो के उत्त्थान के लिए सम्मानित किया गया।

सभी ने सम्मानित महिलाओं को अपना एक नया रास्ता चुन कर अपने आपको आत्मनिर्भर साबित करने के लिए बधाई दी और इसे देश की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा दायक बताया। दीप संस्था के अध्यक्ष श्री अजय प्रकाश जी ने, मैट्रिक्स सोसाइटी के अध्यक्ष डॉ राजेश कुमार सिंह और शोध संस्था के फाउंडर राजीव पांडेय ने सभी अतिथियों का स्मृति चिन्ह और शॉल प्रदान करते हुए स्वागत और सम्मानित किया। दीप संस्था के अध्यक्ष श्री अजय प्रकाश ने सभी अतिथियों को धन्यवाद किया एवं इस सेमिनार के आयोजन को सफल बनाने में मैट्रिक्स सोसाइटी फॉर सोशल सर्विसेज एवम शोध संस्था, एजुकेशनल फोरम

एवं अन्य सहयोगी संगठनों की महती भूमिका का उल्लेख किया एवं सभी का आभार प्रकट किया। इसके अलावा किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने वितीय सहयोग की जरूरत होती हैं। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में वितीय सहयोग के लिए फॉक्स कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट,फॉक्स रूबिकॉन कैपिटल पाटर्नर्स, फॉक्स पेट्रोलियम ग्रुप और एल. आई. सी इंडिया को अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापित एवं आभार किया गया। इस कार्यक्रम में मीडिया पार्टनर्स तौर पर सोशल संवाद, डायलॉग इंडिया, पंचायत खबर, द न्यूज 24, राष्ट्र समाज, यूथ कैम्पस आदि थे। सभी ने सेमिनार उठाए गए मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। ■

श्री वैश्य समाज वसुंधरा का होली मिलन कार्यक्रम

दिनांक 19 मार्च 2022 को श्री वैश्य समाज वसुंधरा (रजिस्टर्ड) ने होली मिलन कार्यक्रम के तहत फूलों की होली का भव्य कार्यक्रम वंदना फार्म हाउस लिंक रोड में किया। समारोह में विशिष्ट अतिथि श्री आर के गर्ग (डायरेक्टर, बिसलेरी) एवं श्री अनुज कुमार अग्रवाल (प्रधान मौलिक भारत एवं प्रधान संपादक डायलॉग इंडिया) ने शिरकत की। श्री अनुज अग्रवाल जी की पूज्यनीय माता आदरणीया श्रीमती सत्यभामा अग्रवाल जी ने भी पूरा कार्यक्रम पूरी रूचि के साथ देखा। भव्य समारोह में बड़ी संख्या में सम्मानित सदस्य एवं अतिथि एकत्र हुए। समाज के प्रधान श्री अनिल कुमार अग्रवाल एवं महासचिव श्री पुनीत कुमार मित्तल ने सभी सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद दिया। समारोह में सी एल गुप्ता, रोहित गुप्ता, राकेश गुप्ता,शशि-शालिनी माहेश्वरी, बाल किशन बंसल, दिव्यानु गुप्ता, नरेश गुप्ता, नरेश अग्रवाल, अवलोक अग्रवाल, मुकेश गुप्ता, मुकेश अग्रवाल, दिव्य गुप्ता,राहुल अग्रवाल, अरुण गुप्ता, प्रतीश गर्ग, एवं अनेकानेक गणमान्य अतिथियों एवं सदस्यों ने कार्यक्रम की शोभा बढाई।

राजू प्रिंस एंड पार्टी ने भव्य फूलों की होली से सभी उपस्थित जन समूह को भक्तिमय एवं रोमांचित कर दिया। पूरा माहौल राधा कृष्ण माहौल में रंग गया।

महासचिव पुनीत कुमार मित्तल ने बताया कि इस मौके पर करीब 600 सदस्य परिवार एकत्र हुए। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर स्वादिष्ट व्यंजनों के विभिन्न स्टॉल लगाए गए। साथ ही लकी ड्रा द्वारा विभिन्न पुरुस्कार दिए गए।

वैश्य समाज, वसुंधरा ग़ाज़ियाबाद द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में सपरिवार भागीदारी। समाज के अध्यक्ष पवन अग्रवाल जी व महासचिव पुनीत मित्तल जी द्वारा मुझे व मेरी माँ सत्यभामा जी को दिए गए सम्मान व अभिनंदन का आभार। ब्रज की संस्कृति को उकेरते नृत्य संगीत व फूलो की होली ने वातावरण को कृष्णमय कर दिया।

जीटीटीसीआई द्वारा आयोजित फ़िजी के दूतावास में होली मिलन का रंगारंग कार्यक्रम

फिजी के हाई कमिश्नर कमलेश शशि प्रकाश एवं जीटीटीसीआई के अध्यक्ष गौरव गुप्ता के आमंत्रण पर आज फिजी दूतावास में आयोजित होली मिलन के रंगारंग कार्यक्रम में बेटे सम्यक सहित भाग लिया व अनेक भारतवंशी देशों के राजदूतों व हाई कमिश्नर से मुलाक़ात की। मॉरीशस, गुयाना, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो के कई अन्य सम्मानित राजदूत इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अमेरिका और बुर्किना फासो के कई राजनयिक इस खूबसूरत कार्यक्रम का हिस्सा थे।

मीना
जी

महामानव की विडम्बना

श्रीकृष्ण अपने युग के एक सर्वोत्तम व सर्वोन्नत प्रभु स्वरूप महामानव हुए हैं। आज उनके लाखों मंदिर, अनगिनत अनुयायी और भक्त हैं। पर अपने समय में वो कितने एकाकी रहे यह बात समझने की कोई भी चेष्टा नहीं करता। उनके साथ केवल कुछ गोपियां पांच पांडव तथा विदुर आदि ही रहे वो भी छूटे। पांडव महाभारत जीतकर अपना राज्य लेकर मगन हो गये। विदुर ने भी अंत समय धृतराष्ट्र के संग ही वन गमन किया।

सब उनका सत्य जानते थे उनकी आवश्यकता सबको होती थी पर उनके साथ कितने रहे कितनों ने उनका एकाकीपन समझने व बांटने की चेष्टा की। भीष्म पितामह को भी शरशैय्या पर पड़े हुए अपनी मुक्ति हेतु मधुसूदन ही याद आए। जब भी किसी को कष्ट या समस्या होती तो श्रीकृष्ण को ही पुकारते। सुदामा भी धन वैभव पाकर अपनी राह चले गये। कब किया उन्होंने गीता के वचनों का पठन-पाठन या शिक्षा का दान, जबकि वो ब्राह्मण शिक्षक थे। इतनी वैभवपूर्ण, सौन्दर्यमयी व भव्य द्वारका नगरी बसाई पर वहां के निवासियों ने ना गीता गुनी और ना ही उसका प्रचार-प्रसार किया। बल्कि भोग विलास में लिप्त होकर इतनी ऐश्वर्यवान नगरी व श्रीकृष्ण की सर्वप्रिय सनातन संस्कृति को ही नष्ट भ्रष्ट बनने का कारण बने। अंत में वो सब भी आपसी वैमनस्य व संघर्ष में समाप्त हो गये। वास्तुकला की अद्‌भुद कृति द्वारका भी समुद्र में विलीन हो गयी।

यही है प्रत्येक सनातन धर्म व मातृभूमि का कल्याण चाहने वाले, सतकर्म करने वाले की नियति- उसके आभामंडल का आनंद व लाभ तो सब उठाना चाहते हैं पर उसके दिखाए सुझाए व बताए मार्ग पर चलने की साधना विरले ही कर पाते हैं। अपने समय में प्रत्येक उन्नत मानव को नकारात्मकता ही अधिक सहनी पड़ती है। जबकि वो अपने सारे दुखों व कष्टों को छुपाकर सबमें सकारात्मकता ही बांटता फिरता है। ग्वालों को इन्द्र के वृष्टि प्रकोप के समय संरक्षण दिया। गोपियों का नीरस जीवन रसमय किया। पांडवों को हर कठिन समय में अवलम्बन दिया। कुंती व द्रौपदी के सम्बल बने। सदा सबके सखा-सहाय बने कि कोई तो उनके उदाहरण स्वरूप जीवन से शिक्षा लेकर अपने को बदले, ऊंचा उठे, प्रभुता प्राप्त करे और सब ओर शांति व आनंद का साम्राज्य हो। इसके लिए अर्जुन को माध्यम बना समस्त ज्ञान निचोड़कर उडेल दिया। सदा का मूर्ख मानव एक ही रट लगाए रहता है कि ज्ञान चाहिए जीवन में कुछ करना है। आनंद पाना है मोक्ष मिल जाए पर इसके लिए उसे ना तो स्वयं पर कर्म करना है ना ही उसे वेद उपनिषद या इन सबका सत्व-गीता, कुछ भी दिखायी नहीं देता। कितनी ही महान आत्माएं समय-समय पर मार्गदर्शन देती रहती हैं। पर उस पर चिंतन मनन कर अपना कर्मपथ सुनिश्चित करने का प्रयत्न कोई विरला ही कर पाता है। इसके विपरीत वाद विवाद तर्क कुतर्क विवेचना आलोचना में, सत्य को नकारने में सारी बुद्धि लगा अपने अहम् को पोषित करने में समय नष्ट करता रहता है। बताये गये ज्ञानानुसार कर्म ना करने की सारी युक्तियां समझा सकता है।

अवतारों के अवतरण की पावन भूमि भारत के महान ऋषि वैज्ञानिकों व संतों ने क्या नहीं बताया या लिपिबद्ध किया। उनके जाने के कई वर्षों बाद उनके मंदिर बन जाते हैं पूजा व स्तुति ज्ञान किये जाते हैं। तब तक वो जिन्होंने उन्हें, उनके समय में पूरी तरह नकारा सताया अपशब्द कहे वो तो यह सब देखने के लिए जीवित नहीं रहते फिर अपनी गलती कैसे समझ आयेगी। यही दौड़ चलती रहती है। सर्वोत्तम मानव, अवतार समय से आगे होता है। जिन पुरानी रूढ़ियों व मान्यताओं का मानव उत्थान में कोई योगदान नहीं होता उन्हें पूर्णतया नकार देता है तथा अन्य मानवों जैसा नहीं होता। यही बात बुद्धिजीवियों व औरों के लिए ईर्ष्या व द्वेष का कारण बन जाती है। सारी शक्ति, उसका महत्व समझने की अपेक्षा उसे नकारने में लगाने लगते हैं।

यही है मानव की विडम्बना, अपना उत्थान हो ना हो पर दूसरे का क्यों होने दें। पर अब कलियुग में झूठ ही झूठ को विनष्ट करने का माध्यम बन जायेगा। मानव को अब यह सत्य समझना ही होगा कि सत्य प्रेम कर्म व प्रकाश का मार्ग ही वास्तविक आध्यात्म है। तो आओ स्वयं के सत्य को जानकर, स्वयं को परिष्कृत कर सही मानव बनने का संकल्प लेकर युग परिवर्तन का श्री गणेश करें। जब सत्यमेव जयते होना आरम्भ हो जाएगा तभी सतयुग का प्रारम्भ होगा।

जय सत्येश्वर
प्रणाम ॐ ॐ ॐ
प्रणाम मीना ॐ

Career Magazine
DIALOGUEINDIA
... Dialogue for Change
Consistent Journey of Rating ...
Career Portal : www.dialogueindiaacademia.com
राष्ट्रवादी पत्रकारिता की सतत् यात्रा ...
News Portal : www.dialogueindia.in
राजनीतिक पत्रिका
डायलॉग इंडिया
************ परिवर्तन की चाह - संवाद की राह
सफलता के 12 वर्ष
12 Year of Success
GET RANKED AMONGST THE TOP COLLEGES IN INDIA
Participate in the Dialogue India National Ranking & Awards for India's Best Colleges / Universities - 2020
DIALOGUE INDIA National Ranking
DIALOGUE INDIA Academia Awards
DIALOGUEINDIA Academia Conclave
DIALOGUEINDIA
India's BEST INSTITUTIONS
मूल्य 30/-
डायलॉग इंडिया
अगस्त, 2021
संघ परिवार
बाजी पलटने की जिद
विपक्षी नेतृत्व का द्वंद
राहुल बनाम ममता
Anuj Agarwal
Group Editor
DIALOGUEINDIA
National President
CAREER PLUS EDUCATIONAL SOCIETY
National President
MAULIK BHARAT
Founder Director
GLOBAL CHAMBER OF SPORTS EDUCATION & CULTURE FOUNDATION
Our Other Initiative
GLOBAL CHAMBER OF SEC
Career Dream
A Leading Institute for Bank / SSC / Railways / LIC / GIC / NDA / CDS / CPF & Other Competitive Exams
Career Plus
Subject : G.S. • ESSAY • P.A. • HISTORY • GEOGRAPHY • SANSKRIT LITT. • HINDI LITT.
Career Plus SKILLS
INSTITUTE OF SKILL DEVELOPMENT
Career Plus
EDUCATIONAL SOCIETY
मौलिक भारत
Head Office : 301/A, 37-38-39, Ansal Building, Commercial Complex, Mukherjee Nagar, Delhi-9
dialogueindia.in@gmail.com • dialogueindiaacademia@gmail.com,
Phone/Fax : 011-27654588, Mob. : 9811424443

This issue Published on 1st April, 2022 Postal Registration No. G-3/DL (N)/252/2020-22, Postal dt. 1st & 2nd Every Month

R.N.I. No. - DELHIN/2009/30089

Career Plus People - Born to Lead

2022 IAS/PCS 2023

PRELIMS • MAINS • PRELIMS CUM MAINS

New ONLINE/OFFLINE Batches in English/Hindi Medium

SUBJECTS AVAILABLE

GEN. STUDIES (for Prelims/Mains), CSAT & ESSAY

HISTORY | GEOGRAPHY | SOCIOLOGY

POLITICAL SCIENCE | PUBLIC ADMINISTRATION

SANSKRIT "LITERATURE" | HINDI "LITERATURE"

By Most Renowned & Competent Facilities under the Leadership & Direction of

Mr Anuj Agarwal & Niraj Kushwaha

Silver Jublee Year (Since 1997)

Career Plus

English / हिन्दी Medium Hostel Facility

EDUCATIONAL SOCIETY

A Legacy of 25 Years

Study Material & Test Series

44 SELECTIONS IN IAS 2020

H.O. : 301/A,37,38,39, Ansal Building, Behind Safal Dairy, Mukherjee Nagar, Delhi-9

9891186435, 9811069629, 9015912244, 011-27654588

Website : www.careerplusonline.com / www.careerplusgroup.com